



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

३ अग्रहायण १९३७ (श०)

(सं० पटना १२८३) पटना, मंगलवार, २४ नवम्बर २०१५

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचनाएँ

१९ नवम्बर २०१५

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, २०१५

सं० १०/प्र०ग०स्था०-१७/२००३-२१४०—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, २००० (२००० का ५६) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा ६८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

अध्याय १ प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।—(१) यह नियमावली “बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, २०१५” कही जा सकेगी।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. परिभाषाएँ।— (१) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, २००० (२००० का ५६) समय-समय पर यथा संशोधित;

(ख) “परित्यक्त” से अभिप्रेत एक अकेला तथा परित्यक्त बालक है, जिसे सम्यक् जाँच के पश्चात समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया हो;

(ग) “बालक के उत्तम हित” से अभिप्रेत किशोर या बालक के भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये लिया गया निर्णय;

(घ) “बालदुर्व्यवहार” से अभिप्रेत वह व्यवहार है जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी शामिल होः—

- शारीरिक, मानसिक, यौन या भावनात्मक कुव्यवहार;
- शब्द या कृत्य द्वारा कोई कार्य जिससे बालक की गरिमा का तिरस्कृत होती हो;
- जीवित रहने के लिए उसकी बुनियादी आवश्यकताओं से वर्चित किया जाना।

(ङ.) “बालक मित्रापूर्ण” से अभिप्रेत कोई प्रक्रिया और व्याख्या निर्वचन, रखैया, वातावरण तथा व्यवहार है, जो दयापूर्ण तथा दूरदर्शी बालक के उत्तम हित में हो;

(च) “सामुदायिक सेवा” से अभिप्रेत अन्य न्यायिक उपचारों एवं शास्तियों के स्थान पर विधि के विरोध में किशोरों द्वारा समाज को प्रदत्त सेवाएँ, निर्दिष्ट करती हैं जो तिरस्कारपूर्ण तथा अमानवीय नहीं हैः—
इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं (केवल गैर-जोखिम वाले भाग) :-

- पार्क की सफाई करना/उद्यान स्थापित करना;
- नर्सिंग गृहों या वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करना;
- स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह में सहायता करना;
- निःशक्त बच्चों की सेवा करना;
- सामुदायिक स्तर पर वृद्धजनों की देखभाल करना;
- समूह कार्य;
- अपने आवास क्षेत्र में मानवता से संबंधित कार्यों में सम्मिलित होना।

(छ) विधि के विरोध में किशोरों के मामले में “निरुद्घता” से अभिप्रेत प्रत्यावर्तनात्मक (restorative) न्याय के सिद्धांतों के संगत “संरक्षात्मक अभिरक्षा” है;

(ज) “प्रारूप” से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत हैं;

(झ) “बालक देखरेख” से अभिप्रेत बाल कल्याण समिति द्वारा किये गये आदेशानुसार पालक माता-पिता द्वारा एक नियत अवधि के लिये देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की देखरेख तथा संरक्षण है;

(ज) “समूह परामर्श” से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित किसी समूह परामर्श कार्यक्रम में किशोर की भागीदारी के लिए किशोर न्यायमंडल द्वारा अधिनियम की धारा 16 के अधीन आदेश अभिप्रेत है;

(ट) “वैयक्तिक देखरेख योजना” किशोर या बालक के लिए व्यापक विकास योजना है, जो आयु विशेष तथा लिंग विशेष की आवश्यकताओं तथा किशोर या बालक के पूर्ववृत पर आधारित होती है तथा जो किशोर या बालक के आत्मसम्मान, गरिमा तथा स्वाभिमान को पुनःस्थापित करने हेतु किशोर या बालक से मंत्रणा करके तैयार की जाती है एवं तदनुसार योजना किशोर या बालक की निम्नांकित आवश्यकताओं पर ध्यान देगीः—

- स्वास्थ्य आवश्यकताएँ;
- भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ;
- शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण आवश्यकताएँ;
- आराम, सृजनात्मकता तथा खेलकूद;
- भावनात्मक लगाव एवं रिश्तेदारी;
- सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा खराब व्यवहार से संरक्षण;
- समाज की मुख्य धारा में शामिल करना; तथा
- निर्मुक्त एवं प्रत्यावर्तन के पश्चात् उसका अनुवर्तन।

(ठ) “संस्था” से अभिप्रेत अधिनियम की क्रमशः धाराओं 8, 9 एवं 34, धारा 34 की उप-धारा (3) तथा धारा 37 के अधीन स्थापित, अभिप्रमाणित या मान्यकृत तथा निर्बोधित कोई सम्प्रेषणगृह, विशेष गृह, बाल गृह या आश्रय गृह हैं;

(ङ) “अधीक्षक” से अभिप्रेत संस्थान के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिये नियुक्त व्यक्ति है;

(ङ) “अनाथ” से अभिप्रेत ऐसा बालक है जो माता-पिता के बिना है या इच्छुक एवं सक्षम विधिक या नैसर्गिक संरक्षक के बगैर है;

(ण) “सुरक्षित स्थान” से अभिप्रेत विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालकों के लिये अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) तथा धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तथा मान्यता प्राप्त कोई संस्था है;

(त) “उपयुक्त व्यक्ति”, “उपयुक्त संस्था” से अभिप्रेत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया गया कोई व्यक्ति या, अधिनियम की धारा 2 के खंडों (ज) एवं (झ) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त पायी गयी कोई संस्था है। इसे उस विनिर्दिष्ट बालक के लिए अस्थायी अवधि तक मामला के आधार पर किया जायेगा। ये संस्थाएं किसी अधिनियम के अधीन निर्बंधित हो सकती हैं;

(थ) “पंजीकृत” से अभिप्रेत धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन निर्बंधित देख-रेख तथा संरक्षण के आवश्यकता वाले बालकों को आवासीय देखरेख या कोई अन्य देखरेख उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थायें या एजेंसियां या स्वैच्छिक संगठन हैं;

(द) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत बिहार सरकार है;

(घ) “धुमंतु तथा कार्यरत बालकों” से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ)(i) के अधीन प्रतिपादित प्रावधानों के अनुरूप आजीविका, देखरेख, संरक्षण तथा सहारे के पर्याप्त साधनों से रहित बालक है;

(न) “अव्यर्पित बालक” से अभिप्रेत ऐसा बालक है, जो समिति की राय में माता पिता या संरक्षक के नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक कारकों के कारण त्यागा हुआ हो;

(2) अधिनियम में परिभाषित तथा प्रयुक्त सभी शब्दों एवं पदों, लेकिन जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में समनुरेशित किया गया है।

अध्याय 2

किशोर न्याय के मूलभूत सिद्धांत तथा बालकों का संरक्षण

3. इन नियमों के प्रशासन में अनुसरण किये जाने वाले मौलिक सिद्धांत।—(1) राज्य सरकार, किशोर न्याय मंडल, बाल कल्याण समिति या अन्य सक्षम प्राधिकार या अभिकरण, यथा स्थिति, इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करेंगे तथा उनके द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

(2) निम्नलिखित सिद्धांत, अन्य के साथ, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के लागू होने, व्याख्या तथा क्रियान्वयन में मूलभूत होंगे:-

I. निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत।—(क) किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को 18 वर्ष की आयु तक किसी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक आशय से निर्दोष होना उपधारित किया जाता है।

(ख) किशोर की या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की या बालक की निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार का प्रारंभिक संपर्क से पश्चातवर्ती देखरेख समेत वैकल्पिक देखरेख तक न्याय तथा संरक्षण की पूरी प्रक्रिया के दौरान सम्मान किया जाएगा।

(ग) किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर का कोई भी विधि विरुद्ध आचरण, जो जीवित रहने के लिए किया जाता है, या वातावरणीय या परिस्थितिजन्य घटकों के कारण किया जाता है या वयस्कों, या समकक्ष समूहों के नियंत्रण के अधीन किया जाता है, निर्दोषिता के सिद्धांतों द्वारा आच्छादित किया जाना है।

(घ) निर्दोषिता की उपधारणा के बुनियादी घटक निम्नलिखित हैं:-

(i) निर्दोषिता की आयु।—निर्दोषिता की आयु वह आयु है, जिससे कम आयु के किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को दाँड़िक न्याय प्रणाली के अधीन नहीं किया जा सकता है। बीजिंग नियम 4(1) स्पष्ट रूप से यह परिपादित करता है कि “आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु का आरंभ होना मानसिक तथा बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कम आयु स्तर पर नियत नहीं किया जायेगा।” इस सिंत के अनुरूप, 18 वर्ष से कम के किशोर या बालक

या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की मानसिक तथा बौद्धिक परिपक्वता समूचे विश्व में अपर्याप्त विचारित की जाती है।

- (ii) **निर्देषिता का प्रक्रियात्मक संरक्षण |**—सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मानक, जो संविधान तथा अन्य संविधियों द्वारा वयस्कों को प्रत्याभूत हैं तथा जो किशोर की या बालक की निर्देषिता की उपधारणा को प्रबल बनाते हैं, किशोरों या बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को प्रत्याभूत होंगे।
- (iii) **विधिक सहायता तथा वादार्थ संरक्षण के उपबंध |**—विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के पास उनके विरुद्ध आरोप के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार तथा विधिक रूप से प्रतिनिधित्व किये जाने का अधिकार होता है। विधिक सेवाओं हेतु वादार्थ संरक्षक, विधिक सहायता तथा ऐसी अन्य सहायता के लिए आवश्यक रूप से उपबंध किये जाने हैं, इसमें स्वयं अपनी पहल पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का भी किशोर का अधिकार सम्मिलित होगा।

II. गरिमा तथा महत्व का सिद्धांत |—(क) व्यवहार, जो बालक की गरिमा की भावना तथा महत्व के सुरुसंगत है, किशोर न्याय का मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित मौलिक मानव अधिकार को प्रतिबिंबित करता है कि सभी मानवों का जन्म स्वतंत्र हुआ है तथा वह गरिमा एवं अधिकारों में समान होते हैं। गरिमा के सम्मान में अपमानित नहीं किया जाना, वैयक्तिक पहचान, सीमाओं तथा स्थान का सम्मान किया जाना, दागदार तथा कर्लकित न किया जाना, सूचना एवं विकल्प प्रस्तुत किया जाना एवं उनके कार्यों के लिये दोषारोपण नहीं किया जाना सम्मिलित होता है।

(ख) किशोर की या बच्चे की गरिमा एवं महत्व के अधिकार का विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ प्रथम संपर्क से बालक से निपटने के लिए सभी उपायों के क्रियान्वयन तक बालक से निपटने की समूची प्रक्रिया के दौरान सम्मान किया जाना तथा संरक्षित किया जायेगा।

III. सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत |—उसके हित को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में स्वतंत्रता से उसके विचारों को व्यक्त करने के प्रत्येक बालक के अधिकार का किशोर न्याय की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में पूर्णतः सम्मान किया जायेगा। सुने जाने के बालकों के अधिकार में विकास के लिए समुचित उपकरणों तथा बच्चे के साथ अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं का सृजन करना, उनके अपनी जीवन से संबंधित निर्णयों में बालकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा परिचर्चा एवं वाद विवाद के लिए अवसर उपलब्ध कराना सम्मिलित होगा।

IV. उत्तम हित का सिद्धांत |—(क) किशोर न्याय के प्रशासन के संदर्भ में लिये गये सभी विनिश्चयों में, किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक के उत्तम हित का सिद्धान्त प्राथमिक विचार होगा।

(ख) किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक के उत्तम हित के सिद्धांत से यह अभिप्रेत होगा उदाहरणार्थ, आपराधिक न्याय, प्रतिदान और दमन के परम्परागत उद्देश्यों को किशोर न्याय के सुधारात्मक और प्रत्यावर्तन उद्देश्यों के लिए राह प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) यह सिद्धान्त विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक हित और नैतिक विकास को सुनिश्चित करना चाहता है ताकि प्रत्येक बालक की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार प्रत्येक बालक को जीवन-यापन करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

V. पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त |—(क) बच्चों का पालन पोषण करने, देखरेख, सहारा और संरक्षण प्रदान करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी जैविक माता-पिता की होगी। तथापि, आपवादिक स्थितियों में, यह जिम्मेदारी इच्छुक दत्तकग्राहक या पालक माता-पिता को प्रदान की जा सकती है।

(ख) बालक के लिए लिये जाने वाले सभी निर्णयों में मूल परिवार को सम्मिलित किया जाना चाहिए जबतक कि ऐसा करना बालक के उत्तम हित में नहीं हो।

(ग) परिवार-जैविक, दत्तकग्राहक या पालक (उस क्रम में) को अधिनियम के अधीन उनकी देखरेख तथा अभिरक्षा के अधीन किशोर या बालक को आवश्यक देखरेख, सहारे और संरक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार निर्णीत किया जाना चाहिए, जब तक कि उत्तम हित के उपाय या आदेश अन्यथा निर्देश न करते हो।

VI. सुरक्षा का सिद्धान्त (कोई भी हानि नहीं, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं, कोई भी उपेक्षा नहीं, कोई भी शोषण नहीं, और कोई भी बुरा व्यवहार नहीं)।—(क) सभी चरणों में, आरंभिक संपर्क से ऐसे समय तक जब वह देखरेख तथा संरक्षण प्रणाली के संपर्क में रहता है, तथा इसके पश्चात्, किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को कोई हानि, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, बुरे बर्ताव, दैहिक दंड या कारावासों में एकांत (solitary) या अन्यथा किसी परिरोध के अध्यधीन नहीं किया जायेगा तथा किशोर या बालक की संवेदनशीलता को कोई हानि पहुंचाने से बचने के लिए अति सावधानी बरती जायेगी।

(ख) देखरेख तथा संरक्षण के नाम पर प्रतिबंधात्मक उपायों तथा प्रक्रिया का आश्रय लिये बिना राज्य की देखरेख तथा संरक्षण में रहने वाले प्रत्येक बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की अधिक बड़ी जिम्मेदारी है।

VII. सकारात्मक उपाय।—(क) उन सकारात्मक उपायों को सक्षम बनाने के लिये प्रावधान बनाये जाने हैं जिनमें सावधानीपूर्वक तैयार की गयी वैयक्तिक देखरेख योजनाओं के माध्यम से किशोर या बालक के कल्याण को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ परिवार, स्वयंसेवियों एवं सामुदायिक समूहों, विद्यालयों एवं मुख्य धारा की अन्य सामुदायिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित करते हुए सभी संभव संसाधनों के पूर्ण संग्रहण सम्मिलित हो।

(ख) सकारात्मक उपायों का लक्ष्य दुर्बलताओं को कम करना तथा विधि के अधीन हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना, एवं किशोर या बालक के साथ प्रभावी, उचित एवं मानवीय रूप से निपटना होगा।

(ग) सकारात्मक उपाय में स्वास्थ्य, शिक्षा, नातेदारी, आजीविका, आराम, मनोरंजन और खेल के लिए उपाय सम्मिलित होंगे।

(घ) ऐसे सकारात्मक उपाय आवश्यक रूप से बालक की पहचान के विकास को सुगम बनायेंगे तथा उन्हें एक समावेशी एवं समर्थकारी बातावरण उपलब्ध करायेंगे।

VIII. गैर कलंकित अर्थविचार, विनिश्चय और कार्यों का सिद्धान्त।—अधिनियम के गैर लांक्षणपूर्ण शब्दों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना है, तथा गिरफ्तारी, प्रतिप्रेषण, अभियुक्त, अभियोग पत्र, विचारण, अभियोजन, वारंट, समन, दोषसिद्धि, अन्तेवासी, अपचारी, उपेक्षित, हिरासत या कारावास जैसे प्रतिकूलात्मक एवं आरोपात्मक शब्दों का प्रयोग अधिनियम के अधीन बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रक्रियाओं में निषिद्ध है।

IX. अधिकारों के समाप्ति नहीं होने का सिद्धान्त।—(क) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के अधिकारों का कोई भी अधित्यजन, चाहे स्वयं उसके द्वारा हो या सक्षम प्राधिकारी या किशोर या बालक की ओर से कार्य कर रहे या कार्य करने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हो, अनुज्ञेय या वैध नहीं है।

(ख) किसी मौलिक अधिकार का इस्तेमाल न किया जाना अधित्यजन के तुल्य नहीं है।

X. समानता तथा गैर भेद-भाव का सिद्धान्त।—(क) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ किशोर या बालक या उसके माता-पिता या संरक्षकों की आयु, लिंग, जन्मस्थान, निर्योग्यता, स्वास्थ्य, प्रास्थिति, नस्ल, प्रजातियता, धर्म, जाति, सांस्कृतिक व्यवहारों, कार्य, गतिविधि या व्यवहार, या किशोर या बालक के नागरिक तथा राजनीतिक दर्जे के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(ख) अधिनियम के अधीन प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पहुंच की समानता, अवसर की समानता, व्यवहार में समानता प्रत्याभूत की जायेगी।

XI. निजता तथा गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त।—किशोर के या बालक के निजता और गोपनीयता का अधिकार कार्यवाहियों और देखरेख की सभी चरणों और संरक्षण प्रक्रिया के जरिये और सभी साधनों द्वारा संरक्षित की जायेगी।

XII. अंतिम मार्ग का सिद्धान्त।—बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संस्थाकरण का कार्य युक्तिसंगत जांच के उपरान्त अंतिम मार्ग का उपाय होगा तथा वह भी न्यूनतम संभव अवधि के लिए।

XIII. प्रत्यावासन और प्रत्यावर्तन का सिद्धान्त।—(क) किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अपने परिवार के साथ पुनः एक किए जाने तथा उसी सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रास्थिति में वापस भेजे जाने का अधिकार होता है जिसका ऐसा किशोर या बालक अधिनियम की परिधि के भीतर आने या किसी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण के प्रति अरक्षित बनने के पहले अधिभोग करता था।

(ख) कोई भी किशोर या बालक, जो अपने परिवार के साथ संपर्क खो चुका है, अधिनियम के अधीन संरक्षण का पात्र होगा तथा यथाशीघ्र अपने परिवार के पास प्रत्यावासित तथा प्रत्यावर्तित किया जायेगा, जबतक कि ऐसे प्रत्यावासन तथा प्रत्यावर्तन के किशोर या बालक के उत्तम हित के विरुद्ध होने की संभावना न हो।

XIV. नयी शुरुआत का सिद्धान्त |—(क) नयी शुरुआत का सिद्धान्त बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के लिए उसकी पूर्व इतिहास को मिटाना सुनिश्चित करते हुए नये आरम्भ को बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य न्यायिक कार्यवाहियों का आश्रय लिये बिना दाँड़िक विधि का अभिकथित रूप से उल्लंघन करने वाले या इस प्रकार माने जाने वाले बच्चों से निपटने के लिए उपायों को प्रोत्साहित करने की ईप्सा करेगा।

अध्याय 3 विधि के विरोध में किशोर

4. किशोर न्याय मण्डल |—प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय मण्डल होंगे, जिन्हें अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित किया जायेगा।

5. किशोर न्याय मण्डल का संरचना |—(1) मण्डल में महानगरीय दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रधान दंडाधिकारी के रूप में तथा, मण्डल के सदस्यों के तौर पर संबंधित जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्याय पीठ का गठन करेंगे:

परन्तु मण्डल का प्रधान दंडाधिकारी मण्डल के समक्ष लंबित मामले का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके त्वरित नियमावरण के लिए यथा आवश्यक उपाय करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक न्याय पीठ के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां होंगी।

(3)(i) बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण रखने वाले दंडाधिकारी को मण्डल के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर अभिहित किया जायेगा।

(ii) ऐसे विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त प्रधान दंडाधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, राज्य सरकार प्रधान मजिस्ट्रेट को बाल मनोविज्ञान एवं बाल कल्याण विषय पर अल्पकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(4) दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के नियम 89 के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निर्मित नामों के पैनल से की जायेगी;

(5) राज्य सरकार मण्डल के सभी सदस्यों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अनुसार बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकारों, किशोर न्याय के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों में ऐसे प्रशिक्षण तथा दिशा निर्धारण की व्यवस्था करेगी, जिसे वह आवश्यक समझती है।

6. मण्डल का कार्यकाल |—(1) मण्डल का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा सदस्यों की नियुक्ति मण्डल की अवधि के साथ सह समाप्त होगी।

(2) सामाजिक कार्यकर्ता मण्डल के सदस्य के रूप में अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) मण्डल के सदस्य की कोई भी पुनर्नियुक्ति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा उसके कार्य के मूल्यांकन तथा इन नियमावली के नियम 89 के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर होगी तथा मण्डल के सदस्यों के कार्य के मूल्यांकन में मण्डल की कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी तथा मामले के नियमावली में योगदान का आकलन आवश्यक रूप से होगा।

(4) कोई सदस्य किसी भी समय एक महीने की अग्रिम नोटिस लिखित में देकर त्यागपत्र दे सकता है या अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) में दिये गये उपबंधानुसार अपने पद से हटाया जा सकता है।

(5) मण्डल में कोई भी रिक्ति चयन समिति द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है, तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति मण्डल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

7. मण्डल के सदस्यों की अर्हताएँ|—(1) मण्डल के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वैसे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु 30 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक का नहीं होगी एवं जो निम्नलिखित अर्हताओं में से

एक अर्हता पूरी करते हों तथा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों से संबंधित मुद्रों तथा बच्चों से संबंधित अन्य विकासात्मक गतिविधियों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन अथवा प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्षों का सक्रिय अनुभव रहा हो:

(i) समाज कार्य/स्वास्थ्य/शिक्षा/मनोविज्ञान/बाल विकास या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान अनुशासन में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करता हो।

(ii) (क) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले उपर्युक्त उम्मीदवारों के जिला में उपलब्ध न होने की दशा में, चयन समिति उप-पैरा (i) में उल्लिखित विषयों में स्नातक डिग्री तथा कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा कर सकती है।

(2) सदस्यों के चयन के समय दो या अधिक उम्मीदवारों की समान अर्हता पाये जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी;

परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के दो सदस्यों की योग्यता समान रहने की स्थिति में सदस्यों के चयन में राज्य स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(3) किसी भी व्यक्ति को मण्डल के सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार नहीं किया जायेगा, यदि वह,—

(i) किसी विधि के अधीन दोषसिद्ध किया गया है;

(ii) बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन में या किसी अन्य मानव अधिकार के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में कभी भी आलिप्त रहा है;

(iii) ऐसा अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक अधियोग धारित किया हो जो उसे मण्डल के कार्य के लिए आवश्यक समय प्रदान करने और ध्यान देने की उसे अनुमति नहीं देता हों;

(iv) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में विहित अर्हता और अनुभव को पूर्ण नहीं करता हो, तथा ऐसे मामलों में चयन समिति, आवश्यक जांच के पश्चात् और ऐसे तथ्य के सिद्ध होने पर, उसका आवेदन अस्वीकृत करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिए तैयार नामों की सूची से अगले व्यक्ति के नाम पर विचार करेगी।

(4) दो सदस्यों में आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा।

8. बैठक तथा यात्रा भत्ते।—मण्डल के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को ऐसे यात्रा और बैठक भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार निर्धारित करें।

9. मण्डल की बैठकें।—(क) मण्डल न्यायालय परिसर से इतर किसी संप्रेक्षण गृह के परिसर या किसी उपर्युक्त स्थान में अपनी बैठकें आयोजित करेगा।

(ख) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला में मण्डल के सुचारू कार्यकलाप के लिये अपेक्षित आधारभूत संरचना, मानव संसाधनों एवं धन के साथ विद्यमान योजना, अगर कोई हो, के मापदंडों के अधीन यथा विहित रूप से, या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किशोर न्यायमंडल का गठन करेगी।

(ग) जिस परिसर में मण्डल अपनी बैठकें आयोजित करता है, वह बाल मित्रतापूर्ण होगा तथा किसी भी प्रकार से न्यायालय कक्ष जैसा नहीं दिखेगा, उदाहरण के लिए बोर्ड एक ऊँचे मंच पर बैठक नहीं करेगा तथा बैठने की व्यवस्था एकरूप होगी तथा कोई गवाहकक्ष नहीं होंगे।

(घ) मण्डल सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अपनी बैठक करेगा, परन्तु बैठक की बारंबारता प्रधान दंडाधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है। राज्य सरकार भी सामान्य तथा विशेष आदेश द्वारा एक सप्ताह में बैठकों की संख्या बढ़ा सकती है।

(ङ) एक वर्ष में प्रधान दंडाधिकारी तथा मण्डल के सदस्यों की कम से कम तीन चौथाई हाजिरी आवश्यक है।

(च) मण्डल का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में कम से कम पाँच घंटे उपस्थित रहेगा।

10. मण्डल के कार्य।—(1) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मण्डल निम्नलिखित कार्यों को करेगा, अर्थात्—

- (क) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के मामले न्यायनिर्णीत करना और निस्तारित करना;
- (ख) अधिनियम की धाराओं 23 से 28 के अधीन कारित किये गये अपराधों का संज्ञान लेना;
- (ग) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए कार्यरत संस्थाओं का अनुश्रवण करना तथा किसी उल्लेखनीय त्रुटियों के मामलों में उनसे अनुपालन सुनिश्चित करना;
- (घ) यथास्थिति संबंधित सरकारी कर्मियों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बोर्ड के किसी आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले पर विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना;
- (ङ.) आवश्यक आधारभूत संरचना या सुविधाएं सृजित करने या उपलब्ध कराने के लिये जिला प्राधिकारी एवं पुलिस को आवश्यक निर्देश निर्गत करना ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय एवं उपचार के न्यूनतम मानक बनाये रखा जा सके;
- (च) देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में समिति के साथ समर्पक रखना;
- (छ) विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से जाँच तथा मामलों के त्वरित निस्तारण को सुगम बनाने के लिए अन्य जिलों में तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मण्डलों के साथ समर्पक रखना;
- (ज) ऐसी अकलित परिस्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना जो अधिनियम के क्रियान्वयन में उद्भूत हो सकती है तथा किशोर के सर्वोत्तम हित में ऐसी कठिनाईयों को दूर करना;
- (झ) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के विषय में अपने समक्ष प्रस्तुत की गई मासिक तथा तिमाही सूचना जिला, राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित राज्य सरकार को भेजना तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन समीक्षा के लिए भेजना;
- (ज) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समनुदेशित कोई अन्य कार्य;
- (ट) बोर्ड किसी मीडिया के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित किसी ऐसी बात को प्रकाशित करेगा जिससे किशोर की पहचान हो जाए;
- (ठ) मण्डल बालक को सम्प्रेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान में, यथास्थिति, रखने के लिए आदेश पारित करेगा अगर जमानत पर बालक को माता-पिता/संरक्षकों की देखरेख में रिहा नहीं किया जा सकता है;
- (ड) मण्डल सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बालिका का पुलिस द्वारा सूर्योदय तथा सूर्योदय के बीच प्रभार नहीं लिया जायेगा;

परन्तु यह कि अगर परिस्थितियाँ पुलिस के लिए ऐसे समय के दौरान बालिका का प्रभार लेना आवश्यक बनाती है, मण्डल को सुनिश्चित करना चाहिए कि बालिका को किसी महिला या बालिका के संबंधी की देखरेख के अधीन रखा जाय, जो वह भी उपयुक्त महिला हो सकती है को सुरक्षित स्थान में या सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाय।

- (ढ) मण्डल को, अगर जाँच के अनुक्रम में किसी भी चरण में, समाधान है कि जाँच के प्रयोजनार्थ बालक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, उसकी हाजिरी से उसे छूट दे सकता है तथा बालक की अनुपस्थिति में जाँच की कार्यवाही कर सकता है;
- (ण) बोर्ड या मण्डल परिवीक्षा पदाधिकारी/केस कार्यकर्ता की रिपोर्ट मंगाये बिना मामले का कोई अंतिम निस्तारण प्रभावी नहीं बनायेगा;
- (त) मण्डल परिवीक्षा पदाधिकारी को सामाजिक जांच करने तथा मण्डल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दे सकता है तथा उसे बालक की मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सीय समस्याओं से संबंधित मामलों पर पेशेवर/विशेषज्ञ राय लाने का भी निर्देश दे सकता है, वशर्ते कि मण्डल विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में पेशेवरों को भी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सके;
- (थ) चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों के बाल चिकित्सा विज्ञान/मनोचिकित्सीय औषधियों के विभागों को पेशेवर राय प्रदान करने के लिये नोडल एजेंसियों के तौर पर मान्यता दी जायेगी।

11. पुलिस और अन्य एजेंसियों की पूर्व और पश्चात् प्रस्तुति कार्यवाही।—(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने से आरोपित किशोर पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, उसे वैसे ही संबंधित पुलिस अधिकारी सूचित करेगा:

(क) नजदीकी पुलिस स्टेशन में समनुदेशित किशोर या बालक कल्याण अधिकारी को मामले का प्रभार लेने के लिए;

(ख) मण्डल के पते के बारे में, जहां किशोर को प्रस्तुत किया जायेगा, और उस तिथि व समय के बारे में, जब माता-पिता या संरक्षक को मण्डल के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता हो, किशोर के पकड़े जाने के बारे में विधि का उल्लंघन करने से आरोपित किशोर के माता-पिता या संरक्षक को;

(ग) जांच करने के लिए मण्डल की सहायता करने वाली संभावित किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य सुसंगत परिस्थितियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसे पकड़े जाने के बारे में संबंधित परिवेश्वा अधिकारी को।

(2) पकड़े जाने के तुरन्त पश्चात्, किशोर को नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जायेगा, जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसार चौबीस घंटों के भीतर मण्डल के समक्ष किशोर को प्रस्तुत करेगा, और जहां ऐसे किशोर या बालक कल्याण अधिकारी को अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपादित प्रावधानों के अनुसार नामनिर्देशित नहीं किया गया हो या किन्हीं शासकीय कारणों से उपलब्ध नहीं हों, तो पुलिस अधिकारी, जिसने किशोर को गिरफ्तार किया है, उसे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने से आरोपित किशोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस किसी भी मामले में किशोर को लॉकअप में नहीं भेजेगा या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी को अपना प्रभार अन्तरित करने में विलम्ब नहीं करेगा, यदि ऐसा अधिकारी नामनिर्देशित किया गया हो।

(4) सम्पर्क विवरणों के साथ विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों और जिसमें सभी नामनिर्देशित किशोर या बालक कल्याण कार्यालयों की सूची प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहज दृश्य स्थानों पर लगाया जायेगा।

(5) उत्तम उपलब्ध सूचना को एकत्रित करने के लिए यह किशोर के माता-पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करना और उन्हें किशोर द्वारा कानून तोड़ने वाले व्यवहार के बारे में बताना नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी या पुलिस पर बाध्यकारी होगा।

(6) पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर की केस डायरी में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी की परिस्थितियों और कारित किया गया अभिकथित अपराध भी अभिलेखित करेगा, जिसे तुरन्त मण्डल को भेजा जायेगा।

(7) पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी गंभीर अपराधों (जिनमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष कारावास से अधिक दण्ड हों) में उनकी अभिकथित आलिप्तता के मामलों में ही किशोर को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रयुक्त करेगा।

(8) ऐसे मामलों में जहां गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से किशोर के हित में होना प्रतीत होती हो, वहां पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी किशोर को देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में मानेगा और उसे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपने रिपोर्ट में देखरेख और संरक्षण के लिए किशोर की आवश्यकता को स्पष्ट किया जायेगा और इस नियमावली के नियम 13(1)(ख) के अधीन मण्डल से समुचित आदेश चाहेगा।

(9) गैर गंभीर प्रकृति (जिसमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष कारावास से कम दण्ड हों) के अपराधों को शामिल करने वाले सभी अन्य मामलों के लिए और उन मामलों में, जहां किशोर के हित में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो, वहां पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी मण्डल को उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ बालक या वार्ड के बारे में किशोर के माता-पिता या संरक्षक को सूचित करेगा, जिसके पास अनुगामी सुनवाई के लिए किशोर को बुलाने की शक्ति होगी।

(10) यदि मण्डल की बैठक नहीं हो, तो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपादित प्रावधानों के अनुसार मण्डल के एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों के साथ कार्य करने में, पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं

होगा, सिवाय जहां किशोर द्वारा कारित किया गया अभिकथित अपराध बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर प्रकृति का हों या जब ऐसा अपराध वयस्कों के साथ संयुक्त रूप से कारित किया जाना अभिकथित किया गया हो। साधारण अपराधों को शामिल करने वाले मामलों के स्थान पर, पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि वाली रिपोर्ट और गिरफ्तार करने की परिस्थितियों और अभिकथित अपराध की परिस्थितियों से संबंधित सूचना लिखेगा और पहली सुनवाई के समक्ष मण्डल को इसे भेजेगा।

(12) राज्य सरकार केवल ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को अधिकृत करेगा, जो परिवीक्षा की सेवाएं प्रदान करने, बातचीत करने, मामले में ऐसे कार्य करने, सुरक्षित स्थान प्रदान करने और विशेष किशोर पुलिस इकाई से पुलिस या किशोर या बालक कल्याण अधिकारी के साथ सहायता करने की स्थिति में हों, और संरक्षण एजेंसियों के रूप में ऐसा करने के लिए योग्यता, सुविधाएं और अनुभव रखते हों, जो गिरफ्तारी तथा अभिकथित अपराध की परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने में, किशोर या प्रभार लेने में, जब तक कि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाये, चौबीस घण्टों के भीतर मण्डल के समक्ष किशोर को वास्तविक तौर पर प्रस्तुत करने में, पुलिस से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी या पुलिस की सहायता कर सकता है।

(13) पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई से किशोर या बालक कल्याण अधिकारी, या अधिकृत स्वैच्छिक संगठन उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसे किशोरों को उनके पास रखा जाता है, उनके प्रभार के अधीन गिरफ्तार या रखे गये किशोरों को भोजन या मूल सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

(14) जब किशोर को मण्डल के एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एवं आदेश प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे आदेश पर मण्डल की अगली बैठक में मण्डल द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

12. आयु अवधारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।—(1) बालक या विधि के विरोध में किशोर से संबंधित प्रथम दृष्टया किशोर/बालकों के मामलों के सिवाय, न्यायालय या मण्डल या इन नियमों के नियम में निर्दिष्ट समिति, यथास्थिति, इस प्रयोजन के लिए आवेदन किये जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारित करेगी।

(2) न्यायालय या मण्डल या समिति देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर या विधि के उल्लंघन वाले आरोपित बालक, यथास्थिति, की किशोरावस्था या उसके शारीरिक अवस्था या दस्तावेजों के आधार पर, अगर उपलब्ध हों, प्रथम दृष्टया निर्णय करेगी तथा उसे यथा स्थिति बाल गृह, संप्रेक्षण गृह अथवा कारावास भेजेगी।

(3) सिवाय उस स्थिति के जहां किशोर या बालक, यथास्थिति, प्रकटतः 12 वर्ष से अधिक का हो सकता है, आयु निर्धारण न्यायालय या मण्डल या समिति, यथास्थिति, द्वारा निर्मांकित कागजातों को प्राप्त करके साक्ष्य का प्रयास किया जायेगा:—

(क)(i) किशोर या बालक द्वारा अध्ययन किये गये कक्षा आठ के उपस्थिति अभिलेख की प्रतिलिपियों समेत प्रवेशिका तथा समतुल्य प्रमाण पत्र तथा इसके अभाव में;

(ii) पहली बार प्रवेश लिये गये विद्यालय (क्रीड़ा विद्यालय से इतर) से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र; तथा इसकी अनुपस्थिति में;

(iii) नगर निगम या नगरपालिका प्राधिकार या पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र; तथा

(ख) उपरोक्त खंड (क) के (i) तथा, या (ii) या (iii) में से किसी की अनुपस्थिति में ही, या अगर न्यायालय या मण्डल या समिति द्वारा ऐसा आवश्यक पाये जाने की दशा में, एक सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा मण्डल द्वारा राय प्राप्त किया जायेगा, जो किशोर या बालक की आयु घोषित करेगा। अगर आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, न्यायालय या मण्डल या समिति यथास्थिति, द्वारा अभिलिखित कारणों से, अगर आवश्यक समझा जाय, बालक या किशोर की आयु एक वर्ष के मार्जिन के भीतर निचले पक्ष पर उसकी आयु मानकर उसे संदेह प्रदान कर सकते हैं तथा, ऐसे मामलों में आदेश पारित करते समय, यथास्थिति उपलब्ध ऐसे साक्ष्य या चिकित्सीय राय, यथास्थिति को विचार में लेकर, उसकी आयु तथा खंडों (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे या इनकी अनुपस्थिति में, ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में खंड (ख) आयु का प्रमाण होगा।

(4) सम्प्रकृत रूप से गठित चिकित्सीय मंडल आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को चिकित्सीय राय सौंपेंगा।

(5) अगर उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रमाण में से किसी के आधार पर किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से नीचे पायी जाती है, न्यायालय या बोर्ड, या, यथास्थिति, समिति लिखित में अधिनियम तथा इन नियमों के प्रयोजन के लिये आयु कथित करते हुए तथा किशोरावस्था या अन्यथा का दर्जा घोषित करते हुए एक आदेश पारित करेगा तथा आदेश की एक प्रतिलिपि ऐसे किशोर या संबद्ध माता-पिता/संरक्षक/व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

(6) इस नियम में अंतर्विष्ट प्रावधान उन निस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे, जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में समुचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के अधीन दंडादेश में छूट प्रदान करना अपेक्षित बनाते हुए अधिनियम के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किशोरावस्था का दर्जा अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

13. मण्डल द्वारा प्रस्तुतिकरण पश्चात् प्रक्रियाएँ।—(1) ‘मण्डल के समक्ष किशोर के प्रस्तुत किये जाने पर, किशोर को प्रस्तुत करने वाले संबंधित किशोर/बाल कल्याण या आरक्षी पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा गिरफ्तारी तथा अभिकथित रूप से कारित अपराध की परिस्थितियों से अंतर्विष्ट एक रिपोर्ट उसी दिन उपलब्ध कारायी जायेगी। ऐसी रिपोर्ट का मण्डल द्वारा पुनर्विलोकन कराया जाएगा, तथा मण्डल उसी दिन पहली संक्षिप्त जांच में निर्मांकित आदेश पारित करेगा, अर्थात् :

(क) मामला निस्तारित करेगा, अगर उसके विधि के उल्लंघन का साक्ष्य निराधार प्रतीत होता है या जहाँ किशोर मामुली विधि तोड़ने में आलिप्त है;

(ख) किशोर को प्रस्तुत किये जाने के समय मण्डल को सौंपी गयी पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोरों से संबंधित मामलों को समिति को अंतरित करेगा;

(ग) अगली तिथि को जांच के लिये उपस्थित होने या किशोर को प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रपत्र-। में एक आदेश के माध्यम से उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा पदाधिकारियों, यथास्थिति, के पर्यवेक्षण या अभिरक्षा में किशोर को निर्मुक्त करेगा;

(घ) प्रपत्र-॥ में एक आदेश के अनुसार केवल गंभीर अपराधों में किशोर की अंतर्ग्रस्तता के मामलों में जांच के लंबित रहते किशोर को संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त संस्था में परिस्तर्वक्त करेगा;

(ङ.) जांच के लंबित रहते निर्मुक्ति के सभी मामलों में, मण्डल सुनवाई की अगली तिथि सूचित करेगा जो प्रथम संक्षिप्त जांच के 15 दिनों के बाद की नहीं होगी, तथा प्रपत्र-3 में एक आदेश के माध्यम से संबंधित परिवीक्षा पदाधिकारी से सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट की भी ईप्सा करेगा।

14. जांच।—(1) मण्डल उचित तथा त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिये निर्मांकित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(क) जांच प्रारंभ करने के समय, मण्डल अपने आप को सामाधान करायेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ अधिवक्ता या परिवीक्षा पदाधिकारी समेत पुलिस द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया गया है तथा ऐसे दुर्व्यवहार की दशा में सुधारात्मक कदम उठायेगा;

(ख) अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियों का यथा संभव यथा सरल ढंग से संचालन किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जायेगी कि किशोर, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थित की गयी हैं, को कार्यवाहियों के दौरान बाल मित्रतापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए;

(ग) मण्डल के समक्ष लाये गये प्रत्येक किशोर को सुने जाने तथा अपनी जांच में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा;

(घ) कम गंभीर अपराधों के मामले, अगर विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा या पुलिस स्टेशन में ही निस्तारित नहीं किये गये हैं, एक महीने के भीतर संक्षिप्त कार्यवाहियों या जांच के माध्यम से बोर्ड द्वारा निस्तारित किये जा सकते हैं, जबकि सात या इससे अधिक वर्ष के दंड का प्रावधान रखनेवाले गंभीर अपराधों के मामलों में, विस्तृत जांच की सम्प्रकृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है;

(ङ.) गंभीर अपराधों से संबंधित जांच के मामलों में भी मण्डल सम्मन के मामलों में विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित जांच में परीक्षा के लिये साक्षीगण/गवाह प्रस्तुत किये जाते हैं, मण्डल इसे ध्यान में रखेगा कि कठोर प्रतिकूल कार्यवाहियों की भावना में जांच का संचालन नहीं किया जाना है तथा यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का इस्तेमाल करेगा ताकि किशोर से प्रश्न किया जा सके एवं पूर्ण उपधारणाओं के साथ कार्यवाही की जा सके जो किशोर के प्रत्यावर्तित किये जाने के अधिकार का पक्ष लेती हैं।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की परीक्षा करते समय तथा उसका बयान अभिलिखित करते समय, मण्डल किशोर को सहज बनाने के लिये तथा न केवल उस अपराध के संबंध में, जिसका किशोर अभियुक्त है, बल्कि गृह तथा सामाजिक वातावरण एवं उस प्रभाव, जिसका किशोर पर प्रभाव पड़ा हो, के संबंध में भी किसी भय के बिना तथ्यों तथा परिस्थितियों को करने हेतु उसे प्रोत्साहित करने के लिये किशोर को बाल मित्रतापूर्ण तरीके से संबोधित करेगा।

(4) परीक्षा का अभिलेख ऐसे प्ररूप में होगा जिसे मण्डल ज्ञान की अंतर्वस्तुओं तथा परिस्थितियों, जिसमें यह किया गया था, को ध्यान में रखकर उपयुक्त समझे।

(5) मण्डल किशोर के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के साथ गिरफ्तारी तथा अभिकथित रूप से कारित अपराध की परिस्थितियों से अंतर्विष्ट पुलिस की रिपोर्ट तथा परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-IV में या मण्डल के आदेशों पर स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र-III के अनुसार तैयार की गयी सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।

(6) मण्डल द्वारा प्रत्येक जांच मामले के प्रारंभ होने की तिथि से चार महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जायेगी तथा केवल आपवादिक मामलों में ही, जिनमें परराष्ट्रीय अपराधिकता, अभियुक्तों की बड़ी संख्या तथा गवाहों की प्रस्तुतिकरण में असाधारण विलम्ब अंतर्गत हो, मण्डल द्वारा कारणों को लेखबद्ध करके जांच की अवधि का दो महीना विस्तार किया जा सकता है।

(7) अन्य सारे मामलों में सिवाय उनके जहां अभिकथित अपराध गंभीर प्रकृति का है, चार से छह माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यवाही समाप्त हो जायेगी।

(8) जहां किशोर द्वारा अभिकथित रूप से कारित अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण कार्यवाहियों में छह महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ है, मण्डल विलम्ब के कारण तथा मामले में शीघ्रता करने के लिये किये जा रहे उपायों को भी कथित करते हुए जिला न्यायाधीश को मामले की एक आवधिक रिपोर्ट भेजेगा।

15. विधिक सहायता।—(1) मण्डल के समक्ष कार्यवाहियों का गैर प्रतिकूल वातावरण में संचालन किया जायेगा, परन्तु अधिवक्ता के अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता जैसे प्रदान सभी सम्यक् प्रक्रिया में ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के लिए विधिक सेवाओं को सुगम बनाने हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निदेश के अनुसार अधिवक्ताओं का पैनल नाम निर्दिष्ट करेगा। उनकी सेवाओं में बालक के साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामलों में अनुतोष प्राप्त करना सम्मिलित हो सकता है।

(3) मण्डल सुनिश्चित करेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता प्राधिकार विधि का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेगा।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार में विधिक पदाधिकारी मण्डल द्वारा चाही गयी विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यता के अधीन होंगे।

(5) मण्डल विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के माता-पिता से संपर्क करने तथा किशोरों के बारे में सुसंगत सामाजिक तथा पुनर्वास सूचना एकत्रित करने जैसे पैरा-विधिक कार्यों में छात्रों, विधिक सेवा स्वयंसेवियों तथा गैर सरकारी संगठनों की सेवायें भी तैनात कर सकता है।

16. जाँच का समाप्त तथा व्यवस्था संबंधी विकल्प।—(1) मण्डल चार महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक जांच पूरा करेगा तथा अभिकथित अपराध में किशोर की संलिप्तता के बारे में एक निष्कर्ष अभिलिखित करके, अधिनियम की धारा 15 में प्रणित सात व्यवस्था संबंधी आदेशों में से एक आदेश पारित करेगा।

(2) कोई आदेश पारित करने के पहले, मण्डल परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा या मण्डल द्वारा ऐसा करने के लिए आदेश दिये गये एक मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की गयी सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त करेगा, तथा रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखेगा।

(3) मण्डल द्वारा पारित सभी व्यवस्था संबंधी आदेशों में किशोर तथा उसके परिवार, जहां संभव हो, के साथ अंतःक्रिया के आधार पर विधि का उल्लंघन करने वाले संबंधित किशोर के लिए परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा तैयार की गयी एक व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रपत्र-**XXI** आवश्यक रूप से अंतर्विष्ट होगी।

(4) जहां मण्डल सलाह तथा भर्त्सना के उपरान्त या समूह परामर्श में भागीदारी के उपरान्त किशोर को निर्मुक्त करने का निर्णय लेता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, ऐसी व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श तथा सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करने के लिये मण्डल द्वारा जिला या राज्य बालक संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भी आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है।

(5) जहाँ मण्डल विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को निर्मुक्त करने तथा उसे माता-पिता या संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखने का निर्णय लेता है, उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में किशोर को निर्मुक्त किया जाता है, के लिये तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए किशोर के सद्व्यवहार तथा समुचित देखरेख के लिए प्रपत्र-V में एक लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकता है।

(6) मण्डल प्रपत्र-**VI** में प्रतिभू के बिना एक वैयक्तिक बंधपत्र के निष्पादन पर विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की निर्मुक्ति का आदेश कर सकता है।

(7) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उपयुक्त संस्था या विशेष गृह की देखरेख में रखे जाने की दशा में, मण्डल इसे ध्यान में रखेगा कि उपयुक्त संस्था या विशेष गृह किशोर के माता-पिता या संरक्षक के निवास स्थान के निकटतम अवस्थित है।

(8) मण्डल, जब यह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है तथा उसे माता-पिता या संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखता है या जहां किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त किया जाता है तथा उसे उपयुक्त संस्था की देखरेख के अधीन रखता है, आदेश कर सकता है कि किशोर को परिवीक्षा पदाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाए। पर्यवेक्षण की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(9) जहाँ मण्डल निर्णय लेता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में व्यवहार किया जाना है, यह उपयुक्त देखरेख, संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए निकटतम समिति के समक्ष ऐसे किशोर के प्रस्तुतिकरण के लिये आवश्यक आदेश करेगा।

(10) जहाँ मण्डल को यह प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, यह किशोर को विशेष गृह में निरूद्धता के लिये भेजे जाने का आदेश कर सकता है।

(11) जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली है तथा उसके द्वारा कारित अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है कि मण्डल के समाधान में, यह न तो स्वयं किशोर के हित में और न ही विशेष गृह के अन्य किशोरों के हित में है, मण्डल किशोर को एक सुरक्षित स्थान पर तथा उसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त समझे गये ढंग से रखे जाने का आदेश कर सकता है।

(12) राज्य सरकार विशेष गृह से इतर सुरक्षित स्थान में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की विशेष कोटि की निरूद्धता का अनुपालन करने के लिये व्यवस्था करेगी।

(13) किसी भी दशा में, निरूद्धता की अवधि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (g) में उपबंधित अधिकतम अवधि से आगे नहीं जायेगी।

17. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिये संस्थाएँ।—(1) राज्य सरकार या तो स्वयं या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन के साथ समझौते के अधीन अपेक्षानुसार प्रत्येक जिला में या जिलों के समूह में बालकों तथा बालिकाओं के लिए पृथक संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान एवं विशेष गृह स्थापित करेगी।

(2) संप्रेक्षण गृह तथा विशेष गृह 11 वर्ष तक, 12-15 वर्ष तथा 16 वर्ष एवं इससे ऊपर की आयु समूह के पृथक्करण एवं वर्गीकरण के अनुसार बालकों तथा बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाएँ स्थापित करेंगी।

(3) प्रत्येक संस्था के कर्मचारी तथा उसमें निवास कर रहे बच्चों द्वारा इस्तेमाल के लिये अधिनियम, राज्य द्वारा बनाये गये नियमों की एक प्रतिलिपि रखेगी।

(4) राज्य सरकार एक परिचालनात्मक निर्देशिका तैयार करेगी।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए सभी सुविधाएँ तथा सेवाएँ अधिनियम तथा राज्य के नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा अनुरक्षित की जायेंगी।

18. निर्मुक्ति।—(1) अधीक्षक मण्डल द्वारा किये गये आदेशानुसार स्थगन की अवधि के समाप्ति पर मुक्त किये जानेवाले विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का एक रोस्टर बनाकर रखेगा।

(2) प्रत्येक मामला उपयुक्त रूप से निर्मुक्त तथा निर्मुक्त उपरान्त किशोर को समाज के मुख्य धारा में लाने को सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध अधीक्षक, परिवीक्षा पदाधिकारी, बाल कल्याण पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता द्वारा इन नियमों के नियम 12 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(3) व्यक्तिगत देखरेख योजना के अधीन तैयार की गयी तथा इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति द्वारा समय समय पर पुनर्विलोकित की गयी निर्मुक्त पूर्व तथा निर्मुक्त पश्चात योजना के अनुसार निर्मुक्त होगी तथा निर्मुक्त के सभी मामलों में, निर्मुक्त के समय के काफी पहले आवश्यक कार्रवाई तथा तैयारी प्रारंभ की जायेगी एवं इसमें निर्मुक्त पश्चात् अनुवर्ती कार्य के लिये तैयारी सम्मिलित होगी।

(4) किशोर की निर्मुक्त तथा निर्मुक्त की सटीक तिथि की सामयिक सूचना माता पिता या संरक्षक को प्रदान की जायेगी तथा इस तिथि को किशोर का प्रभार लेने के लिए माता-पिता या संरक्षक को संस्था आने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(5) अगर माता-पिता या संरक्षक यथास्थिति, नियत तिथि को आने में तथा किशोर का प्रभार लेने में विफल रहते हैं, किशोर को संस्थान के अनुरक्षक द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक के पास ले जाया जायेगा; तथा लड़की के मामले में, उसे महिला अनुरक्षक द्वारा ले जाया जायेगा जो उसकी अभिरक्षा उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंप देंगे।

(6) निर्मुक्त या उन्मोचन के समय, किशोर को वस्त्रों का एक सेट तथा आवश्यक शृंगार सामग्रियां उपलब्ध करायी जायेंगी।

(7) अगर किशोर के कोई माता-पिता या संरक्षक नहीं हैं, उसे समुचित निर्देश के लिए देखरेख गृह/बाल कल्याण समिति के पास भेजा जा सकता है, या उसके नियोजन की दशा में, उस व्यक्ति के पास जिसने किशोर को नियोजित करने का वचन दिया है।

(8) लड़कियों के संस्थान का अधीक्षक लड़की की सहमति तथा मण्डल के अनुमोदन के अध्यधीन समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रियानुसार 18 वर्ष से ऊपर की लड़की को देख-रेख गृह भेजकर या कोई काम काज या लाभपूर्ण नियोजन प्रदान कराकर उसकी सहायता कर या, पारिवारिक जीवन में बसने में उसकी सहायता करके उसके सामाजिक पुनः एकीकरण में लड़की की सहायता कर सकता है।

(9) अधीक्षक प्रपत्र-VII में किसी किशोर की निर्मुक्ति का आदेश करेगा जिसकी निरुद्घता की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा की गयी कार्रवाई के सात दिनों के भीतर मण्डल तथा समाज कल्याण निदेशक को सूचित करेगा एवं अगर निर्मुक्ति की तिथि रविवार को या किसी सार्वजनिक अवकाश को पड़ती है, किशोर को निर्मुक्ति की पंजी में की जानेवाली इस प्रभाव की प्रविष्टि के साथ पूर्वगामी दिन निर्मुक्ति किया जा सकता है। विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने समेत अधीक्षक अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दावी होगा, अगर वह ऐसी निर्मुक्ति के दिन किशोर को निर्मुक्त करने या आदेश क्रियान्वित करने में विफल रहता/रहती है।

(10) अधीक्षक समुचित मामलों में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित दरों पर निर्वाह धन, तथा रेलवे या पथ के किराये, या दोनों, यथास्थिति, के भुगतान का आदेश कर सकता है।

(11) उपयुक्त मामलों में, अधीक्षक किशोर को ऐसी अधिकतम लागत के अध्यधीन, जो संस्था द्वारा निर्धारित की जाये जो निर्मुक्ति पश्चात योजना का भी भाग होगी, कोई कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे छोटे मोटे उपकरण उपलब्ध करा सकता है।

(12) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के पास निर्मुक्ति के उपरान्त जाने के लिए कोई स्थान नहीं है या पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये वह अपने रहने की अवधि पूरी हो जाने के उपरान्त संस्था में रहने का आग्रह करता है,

अधीक्षक सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अध्यधीन कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था किये जाने के समय तक उसे रहने की अनुमति दे सकता है; या उसे उत्तर रक्षा गृह में स्थानांतरित किया जा सकता है।

19. अधिनियम की धाराओं 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 के संबंध में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया |—(1)
अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्रतिपादित प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में,—

(क) मण्डल/समिति प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लेगा तथा अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच प्रारंभ करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा; तथा

(ख) जहां बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय या राज्य आयोग अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्वतः स्फूर्त संज्ञान लेता है, यह जिला या संबद्ध जिले के राज्य बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य को मण्डल के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश देते हुए उन्हें सूचित करेगा।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक के भाग निकलने की दशा में, 24 घंटों के भीतर निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी—

(क) संस्था का अधीक्षक मण्डल/समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अन्य संबद्ध प्राधिकारियों को इसकी एक प्रतिलिपि के साथ पहचान चिन्हों तथा छायाचित्र समेत किशोर या बच्चे के विवरणों तथा हुलिये के साथ क्षेत्र के पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को तत्काल एक रिपोर्ट भेजेगा;

(ख) आश्रय गृहों या ड्रौप-इन केन्द्र से इतर संस्थाओं के अधीक्षक प्रहरियों या संबद्ध कर्मचारीगण को किशोर की तलाश में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों जैसे स्थानों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा जहां किशोर के जाने की संभावना है;

(ग) माता-पिता या संरक्षक अगर कोई हों, को ऐसे भाग निकलने के बारे में तत्काल सूचित किया जायेगा; तथा

(घ) आश्रय गृहों या ड्रौपिंग केन्द्र से इतर संस्थान का अधीक्षक इस प्रकार भाग निकलने के बारे में जांच आयोजित करेगा तथा मण्डल या समिति या संबद्ध प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा तथा अगली बैठक में पुनर्विलोकन के लिये इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(3) धाराओं 23, 24, 25 एवं 26 में विनिर्दिष्ट विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक के विरुद्ध अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के अलावा जमानती होंगे या गैर जमानती होंगे तथा पुलिस, मण्डल तथा संबद्ध प्राधिकारीगण एवं कृत्यकारीगण पर प्रक्रियाएं तदनुसार लागू होंगी।

अध्याय 4 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक

20. बाल कल्याण समिति |—प्रत्येक जिला में एक बाल कल्याण समिति होगी, जिसे अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गठित किया जायेगा।

21. बाल कल्याण समिति की संरचना |—(1) समिति में संबंधित जिले के एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी तथा समिति में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से लिए जाएँगे।

(2) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियम 89 के अधीन प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा स्थापित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) चयन समिति, समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन करते समय सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कोई भी आवेदक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या बाल देखभाल संस्थान या चाईल्डलाइन संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हो।

(4) राज्य सरकार समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के लिये बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकारों, सामाजीकरण तथा पुनर्वास में ऐसा प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश, किशोर न्याय के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा सुसंगत वैधानिक प्रणाली उपलब्ध करायेगी जिसे वह आवश्यक समझे।

22. समिति का कार्यकाल |—(1) समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल होगा तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल समिति के कार्यकाल के सहवर्ती होंगे।

(2) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य अधिकतम दो लगातार कार्यकालों के लिये पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं।

(3) समिति के सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर तथा चयन समिति की अनुशंसा पर होगा।

(4) समिति के कार्यकाल के पूरा होने पर क्रमता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार विद्यमान समिति के कार्यकाल के समाप्ति के पहले एक नयी समिति का गठन करेगी; जिसके उपरान्त विद्यमान समिति सभी अधिलेख तथा सूचना नवगठित समिति के हवाले कर देगी।

(5) अध्यक्ष या सदस्य लिखित में एक महीना का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) में किये गये प्रावधानानुसार पद से हटाये जा सकते हैं।

(6) समिति में कोई आकस्मिक रिक्त चयन समिति द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है, तथा वह समिति की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।

23. समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए अर्हताएं।— (1) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति वैसे पात्र होंगे जिनकी आयु 30 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक का नहीं होगी एवं जो निम्नलिखित अर्हताओं में से एक अर्हता पूरी करते हों तथा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों से संबंधित मुददों तथा बच्चों से संबंधित अन्य विकासात्मक गतिविधियों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन अथवा प्रबंधन में कम से कम पांच वर्षों का सक्रिय अनुभव रहा हो:

- (i) समाज कार्य/ मनोविज्ञान/ बाल विकास/शिक्षा/समाजशास्त्र/विधि/अपराध शास्त्र या या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान अनुशासन में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करता हो।
- (ii) (क) उपर्युक्त के अनुसार न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले उपर्युक्त उम्मीदवारों के जिला में उपलब्ध न होने की दशा में, चयन समिति उप-पैरा (i) में उल्लिखित विषयों में स्नातक डिग्री तथा कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा कर सकती है।
- (iii) शिक्षक, चिकित्सक या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जो बच्चों से संबंधित कार्य में संलग्न रहे हों।

(2) चयन हेतु अनुशरणित सदस्यों में से, उच्चतम शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले सदस्य को समिति के अध्यक्ष पद पर चयनित किया जायेगा।

(3) किसी भी व्यक्ति का समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसका,

- (i) दोषसिद्धि का पिछला इतिहास है;
- (ii) किसी अनैतिक कार्य में या बाल दुर्ब्यवहार के किसी कार्य में या बाल श्रम के नियोजन में संलिप्त रहा है;
- (iii) कोई ऐसा पूर्णाकालिक व्यवसाय धारण किये हुये है जो उसे अधिनियम तथा नियमों के अनुसार समिति के कार्य के प्रति आवश्यक समय तथा ध्यान प्रदान करने नहीं दे सकता है;
- (iv) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में विहित अर्हता एवं अनुभव को पूरा नहीं करता है, तथा ऐसी दशा में चयन समिति सम्यक् जांच के उपरान्त या ऐसे तथ्य के सिद्ध हो जाने पर उसका आवेदन अस्वीकार करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गयी नामों की सूची से अगले व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी।

(4) दो सदस्यों में आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा।

24. बैठक तथा यात्रा भत्ते।— समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा बैठक के भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

25. समिति की बैठक।— (1) समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर में या, बाल गृह के निकट किसी स्थान पर या, अधिनियम के अधीन चल रही किसी संस्था के एक उपर्युक्त परिसर में आयोजित करेगी।

(2) देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या बच्चों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि बच्चे या बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, समिति बच्चे या बच्चों तक पहुंचने के लिए बाहर निकल सकती हैं तथा ऐसे स्थान पर अपनी बैठक कर सकती है जो ऐसी बालक या बच्चों के लिए सुविधाजनक हो।

(3) जिस परिस्मर में समिति अपनी बैठकें आयोजित करती है, वह बाल मित्रतापूर्ण होगा तथा किसी भी ढंग से न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा, उदाहरण के लिए समिति को एक ऊंचे मंच पर बैठक नहीं करनी है तथा बैठने की व्यवस्था एकरूप होगी एवं गवाह के कठघरे नहीं होंगे।

(4) समिति सप्ताह में कम से कम तीन दिन बैठक करेगी, जिसे मामले तथा कार्य के लंबित रहने पर निर्भर रहते हुए राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

(5) एक वर्ष में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की कम से कम तीन चौथाई हाजिरी आवश्यक है।

(6) समिति का प्रत्येक सदस्य आधिकारिक कार्य घंटों के दौरान प्रत्येक बैठक में कम से कम पांच घंटे उपस्थित रहेगा जिसे कार्य के लंबित रहने पर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

26. समिति के कार्य तथा शक्तियाँ — समिति अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित कार्य करेगी, अर्थात्:—

- (क) समिति के समक्ष प्रस्तुत बालक का संज्ञान लेना एवं उसे अपने पास लेना;
- (ख) समिति के समक्ष लाये गये मामलों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना;
- (ग) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार की सहायता से देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चों तक पहुंचना जो कठिन परिस्थितियों में होने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नहीं हैं;
- (घ) बच्चे की सुरक्षा तथा कुशल क्षेम से संबंधित तथा इन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर आवश्यक जांच का संचालन करना;
- (ङ.) बाल कल्याण पदाधिकारियों या परिवीक्षा पदाधिकारियों या गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच संचालित करने तथा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना;
- (च) प्रत्येक बच्चों की देखरेख के लिए योजना तैयार करना;
- (छ) तत्काल आश्रय समेत बच्चे के लिए आवश्यक देखरेख तथा संरक्षण सुनिश्चित करना;
- (ज) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण या अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्ती कार्य करने एवं समन्वय समेत इस संबंध में माता-पिता या संरक्षकों या उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं को आवश्यक निर्देश पारित करने सहित समुचित पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना;
- (झ) बाल गृह/आश्रय गृह/ड्रॉप-इन केन्द्रों के अधीक्षक को आश्रय तथा देखरेख के लिए अपेक्षित बच्चों को अपने पास लेने का निर्देश देना;
- (ज) समिति द्वारा निपटाये गये प्रत्येक मामले के विस्तृत केस अभिलेख को दस्तावेज के रूप में रखना तथा अनुरक्षित करना;
- (ट) बच्चों के लिए बाल मित्रतापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना;
- (ठ) बच्चों के देखरेख तथा संरक्षण के लिए राज्य सरकार को 'उपयुक्त संस्थाओं' की अनुशंसा करना;
- (ड) विनिर्दिष्ट मामलों में अस्थायी अवधि के लिये 'उपयुक्त व्यक्तियों' को घोषित करना;
- (ढ) किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिये विधिक रूप से मुक्त घोषित करना;
- (ण) अपने अधिकारिता में लापता बच्चों के संबंध में सूचना रखना तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (त) देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले मामलों के संबंध में मंडल के साथ संपर्क बनाये रखना;
- (थ) ऐसी प्रत्येक संस्था का दौरा करना जहां बच्चे रखे जाते हैं तथा राज्य सरकार की सहायता से इन संस्थाओं में बच्चों की स्थिति की समीक्षा करने के लिये कम से कम तीन महीनों में एक बार देखरेख तथा संरक्षण एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण को बुलाना तथा आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना;
- (द) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वैसे संघों तथा अभिकरणों का अनुश्रवण करना जो बच्चों से संबंधित हैं ताकि बच्चों के शोषण तथा उसके साथ दुर्व्यवहार को रोका जा सके;
- (ध) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार की सहायता से बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण में संलग्न शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षी एवं श्रम विभाग तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना;

- (न) जब कभी भी आवश्यक हो, सामाजिक जांच, प्रत्यावर्तन तथा पुनर्वास समेत पूर्वोक्त में से किसी के भी कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क रखना तथा उनसे जुड़ना; तथा
- (प) बच्चों तथा बयस्कों से समान रूप से सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक सुझाव पेटी रखना तथा आवश्यक कार्रवाई करना;
- (फ) समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन की सहायता से, बच्चे के पुनर्वास तथा तथा सामाजिक पुनः एकीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कॉर्पोरेट तथा सामुदायिक अभिकरणों की एक सूची रख सकती है;
- (ब) त्वरित जांच तथा बच्चे के प्रत्यावर्तन या पुनर्वास को सुगम बनाने के लिये अन्य जिलों में समितियों तथा अन्य संबद्ध निकायों के साथ संपर्क रखना;
- (भ) बच्चे या किसी अन्य संबंधित मामले के बारे में मासिक रिपोर्ट तैयार करना एवं, जब कभी भी आवश्यक हो, इसे जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजना;
- (म) बाल कल्याण समिति आवश्यक जांच पड़ताल का संचालन करने के उपरान्त त्याग किये गये बालक का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये स्थानीय प्राधिकार को निर्देश निर्गत कर सकती है;
- (य) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेशित कोई अन्य कार्य।

27. समिति के संबंध में प्रक्रिया—(1) बैठक के लिए गणपूर्ति उपस्थित होनेवाले तीन सदस्यों से होगी, जिनमें अध्यक्ष सम्मिलित हो सकता है।

(2) किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा लिये गये किसी निर्णय के लिए, जब समिति बैठक नहीं कर रही है, समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) समिति द्वारा लिये गये अपने सभी आदेशों की प्रतियाँ जिला बाल संरक्षण इकाई को यथा आवश्यक अनुपालन एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगी।

(4) समिति मामलों के निस्तारण के पहले बालक की आयु, विकास की अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, राय एवं बाल कल्याण पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता की अनुशंसा को विचार में लेगी।

(5) मामले के अंतिम निस्तारण के लिए, अध्यक्ष समेत कम से कम दो सदस्यों द्वारा समिति का आदेश हस्ताक्षरित किया जायेगा।

28. समिति के समक्ष बालक का प्रस्तुतिकरण—(1) देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को यात्रा के समय को छोड़ते हुए 24 घंटों के भीतर निर्मांकित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा—

- (क) किसी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या अभिहित पुलिस पदाधिकारी द्वारा;
- (ख) किसी लोक सेवक द्वारा;
- (ग) चाईल्ड लाईन, एक निर्बंधित स्वैच्छिक संगठन या किसी ऐसे स्वैच्छिक संगठन या अभिकरण द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यकृत हो;
- (घ) सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा;
- (ङ.) किसी लोक-हितोन्मुख नागरिक द्वारा; या
- (च) स्वयं बालक द्वारा।

(2) जब कभी भी उपोक्त व्यक्ति/व्यक्तिगण द्वारा देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रभार लेते हैं, बालक, उस स्थिति जिससे उसे बचाया गया है, स्थान समेत उस समय, जब व्यक्ति ने बालक का प्रभार लिया था, के विवरण प्रदान करते हुए पुलिस थाना या चाईल्ड लाईन को यथा संभव यथा शीघ्र सूचना प्रदान की जायेगी। बालक का प्रभार लेने वाला व्यक्ति अपने नाम, पता तथा जिस संगठन के लिये वह काम कर रहा है, उसके विवरण एवं बचाव दल के सदस्यों के अन्य सुसंगत विवरण भी प्रदान करेगा।

(3) दो वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में, जो चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, व्यक्ति या संगठन बालक के छायाचित्र के साथ समिति को 24 घंटों के भीतर एक लिखित रिपोर्ट भेजेगा तथा इस प्रभाव के एक चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ बालक के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) समिति उसके ध्यान में लाये गये मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकती है तथा जहाँ आवश्यक हो, देखभाल तथा संरक्षण के आवश्यकता वाले बालक तक पहुंच सकती है तथा ऐसे कार्यों को पूरा करने में राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार समिति को आवश्यक समर्थन तथा सहायता उपलब्ध कराएगी।

(5) समिति के बैठक न करने की दशा में, समिति के समक्ष बालक के पेश किये जाने के समय तक माता-पिता या संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थाओं की, यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिये बालक को अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार समिति के एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) एकल सदस्य के भी पहुंच के भीतर न होने की दशा में, या समय के अनुकूल न होने पर, बालक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी गैर सरकारी संगठन या चाईल्ड लाईन या पुलिस द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीकृत बालकों के लिये समुचित संस्था ले जाया जाएगा, तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के समय तक ऐसी संस्था में रखा जायेगा।

(7) संबद्ध संस्था ऐसे बालक के बारे में समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को सूचित करेगी एवं 24 घंटों के भीतर समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करेगी तथा ऐसे मामलों में, उस व्यक्ति के लिए, जो देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को संस्था तक लाता है, समिति के समक्ष बालक के प्रस्तुत किये जाने के समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं हो सकता है। अगर संस्था राजकीय बालगृह है, बालक को समिति की अगली बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

(8) जो कोई भी समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करता है, उन परिस्थितियों, जिनके अधीन बालक उनके ध्यान में आया था, तथा पुलिस एवं लापता व्यक्ति दस्ता को सूचित करने में उनके द्वारा किये गये प्रयासों पर एक रिपोर्ट सौंप सकता है तथा उन मामलों में जहाँ कोई मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन या कोई पुलिसकर्मी समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करता है, उन्हें भी बालक के परिवार का पता लगाने के लिये उनके द्वारा किये गये प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(9) समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिये या किसी संस्था में भर्ती कराने के लिये बालक की कोई सामान्य चिकित्सीय या वंशावली संबंधी परीक्षा एक पूर्वापेक्षा नहीं होगी।

(10) समिति लापता बालकों के मामलों एवं बालकों के साथ हिंसा, शोषण एवं दुर्व्वहार के मामलों में भी पुलिस परिवाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के दाखिले को सुगम बनायेगी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला या राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार या स्वैच्छिक संगठनों में विधिक अधिकारी के माध्यम से अपेक्षित विधिक सहायता की व्यवस्था करेगी।

(11) प्रत्येक समिति देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के बारे में उनके द्वारा प्राप्त सूचना मासिक एवं त्रैमासिक रूप से जिला तथा राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भेजेगी।

(12) समिति की कार्यवाहियों के दौरान बालक को बाल मित्रतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) समिति के पास अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक पैनलीकृत सूची होगी जो दुर्व्वहार किये गये बालकों के मामलों से निपटने में समिति की सहायता करेगी तथा जो दुर्व्वहार किये गये बालकों को विधिक सेवाएँ पहुंचाना सुगम बनाने के लिए लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के साथ भी अंतःक्रिया कर सकती हैं, जब ऐसे बालकों से संबंधित मामलों पर नियमित दांडिक न्यायालयों में विचार किया जाता है। जहाँ तक संभव हो सके, बालिका के मामले में लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक का अधिमानतः एक महिला होगी।

(14) जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से परिवार का पता लगाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जाना चाहिए, तथा मान्यकृत स्वैच्छिक संगठनों, चाईल्ड लाईन या पुलिस की भी सहायता ली जा सकती है।

(15) समिति जांच के लंबित रहते बालक को आयु तथा लिंग के लिए समुचित सुविधाओं वाले नामनिर्देशित सुरक्षित स्थान पर भेजेगी तथा ऐसी अवस्था में, राज्य सरकार परिवहन उपलब्ध करायेगी या वास्तविक किराये के आधार पर ऐसे खर्चों के लिये आवश्यक वजटीय आवंटन करेगी।

(16) बालक को जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से सादे वस्त्रों में पुलिस पदाधिकारी या स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि द्वारा या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा, जिसे समिति द्वारा उपयुक्त माना गया हो, सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है तथा बालिका के मामले में, महिला अनुरक्षक बालिका के साथ होगी।

(17) राज्य सरकार द्वारा समिति को सभी मान्यकृत बाल देखरेख संस्थानों की क्षमता तथा अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथा विहित समुचित सुविधाओं के साथ उनकी एक सूची, सभी बाल संबंधित संसाधन सेवाओं की एक सूची तथा देश भर की सभी बाल कल्याण समितियों के संपर्क विवरणों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

(18) समिति जांच के लंबित रहते बालक को माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखकर प्रपत्र-VIII में आदेश करते समय, या प्रत्यावर्तन के समय, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्रपत्र-IX में वचनबद्धता देने के लिए निर्देश दे सकती है।

(19) जब कभी भी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखने का आदेश करती है, यह गृह तथा माता-पिता या संरक्षक एवं पिछले इतिहास की विशिष्टियों के साथ प्रपत्र-X में ऐसी संस्था के अधीक्षक को जांच के लंबित रहते अल्प अवधि के लिये रखने के आदेश की एक प्रतिलिपि अग्रसारित करेगी।

(20) जब कभी भी समिति अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन प्रत्यावर्तन के भाग के तौर पर बालक को उपयुक्त संस्था में रखे जाने का आदेश करती है, यह ऐसी संस्था के अधीक्षक को प्रपत्र-XI में प्रत्यावर्तन के अपने आदेश की एक प्रति अग्रसारित करेगी।

- (21)(क) समिति को इसका भी समाधान करना चाहिए कि बालक को पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार तंग नहीं किया गया है, जो बाल कल्याण समिति के समक्ष लाने के प्रयोजनार्थ बालक का प्रभार लेता है।
- (ख) समिति अंतिम निस्तारण किये जाने के समय तक प्रतिभू समेत या इसके बिना बालक को माता-पिता/संरक्षक की देखरेख में छोड़ सकती है।
- (ग) समिति कार्यवाही का संचालन औपचारिक ढंग से करेगी यह सुनिश्चित करने के लिए बालक का हित सर्वोपरि महत्व का है।
- (घ) समिति देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का हित प्रभावित करने से संबंधित कोई सामग्री प्रकाशित करने के लिए किसी मीडिया के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगी।
- (ङ.) समिति देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से पूछताछ करेगी तथा दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 में यथा अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार कथनों को दर्ज करेगी।
- (च) अगर समिति को जांच के अनुक्रम में किसी भी अवस्था में यह समाधान हो कि जांच के प्रयोजनार्थ बालक की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकती है।

(22) बालक को, जहां तक संभव हो सके, उस संस्था में रखा जायेगा जो, उस स्थान के निकटतम हो जहां के उसके माता-पिता या संरक्षक हों, जबतक कि माता-पिता या संरक्षकों द्वारा भी बालक के साथ दुर्व्यवहार या शोषण न किया गया हो।

29. जांच की प्रक्रिया— (1) जब कोई बालक समिति के समक्ष लाया जाता है, समिति प्रपत्र-XII में आदेश के माध्यम से जांच का संचालन करने के लिये मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता या परिवीक्षा पदाधिकारी या केस-कार्यकर्ता या बाल कल्याण पदाधिकारी को सौंप देगी।

(2) समिति एक वैयक्तिक देखरेख योजना तैयार करने तथा उपयुक्त पुनर्वास के लिए पूछताछ किये जाने वाले विवरणों या विशिष्टियों के बारे में संबद्ध व्यक्ति या संगठन को निर्देश देगी।

(3) परिवीक्षा पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता या बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा संचालित सभी जांच प्रपत्र-XIII के अनुसार होगी तथा इन्हें आवश्यक रूप से विस्तार से बालक की परिवारिक स्थिति का आकलन उपलब्ध कराना है, तथा लिखित में स्पष्टीकृत करना है कि क्या बालक को उसके परिवार के पुनः हवाले करना उसके उत्तम हित में होगा।

(4) जांच आवश्यक रूप से चार महीनों के भीतर या ऐसी लधुतर अवधि के भीतर, जिसे समिति द्वारा यथा निर्धारित किया जाय, पूरी की जानी है। परन्तु यह कि समिति बालक के उत्तम हित में तथा लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से विशेष परिस्थितियों के अधीन उक्त अवधि बढ़ा सकती है।

(5) जांच के समापन के उपरान्त, अगर बालक बाल-गृह में बने रहने के लिए आदेशों के अधीन है, समिति गृह-अधीक्षक को ऐसे बालक का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रगति की वार्षिक समीक्षा के लिए समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने का निर्देश देगी।

30. बाल गृह।—(1) राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिये नीचे विनिर्दिष्ट रीति से पृथक गृहों को स्थापित करेगी:—

- (क) सभी बाल गृहों को अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) तथा इन नियमों के नियम 74 के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं के तौर पर पंजीकृत किया जायेगा;
- (ख) सभी बाल गृह नियम 73 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अभिप्राणित किये जायेंगे;
- (ग) सभी बाल गृह उनके द्वारा प्राप्त देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के बारे में संबद्ध समिति को सूचित करेगी;
- (घ) प्रत्येक बाल गृह में शिशुओं के लिए समुचित सुविधाओं के साथ 0-5 वर्ष के आयु समूह में बालक के लिए अलग सुविधाएँ शामिल होंगी;
- (ड.) 06 से 18 वर्ष के आयु समूह वाले बालकों तथा बालिकाओं के लिए पृथक बाल गृह स्थापित किये जाएँगे;
- (च) 06 से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को 06 से 10 वर्षों, 11 से 15 वर्षों तथा 16 से 18 वर्षों के तीन समूहों में पृथक किया जायेगा।

(2) इन नियमों के नियम 56 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के माध्यम से समुदाय तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों एवं जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को सम्मिलित करके बालक देखरेख के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रत्येक बाल गृह में एक समावेशी बाल देखरेख केन्द्र होगा तथा राज्य सरकार नियमित समीक्षाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा या किसी मान्यकृत स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाये जा रहे बाल गृहों के कार्यकलाप की एक वार्षिक निष्पादन समीक्षा करेगी।

(3) ऐसे केन्द्र की गतिविधियां निम्नान्कित पर केन्द्रित होंगी:—

- (क) विनिर्दिष्ट रूप से बालक के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक आवश्यकताओं, शिक्षा, कौशल विकास, संरक्षण एवं विशेष आवश्यकताओं, अगर कोई हों, को सम्बोधित करते हुए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक बालक के लिये वैयक्तिक देखरेख योजनाएं तैयार करना तथा इनका समीक्षा करना;
- (ख) बालक पारिवारिक देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं प्रायोजन जैसी परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवाएँ;
- (ग) पारिवारिक परामर्श, पोषण, स्वास्थ्य हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक हस्तक्षेप तथा प्रायोजक उपलब्ध कराकर उपेक्षा से बचाने के लिये संघर्ष या आपदा की स्थितियों में तथा सतत या असाध्य व्याधि से प्रभावित किशोर या बच्चों के लिये विशिष्टिकृत सेवाएं;
- (घ) चाईल्ड लाईन (शुल्क मुक्त हेल्प लाईन सं 1098) के माध्यम से आपातकालीन पहुँच सेवा;
- (ड.) छह से कम वर्षों के बच्चों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं के साथ संपर्क रखना;
- (च) वैसे संगठनों तथा व्यक्तियों के साथ संपर्क रखना जो बच्चों को समर्थक सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं;
- (छ) बालकों के लिये विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक स्वयंसेवियों के लिए अवसर;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि बालक परिवार के प्रति सकारात्मक रवैया विकसित करे तथा परिवार के साथ एक जुड़ाव उत्पन्न करे; तथा समूह परामर्श की व्यवस्था करना।

31. आश्रय गृह।—(1) देखरेख तथा संरक्षण की तत्काल आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जैसे कि सड़क पर रहने वाले बालक तथा भागे हुए बालकों के लिए, राज्य सरकार स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपेक्षित संख्या में आश्रय गृहों या ड्रॉप-इन केन्द्रों (खुला आश्रय) की स्थापना का समर्थन करेगी।

(2) आश्रय गृहों में सम्मिलित होंगे—

- (क) अस्थायी आश्रय तथा देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि वाले अल्पावास गृह;
- (ख) बालक को तत्काल देखरेख तथा संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम चार महीनों की अवधि वाली संक्रमणकालीन सुविधाएँ;
- (ग) दिन में देखरेख या रात्रि में आश्रय सुविधा की आवश्यकता वाले बालकों के लिये 24 घंटे चलने वाले ड्रॉप-इन केन्द्र।

(3) आश्रय गृहों या ड्रॉप-इन केन्द्रों में पहनने ओढ़ने, खाने पीने, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख तथा पोषण, स्वच्छ पेय जल एवं स्वच्छता के मामलों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था के अलावा रहने-सहने की न्यूनतम सुविधाएं होंगी।

(4) इन नियमों के नियम 41(2)(घ) के अनुसार बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक आश्रय गृह होंगे।

(5) सभी आश्रय गृह शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श तथा मनोरंजन के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे या स्वैच्छिक संगठनों या कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग करके इनकी व्यवस्था करेंगे।

(6) समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, लोक सेवक, चार्डल लाइन्स, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वयं बालक किसी बालक को ऐसे आश्रय गृह निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(7) सभी आश्रय गृह बालक की छाया चित्र के साथ आश्रय गृह की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की रिपोर्ट समिति, लापता व्यक्ति व्यूरो या विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई को सौंपेंगे।

(8) आश्रय स्थलों में रहने वाले बच्चों के उपयुक्त देखरेख, संरक्षण, विकास, पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के लिए प्रभारी पदाधिकारी, बाल कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाएं उपलब्ध कार्यालय जायेंगी।

(9) कोई भी बालक विशेष परिस्थितियों के सिवाय समिति के अनुमोदन से सामान्य रूप से आश्रय गृह में एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा।

32. बालकों के यौन शोषण के निवारण के लिए दिशा निर्देश।—राज्य सरकार, किशोर न्याय मण्डल, बाल कल्याण समिति, अन्य सक्षम प्राधिकार तथा अधिकरण बालकों के उत्तम हित में सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, विद्यालय एवं ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थाएं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

अध्याय 5

पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण

33. पुनर्वास तथा सामाजिक पुनः एकीकरण।—पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण का प्रधान लक्ष्य परिवार के भीतर जहाँ संभव हो, पुनर्वास के माध्यम से बच्चों की गरिमा तथा आत्मसम्मान पुनः स्थापित करने में तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने में उनकी सहायता करना है, या अन्यथा देखरेख के वैकल्पिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा करना है तथा दीर्घकालीन संस्थागत देखरेख अंतिम उपाय होगा।

34. दत्तक ग्रहण।—(1) दत्तक ग्रहण का प्रधान लक्ष्य ऐसे बालक को स्थायी स्थानापन्न परिवार उपलब्ध कराना है जिसकी देखरेख उसके जैविक माता-पिता द्वारा नहीं की जा सकती है।

(2) दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिए, अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकार द्वारा निर्गत एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गनिर्देश लागू होंगे।

(3) अनाथ हो चुके तथा परित्यक्त बालकों के मामलों में निर्मांकित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्—

- (क) जब कभी भी विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अधिकरण किसी परित्यक्त बालक को प्राप्त करता है, यह 24 घंटों के भीतर पुलिस थाना को मामलों की सूचना देगा;

(ख) विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सभी अनाथ हो चुके तथा परित्यक्त बालकों, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है, को यात्रा में लगे समय को हटाते हुए ऐसे बालकों को प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ग) कोई बालक दत्तक ग्रहण के लिए योग्य बन जाता है जब समिति अपनी जाँच पूरी कर लेती है तथा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर देती है;

(घ) ऐसी घोषणा प्ररूप-XIV में की जायेगी;

(ङ.) बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के समय आवश्यक रूप से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा;

(च) जब कभी भी किसी परित्यक्त नवजात के बारे में पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, पुलिस नवजात को प्रभार में लेगी तथा तत्काल चिकित्सीय सहायता एवं देखरेख उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी;

(छ) बाद में, बालक को किसी विशिष्टिकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण या मान्यता प्राप्त या अभिप्राणित बाल गृह में या सरकारी अस्पताल की बाल चिकित्सा इकाई में रखा जायेगा जिसके उपरान्त 24 घंटों के भीतर समिति के समक्ष बालक को पेश किया जायेगा;

(ज) बालक को परित्यक्त घोषित करने तथा उसे दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र अभिप्राणित करने की प्रक्रिया:-

- (i) परित्यक्त बालक के मामले में, मान्यता प्राप्त अभिकरण 24 घंटों के भीतर समिति को सूचित करेगा तथा उस पुलिस थाने, जिसके अधिकार क्षेत्र में परित्यक्त पाया गया था, में दाखिल रिपोर्ट की प्रति के साथ समिति के समक्ष उसे पेश करेगा;
- (ii) समिति जाँच की एक प्रक्रिया संस्थित करेगी, जिसमें परिवीक्षा पदाधिकारी या बाल कल्याण पदाधिकारी, यथा स्थिति, द्वारा संचालित गहन जाँच सम्मिलित होगी एवं वह एक महीने के भीतर निष्कर्षों से युक्त प्ररूप-XIII में रिपोर्ट समिति को सौंपेगा;
- (iii) दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा घोषणा की जायेगी, ऐसा कथित करते हुए कि कम से कम एक अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में अधिसूचना करने के उपरान्त भी बालक के लिए कोई दावेदार नहीं आया है तथा दो वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, दूरदर्शन या किसी अन्य प्रचलित माध्यम पर अतिरिक्त घोषणा या रेडियो पर घोषणा तथा लापता व्यक्ति दस्ते या ब्लूरो को अधिसूचना प्रदान की जायेगी;
- (iv) दो वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में बच्चे के पाये जाने के समय से 60 दिनों की अवधि के भीतर (iii) में कथित उपाय किये जायेंगे तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के मामले में, यह अवधि चार महीने होगी;
- (v) अधिसूचना की अवधि इस उप-नियम के खंड (2) के अधीन संचालित की जानेवाली जाँच तथा प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट के साथ-साथ चलेगी;
- (vi) समिति इस उप-नियम के खंडों (2) एवं (3) के अधीन की गयी विशिष्टिकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की घोषणा समेत जाँच की प्रक्रिया के समापन पर बालक को दत्तक ग्रहण के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी;
- (vii) सात वर्ष से ऊपर के किसी भी बच्चे को, जो समझ सकता है तथा अपनी राय व्यक्त कर सकता है, बाल कल्याण समिति के समक्ष अभिलिखित उसकी सहमति के बिना दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित नहीं किया जायेगा।

(4) अभ्यर्पित बालक के मामले में निम्नांकित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्:-

- (क) अभ्यर्पित बालक वह बालक है जिसे समिति द्वारा जाँच की सम्यक् प्रक्रिया के उपरान्त ऐसा घोषित किया गया था तथा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किये जाने के लिए, 'अभ्यर्पित' बालक निम्नांकित में से कोई भी होगा:-

- (i) गैर सहमतिजन्य संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न;
- (ii) किसी अविवाहित माता से या विवाहेतर संबंध से उत्पन्न;
- (iii) ऐसा बालक, जिसके मामले में जैविक माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तथा जीवित माता/पिता देखरेख करने में अक्षम है;
- (iv) ऐसा बालक, जिसके माता-पिता या संरक्षक उनके नियंत्रण से परे भौतिक, भावनात्मक एवं सामाजिक कारकों के कारण उसे छोड़ देने पर विवश हो गये हैं।

(ख) दत्तक ग्रहण के परिणामों को स्पष्ट करते हुए तथा बच्चे को माता-पिता के पास रखने की संभावनाओं की खोज करते हुए माता-पिता को समझाने के लिए समिति द्वारा गंभीर प्रयास किये जायेंगे तथा अगर, माता-पिता अपने पास रखने के अनिच्छुक हैं, तब, ऐसे बच्चों को प्रारंभ में पालक देखरेख में रखा जायेगा या उनके प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जायेगी;

(ग) अगर अभ्यर्पण अपरिहार्य है, समिति की उपस्थिति में गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्ररूप-XV में अभ्यर्पण-विलेख निष्पादित किया जायेगा;

(घ) दत्तक ग्रहण अभिकरण अभ्यर्पण के उपरान्त जैविक माता, पिता या दोनों को प्रदत्त पुनर्विचार की दो महीने की समयावधियों के पूरे होने की प्रतीक्षा करेंगे;

(ङ.) ऐसे बालक, जिसकी जैविक माता, पिता या दोनों द्वारा उसका अभ्यर्पण किया गया है, के मामले में समिति के समक्ष माता, पिता या दोनों द्वारा अभ्यर्पण का दस्तावेज निष्पादित किया जायेगा;

(च) सम्यक् जाँच के उपरान्त, समिति प्ररूप-XIV में या, यथास्थिति, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण दिशा निर्देशों के अनुसार साठ दिनों की पुनर्विचार अवधि के उपरान्त अभ्यर्पित बालक को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।

(5) अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजनों के लिए, 'न्यायालय' से अभिप्रेत ऐसा सिविल न्यायालय है, जिसे दत्तक ग्रहण तथा संरक्षणत्व के मामलों में अधिकारिता है तथा इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश का न्यायालय, परिवार न्यायालय तथा सिविल न्यायालय आ सकते हैं।

35. पालक देखरेख।—(1) ऐसे बालकों के लिए जिसे दत्तक ग्रहण में नहीं रखा जा सकता है, परिवीक्षा पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता यथास्थिति, की निगरानी के अधीन अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) में यथा प्रदत्त पालक देखरेख का कार्य करने के लिए प्ररूप-XVII में सक्षम प्राधिकार द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा, तथा पालक देखरेख की अवधि बालक की आवश्यकता पर निर्भर होगी।

(2) राज्य सरकार स्वयं अपना पालक देखरेख कार्यक्रम तैयार करेगी या केन्द्र सरकार द्वारा यथा विहित या अधिसूचित किसी दिशा निर्देश या कार्यक्रम या योजना को अपनायेगी ताकि बालकों के संस्थानीकरण को घटाया जा सके तथा प्रत्येक बालक के लिए पालन पोषण करने वाला पारिवारिक वातावरण तैयार किया जा सके।

(3) राज्य सरकार पालक देखरेख कार्यक्रम तैयार करने में मण्डलों या समितियों, बालकों के लिए वैकल्पिक देखरेख पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों एवं संगठनों से मंत्रणा करेगी।

(4) बच्चों का गैर संस्थानीकरण करना एवं उन्हें पालक देखरेख में रखना बाल कल्याण समिति की सहमति से किया जायेगा।

36. पालक देखरेख के लिए परिवारों के चयन के लिए मापदंड।—(1) इन नियमों के नियम 35 के अधीन आच्छादित बालकों के मामले में, पालक देखरेख के लिए परिवारों के चयन हेतु निम्नांकित मापदंड लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) पालक माता-पिता के पास परिवार के भीतर संतुलित भावनात्मक सामंजस्य होना चाहिए;
- (ख) पालक माता-पिता की ऐसी आय होनी चाहिए जिससे वह बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो तथा पालक देखरेख भरण-पोषण भुगतान पर निर्भर न हो;
- (ग) मासिक पारिवारिक आय पालक बालकों की देखरेख करने के लिए पर्याप्त होनी होगी तथा समिति द्वारा अनुमोदित होगी;

(घ) यह निर्धारित करने के लिए कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं, ह्युमन इम्युनो डिफिसियेंसी वायरस (HIV), तथा हिपेटाईटिस B जाँचने के लिए परीक्षणों समेत परिवार में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय प्रतिवेदन प्राप्त की जानी चाहिए;

(ड.) पालक माता-पिता के पास बच्चों की देखरेख का अनुभव होना चाहिए तथा उपयुक्त बालक देखरेख प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए;

(च) पालक माता-पिता को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्थायित्व युक्त होना चाहिए;

(छ) घर में पर्याप्त स्थान तथा बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए;

(ज) पालक देखरेख परिवार को अधिकथित नियमों का अनुसरण करने का इच्छुक होना चाहिए जिसमें बाल चिकित्सक के यहां नियमित रूप से जाना, बालक का स्वास्थ्य बनाये रखना तथा उनके रिकॉर्ड रखना सम्मिलित है;

(झ) परिवार को समझौते पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक होना चाहिए तथा जब कभी भी ऐसा करने के लिए कहा जाय, विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण को बालक को वापस कर देना चाहिए;

(अ) पालक माता-पिता को प्रशिक्षण या दिशा निर्देशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए;

(ट) पालक माता-पिता को अभिकरण द्वारा अनुमोदित बाल चिकित्सक के पास बालक को नियमित जाँच पड़ताल हेतु (नवजातों के मामले में महीने में कम से कम एक बार) ले जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए; तथा

(ठ) एकल माता-पिता को विपरीत लिंग के बच्चों की पालक देखरेख प्रदान नहीं की जा सकती है, जिनके बीच आयु का अंतर बीस वर्ष से कम हो।

(2) जाति, धर्म, प्रजातीय प्रस्थिति, निःशक्तता के आधार पर पालक माता-पिता के चयन में कोई भेदभाव नहीं होगा तथा पालक देखरेख के लिए रखने का निर्णय करने में बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति तथा उत्तम हित सर्वोपरी होगा।

(3) पालक माता-पिता को बाल कल्याण पदाधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्ररूप-XVI के अनुसार किये गये गहन आकलन के उपरान्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में अधिकथित प्रावधानों के अनुसार बालक को हवाले करने के पहले समिति द्वारा 'उपयुक्त व्यक्ति' घोषित किया जायेगा।

37. पूर्व दत्तक ग्रहण पालक देखरेख।—पूर्व दत्तक ग्रहण पालक देखरेख के मामले में, धारा 42 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध तथा अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन अधिसूचित तत्सम् दिशा निर्देश लागू होंगे।

38. प्रायोजन।—(1) राज्य सरकार गैर-सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समितियों, अन्य प्रासारिक सरकारी अभिकरणों या कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ मंत्रणा करके प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार, जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई की सहायता से, जोखिम से भरे परिवारों तथा बच्चों को चिन्हित करेगी एवं बालक की शिक्षा, स्वास्थ्य या पोषण तथा अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए प्रायोजन के रूप में आवश्यक समर्थक सेवाएँ उपलब्ध करायेगी।

(3) बाल गृह तथा विशेष गृह अधिनियम की धारा 43 में यथा अधिकथित प्रायोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।

(4) प्रायोजन प्राप्त करने वाली संस्थाएँ कार्यक्रम के लिए सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों के उपयुक्त तथा पृथक हिसाब किताब रखेंगी।

(5) किशोर या बालक को प्रायोजन के माध्यम से सहारे के लिए मण्डल या समिति प्रपत्र XVIII में एक आदेश देगी तथा समुचित कार्रवाई के लिए जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई राज्य सरकार को एक प्रतिलिपि भेजेगी।

39. पश्चातवर्ती देखरेख संगठन।—(1) 'राज्य सरकार सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए संस्था आधारित जीवन से समाज की मुख्य धारा में उनके आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ' किशोरों या बालकों द्वारा विशेष गृह एवं बाल गृह छोड़ देने के उपरान्त उनकी देखरेख के लिये पश्चातवर्ती कार्यक्रम स्थापित करेगी।

(2) अधिनियम की धारा 44 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम 18 से 21 वर्ष की आयु समूह के ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है या वह अपना भार उठाने में असमर्थ हैं।

(3) पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के अधीन 18 वर्ष पूरे कर लेनेवाले किशोर या बालक को रखने के लिए प्ररूप-XIX में मण्डल या समिति द्वारा एक बार आदेश पारित कर देने पर, ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि जिला एवं राज्य बाल संरक्षण इकाई तथा समाज कल्याण निदेशक को भेजी जायेगी, जो पश्चातवर्ती देखरेख की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सूचना की एक प्रतिलिपि संबद्ध गृह के अधीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) मण्डल या समिति या बोर्ड को पश्चातवर्ती कार्यक्रम में रखे गये व्यक्तियों पर अधिकारिता होगी।

(5) इन संगठनों का उद्देश्य ऐसे बालकों को समाज के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम बनाना होगा तथा इन संक्रमण कालीन गृहों में उनके रहने के दौरान इन बालकों को संस्था आधारित जीवन से एक सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(6) किसी पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में शामिल किये गये सभी किशोरों या बालकों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी उपयुक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से लाभार्थी माना जाना है।

(7) कार्यक्रम के प्रमुख संघटकों में सम्मिलित होंगे:—

(क) 18 से 21 वर्ष आयु वाले युवा व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक समूह आवासन;

(ख) व्यवसायिक प्रशिक्षण, नियोजन-उन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रोत्साहन प्रदान करना एवं गृह के किराये और चलाये जाने में अंशदान करने का बढ़ावा देना;

(ग) राज्य के सहरों के बिना क्रमिक रूप से अपना भार उठाने तथा अपनी आय के माध्यम से पर्याप्त राशि की बचत करने के उपरान्त स्वयं अपने स्थान पर रहने के लिए समूह गृह से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन;

(घ) उनकी पुनर्वास योजनाओं पर परिचर्चा करने तथा उनकी उर्जा के लिए रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करने तथा उनके जीवन में संकट की अवधियों से उबरने के लिए इन समूहों के साथ नियमित संपर्क में रहने हेतु किसी समकक्ष परामर्शी की व्यवस्था करना।

(8) उनके द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर तथा ऐसे ऋण की आवश्यकता होने के सम्यक् सत्यापन के उपरान्त उद्यम संबंधी गतिविधियाँ स्थापित करने के इच्छुक युवाओं के लिए पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में ऋणों की व्यवस्था की जा सकती है, तथा इस संबंध में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में युवाओं को आवश्यक व्यावसायिक परामर्श तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में भरती कराये गये व्यक्ति के नाम से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक बचत खाता, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे दस्तावेजों के निर्गमन को सुगम बनायेगा।

40. सम्पर्क तथा समन्वय।—(1) राज्य सरकार मण्डल या समिति, यथास्थिति, के माध्यम से किशोर या बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी, कॉरपोरेट तथा अन्य सामुदायिक अभिकरणों के बीच प्रभावी सह-संबंध स्थापित करेगी।

(2) सरकार अधिनियम तथा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य या जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग की भूमिकाओं तथा उत्तदायित्वों को चिह्नित करेगी तथा उन्हें अधिसूचना के माध्यम से सूचित करेगी।

(3) राज्य सरकार किसी उपयुक्त अभिकरण के साथ समन्वय करके समय-समय पर इन विभागों के कृत्यकारीगण के समुचित प्रशिक्षण तथा उन्हें सुग्राही बनाने की व्यवस्था करेगी।

(4) राज्य सरकार राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप, मादक द्रव्यों की लत छुड़ाने, विधिक सहायता सेवाएँ इत्यादि जैसी विशिष्टिकृत सेवाओं तथा तकनीकी सहायता के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी संपर्क तथा सह-संबंध विकसित करेगी।

(5) कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा, शिविर, परामर्श तथा मनोविनोद की सेवाओं को आयोजित करने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों के संगठन की स्वैच्छिक भागीदारी प्रोत्साहित की जायेगी।

अध्याय 6

संस्थाओं के लिए देखरेख के मानक

41. भौतिक अवसंरचना।—— (1) देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे तथा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए गृह पृथक परिसरों से कार्य करेंगे।

(2) प्रत्येक संस्था में वास सुविधा निम्नांकित मानदंडों के अनुसार होगी, अर्थात्,

(क) सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान:

- (i) बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक सम्प्रेक्षण गृह;
- (ii) शारीरिक तथा मानसिक स्थिति तथा कारित अपराध की प्रकृति को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए किशोरों की आयु, अधिमानतः 7-11 वर्ष, 12-15 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के अनुसार उनका वर्गीकरण तथा पृथक्करण।

(ख) विशेष गृह:

- (i) 10 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं के लिए अलग विशेष गृह तथा बालकों के लिए 11 से 15 तथा 16 से 18 वर्ष की आयु समूह के अनुसार वर्गीकरण एवं पृथक्करण;
- (ii) किशोरों की आयु तथा अपराधों की प्रकृति एवं उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण तथा पृथक्करण;
- (iii) राज्य सरकार उन किशोरों, जिन्हें अधिनियम की धारा 16 के अधीन मण्डल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, को निवास सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर यथा विहित ढंग से एक 'सुरक्षित स्थान' अधिसूचित करेगी।

(ग) बाल गृह:

- (i) नवजातों के लिए समुचित सुविधाओं के साथ 0-5 वर्षों की आयु समूह के बच्चों के लिए पृथक सुविधाएँ।
- (ii) 6 से 18 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक बाल गृह तथा 6 से 10, 11 से 15 एवं 16 से 18 वर्ष के आयु समूह के अनुसार वर्गीकरण एवं पृथक्करण;

(घ) आश्रय गृह:

- (i) बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक आश्रय गृह;
- (ii) बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक आश्रय गृह तथा 6 से 10, 11 से 15 एवं 16 से 18 वर्ष के आयु समूह के अनुसार वर्गीकरण एवं पृथक्करण।

(3) 50 किशोरों या बच्चों को रखने वाली किसी संस्था के भवन या वास सुविधा में निम्नांकित के लिए स्थान सम्मिलित होगा:-

- (i) दो शयनकक्ष या लिविंग कक्ष,
- (ii) दो कक्षाएं,
- (iii) रुग्न कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष,
- (iv) रसोई घर तथा भोजन कक्ष, भंडार,
- (v) मनोरंजन कक्ष या हॉल, पुस्तकालय,
- (vi) स्नान कक्ष, शौचालय/संडास (latrines),
- (vii) परामर्श तथा मार्गदर्शन कक्ष,
- (viii) कार्यालय कक्ष,
- (ix) अधीक्षक का कक्ष,
- (x) कार्यशाला,
- (xi) अधीक्षक के लिए आवास,
- (xii) किशोर न्याय मण्डल/बाल कल्याण समिति के लिए कक्ष,
- (xiii) किशोरों या बालकों की कुल संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्रफल का क्रीड़ा स्थल,

(4) अधीक्षक संस्था के भीतर रहेगा तथा उसे आवास उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर वह उचित कारणों से गृह में रहने में सक्षम नहीं है (निदेशक, समाज कल्याण की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी), तब ऐसी दशा में संस्था का कोई अन्य वरीय कर्मचारी सदस्य संस्था में रहेगा तथा बालकों या किशोरों की समग्र देखरेख का पर्यवेक्षण करने तथा, किसी संकट या आपात स्थिति के मामले में निर्णय लेने की स्थिति में होगा।

(5) (i) नियम 41(3) में अधिकथित मानदंडों के अनुसार वास सुविधा के मानकों का यथा संभव सीमा तक अनुपालन किया जायेगा तथा इसमें कम से कम निर्मांकित सुविधाएं सम्मिलित होंगी:

- (क) शयन कक्ष या जीवन निर्वाह (लिविंग) कक्षः प्रत्येक किशोर या बालक के लिए 40 वर्ग फुट।
- (ख) शौचालय तथा स्नान कक्षः प्रत्येक आठ बच्चों के लिए कम से कम एक।
- (ग) कक्षा : 25 बच्चों के लिए प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फुट।
- (घ) रूग्न कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्षः प्रत्येक कक्ष के लिए 375 वर्ग फुट।
- (ङ) कार्यशाला : प्रत्येक किशोर या बालक के लिए 75 वर्ग फुट।
- (च) क्रीड़ा स्थल : संस्था में किशोरों की कुल संख्या के अनुसार प्रत्येक संस्था में पर्याप्त क्रीड़ा स्थल क्षेत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

- (ii) दुर्घटनाओं के निवारण के लिए उपयुक्त तथा समतल सतह का निर्माण किया जायेगा।
- (iii) लिंग, आयु-उपयुक्तता तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच के भीतर होने के निबंधनों में पर्याप्त प्रकाश, संवातन, तापन तथा शीतन व्यवस्थाएं, स्वच्छ पेय जय एवं स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्थाएं होंगी।
- (iv) अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएं प्राथमिक उपचार किट, रसोई घर, शयन कक्षों, भंडार कक्षों, परामर्शी कक्ष में अग्निशामकों, विद्युत संस्थापनों की आवर्ती समीक्षा, खाद्य सामग्रियों की उपयुक्त भंडारण तथा निरीक्षण, जल भंडारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तथा आपात स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था करेंगी।

(6) सम्प्रेक्षण गृह तथा विशेष गृह बाल मित्रतापूर्ण होंगे तथा किसी भी ढंग से कारागार या लॉकअप जैसे नहीं दिखेंगे।

42. पहनावे तथा बिस्तर की व्यवस्था।—पहनावे तथा बिस्तर की व्यवस्था मापदंड तथा जलवायिक दशाओं के अनुसार होंगी। प्रत्येक किशोर या बच्चे की आवश्यकताएं तथा पहनावे तथा बिस्तर संबंधी आवश्यकता के न्यूनतम मानक की नियमों की अनुसूची-। में अभिकथित है (बच्चों/किशोरों की आवश्यकतानुसार न्यूनतम मानकों में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है)।

43. स्वच्छता तथा आरोग्य।—प्रत्येक संस्था में निर्मांकित सुविधाएं होंगी, अर्थात्:-

- (क) पर्याप्त मात्रा में उपचारित पेयजल; जल फिल्टर संस्थापित किये जायेंगे;
- (ख) स्नान तथा कपड़ों को धोने के लिए पर्याप्त जल, परिसर का रखरखाव तथा स्वच्छता;
- (ग) उपयुक्त जलनिकासी प्रणाली;
- (घ) कुड़ा करकट के निपटारे के लिए व्यवस्थाएं;
- (ङ) मच्छरदानियों की व्यवस्था करके मच्छरों से संरक्षण;
- (च) वार्षिक कीट नियंत्रण;
- (छ) आठ बालकों के लिए कम से कम एक के अनुपात में सुप्रकाशित तथा हवादार शौचालय एवं स्नान कक्षों की पर्याप्त संख्या;
- (ज) धोने के लिए पर्याप्त स्थान;
- (झ) स्वच्छ तथा कीट मुक्त रसोईघर एवं बर्तन धोने के लिए पृथक स्थान;
- (अ) बिस्तर तथा वस्त्रों को सुखाने की व्यवस्था;
- (ट) स्वच्छ रूग्न कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष/चिकित्सा केन्द्र।

44. दैनिक दिनचर्या।—(1) प्रत्येक संस्था में बाल समितियों के साथ मंत्रणा करके किशोरों या बालकों के लिए विकसित की गयी दैनिक दिनचर्या होंगी, जिसे संस्था के भीतर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) दैनिक दिनचर्या अन्य के साथ-साथ एक विनियमित तथा अनुशासित जीवन, वैयक्तिक आरोग्य तथा स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगठित मनोविनोद तथा खेलकूद, नैतिक शिक्षा, सामूहिक गतिविधियों, प्रार्थना तथा सामुदायिक गायन एवं रविवारों तथा अवकाशों के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी।

45. पोषण तथा आहार मापदंड — संस्थाओं द्वारा निम्नांकित पोषण तथा आहार मापदंड का अनुसरण किया जायेगा, अर्थात्,

- (क) बालकों को नाश्ता समेत प्रतिदिन चार बार भोजन उपलब्ध कराए जायेंगे;
- (ख) इन नियमों की अनुसूची-II में वर्णित न्यूनतम पोषणात्मक मानक तथा आहार मापदंड के अनुसार संतुलित आहार एवं स्वाद में विविधता से सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से मेन्यु तैयार किया जायेगा;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्था अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पोषण संबंधी मानक तथा आहार मापदंड का कठोरतापूर्वक अनुपालन करेगी (बच्चों/किशोरों की आवश्यकतानुसार न्यूनतम मानकों में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है);
- (घ) अवकाशों तथा त्योहारों में किशोरों एवं बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराये जा सकते हैं;
- (ङ.) नवजातों तथा रोगग्रस्त किशोरों या बालकों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकता पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार विशेष आहार उपलब्ध कराया जायेगा।

46. चिकित्सीय देखरेख—प्रत्येक संस्था—

- (क) मासिक चिकित्सीय जांच पड़ताल के आधार पर प्रत्येक किशोर या बच्चे के चिकित्सा विवरण पत्र का संधारण करेगी तथा आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायेगी;
- (ख) सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा विवरण पत्र में वजन तथा ऊंचाई का अभिलेख, किसी रोग या उपचार, तथा अन्य शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं के विवरण सम्मिलित हैं;
- (ग) किशोरों या बच्चों की नियमित चिकित्सीय जांच तथा उपचार के लिए सभी कार्य दिवसों पर बुलावे पर चिकित्सक के उपलब्ध होने की सुविधा समेत चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था रखेगी;
- (घ) आपातिक औषधियों तथा खाने-पीने की वस्तुओं के भंडार सहित प्राथमिक उपचार किट समेत एवं स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सीय उपकरण रखेगी;
- (ङ.) प्राथमिक उपचार से निपटने में सभी कर्मचारीगण को प्रशिक्षित करेगी;
- (च) उनकी चिकित्सकों तथा इन्हीं द्वारा नियमित दोरों के लिए तथा संस्थाओं के भीतर आवर्ती रूप से स्वास्थ्य शिकिरों को आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालयों, अन्य अस्पतालों, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ सह-संबंध स्थापित करेगी;
- (छ) टीकाकरण आच्छादन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी तथा उनके संबंध में उपयुक्त विवरण का संधारण करेगी;
- (ज) सांसर्गिक या संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय करेगी;
- (झ) बदतर हो रहे स्वास्थ्य के मामलों या गंभीर मामलों को निकटतम सिविल अस्पताल या मान्यकृत उपचार केन्द्रों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रणाली तैयार करेगी;
- (झ) बीमार बालकों को सतत चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन रखेगी;
- (ट) भर्ती करने के समय चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर जोर दिये बिना किसी किशोर या बालक को भर्ती करेगी;
- (ठ) किसी संस्था में भर्ती कराये गये प्रत्येक किशोर या बालक की चिकित्सीय परीक्षा के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 24 घंटों के भीतर तथा विशेष मामलों या चिकित्सीय आपात स्थितियों में तत्काल चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगी;
- (ड) अंतरण के समय या अंतरण के पहले 24 घंटों के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किशोर या बालक की चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगी;

(ठ) किशोर या बालक के माता-पिता या संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना उसका कोई शल्य क्रियात्मक उपचार नहीं करेगी, जबतक कि माता-पिता या संरक्षक में से कोई खोजा न जा सकता हो तथा किशोर या बच्चे की स्थिति ऐसी हो कि चिकित्सा पदाधिकारी के राय में किसी भी विलम्ब से किशोर या बच्चे को अनावश्यक कष्ट होगा या इसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी, या अन्यथा संस्था के अधीक्षक से इस प्रभाव की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसा नहीं करेगी;

(ण) प्रत्येक किशोर या बच्चे के साथ नियमित परामर्श की व्यवस्था करेगी या इसे उपलब्ध करायेगी तथा संस्था के भीतर परामर्शी सत्रों के लिए पृथक कक्षों समेत ऐसी सेवाओं की आवश्यकता वाले किशोरों के लिए विनिर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगी;

(त) ऐसे बालकों, जिन्हें विशिष्ट मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण तथा पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता है, को योग्य कर्मियों द्वारा प्रशासित समुचित केन्द्र निर्दिष्ट करेगी जहां ये कार्यक्रम संबद्ध बालक की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्दिष्टताओं के अनुकूल किये जायेंगे।

47. मानसिक स्वास्थ्य।—(१) संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रत्येक किशोर या बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का विवरण रखा जायेगा।

(२) वातावरण-आधारित हस्तक्षेप, जो कि बच्चों के लिए एक समर्थकारी वातावरण सृजित करना है, तथा वैयक्तिक उपचार ये दोनों ही प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक है तथा इन सभी संस्थाओं में उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्पष्टीकरण।— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, वातावरण आधारित हस्तक्षेप उबरने की एक प्रक्रिया है, जो किसी संस्था में एक समर्थकारी माहौल तथा वातावरण उपलब्ध कराकर प्रारंभ होती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का पता चल सके तथा अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने के लिए उनके पास विकल्प एवं अधिकार हों तथा इस प्रकार, वह विकसित हो सके एवं अपने नकारात्मक अनुभव से आगे जाकर पहचान कर सकें तथा बच्चे पर ऐसे हस्तक्षेप का निर्णयक भावनात्मक प्रभाव होता है।

(३) किसी संस्था में वातावरण किशोरों या बालकों को अपनी स्थिति से निपटने एवं पुनःविश्वास प्राप्त करने में सक्षम बनाते हुए दुर्व्यवहार से मुक्त होना चाहिए।

(४) किसी संस्था में किशोरों या बालकों की देखरेख में शामिल सभी व्यक्तियों को एक सक्षमकारी वातावरण तैयार करने में भाग लेना चाहिए तथा चिकित्सक के साथ सहयोग करके कार्य करना चाहिए।

(५) वैयक्तिक उपचार एक विशिष्ट प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था एक निर्णयक मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के तौर पर इसके लिए व्यवस्थाएं करेगी।

(६) संस्था में प्रत्येक किशोर या बच्चे के लिए विशिष्ट तथा नियमित वैयक्तिक उपचार हेतु प्रशिक्षित परामर्शीयों की सेवाएं या बाल मार्गदर्शन केन्द्रों, मनोविज्ञान तथा मनोचिकित्सा विभागों जैसे बाहरी अभिकरणों या समरूप सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों के साथ सह-संबंध उपलब्ध होगा।

(७) संस्था से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा करके प्रत्येक किशोर या बच्चे के लिए बाल कल्याण पदाधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख योजना विकसित की जायेगी तथा संबद्ध किशोर या बालक की वैयक्तिक देखरेख योजना के साथ समेकित कर दी जायेगी।

(८) प्रत्येक मामले की संचिका में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाएं संधारित की जायेगी तथा प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना में समेकित कर दी जायेगी।

(९) इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति के समक्ष प्रत्येक महीना तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष त्रैमासिक रूप से सभी देखरेख योजनाएं प्रस्तुत की जायेगी।

(१०) समुचित रूप से प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किये गये मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा निदान के बिना मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए किसी भी किशोर या बच्चे को उपचार प्रदान नहीं किया जायेगा।

48. शिक्षा।—(१) प्रत्येक संस्था आयु तथा क्षमता के सभी किशोरों या बालकों को अपेक्षानुसार संस्था के भीतर एवं बाहर दोनों स्थान पर औपचारिक, अनौपचारिक तथा जीवन दक्ष शिक्षा उपलब्ध करायेगी।

(2) शैक्षणिक अवसरों के कई विकल्प होंगे जिनमें मुख्य धारा के समावेशी विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, खुले विद्यालय, गैर औपचारिक शिक्षा एवं शिक्षण तथा जहां आवश्यक हो, विशेष शिक्षकों से आगत प्राप्त करना सम्मिलित है।

(3) जहां कहाँ भी आवश्यक हो, स्वयं स्वैच्छिक सेवाओं को प्रोत्साहित करके या कोचिंग केन्द्रों के साथ जुड़कर संस्थाओं में विद्यालय जानेवाले बच्चों को अतिरिक्त कोचिंग उपलब्ध करायी जायेगी।

49. व्यावसायिक प्रशिक्षण।—(1) प्रत्येक संस्था किशोरों या बालकों को लाभपूर्ण एवं बाजारोन्मुख, आय अर्जक व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी।

(2) संस्थाएं तकनीकी अनुदेश के मान्यकृत संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, सरकारी एवं निजी संगठनों या इन्टरप्राइजों, अभिकरणों या नियोजन अभिकरणों में दक्षता खनेवाले गैर सरकारी संगठनों के साथ सह-संबंध विकसित करेंगी।

(3) संस्थान का अधीक्षक अप्रेन्टिस के तौर पर 16 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के नियोजन के लिए तर्कसंगत प्रयास करेगा।

50. मनोविनोद की सुविधाएँ।—(1) संस्थाओं में सभी किशोरों एवं बालकों को मार्गदर्शित मनोविनोद की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इसमें इन्डोर एवं आउटडोर खेलकूद, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक एवं बाहर जाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुस्तकालय सम्मिलित होंगे।

(3) प्रत्येक संस्था सभी बालकों को मनोविनोद संबंधी गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्रियां, खिलौने एवं गेम्स उपलब्ध करायेगी।

51. किशोरों या बालकों का संस्थागत प्रबंधन।—(1) नये भर्ती किये गये किशोर के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:—

- (क) प्राप्त करना तथा तलाशी लेना। किशोरी या लड़की की तलाशी किसी महिला कर्मचारी द्वारा ली जायेगी, तथा शिष्टता एवं गरिमा को सम्प्रकृत रूप से ध्यान में रखते हुए बालिका तथा बालक दोनों की तलाशी ली जायेगी;
- (ख) किशोर की वैयक्तिक वस्तुओं तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का रोगाणुनाशन तथा भंडारण, एक पृथक पंजी में वस्तुओं की प्रविष्टि करना;
- (ग) स्नान करना तथा केस काटना (जबतक कि धर्म द्वारा निषिद्ध न हो);
- (घ) प्रसाधन सामग्रियां, वस्त्रों का नया सेट, बिछौना तथा अन्य साज-सज्जा एवं उपस्कर जारी करना (मापदंडों के अनुसार);
- (ड.) ऐसे प्रत्येक किशोर के मामले में, जिसपर सांसारिक या संक्रामक रोगों, मानसिक रोगों या नशे की लत से ग्रस्त होने का संदेह हो, चिकित्सीय परीक्षा तथा उपचार, जहां आवश्यक हो;
- (च) सांसारिक रोग से ग्रस्त बालक के मामले में जिसमें विशेष देखरेख तथा सावधानी की आवश्यकता है, विशेष रूप से कर्णांकित शयन कक्षों या वार्डों या अस्पतालों में पृथक्करण;
- (छ) परीक्षाओं, साक्षात्कार में उपस्थित होने, माता-पिता को पत्र लिखने, वैयक्तिक समस्याओं जैसी किशोरों की तात्कालिक तथा अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना तथा मण्डल या समिति के आदेशानुसार अधीक्षक द्वारा किशोर की आयु का सत्यापन।

(2) संस्थान से जुड़े परीक्षा पदाधिकारियों या बाल कल्याण पदाधिकारियों या व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं या व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं में से नये भर्ती किये गये प्रत्येक किशोर या बालक को एक केस कार्यकर्ता आवर्दित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक नये भर्ती किये गये किशोर को संस्था तथा इसके कार्यकलाप से परिचित कराया जायेगा एवं निम्नांकित क्षेत्रों में वह दिशा निर्धारण प्राप्त करेगा:—

- (क) वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा आरोग्य तथा स्वच्छता;
- (ख) संस्थागत अनुशासन तथा व्यवहार के मानकों, बड़ों एवं शिक्षकों के लिए सम्मान;
- (ग) दैनिक दिनचर्या, समकक्ष के साथ अंतःक्रिया, विकासात्मक अवसरों का यथेष्ट इस्तेमाल; तथा
- (घ) संस्था के भीतर अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं बन्धनों के क्षेत्र में।

(4) नाम निर्देशित पदाधिकारी भर्ती पंजी में किशोर या बालक के नाम की प्रविष्टि करेगा तथा उपयुक्त निवास सुविधा आवंटित करेगा।

(5) छाया चित्र भी रेकार्ड के लिए तत्काल लिया जाना है तथा केस कार्यकर्ता या परिवीक्षा पदाधिकारी या कल्याण पदाधिकारी अन्वेषण तथा उस व्यक्ति के साथ पत्राचार प्रारंभ करेगा जिसका किशोर या बालक ने नाम लिया हो।

(6) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि संस्था द्वारा प्राप्त किये गये किशोर या बालक की वैयक्तिक वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायें तथा वैयक्तिक वस्तुएं पंजी में दर्ज की जायें तथा इन वस्तुओं को किशोर या बालक को आवश्यक रूप से लौटा देना है जब वह संस्था को छोड़ता है।

(7) भर्ती किये गये किशोर की शैक्षणिक स्तर तथा व्यावसायिक अभिरूचि का शिक्षक, कार्यशाला पर्यवेक्षक तथा अन्य तकनीकी कर्मचारीगण द्वारा संचालित परीक्षण एवं साक्षात्कार के आधार पर आकलन किया जा सकता है तथा बाहर के विशेषज्ञों एवं समुदाय आधारित कल्याण अभिकरणों, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, बाल मार्गदर्शन विलनिक अस्पताल एवं स्थानीय चिकित्सकों, खुले विद्यालय या जन शिक्षण संस्थान के साथ भी आवश्यक सह-संबंध स्थापित किये जा सकते हैं।

(8) किसी संस्था में भर्ती किये गये किशोर या बालक का केस इतिवृत्त प्ररूप-**XX** के अनुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें उसकी सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना होगी तथा घर, माता-पिता या संरक्षकों, नियोक्ता, विद्यालय, मित्रों एवं समुदाय समेत सभी संभव एवं उपलब्ध स्रोतों से ऐसी सूचना संदेव संकलित की जा सकती है।

(9) विद्यमान सरकारी या स्वैच्छिक कल्याण संगठनों के साथ निकट सहयोग करते हुए सभी संस्थाओं में निर्मुक्ति पूर्व योजना तथा विशेष गृहों से मुक्त किये गये मामलों के अनुवर्तन का एक सुविचारित कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

(10) वगैर अनुमति के या संस्था से जाने वाले या संस्था के भीतर कोई अपराध कारित करने वाले किशोर या बालक की दशा में, सूचना संबद्ध संस्था के अधीक्षक द्वारा पुलिस तथा परिवार को, अगर ज्ञात हो, भेज दी जायेगी; तथा किशोर या बालक का वहां पता लगाने, जहां किशोर या बालक लापता है, के प्रयासों के साथ परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट मण्डल या समिति, यथास्थिति, को भेज दी जायेगा।

(11) प्रत्येक किशोर या बच्चे के केस इतिवृत्त, परिस्थितियों एवं वैयक्तिक आवश्यकताओं के आधार पर बालक का पुनर्वास करने तथा पुनःएकीकृत करने के अंतिम लक्ष्य के साथ संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक किशोर या बालक के लिये एक वैयक्तिक देखरेख योजना तैयार करेगा;

होगी:—

- (क) अधीक्षक बाल कल्याण पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता, या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ प्ररूप-**XXI** के अनुसार उसके भर्ती होने के एक महीने के भीतर किसी संस्था में रहने वाले प्रत्येक बालक के लिये एक वैयक्तिक देखरेख योजना तैयार करेगा;
- (ख) सभी देखरेख योजनाओं में किशोर या बालक के पुनःस्थापन, पुनर्वास, पुनःएकीकरण एवं अनुवर्ती कार्य के लिए योजना सम्मिलित होगी;
- (ग) रिहाई या परिवार को पुनः वापस करने या प्रायोजन या पालक देखरेख या दत्तक ग्रहण के विकल्पों समेत समुचित विकास तथा पुनर्वास के लिए इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति द्वारा देखरेख योजना की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी;
- (घ) किशोर या बालकों की देखरेख योजना तैयार करते समय उनसे परामर्श लिया जायेगा;
- (ङ.) अंतरण या वापस भेजने या पुनःस्थापन के मामलों में देखरेख योजना का सातत्व सुनिश्चित किया जायेगा।

52. निषिद्ध वस्तुएं—कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित निषिद्ध वस्तुओं को संस्था के भीतर नहीं लाएगा, अर्थात्:—

- (क) आगनेयायुध या अन्य हथियार चाहे इनके लिए अनुज्ञाप्ति अपेक्षित हो या नहीं (जैसे चाकु, ब्लेड, लाठी, भाला एवं तलवारें);
- (ख) किसी भी प्रकार का अल्कोहल तथा स्प्रिट;
- (ग) भांग, गांजा, अफीम या अन्य स्वापक या मनःप्रभावी पदार्थ;
- (घ) तम्बाकु, सिगरेट, गुटका; या
- (ङ.) किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य वस्तु।

53. तलाशी एवं निरीक्षण पर पायी गयी वस्तुएँ—(1) अधीक्षक इसकी निगरानी करेगा कि संस्था में प्राप्त किये गये प्रत्येक किशोर की गरिमा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना किशोर की तलाशी ली जाय, उसके वैयक्तिक सामानों का निरीक्षण किया जाये तथा किशोर के पास पायी गयी बहुमूल्य वस्तुओं को अधीक्षक/प्रभारी पदाधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाय।

(2) बालिकाओं की तलाशी कर्मचारीगण में से किसी महिला सदस्य द्वारा ली जायेगी तथा शिष्टता एवं गरिमा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए बालिकाओं तथा बालकों दोनों की तलाशी ली जायेगी।

(3) प्रत्येक संस्था में, किशोर के पास पाये गये धन, बहुमूल्य वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं के विवरण ‘वैयक्तिक वस्तु पंजी’ में रखे जायेंगे।

(4) प्रत्येक किशोर से संबंधित वैयक्तिक वस्तु की पंजी में की गयी प्रविष्टियां किसी गवाह की उपस्थिति में किशोर को पढ़कर सुनायी जायेगी, जिसका ऐसी प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रमाण में हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा इसे अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

54. वस्तुओं का निस्तारण—किसी संस्था में प्राप्त किये गये या रखे गये किसी किशोर के धन या बहुमूल्य वस्तुओं का निम्नलिखित रीति से निस्तारण किया जायेगा, अर्थात्:

- (क) किशोर को किसी संस्था भेजने का निर्देश देते हुए उस किशोर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आरेश किये जाने पर, अधीक्षक समय-समय पर अभिकथित ढंग से किशोर के नाम से विक्रय आगमों के साथ ऐसे किशोर का धन जमा करा देगा;
- (ख) किशोर का धन अधीक्षक के पास रखा जायेगा तथा बहुमूल्य वस्तुओं, वस्त्रों, बिछौने एवं अन्य वस्तुओं, अगर कोई हो, को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा;
- (ग) जब ऐसे किशोर को एक संस्था से एक अन्य संस्था अंतरित किया जाता है, उसके सारे धन, बहुमूल्य वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं को उनके आकार प्रकार के पूर्ण तथा शुद्ध विवरण एवं आकलित मूल्य के साथ उस संस्था के अधीक्षक के पास किशोर के साथ भेज दिया जायेगा जहां उसे अंतरित किया गया है;
- (घ) ऐसे किशोर की निर्मुक्ति के समय, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी बहुमूल्य वस्तुएँ तथा अन्य सामग्रियाँ एवं किशोर के नाम जमा किये गये धन स्वयं किशोर या बालक या माता-पिता या संरक्षक, यथास्थिति, को सौंप दिये जायेंगे एवं पंजी में इस निमित्त एक प्रविष्टि की जायेगी तथा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी;
- (ड.) जब संस्था में किसी किशोर की मृत्यु हो जाती है, मृतक द्वारा छोड़े गये बहुमूल्य सामान तथा अन्य सामग्रियाँ तथा किशोर के नाम जमा किये गये धन अधीक्षक द्वारा किसी ऐसी व्यक्ति के हवाले कर दिये जायेंगे जो उनपर अपना दावा सिद्ध कर देता है तथा एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करता है;
- (च) ऐसे व्यक्ति से ऐसी बहुमूल्य वस्तुएँ या अन्य सामग्रियाँ तथा राशि प्राप्त करने की रसीद ली जायेगी;
- (छ) अगर ऐसे किशोर की मृत्यु या पलायन की तिथि से छह महीनों की अवधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है, नियमों के नियम 56 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बहुमूल्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं एवं राशि का निस्तारण किया जायेगा। अधिनियम की धारा 61 में यथा वर्णित निधि में धन जमा करा दिया जायेगा।

55. वाद संचिका का संधारण—(1) प्रत्येक किशोर या बच्चे की केस संचिका का संस्था में संधारण किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सूचनाएँ अंतर्विष्ट होंगी:—

- (क) उस व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट जिसने मण्डल के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किया था;
- (ख) अधीक्षक की, परिवीक्षा पदाधिकारी की या बाल कल्याण पदाधिकारी की, परामर्शी की तथा केस कार्यकर्ता की रिपोर्टें;
- (ग) पिछली संस्था से प्राप्त कोई सूचना, अगर कोई हो;
- (घ) किशोर के साथ प्रारंभिक अंतःक्रिया की रिपोर्ट, परिवार के सदस्यों, संबंधियों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त सूचना तथा विविध सूचना;
- (ड.) अतिरिक्त सूचना का स्रोत;

- (च) कर्मचारीगण से प्राप्त सम्प्रेक्षण रिपोर्ट;
- (छ) चिकित्सा पदाधिकारी से नियमित स्वास्थ्य दशा संबंधी रिपोर्ट, नशे की लत छुड़ाने की प्रगति रिपोर्ट, मनोवैज्ञानिक परामर्श या किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, जहां प्रयोज्य हो; के मुकाबिल प्रगति रिपोर्ट;
- (ज) बुद्धिमत्ता गुणक (IQ) परीक्षण, अभिरूचि परीक्षण, शौक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षण;
- (झ) सामाजिक इतिहास;
- (झ) केस कार्यकर्ता तथा अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत सारांश एवं विश्लेषण;
- (ट) प्रशिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम से संबंधित एवं बरती जानेवाली विशेष सावधानियों के बारे में अनुदेश;
- (ठ) अवकाश तथा अन्य प्रदत्त विशेषाधिकार;
- (ड) विशेष उपलब्धियां एवं नियमों का उल्लंघन, अगर कोई हो;
- (ढ) त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन;
- (ण) प्रपत्र-XXI में यथा विहित निर्मुक्तिपूर्व कार्यक्रम, निर्मुक्ति पश्चात् योजना तथा अनुवर्ती योजना समेत वैयक्तिक देखरेख योजना;
- (त) पर्यवेक्षण के अधीन अनुपस्थिति की छुट्टी या निर्मुक्ति;
- (थ) रिहाई;
- (द) अनुवर्ती रिपोर्ट;
- (ध) वार्षिक छायाचित्र;
- (न) विहित प्ररूप-XX में सम्यक रूप से भरा गया केस इतिवृत्त;
- (प) सक्षम प्राधिकार के निर्देशानुसार निर्मुक्ति-पश्चात मामलों की अनुवर्ती रिपोर्ट, अगर कोई हो, तथा;
- (फ) टिप्पणीयाँ।

(2) संस्थाओं तथा मण्डल या समिति द्वारा संधारित सभी केस संचिकाओं को, जहां तक संभव हो, कम्प्युटरीकृत किया जायेगा तथा नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा ताकि राज्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से आंकड़े उपलब्ध रहें।

56. प्रबंधन समिति—(1) प्रत्येक संस्था में संस्था के प्रबंधन तथा प्रत्येक किशोर एवं बालक की प्रगति के अनुश्रवण के संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेश के माध्यम से गठित एक प्रबंधन समिति होगी।

(2) वैयक्तिक देखरेख योजनाओं के अनुसार समुचित देखरेख तथा उपचार सुनिश्चित करने के लिए, किशोर या बालक को आयु, अपराध की प्रकृति या अपेक्षित देखरेख के प्रकार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं निवास के आदेश की अवधि के आधार पर समूहों में शामिल किया जायेगा।

(3) प्रबंधन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:—

(i)	जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई)	-	अध्यक्ष
(ii)	अधीक्षक	-	सदस्य-सचिव
(iii)	परिवीक्षा पदाधिकारी या बाल कल्याण पदाधिकारी या केस कार्यकर्ता	-	सदस्य
(iv)	जिला चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य
(v)	मनोवैज्ञानिक या परामर्शी	-	सदस्य
(vi)	कार्यशाला पर्यवेक्षक या व्यवसाय अनुदेशक	-	सदस्य
(vii)	शिक्षक	-	सदस्य
(viii)	किशोर न्याय मण्डल या बाल कल्याण समिति का सामाजिक कार्यकर्ता	-	सदस्य
(ix)	प्रत्येक बाल समिति से किशोर या बालक का प्रतिनिधि (सभी आयु समूहों के किशोरों या बालकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मासिक चक्रानुक्रम आधार पर)	-	सदस्य
(x)	वरीय नागरिक फोरम तथा/या रेजिडेंट कल्याण संघ से प्रतिनिधि	-	सदस्य
(xi)	गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

(4) जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनो-वैज्ञानिक देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा विधिक सहायता जैसी पेशेवर एवं तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने में स्वैच्छिक संगठन समिलित हैं, प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति की बैठकों में विशेष आमत्रित अतिथि के तौर पर ऐसे स्वैच्छिक संगठन के चार प्रतिनिधियों को आमत्रित कर सकती है।

(5) ऐसे जिले में जहां जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन नहीं किया गया है, जिला अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होगा।

(6) (क) प्रबंधन समिति निम्नलिखित पर विचार करने तथा समीक्षा करने के लिए यथा संभव बारंबार बैठक करेगी परन्तु प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार;

- (i) अधिकारीकार्यक्रम देखरेख या संस्थागत देखरेख, आवासन, गतिविधि के क्षेत्र एवं अपेक्षित प्रवेशण या हस्तक्षेप के प्रकार;
- (ii) चिकित्सीय सुविधाएँ एवं उपचार;
- (iii) खाने पीने, जल, स्वच्छता तथा आरोग्य दशाएं;
- (iv) किशोरों या बालकों के साथ मानसिक स्वास्थ्य अन्तःक्षेप;
- (v) किशोरों एवं बालकों की वैयक्तिक समस्याएं, विधिक सहायता सेवाओं तथा संस्थागत समायोजन के प्रावधान पर जिसके परिणामतः वैयक्तिक देखरेख योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा होनी है;
- (vi) नियोजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अवसर;
- (vii) शिक्षा तथा जीवन दक्षता विकास कार्यक्रम;
- (viii) सामाजिक समायोजन, आमोद प्रमोद, समूह कार्य संबंधी गतिविधियां, मार्ग दर्शन तथा परामर्श;
- (ix) प्रगति की समीक्षा, किशोरों एवं बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार आवासीय कार्यक्रमों का समायोजन तथा उपार्तण;
- (x) पश्चात्तवर्ती देखरेख सेवाओं के साथ सहयोग करते हुए रिहाई के पश्चात् एवं प्रत्यावर्तन के पश्चात् पुनर्वास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा दो वर्षों की अवधि तक अनुवर्तन;
- (xi) निर्मुक्ति-पूर्व या प्रत्यावर्तन-पूर्व तैयारी;
- (xii) निर्मुक्ति या प्रत्यावर्तन;
- (xiii) निर्मुक्ति पश्चात् या प्रत्यावर्तन पश्चात् अनुवर्ती कार्य;
- (xiv) उपलब्ध अवसरंचना तथा सेवाओं समेत देखरेख के न्यूनतम मानक;
- (xv) दैनिक दिनचर्या;
- (xvi) बालकों के आवासीय जीवन में शिक्षा, व्यावसायिक गतिविधियां, आमोद प्रमोद तथा शौक (hobby) के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी तथा स्वैच्छिक सहयोग;
- (xvii) इसकी निगरानी करना कि अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सभी पंजीयों का संस्था द्वारा संधारण किया जाता है, मासिक समीक्षा बैठकों में इन पंजीयों की जांच-पड़ताल करना तथा सत्यापन करना, सम्यक् रूप से स्टार्टिप्ट तथा हस्ताक्षरित करना;
- (xviii) बालकों की समितियों से संबंधित मामले;
- (xix) कोई अन्य मामला जिसे अधीक्षक सामने लाना चाहे।
- (ख) अधीक्षक केस सांचिका में प्रत्येक किशोर या बालक की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा जिला बाल संरक्षण इकाई या मण्डल या समिति को, यथास्थिति, इसकी प्रतिलिपि भेजेगा।

(7) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में एक शिकायत तथा प्रतितोषण की व्यवस्था स्थापित करेगी एवं प्रत्येक संस्था में आसानी से पहुंचने योग्य स्थान पर या बालकों के कक्षों या शयन कक्षों में बाल सुझाव पेटी संस्थापित की जायेगी।

(8) (क) बाल सुझाव पेटी, जिसकी चार्चायां प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अधिकारी में रहेंगी, के बाल समितियों के सदस्यों की मौजूदगी में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या जिला बाल संरक्षण इकाई से आये उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह जांच की जायेगी।

(ख) अगर कोई ऐसी समस्या या सुझाव है जिसपर तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चर्चा करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति की आपाती बैठक बुलायेगा।

(ग) आपाती बैठकों को संचालित करने के लिए गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी, जिनमें बाल समितियों के दो सदस्य, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति या मण्डल के सदस्य, यथास्थिति, तथा संस्था के अधीक्षक सम्मिलित होंगे।

(घ) संस्था के अधीक्षक के विरुद्ध गंभीर अभिकथन या शिकायत होने की दशा में, वह आपात बैठक का हिस्सा नहीं होगा तथा प्रबंधन समिति के एक अन्य उपलब्ध सदस्य को उसके स्थान पर सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ.) सुझाव पेटी के माध्यम से प्राप्त सभी सुझावों तथा आपात बैठक में दिये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप की गयी कार्रवाई या किये जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठक में परिचर्चा तथा समीक्षा के लिए रखी जायेगी।

(9) एक बाल सुझाव पुस्तिका प्रत्येक संस्था में रखी जायेगी जहां शिकायतों एवं प्रबंधन समिति द्वारा की गयी कार्रवाईयां सम्यक् रूप से अभिलिखित की जायेंगी तथा प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठक के उपरान्त अनुवर्ती कार्य बाल समितियों को संसूचित कर दिया जायेगा।

(10) मण्डल या समिति छह महीनों में कम से कम एक बार बाल सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करेगी।

57. बाल समितियाँ— (1) किशोरों या बालकों के लिए प्रत्येक संस्था का अधीक्षक बालकों के तीन विभिन्न आयु समूहों, जैसे कि 6-10 वर्ष, 11-15 वर्ष तथा 16-18 वर्ष के आयु समूहों के लिए बाल समिति की स्थापना को सुगम बनायेगा तथा इन बाल समितियों का केवल बालकों द्वारा गठन किया जायेगा। वह स्वच्छता एवं आरोग्य समिति, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति, आमोद प्रमोद समिति इत्यादि हो सकती हैं।

(2) ऐसी बाल समिति को निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा:—

- (क) संस्था की दशा में सुधार करना;
- (ख) देखरेख की अनुसरण किये जाने वाले मानकों की समीक्षा करना;
- (ग) दैनिक दिनचर्या तथा आहार मापदंड तैयार करना;
- (घ) शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा मनोविनोद संबंधी योजनायें विकसित करना;
- (ङ.) संकट से निपटने में एक दूसरे की सहायता करना;
- (च) समकक्षों तथा देखरेख प्रदान करने वालों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार तथा शोषण की सूचना देना;
- (छ) वॉलपेपर या सूचना पत्रों या चित्रकारी या संगीत या थियेटर के माध्यम से अपने विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति करना;
- (ज) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्थानों का प्रबंधन।

(3) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियां प्रत्येक महीने बैठक करे तथा अपनी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिए एक पंजी रखें, एवं प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठकों में इसे उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

(4) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लेखन सामग्री तथा स्थान एवं मार्गदर्शन समेत बाल समितियों को आवश्यक सहायता तथा सामग्रियां उपलब्ध करायी जाए।

(5) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन या परामर्शी निम्नांकित कार्यों में बाल समितियों की सहायता कर सकता है,—

- (क) उनके नेताओं का चयन करने में;
- (ख) मासिक बैठकों का संचालन करने में;
- (ग) बाल समितियों के कार्यकलाप के लिए नियमों को तैयार करने तथा इनका अनुसरण करने में;
- (घ) अभिलेखों एवं बाल सुझाव पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों का संधारण करने में;
- (ङ.) किसी अन्य नव-प्रवर्तनशील गतिविधि में।

(6) प्रबंधन समिति बाल समितियों के गठन तथा कार्यकलाप पर अधीक्षक से एक प्रतिवेदन चाहेगी, अपनी त्रैमासिक बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी तथा जहां अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करेगी।

58. पुरस्कार और उपार्जन—अधीक्षक द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार किसी किशोर या बालक को उसके नियमित कार्य और अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया

जाएगा; और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस किशोर या बालक को लेने के लिए आने वाले उसके माता-पिता अथवा अभिभावक अथवा स्वयं बच्चे को देकर रसीद ली जाएगी।

59. किशोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान।—(1) किशोर या बालक के माता-पिता और रिश्तेदारों को महीने में एक बार उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी अथवा विशेष परिस्थिति में अधीक्षक द्वारा यथानिर्धारित मुलाकात की अवधि के अनुसार मास में एक से अधिक बार भी बालक से मिलने की अनुमति उसके माता-पिता या रिश्तेदारों को दी जाएगी, सिवाय उन मामलों में जब यह पाया जाता हो कि उन माता-पिता या रिश्तेदारों या अभिभावकों ने ही बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण किया था।

(2) संस्था में रह रहे किशोरों या बालकों को पत्रों को प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा और उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे यथोचित समय पर जितने चाहे पत्र लिखें, तथा यदि किशोरों या बालकों के माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों का पता मालूम हो, तो संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक किशोर या बालक प्रतिमास अपने अभिभावकों को एक पत्र लिखें, जिसका डाक महसूल संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) अधीक्षक किसी भी किशोर या बालक को या उसके द्वारा लिखे गए किसी पत्र का परिशोलन कर सकेगा तथा पर्याप्त समझे गए कारणों से वह ऐसे पत्र को देने या भेजने से इन्कार कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में अपने कारणों को लेखबद्ध करके पत्र समिति को भेजेगा।

(4) विशेष परिस्थिति में, या बोर्ड या समिति के आदेशानुसार, अधीक्षक किसी किशोर या बालक को अपने माता-पिता या अभिभावक या रिश्तेदार से दूरभाष पर बातचीत करने की अनुमति देगा।

60. किसी किशोर या बालक की मृत्यु।—किसी संस्था में किसी किशोर या बालक की मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

(1) संस्था में किसी किशोर या बालक की अप्राकृतिक मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में संस्था के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मृत्यु-समीक्षा और शब-परीक्षण यथाशीघ्र किया जाए।

(2) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी किशोर या बालक की मृत्यु की दशा में अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा तथा इस मामले की लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति, राष्ट्रीय अथवा राज्य बालक अधिकार अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी तथा उस किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।

(3) अकस्मात् मृत्यु या हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु या आत्महत्या या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में मामला (केस) कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या कल्याण अधिकारी द्वारा इस घटना की सूचना, अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत दी जाएगी तथा अधीक्षक तत्काल, निकटवर्ती पुलिस थाना, बोर्ड या समिति और मृतक किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।

(4) यदि संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी किशोर या बालक की मृत्यु हो जाती है तो संस्था का अधीक्षक उस पुलिस थाने के अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल तथा मृतक किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को इस विषय में अविलम्ब सूचित करेगा।

(5) अधीक्षक, उस निकटवर्ती मजिस्ट्रेट को, जो मृत्यु समीक्षा कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, तथा यथास्थिति बोर्ड या समिति को तत्काल इस मामले की सूचना देगा।

(6) संस्था के अधीक्षक व चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियों का व्यौरा दर्ज करके एक रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट, जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में यह मामला आता हो, उस थाने के प्रभारी अधिकारी, समिति और जिला चिकित्सा अधिकारी या जिस निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच हेतु किशोर या बालक का शब्द भेजा गया हो, उस अस्पताल को भेजेंगे और अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार अभिलिखित करेंगे और इसकी रिपोर्ट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी तथा संबद्ध दंडाधिकारी को देंगे जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो।

(7) ऐसे किसी किशोर या बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य व्यौरों के संबंध में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच की कार्रवाई के लिए अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

(8) मृत्यु-समीक्षा होते ही मृतक किशोर या बालक का शव उसके माता-पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा अथवा किसी दावेदार के उपस्थित न होने की दशा में उस किशोर या बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार अधीक्षक की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

61. किशोर या बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण।—(1) प्रत्येक संस्था बालकों को दुराचार, उनका शोषण, उपेक्षा और उससे दुर्व्यवहार से निवारण एवं संरक्षा के प्रोटोकॉल जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(2) संस्था का अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई दुराचार, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और इसमें कर्मचारियों का इस बात से अवगत रहना भी शामिल है कि शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार का अर्थ क्या है और ऐसे शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के प्रारंभिक संकेत क्या होते हैं तथा ऐसे मामलों में कौन सी कार्रवाई करनी है।

(3) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में, जिसमें उनकी उपेक्षा सम्मिलित है, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी—

- (i) दुर्व्यवहार और शोषण की घटना की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल अधीक्षक को दी जानी चाहिए।
- (ii) शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुर्व्यवहार का आरोप जानकारी में आने पर अधीक्षक बोर्ड या समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो विशेष अन्वेषण का आदेश देगी।
- (iii) बोर्ड या समिति ऐसे मामले को दर्ज करने तथा ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने का स्थानीय पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी।
- (iv) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी कि समस्त जांच कार्य संपन्न हो और किशोर या पीड़ित बच्चे को विधिक-सहायता और परामर्श उपलब्ध कराए जाए।
- (v) बोर्ड या समिति ऐसे किशोर या बालक को किसी अन्य सुरक्षित संस्था, या स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थानान्तरित करेगी।
- (vi) संस्थाओं में किशोरों या बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी।
- (vii) संस्था का अधीक्षक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और ऐसी घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखेगा।
- (viii) बोर्ड या समिति प्रत्येक संस्था में गठित किशोर समिति से, दुराचार और शोषण संबंधी तथ्य की जाँच हेतु विमर्श कर सकता है और उससे निपटने में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकारों के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों अथवा संकट अन्तःक्षेप केन्द्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

62. भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित किशोर या बालक।—(1) जब इस अधिनियम उपर्यादों के अधीन किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की देख-रेख में रखा गया बालक किसी ऐसे रोग या ऐसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित पाया जाता हो, जिसके लिए लम्बे चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता हो या वह किसी स्वापक (नारकोटिक ड्रग) या मनः प्रभावी पदार्थ का आदि हो तो उस बालक को सक्षम-प्राधिकारी के आदेश से अनुमोदित संस्था में रहने की शेष अवधि या ऐसी अवधि के लिए उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी स्थान पर रखा जायगा जिसे उस बालक की समुचित चिकित्सा के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में आवश्यक समझा गया हो।

(2) जहाँ उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन बालक के स्थानान्तरण का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता हो कि बालक रोग से या शारीरिक या मानसिक शिकायत से स्वस्थ हो गया है, फिर भी अभिरक्षा में रहने योग्य है तो संस्था को भेजने के प्रभारी व्यक्ति को या उस उपर्युक्त व्यक्ति को, जिससे या जिससे उसका स्थानान्तरण किया गया हो को आदेश करेगा अथवा यदि बाल गृह में रखे जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी हो तो उसे उन्मुक्त करने का आदेश करेगा।

(3) जहाँ सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रसित बालकों के मामले में उप-नियम (1) के अधीन कार्रवाई कर ली गई हो वहाँ उप-नियम के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त बालक को यथा स्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के पास पुनर्वापसी के पूर्व, समाधान होने पर कि ऐसी कार्रवाई उक्त बालक के हित में होगी यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को बुलाकर समाधान कर लेगा कि वैसे माता-पिता या अभिभावक बालक को पुनः संक्रमित नहीं करें।

(4) जिस स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर या निकटवर्ती जिले या राज्य में गंभीर मनोरोगों या शारीरिक रोग और संक्रमण से पीड़ित किशोर या बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए इस अधिनियम की धारा 58 के अधीन यथावश्यक संगठन मौजूद नहीं है, उस स्थान पर राज्य सरकार ऐसे किशोर या बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथावश्यक संगठनों की स्थापना करेगी।

63. किशोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्टी।—(1) किसी संस्था में रहने वाले किशोर या बालक को संस्था की देखरेख में परीक्षा या नामांकन कराने के लिए या परिवार में विवाह जैसे विशेष अवसरों पर या मृत्यु या दुर्घटना या गंभीर बीमारी के आपातकालीन समय में अवकाश पर जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) यात्रा के समय को छोड़कर सामान्य रूप से अधिकतम सात दिनों की अल्पकालिक छुट्टी अधीक्षक द्वारा सिफारिश की जाती है, किंतु ऐसी छुट्टी बोर्ड या समिति द्वारा मंजूर की जाएगी।

(3) किशोर के माता-पिता या अभिभावक या किशोर या बालक की ओर से अधीक्षक छुट्टी के लिए बोर्ड या समिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें छुट्टी का प्रयोजन और छुट्टी की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए किशोर या बालक को छोड़ने का अनुरोध होगा।

(4) अनुपस्थिति की छुट्टी के आवेदन पर विचार करते समय बोर्ड या समिति, किशोर या बालक या उनके माता-पिता या अभिभावकों को सुनेगी और यदि बोर्ड या समिति यह समझती है कि ऐसी छुट्टी को मंजूर करना किशोर या बालक के हित में है तो समुचित आदेश दिया जाएगा और बोर्ड या समिति परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी से एक रिपोर्ट उस दशा में मांग सकेगा, जब किशोर या बालक या संबंधित माता-पिता या अभिभावक द्वारा दी गई प्रारंभिक सूचना उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है।

(5) छुट्टी मंजूर करने का आदेश जारी करते समय या पर्यवेक्षण के अधीन मुक्त करते समय सक्षम प्राधिकारी छुट्टी के आदेश के साथ छुट्टी की अवधि तथा शर्तों का उल्लेख करेगा और यदि छुट्टी की अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो किशोर या बालक को संस्था में वापस बुलाया जा सकेगा।

(6) माता-पिता या अभिभावक किशोर या बालक के मार्गरक्षक की व्यवस्था करेगा और जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ अधीक्षक परिवार के स्थान तक और वहाँ से वापस आने के समय किशोर या बालक के मार्गरक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावक मार्गरक्षण के लिए इच्छुक हो किंतु आर्थिक रूप से सक्षम न हों, तो अधीक्षक उनके लिए नियमों के अधीन यथा अनुमान्य यात्रा खर्च की व्यवस्था करेगा।

(7) यदि किशोर या बालक छुट्टी की अवधि के दौरान परिवार से भाग जाता हो तो इनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा संस्था के अधीक्षक को तत्काल सूचित किया जाना अपेक्षित है तथा उन्हें ढूँढ़ने का प्रयास किया जाना आवश्यक है और यदि वे पाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल संस्था में वापस लाया जाएगा।

(8) यदि किशोर या बालक चौबीस घंटे के भीतर नहीं पाया जाता हो तो अधीक्षक निकटतम पुलिस थाने और गुमशुदा व्यक्ति-ब्यूरो को इसकी सूचना देगा किंतु किशोर या बालक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और अधिनियम के अधीन अभिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(9) यदि किशोर या बालक के माता-पिता या अभिभावक छुट्टी की अवधि में इनकी उचित देखरेख नहीं करते हों या निर्धारित अवधि के भीतर किशोर या बालक को संस्था में वापस नहीं लाते हों, तो आगे से ऐसे अवसरों पर छुट्टी से इन्कार किया जा सकेगा।

(10) यदि किशोर या बालक मंजूर की गई छुट्टी के अवसान पर संस्था में वापस नहीं आता है तो बोर्ड या समिति किशोर का प्रभार संभालने तथा उसे संस्था में वापस लाने के लिए ऐसे मामले को पुलिस को सौंप देगी।

(11) ऐसी छुट्टी की अवधि संस्था में किशोर या बालक के ठहरने की अवधि की गणना करते समय संस्था में रहने की अवधि में शामिल होगी, और छुट्टी की अवधि के पश्चात् संस्था से अनुपस्थित रहने की अवधि संस्था में रहने की अवधि से अपवर्जित की जाएगी।

64. निरीक्षण I—(1) राज्य सरकार इस नियमावली के नियम 89 के अधीन गठित चयन-समिति की सिफारिश पर राज्य, जिला या नगर स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन तीन वर्षों के लिए करेगी।

(2) निरीक्षण समितियां इन संस्थाओं का दौरा करेंगी और संस्था की स्थितियों, सुरक्षा हेतु प्रक्रियाओं की उपयुक्तता, कल्याण एवं स्थायित्व का निरीक्षण करेगी, संस्थाओं द्वारा अनुपालित देखरेख और संरक्षण के मानकों का पुनर्विलोकन करेंगी, बाल अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी घटना के प्रति सतर्कता और इस नियमावली के नियम 56 और 57 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के कार्यों और बाल समिति के कार्यकलापों की जांच-पड़ताल करेंगी और समुचित निर्देश देंगी।

(3) यह दल संस्था के सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगा।

(4) इस दल में न्यायिक, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग, चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, स्वैच्छिक संगठनों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित सात सदस्य होंगे।

(5) प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(6) निरीक्षण दौरे में कम से कम तीन सदस्य होंगे।

(7) दल संस्थाओं को या तो सूचित करके दौरा करेगा या औचक दौरा करेगा।

(8) दल अपने दौरे में बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनसे बेद्विक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।

(9) बालकों के बारे में निष्कर्षों और सुझावों पर सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(10) निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, निष्कर्ष तथा सुझाव जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।

65. सामाजिक लेखा-जोखा।—(1) राज्य सरकार, बोर्ड या समिति या विशेष किशोर पुलिस इकाई, जहां अपेक्षित हो, की स्थापना से सम्बद्ध मामलों की बोर्ड या समिति या विशेष किशोर पुलिस इकाई के कामकाज की, संस्थाओं और कर्मचारियों के कामकाज की, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कामकाज की, किशोर न्याय के बालक अनुकूलन प्रशासन और राज्य में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बद्ध अन्य किसी भी मामले का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी।

(2) मानसिक स्वास्थ्य, बालक देख-रेख और संरक्षण एवं लोक दायित्व के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को शामिल करके एवं इनके सहयोग से सामाजिक लेखा जोखा कराया जाएगा।

66. वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई।—(1) बोर्ड या समिति, किशोर या बालक और इनके माता-पिता या अभिभावक की समुचित सुनवाई और साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए बोर्ड या समिति द्वारा निर्देशित पर्यवेक्षण अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टें और मामले के निर्णय के लिए बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए सम्बद्ध कागजात या रिपोर्ट के आधार पर किशोर या बालक को वापस भेजने का आदेश देगी।

(2) बोर्ड या समिति प्रपत्र-XXII के अनुसार, मार्गरक्षण के आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे जाने के आरेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को भेजेगी जो किशोर या बालक को वापस भेजने के लिए निधि उपलब्ध कराएगी।

(3) वापस भेजे जाने के मामले में यथास्थिति कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं या बाल कल्याण अधिकारियों या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के रूप में वापस भेजने की योजना तैयार की जाएगी और यह इस नियमावली के नियम 56 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति के पुनर्विलोकन और सिफारिश पर आधारित होगी।

(4) पुलिस के अतिरिक्त बोर्ड या समिति भी किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।

(5) किशोरियों या बालिकाओं को महिला मार्गरक्षण दल के साथ भेजा जाएगा।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी का निर्देश हो तो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए किये गये व्यय जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे।

(7) जब कोई किशोर या बालक अपने घर वापस नहीं जाना चाहता तो बोर्ड या समिति अपने अभिलेख में इस बात को दर्ज करेगी तथा उसे घर जाने हेतु न तो बाध्य किया जाएगा, और न ही समझाया जाएगा, विशेष रूप से यदि बाल कल्याण अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की सामाजिक जांच रिपोर्ट से यह निश्चित हो गया हो कि परिवार में पुनः जाना

किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, या माता-पिता या अभिभावक किशोर या बालक को पुनः वापस लेने से इनकार करते हों।

(8) बालक को वापस भेजने में सहायता हेतु बोर्ड या समिति द्वारा समनुदर्शित बाल कल्याण पदाधिकारियों या परिवीक्षा पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी, जो व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग रूप में होगी।

(9) सम्बद्ध बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन दो वर्षों की अवधि तक तिमाही अनुवर्ती रिपोर्ट बोर्ड या समिति को तथा इसकी एक प्रति उस संस्था के अधीक्षक को भेजेगा, जहाँ किशोर या बालक रह रहा हो।

(10) अनुवर्ती रिपोर्ट में किशोर या बालक को वापस भेजने के पश्चात् उसकी स्थिति तथा किशोर या बालक की असुरक्षा में उत्तरोत्तर कमी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली इनकी जरूरतों के बारे में स्पष्ट उल्लेख होगा।

(11) अधीक्षक किशोर या बालक की केस फाइल में अनुवर्ती रिपोर्ट भी रखेगा तथा अगली बैठक में इसे, इस नियमावली के नियम 56 के अधीन गठित प्रबंधन-समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(12) अधीक्षक अनुवर्ती रिपोर्टों की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजेगा।

(13) जहाँ सरकारी कार्यकर्ताओं या गैर-सरकारी संगठनों के न होने के कारण अनुवर्ती कार्रवाई सम्भव नहीं हो, वहाँ सम्बद्ध जिला बाल संरक्षण इकाई बोर्ड या समिति को जरूरी सहायता प्रदान करेगी।

67. आगन्तुक पुस्तिका।—(1) प्रत्येक संस्था में आगन्तुक पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें वहाँ आने वाले व्यक्ति अपने आगमन की तारीख और उचित सुझावों को लेखबद्ध करेंगे।

(2) संस्था का अधीक्षक ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या निदेशक, समाज कल्याण को भेजेगा। प्रविष्टियां भेजते समय अपनी इच्छानुसार अपना स्पष्टीकरण अथवा अन्य अभ्युक्तियां दे सकेगा, जिस पर नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथावश्यक आदेश जारी कर करेगा।

68. रजिस्टरों का रखा जाना।—अधीक्षक, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जरूरी तथा इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों और प्रपत्रों को अपने कार्यालय में रखेगा। रजिस्टरों, फाइलों या पुस्तिकाओं की सूची में कम से कम निम्नलिखित सामग्री शामिल होगी:—

- (क) प्रवेश और उन्मुक्ति रजिस्टर
- (ख) पर्यवेक्षण रजिस्टर
- (ग) चिकित्सा फाइल या चिकित्सा रिपोर्ट
- (घ) पोषण आहार फाइल
- (ड.) स्टॉक रजिस्टर
- (च) लॉग-बुक
- (छ) आदेश पुस्तिका
- (ज) बैठक पुस्तिका
- (झ) रोकड़ बही
- (ज) बजट विवरण फाइल
- (ट) जाँच रिपोर्ट फाइल
- (ठ) व्यक्तिगत देखरेख योजना के साथ व्यक्तिगत केस फाइल
- (ड) बाल सुझाव पुस्तिका
- (ड.) आगंतुक पुस्तिका
- (ण) कर्मचारी संचालन रजिस्टर
- (त) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर
- (थ) प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर
- (द) बाल समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर
- (ध) कर्मचारियों और किशोरों या बालकों की उपस्थिति रजिस्टर

(न) परिवाद एवं की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन रजिस्टर
 (प) अंतःवासियों को पुरस्कार एवं दंड रजिस्टर।

69. गृहों के कार्मिक या कर्मचारी—(1) प्रत्येक गृह के कार्मिकों की संख्या तथा प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) गृह के आकार, क्षमता, कार्यभार, कार्यों के वितरण और कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुसार संस्थागत, संगठनात्मक ढाँचा निश्चित किया जाएगा।

(3) किसी गृह में पूर्णकालिक कर्मचारियों में आवश्यकतानुसार, अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी (पर्यवेक्षण गृह या विशेष गृह की दशा में), मामला कार्यकर्ता (बाल गृह या आश्रय गृह या परवर्ती देखरेख संगठन की दशा में), परामर्शदाता, शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक, चिकित्सीय कर्मचारीवृद्ध, प्रशासनिक कर्मचारीवृद्ध, अवधायक (केयर टेकर), स्वयंसेवक, भंडारपाल, रसोईया, हेल्पर, धोबी, सफाई कर्मचारी तथा माली शामिल हो सकेंगे।

(4) अंशकालिक कर्मचारीवृद्ध में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और समय-समय पर अपेक्षित अन्य वृत्तिक सम्मिलित हो सकेंगे।

(5) गृह के कर्मचारी अधीक्षक के नियंत्रण और सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में रहेंगे, जो आदेश द्वारा उनके विनिर्दिष्ट विशिष्ट दायित्वों को अवधारित करेगा और समय-समय पर किए गए ऐसे आदेशों से संबद्ध प्राधिकारी को अवगत रखेगा।

(6) अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(7) कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार की जाएगी।

(8) 50 किशोरों या बालकों की क्षमता वाली किसी संस्था के लिए निम्नलिखित स्वरूप के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव है:-

क्र. सं.	कर्मचारी/कार्मिक	पदों की संख्या
1	प्रभारी पदाधिकारी (अधीक्षक)	1
2	परामर्शदाता	1
3	परिवीक्षा अधिकारी या मामला कार्यकर्ता	1
4	गृह माता या गृह पिता (हर 25 बालकों के लिए एक)	2
5	शिक्षक (स्वैच्छिक या अंशकालिक)	1
6	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-सह-योग प्रशिक्षक (स्वैच्छिक या अंशकालिक)	1
7	चिकित्सक (स्वैच्छिक या अंशकालिक)	1
8	कला और हस्तशिल्प-सह-संगीत शिक्षक (स्वैच्छिक या अंशकालिक)	1
9	पारा-चिकित्सकीय कर्मचारी	1
10	भंडारपाल-सह-लेखापाल	1
11	रसोईया	1
12	सहायक (हेल्पर)	1
13	सफाईकर्मी	2
14	सुरक्षा गार्ड	3
कुल		18

(9) शिशुओं को रखने वाली संस्थाओं या 12 वर्ष तक के बच्चे या वैसे बच्चे जो शारीरिक एवं मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों की दशा में आया और पारा-चिकित्सकीय कर्मचारियों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।

70. संस्था के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व।—(1) अधीक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के रख-रखाव का होगा तथा किशोरों या बालकों और कर्मचारीवृद्धि को आवश्यकता पड़ने पर हर समय उपलब्ध रहने के लिए संस्था के परिसर में ही रहेगा और यदि संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो अधीक्षक संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने तक संस्था के निकट ही किसी स्थान पर रहेगा।

(2) अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

- (क) अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन;
- (ख) बोर्ड या समिति के आदेशों का अनुपालन;
- (ग) किशोरों या बालकों को प्यार, स्नेह, देखरेख, विकास और कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करना;
- (घ) संस्था में देखरेख के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना;
- (ङ.) भवन और परिसरों का समुचित रखरखाव;
- (च) संस्था का प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं चक्कर लगाना, खाद्य सामग्री के अलावा परासे जाने वाले भोजन आदि का उचित भण्डारण तथा निरीक्षण सहित सुरक्षा उपाय तथा आवधिक निरीक्षण;
- (छ) किशोरों या बालकों के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और मॉनिटर करना;
- (ज) यथास्थिति, प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों या सुधारात्मक कार्यकलापों सहित सभी संस्थागत कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा प्रचालनों का नियोजन, कार्यान्वयन और समन्वयन;
- (झ) आकस्मिकताओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई जिसमें नियमित अग्निड्रिल और खाली कराने की योजना भी शामिल है;
- (ज) संस्था के परिसर के भीतर दुर्घटना और आग से बचाव के निवारक उपाय सुनिश्चित करना;
- (ट) जल भण्डारण, बिजली-संयंत्र, आपत्ताकालीन रोशनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था;
- (ठ) संयंत्रों और उपस्करणों का सावधानीपूर्वक संचालन;
- (ड) सांसारिक या संक्रामक रोगों से पीड़ित किशोरों या बालकों को अलग-अलग रखना;
- (ढ) दैनिक रुटीन का पालन और अनुपालन करना;
- (ण) केस फाइल में किशोर या बालक की मासिक रिपोर्ट को फाइल करना;
- (त) संस्था में स्थानीय और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन;
- (थ) किशोरों या बालकों के भ्रमण या सैर अथवा पिकनिक का आयोजन करना;
- (द) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण;
- (ध) कार्मिकों को कार्यों का आवंटन;
- (न) कार्मिकों के कल्याण तथा कर्मचारीवृद्धि के अनुशासन पर ध्यान देने सहित कार्यालय प्रशासन का पर्यवेक्षण;
- (प) सभी अनुशासनिक मामलों में त्वरित, कठोर और विचारशील कार्रवाई;
- (फ) प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- (ब) अधिनियम और नियमावली के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रख-रखाव;
- (भ) जब कभी आवश्यक है, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के साथ सम्पर्क, समन्वयन तथा सहयोग करना; और
- (म) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक किशोर को विधिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता मिल रही है, जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि अधिकारी से समन्वय करना और जहाँ कहीं जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन नहीं हुआ है, वहाँ जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- (य) बाल समितियों की बैठक को सुनिश्चित करना एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना।

(3) अधीक्षक के अन्य दायित्व भी हैं यथा

- (i) नियमों एवं विनियमों की विरचना के अंतर्गत बाल अधिकारों को सभी संभव तरीके से सुनिश्चित करना;
- (ii) वह कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा और संस्था के सुचारू तथा प्रभावी कार्य संचालन के लिए अनुदेश निर्गत करेगा;
- (iii) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपने दायित्व का निवाह नियमों एवं विनियमों के अनुसार कर रहे हैं तथा बालकों को गुणात्मक एवं पूरी मात्रा में भोजन, बच्चों की अभिरुचि एवं जरूरत के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, बजट और लेखा पर तथा संस्था के वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण रखेगा, संस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए योजना एवं गैर योजना स्कीमों का प्रस्ताव करेगा;
- (iv) संस्था के अधीक्षक महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेजों, विलेखों, एकरानामा, कर्मचारियों के निजी फाईलों, अभिलेख, बच्चों की कीमती वस्तुओं आदि का अभिरक्षक होगा;
- (v) अधीक्षक सुरक्षित पेयजल, संस्था में उचित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थितियों, बालक/किशोरों के उचित स्वास्थ्य देखरेख आदि का उत्तरदायी होगा;
- (vi) अधीक्षक रात्रि के समय पखवारा में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि रात्रि के समय संस्था का संस्थागत प्रबंधन नियंत्रित एवं सतर्कता में है,
- (vii) अधीक्षक अंतःवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करेगा तथा विभिन्न समितियों की बैठक का अयोजन करेगा तथा कार्यवाही का संचालन करेगा और यह पर्यवेक्षण करेगा कि समितियों के निर्णय प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों;
- (viii) वह प्रत्येक बालक के लिए पुनर्वास योजना बनाने का उत्तरदायी होगा।

71. उपाधीक्षक के कर्तव्य |—उपाधीक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्न हैं:—

- (क) स्थापन आदेशों का अभिरक्षक,
- (ख) भोजन की तैयारी, भोजन के वितरण का पर्यवेक्षण तथा संर्बंधित अभिलेखों आदि का रख-रखाव
- (ग) क्रियाकलापों में बच्चों की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों एवं कर्मचारियों के साथ खुली बैठक का संचालन करना
- (घ) बच्चों के माता-पिता के साथ अंतर्विक्षा संचालित एवं बाह्य व्यक्तियों के साथ बच्चों के संवाद का नियमितीकरण
- (ङ.) बच्चों के सेमिनार, सांस्कृतिक-कार्यक्रम, बैठक आदि में भाग लेना सुलभ करना
- (च) सकारात्मक सुदृढ़ीकरण/ज्ञानात्मक पुनर्संरचना के उपयोजन को अनुश्रवण करना, गृह माता-पिता या वार्डन के साथ परामर्श करके स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना;
- (छ) बाह्य भोज्य पदार्थ का अनुश्रवण करना यदि बच्चों के माता-पिता द्वारा आपूरित किया जाता हो,
- (ज) बाल गृह में आपूरित कपड़े एवं बिछावन का अभिरक्षक,
- (झ) शिविर, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट, रेडक्रास के कार्य इत्यादि जैसे पाठ्योत्तर क्रियाकलापों का आयोजन;
- (ज) बच्चों के सुरक्षात्मक एवं विकासात्मक अधिकार को सुनिश्चित करना;
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को मापदंड के अनुसार जरूरी भोजन एवं वस्त्र मिले,
- (ठ) पानी, बिजली आदि सहित परिसर की स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत संरचना का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (ड) अधीक्षक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य एवं दायित्व, उपाधीक्षक का पद नहीं रहने पर अधीक्षक द्वारा कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

अध्याय 7
विविध

72. उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्था को मान्यता प्रदान करना।—(1) किसी भी व्यक्ति को, जो अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, देखरेख, संरक्षण या उपचार की आवश्यकता वाले किशोर या बालक को प्राप्त करने का इच्छुक है, उसके प्रत्यय-पत्रों एवं प्रतिष्ठा के सम्बन्ध सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त व्यक्ति के तौर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(2) किसी भी उपयुक्त स्थान या संस्था को, जिसका प्रबंधक यथा आवश्यक अवधि के लिए देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर या बालक को अस्थायी रूप से प्राप्त करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा पर उपयुक्त संस्था के रूप में राज्य सरकार द्वारा मान्यकृत किया जा सकता है।

(3) उपयुक्त संस्था के तौर पर मान्यकृत कोई संस्था,—

- (क) अधिनियम तथा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली में अधिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करेगी;
- (ख) अधिनियम तथा नियमावली में अधिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करने की क्षमता तथा इच्छा रखेगी;
- (ग) किशोरों एवं बालकों को प्राप्त करेगी तथा देखरेख एवं संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायेगी;
- (घ) किशोर या बालक को किसी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा के अध्यधीन होने से बचायेगी; तथा
- (ङ.) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का अनुपालन करेगी।

(4) मण्डल तथा समिति के कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संस्थानों की सूची रखी जायेगी।

(5) सांपार्श्विक शाखाओं वाली कोई उपयुक्त संस्था सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसमें रखे गये किशोर या बालक को अपनी किसी भी शाखा में भेज सकती है।

(6) किसी व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति घोषित करने या किसी संस्था को उपयुक्त संस्था के रूप में अनुशासित करने के पहले, सक्षम प्राधिकारी सम्यक् जांच पड़ताल करेगा तथा समाधान होने पर ही, मान्यता प्रदान की जायेगी।

73. संस्थाओं के प्रबंधन और परवर्ती देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण।—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणन के इच्छुक किसी भी संगठन को राज्य सरकार के पास नियमों, संगम-अनुच्छेद के उपनियमों, सोसायटी या संगठन द्वारा प्रदान की जा रही बाल देखरेख विशेषज्ञों की सेवाओं की स्थिति और पिछला अभिलेख दर्शित करने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संगठन में ठहरने और भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, शैक्षिक सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उपचार सेवाओं के लिए किये गए उपबंधों के सत्यापन के पश्चात् अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 और 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणन या मान्यता प्रदान करेगी, परन्तु यह तब जब कि संगठन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित सेवाओं के मानकों को पूरा करता हो और समय-समय पर यह भी सुनिश्चित करेगी कि उसके प्रभार में रखे गए किशोरों या बालकों का समग्र विकास और वृद्धि हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई संगठन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो आवश्यक जांच के पश्चात, मान्यता के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।

(3) राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था का प्रबंधन प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को, जो ऐसी संस्था को चलाने की क्षमता रखता हो, हस्तांतरित करेगी तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए समझौते के ज्ञापन के अधीन अपेक्षित उत्तरायित्वों का वहन करने के लिए उक्त स्वैच्छिक संगठनों को उपयुक्त संस्था के रूप में प्रमाणन या मान्यता प्रदान कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन की शर्तों, नियमों, प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है, किसी भी समय संगठन के प्रबंधक को सूचना जारी करके यह घोषित करेगी कि संगठन का प्रमाणन या मान्यता, यथास्थिति सूचना में उल्लिखित विशेष तारीख से वापस ली गयी है तथा उक्त तारीख से संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 अथवा 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देगा।

परन्तु यह कि संबंधित संगठन को तीस दिन की अवधि के भीतर उस संगठन के प्रमाणन या मान्यता की वापसी के कारणों के विरुद्ध लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(5) प्रमाण पत्र या मान्यता को वापस लेने या पुनः प्रदान करने का विनिश्चय जिला बाल कल्याण समिति या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकार के जांच के आधार पर लिया जा सकेगा।

(6) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संस्था के प्रभारी अधिकारियों को तीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।

(7) जब कोई संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, तब वहां रखे गए किशोरों या बालकों को अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में स्थानान्तरित किया जाएगा या उनके छोड़ने और स्थानान्तरण से संबंधित अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन छोड़ दिया जाएगा तथा यथास्थिति उनके छोड़ने अथवा स्थानान्तरण की सूचना बोर्ड या समिति को दी जाएगी।

74. अधिनियम के अधीन पंजीकरण |—(1) देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाएं चलाने वाले सभी संस्थान, चाहे सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाये जा रहे हों, अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन पंजीकृत कराएं।

(2) ऐसे सारी संस्थाएं नियमावली, उप-नियमों, संगम ज्ञापन, अधिशासी निकाय, पदधारकों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्रों (**balance sheet**), संस्था या संगठन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामाजिक या जन सेवा के पिछले अभिलेख के विवरण की एक प्रतिलिपि सहित राज्य सरकार के पास आवेदन करेंगी, जो यह सत्यापित करने के उपरान्त कि बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने सहने की सुविधाओं, अगर कोई हों, व्यावसायिक सुविधाओं तथा पुनर्वास की गुंजाईश के लिए संस्था या संगठन में प्रावधान किए गए हैं, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन एवं इस नियम के अनुसार ऐसे संगठन को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत कर सकती है।

75. प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठनों को सहायता अनुदान |—(1) अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41(4) या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन, प्रमाणन या मान्यता प्रवर्तन या जब पंजीकरण प्रवृत्त हो, उस अवधि के दौरान अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके द्वारा प्राप्त किशोरों या बालकों के निर्वाह के लिए तथा उनकी शिक्षा, उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास पर किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) अगर कोई संगठन, सहायता अनुदान अनाथालय नियंत्रण बोर्ड या किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त कर रहा हो तो उसे सहायता देय नहीं होगा।

(3) अधिनियम की धारा 8, 9, 34(3), 37, 41(4) और 44 के अधीन सरकार द्वारा संचालित उस गृहों के प्रबंधन को स्वैच्छिक संगठनों को हस्तान्तरण करने की दिशा में जो बजट सरकार उस गृह पर खर्च कर रही थी, उतनी ही राशि, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संगम-ज्ञापन के, जिसमें उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व का विवरण होगा, अधीन सहायता अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संगठन को दी जाएगी।

76. बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश |—(1) संस्था के परिसर में किसी भी अजनबी व्यक्ति को, अधीक्षक की अनुमति या बोर्ड या समिति के आदेश के सिवाय प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(2) विशिष्ट मामलों में जहाँ माता-पिता या अभिभावक अन्य राज्यों या जिलों से लम्बी दूरी तय करके आए हैं, अधीक्षक माता-पिता या अभिभावकों को परिसर में प्रवेश करने और बालकों से मिलने की अनुज्ञा देगा परन्तु यह तब जबकि उनके पास उपयुक्त पहचान-पत्र हो तथा उनके बारे में किशोर या बालक को प्रताड़ित और उत्पीड़ित करने की रिपोर्ट न हो।

77. पहचान फोटो |—(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित गृह में प्रवेश के समय प्रत्येक किशोर या बालक का फोटो खींचा जाएगा।

(2) एक फोटो किशोर या बालक की केस फाइल में रखा जाएगा, एक फोटो सूचक-कार्ड में चिपकाया जाएगा, एक फोटो क्रमिक संख्या दी हुई एल्बम में रखा जाएगा तथा निर्गेटिव दूसरी एल्बम में रखा जाएगा। फोटो की एक-एक प्रति यथास्थिति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ-साथ जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी।

(3) संस्था से गुमशुदा बालक या संस्था द्वारा गुमशुदा बालकों को स्वीकार करने की दशा में संबंधित विवरण के साथ बालक का एक फोटो गुमशुदा व्यूरो तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा।

78. पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होना।—इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किशोर या बालक के साथ काम करते समय, गिरूतारी के समय को छोड़कर, पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में होंगे न कि पुलिस की वर्दी में ताकि दोस्ताना माहौल हो।

79. हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध।—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विधि के उल्लंघन के मामले में किशोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी।

80. मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।—(1) जब किसी किशोर या बालक को बोर्ड या समिति से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि पेश व्यक्ति एक किशोर या बालक है, वह कारण लेखबद्ध करेगा तथा किशोर या बालक को उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा।

(2) यदि किशोर को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट मामले को जाँच और निपटान के लिए बोर्ड को अंतरित करेगा।

(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को अपराध के पीड़ित के रूप में ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसे अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट बालक की देखरेख और संरक्षण, पुनर्वास और वापस भेजने के लिए उपयुक्त समिति के पास भेज देगा।

81. स्थानान्तरण।—(1) जाँच के दौरान यदि पाया जाता है कि किशोर या बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान से है, तो बोर्ड या समिति, किशोर या बालक के स्थानान्तरण का आदेश करेगी तथा आदेश की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी। बशर्ते कि:

- (i) ऐसा स्थानान्तरण किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित में हो;
- (ii) किसी बालक के मात्र इस आधार पर कि बालक ने समस्याएँ पैदा की है या विद्यमान संस्थान में उसको संभालना मुश्किल हो गया है या किसी पुरानी या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित होने या असमर्थता के कारण स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा;
- (iii) ऐसा स्थानान्तरण साक्ष्यों के पूरा होने और उनकी प्रतिपरीक्षा के पश्चात ही, जो किशोरों या बालकों से संबंधित विधायी प्रक्रिया अपेक्षित हो, किया जाएगा और ऐसे स्थानान्तरण के कारण या परिस्थितियों को लेखबद्ध किया जाएगा।

(2) तदनुसार, राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई:-

- (i) उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी को, जिसके कार्यक्षेत्र में बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानान्तरण का आदेश किया गया है, स्थानान्तरण की सूचना भेजेगी।
- (ii) संस्था के अधीक्षक को, जहाँ बालक को स्थानान्तरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(3) राज्य सरकार या राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई से सूचना की प्रति प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी आदेश में उल्लिखित स्थान या व्यक्ति से बालक को लाने के लिए सरकारी खर्च पर अनुरक्षक की व्यवस्था करेगा।

(4) ऐसे स्थानान्तरण पर किशोर या बालक की केस फाइल और अभिलेख किशोर या बालक के साथ भेजी जाएगी।

82. किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रिया।—(1) किशोर या बालक, जिसका सामान्य निवास-स्थान सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है, सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 50 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, वह परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी, निवास स्थान पर, किशोर या बालक को प्राप्त करने के लिए नातेदारों या अन्य व्यक्ति की उपयुक्तता और इच्छा जानने तथा क्या ऐसा नातेदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति किशोर या बालक की उचित देखभाल और नियंत्रण कर सकता है, की जाँच करने के लिए निर्देश देगा।

(2) जहाँ किशोर या बालक को उसके सामान्य निवास-स्थान अथवा नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का आदेश किया जाता है, उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति से प्रपत्र-V या प्रपत्र-IX में वचन लेने के साथ-साथ प्रपत्र-VI में किशोर या बालक से किसी प्रतिभूति के बिना बंध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा।

(3) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन दिए गए बंध-पत्र या वचन-पत्र या दोनों के किसी उल्लंघन से किशोर सक्षम प्राधिकारी के सामने लाए जाने का दायी होगा, जो किशोर को किसी संस्था या गृह में भेजने का आदेश का सकेगा।

(4) किसी भी किशोर या बालक को, जो विदेशी है तथा उसका परिवार से सम्पर्क टूट चुका है, संरक्षण का अधिकार होगा।

(5) विदेशी किशोर या बालक को संबंधित देश के दूतावास और उच्च आयोग के साथ समन्वय करके उसके मूल देश को यथाशीघ्र प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(6) बोर्ड या समिति अपने आदेशों पर प्रत्यावर्तित किए गए प्रत्येक विदेशी किशोर या बालक के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित करेगा।

(7) अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी:-

- (क) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, जिसे इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था;
- (ख) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके कार्यक्षेत्र में वह स्थान आता है, जहाँ किशोर या बालक को भेजा जाना है;
- (ग) सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान आता है, जहाँ किशोर या बालक को भेजा जाना है;
- (घ) नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति, जिसे किशोर या बालक को प्राप्त करना है;
- (ड.) अनुमोदित मार्गरक्षी या फैक्स या संचार के तक्तालिक साधन से;

(8) इस नियम के उप-नियम (6) के अधीन आदेश लम्बित रहने के दौरान सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को यथास्थिति संप्रेक्षणगृह या बालगृह भेजेगा।

(9) जब कभी सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को धारा 50 के अधीन उनके निवास के सामान्य स्थान पर भेजना उपयुक्त समझता है, सक्षम प्राधिकारी नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, जो किशोर या बालक को प्राप्त करेगा, सूचित करेगा तथा उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को गृह में आने के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख को किशोर या बालक का प्रभार लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

(10) किशोर या बालक को भेजते समय, इस नियम के उप-नियम (8) के अधीन उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति की समुचित श्रेणी में दोनों ओर की यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय, किशोर या बालक की गृह से उसके निवास के सामान्य स्थान तक की यात्रा हेतु व्यय का भुगतान करने के लिए गृह के प्रभारी अधिकारी को निर्देश भी दे सकेगा।

(11) यदि नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को किशोर या बालक का कार्यभार लेने में असफल रहता है तो किशोर या बालक को उसके निवास के सामान्य स्थान पर संप्रेक्षण गृह के अनुरक्षक द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़कियों की दशा में कम से कम एक अनुरक्षक महिला होगी।

83. राज्य बाल संरक्षण इकाई।—(1) राज्य सरकार यथावश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राज्य बाल संरक्षण इकाई की स्थापना करेगी।

(2) राज्य बाल संरक्षण इकाई के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:- अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन तथा अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरणों एवं संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के अलावे यह इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों के साथ-साथ अन्य कृत्यों का उत्तरदायी होगा:-

- (क) जिला बाल संरक्षण इकाईयों की स्थापना, सहायता और उसका अनुश्रवण करना;
- (ख) बोर्ड या समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रतिनिधित्व करना;
- (ग) बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद्, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर गृह एवं अन्य संस्था या अधिकरण को प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करना तथा आवश्यक निधि समय पर आवंटित करना;

(घ) बच्चों तथा अधिनियम के अधीन स्थापित इकाईयों से संबंधित सभी डाटा का दस्तावेजीकरण, समय-समय पर यथापेक्षित प्रतिवेदनों का प्रकाशन करना, जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए आई. ई. सी. (सूचना, शिक्षा, संचार) सामग्री या इसी तरह की अन्य सामग्री तैयार करना जिसमें वृत्त चित्र, वेबसाइट पर सामग्री, पोस्टर, विवरणिका इत्यादि भी शामिल है।

(ङ.) बाल संरक्षण के मुद्दों पर अन्तर क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने के लिए सभी सरकारी विभागों (राज्य एवं केन्द्र), जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण बाल श्रम, बाल विवाह, दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग), दुराचार, बाल अधिकार, पुलिस न्यायपालिका, एच. आई. बी.एड्स इत्यादि से संबंधित विभाग भी सम्मिलित हैं, के साथ नेटवर्क एवं समन्वय स्थापित करना। यह इकाई बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए राज्य में इस तरह सृजित या अवस्थित इकाईयों तथा किसी दूसरे राज्य की इकाईयों के साथ समन्वयन स्थापित करेगी जिसमें राज्यस्तरीय दत्तक समन्वय अभिकरण, राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण, चाइल्ड लाइन आदि भी शामिल हैं।

(च) बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना एवं नेटवर्क तैयार करना, जिसमें मान्यता के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के आवेदन पर कार्रवाई करना, प्रमाणन, रजिस्ट्रीकरण या सहायता अनुदान भी शामिल है।

(छ) अधिनियम के अधीन कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी संगठन के सभी कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना, एवं प्रशिक्षण हस्तकों और पाठ्यक्रम का निर्माण करना, संसाधनों की सूची बनाना तथा पण्डारियों (स्टेक होल्डर) के बीच वितरित करने के लिए ऐसी सामग्री एवं हस्तकों का प्रकाशन करना।

(ज) देख-रेख का न्यूनतम मापदंड स्थापित करना तथा अधिनियम के अधीन स्थापित सभी संस्थाओं में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(झ) समितियों के कार्यकलाप का पुनर्विलोकन करना।

(ञ) यथास्थिति अधिनियम के उपबंधों तथा केन्द्र सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्कीम बनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना, जिसमें दत्तक ग्रहण, पालक देख-रेख, उत्तर देख रेख कार्यक्रम, प्रायोजन इत्यादि भी शामिल है।

(ट) शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिल कर क्षमता, जागरूकता, दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण, अध्ययन या प्रभाव मूल्यांकन तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना।

(ठ) जब जैसी जरूरत हो प्रभावी नीति निर्धारण सूचना एवं कार्यान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबद्ध विभाग चाहे किसी नाम से हों, को आवश्यक सामग्री (इनपुट) उपलब्ध कराना।

84. जिला बाल संरक्षण इकाई।—(१) राज्य सरकार प्रत्येक जिला में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना यथावश्यक पदाधिकारियों एवं वैसे कर्मचारियों एवं नियोजितों के साथ करेगी।

(२) जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य-अधिनियम के विभिन्न उपबंध के समग्र कार्यान्वयन, अधिनियम के अधीन स्थापित अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के अलावे जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (i) राज्य बाल संरक्षण इकाई के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश का कार्यान्वयन करेगी।
- (ii) जिला स्तरीय इकाई जैसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला सलाहकार बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बच्चों की संस्थाओं, किशोर गृह, बाल गृह आदि की सहायता करेगी तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना निधि, कर्मचारी के साथ उनके कार्यालयों की स्थापना में सहयोग करेगी;
- (iii) बोर्ड के सदस्यों एवं समिति के कार्य सम्पादन का मूल्यांकन करेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।
- (iv) किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, जिला सलाहकार परिषद तथा जिला निरीक्षण समिति के सामाजिक सदस्यों हेतु प्राप्त आवेदनों को अधिनियम तथा नियमावली अंतर्गत निर्धारित अर्हता के

अनुसार अनुबोधक्षण एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला पदाधिकारी तथा शिक्षा अथवा स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गठित तीन सदस्यों की अनुबोधक्षण समिति द्वारा की जाएगी।

अनुबोधक्षण समिति के सदस्य सचिव संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई होंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई प्राप्त सभी आवेदनों को अनुबोधक्षण समिति के मंतव्य सहित भेजेंगे।

- (v) राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार समिति के सदस्यों, सलाहकार मंडल/निरीक्षण दल के सदस्यों तथा ऐसे सारे आवेदनों पर विचार करना।
- (vi) सर्वोक्षण, अभियान या यथावश्यक ऐसे अन्य तरीके से देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान करेगी और उनका डाटा बेस तैयार करेगी तथा उन्हें संरक्षण, आपातकालीन सेवा, देख-रेख, पुनर्स्थापन या पुर्नवास हेतु अभिकरणों की पहचान कर, उनके साथ जोड़ेगी;
- (vii) बाल संरक्षण मुद्रों पर अंतर-क्षेत्रीय संबंध बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, शहरी बुनियादी सेवाएँ, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, युवा कार्य एवं संस्कृति, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी सहित सभी सरकारी विभागों से नेटवर्क और समन्वय करेगी;
- (viii) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना;
- (ix) प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक-ग्रहण और परवर्ती देखभाल सहित परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं का क्रियान्वयन करेगी;
- (x) जोखिम में रह रहे परिवारों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करेगी;
- (xi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का निर्धारण करना तथा कठिन परिस्थितियों में बालकों की प्रवृत्ति और पद्धति को मॉनीटर करने के लिए जिला विशिष्ट डाटा बेस तैयार करेगी,
- (xii) संसाधन निदेशिका तैयार करने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियन्तकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना तथा समय-समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराएगी;
- (xiii) कार्यक्रमों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के साथ-साथ अपने कार्यों के निष्पादन हेतु जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिश्चित करेगी;
- (xiv) संस्थागत, दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखभाल और प्रायोजन के माध्यम से बालकों का उनके परिवार में समेकन अथवा दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक पुनर्वास के लिए बालकों को रखने के लिए सभी स्तरों पर बालकों के स्थानांतरण में सहायता करेगी;
- (xv) जिला स्तर पर परिवार आधारित गैर-संस्थागत सेवाओं के क्रियान्वयन में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता करेगी;
- (xvi) बाल कल्याण क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से जिले में अभिकरणों और संस्थाओं के दक्षतापूर्ण मॉनीटर और पर्यवेक्षण के लिए परिमाप और यंत्र विकसित करेगी।
- (xvii) जिले में बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान कर रही सभी संस्थाओं या अभिकरणों का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करेगी;
- (xviii) बालकों को प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन करने वाले सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर-सरकारी) को प्रशिक्षण देंगी और उनकी क्षमता निर्माण करेगी;
- (xix) अधिनियम के क्रियान्वयन तथा प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए चाइल्डलाइन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों, गृहों के प्रभारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा लोक सदस्यों सहित जिला स्तर पर सभी पक्षों के साथ तिमाही बैठकों का आयोजन करेगी;
- (xx) राज्य स्तर पर राज्य बाल कल्याण इकाई, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों तथा अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाईयों के साथ सम्पर्क बनाएगी।

85. विशेष किशोर पुलिस इकाई।—(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर तथा देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करेगी।

(2) विशेष किशोर पुलिस इकाई जिला के सभी पुलिस थाना, अन्य जिलों में स्थापित विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय भी करेगी।

(3) इस इकाई में विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पर्कित के) के साथ दो भुगतेय सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) और जिला के सभी किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी होंगे।

(4) जिला के सभी पुलिस थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को बाल कल्याण पदाधिकारी के रूप में पदाधिकारी किया जाएगा जो बालकों के मामलों के साथ संवेदनशील बर्ताव करेगा और जिला के विशेष किशोर पुलिस इकाई को मामले की रिपोर्ट करेगा।

(5) सामाजिक अनुसंधान, परामर्श, देख-रेख, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास सहित बालकों की देख-रेख और संरक्षण में उसे सहायता प्रदान करने वाली रीति से विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इकाई के सहायतार्थ विशेष किशोर पुलिस इकाई मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन, ग्राम सभा, पंचायत या चाइल्ड लाईन को सहबद्ध कर सकेगा।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या कोई अन्य अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारियों को तथा बालकों से संबंधित मामलों की कार्रवाई से सहबद्ध अन्य व्यक्तियों को नियमित प्रशिक्षण और यथावश्यक अधिविन्यास प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करना विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारियों और बाल कल्याण पदाधिकारी के लिए आज्ञापक होगा।

(7) एक ओर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथासंशोधित) तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों में तथा दूसरी ओर, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 या उसके अधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली या किसी हस्तक या शासकीय निदेशों के उपबंधों में कोई विरोधाभाष होने की स्थिति में बालक के सर्वोत्तम हित में विनिश्चय किया जाएगा।

(8) विशेष किशोर पुलिस यूनिट विशेष रूप से गिरफ्तारी के समय, आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने में, प्रस्तुत किये जाने तक किशोरों का प्रभार रखने के लिए और मण्डल के समक्ष इन नियमों के नियम 11(12) के अनुसार प्रस्तुत करने के समय तक विशेष किशोर पुलिस यूनिटों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों की सहायता करने के प्रायोजन के लिए ग्राम सभा, पंचायत तथा राज्य सरकार द्वारा संरक्षण एजेंसियों के रूप में प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठनों से सहायता चाहेगी।

(9) जिले में पुलिस अधीक्षक विशेष किशोर पुलिस यूनिट का प्रधान होगा और समय समय पर इसके कार्य का अवलोकन करेगा।

(10) पुलिस महानिरीक्षक की रैंक से अन्यून पुलिस से नोडल अधिकारी को अधिनियम के अधीन बालकों या किशोरों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर पुलिस के साथ समन्वय और अपवृद्धि करने के लिए प्रत्येक राज्य में नाम निर्देशित किया जाएगा।

(11) आवश्यक जाँच के पश्चात् मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बालक को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया कोई भी पुलिस अधिकारी अपराध के लिए अभियोजित किये जाने के अलावा सेवा से हटाये जाने का दावी होगा।

86. अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी।—विद्यमान परिवीक्षा सेवा में वृद्धि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाये गये स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उनकी सेवाओं को क्रियान्वयन तंत्र में भी सहयोजित किया जाएगा।

87. अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारीवृद्ध की निरहताएं।—(1) अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या केस-वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारीवृद्ध अपने पर्यवेक्षण या स्वयं के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किशोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।

(2) किसी देखभाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किशोर या बालक के शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जाँच के पश्चात् निरहता का पात्र बनाएगी।

88. कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।—(1) राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण इकाई की सहायता से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के कार्यान्वयन में संलग्न कार्यक्रमों के लिए उनकी कानूनी दायित्वों एवं कार्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं अथवा प्रशिक्षण और शोध संस्थान के सहयोग से नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेगी और क्षमता निर्माण करेगी।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

- (क) नए भर्ती किए गए कर्मचारीवृद्ध देखभाल कार्यकर्ताओं, सदस्यों, पुलिस, इत्यादि का अभिविन्यास और प्रशिक्षण,
- (ख) समस्त देखभालकर्ताओं के लिए वर्ष में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, तथा
- (ग) कर्मचारीवृद्ध सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ।

89. चयन समिति तथा इसकी संरचना।—(1) राज्य सरकार, तीन वर्ष की अवधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सात सदस्य होंगे:—

- (क) अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय या अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश या वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त हो, को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,
- (ख) सदस्य सचिव के रूप में संबद्ध विभाग से एक प्रतिनिधि जो निदेशक से अन्यून पर्कित का हो।
- (ग) बाल अधिकार मुद्रे पर कार्यरत किन्तु बालकों से संबंधित संस्थान का संचालन नहीं करने वाले जाने माने गैर सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि;
- (घ) समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल विकास, शिक्षा, विधि, अपराध-विज्ञान आदि से और बाल मुद्रों संबंधी कार्य का अनुभव रखने वाले संबंधित शैक्षणिक निकायों से दो प्रतिनिधि,
- (ङ.) राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, का प्रतिनिधि अधिमानतः वह संबद्ध व्यक्ति जो बाल अधिकार के मुद्रे देखता हो तथा
- (च) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक संयुक्त सचिव स्तर का अनुसूचित जाति/जनजाति सरकारी पदाधिकारी।

(2) चयन समिति अपेक्षानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगा तथा सदस्य सचिव ऐसी बैठकों के आयोजन का उत्तरदायी होगा।

(3) चयन समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को लिखित त्यागपत्र सौंप सकेगा। त्याग-पत्र से उत्पन्न ऐसी कोई रिक्ति, चयन समिति की रचना के अनुसार, अधिमानतः चार सप्ताह में, तत्काल भरी जाएगी तथा ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल चयन समिति की बूची हुई अवधि तक होगा।

90. चयन समिति के कार्य।—(1) चयन समिति राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला या नगर स्तरीय निरीक्षण समिति/सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों की सूची का चयन एवं अनुशंसा करेगी।

(2) चयन समिति जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अनुरूपित नामों की सूची पर विचार करेगी। किसी भी राज्यस्तरीय समिति या बोर्ड के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई चयन समिति को नामों की अनुशंसा करेगी। चयन समिति छाँटे गये आवेदनों की व्यक्तिगत अन्तर्वेक्षा सहित चयन हेतु आवेदनों पर कार्रवाई की पद्धति विहित कर सकेगी।

(3) चयन समिति द्वारा इस प्रकार अनुरूपित नामों की सूची पर बोर्ड, समिति या इकाई के कार्यकाल के अन्तर्गत होनेवाली किहीं रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) बोर्ड या समिति में नियुक्ति के हेतु सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(5) बोर्ड या समिति के सदस्यों की नियुक्ति करने में चयन समिति जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के द्वारा इस आशय के सार्वजनिक विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।

(6) बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी शिकायत की स्थिति में चयन समिति आवश्यक जाँच करेगी तथा यदि अपेक्षित हो तो ऐसे सदस्य की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को करेगी।

(7) बोर्ड या समिति के सदस्य की नियुक्ति के लिए नाम की अनुशंसा करते समय चयन समिति प्रत्येक बोर्ड या समिति की ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए जो बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होती हो, नामों की सूची तैयार करेगी।

(8) बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ऐसी रिक्तियों के भरने के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(9) राज्य संरक्षण इकाई या राज्य सरकार चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची के आधार पर रिक्तियों को भरेगी।

91. सलाहकार बोर्ड।—(1) राज्य सरकार, तीन वर्षों के लिए राज्य, जिला तथा नगर स्तर पर सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप में करेगी:-

- (क) मुख्य सचिव- अध्यक्ष
- (ख) प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग- संयोजक
- (ग) स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, विधि, श्रम एवं भवन निर्माण विभागों से सचिव या उनके प्रतिनिधि
- (घ) चयन समिति के अध्यक्ष
- (ङ.) बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि
- (च) विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

- (i) गृह की स्थापना एवं रख-रखाव से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना,
- (ii) अधिनियम की धारा 61 के अधीन यथा उपबंधित रूप में निधि के सृजन एवं प्रबंधन के लिए सलाह देना,
- (iii) विभिन्न उपबंधों, सुविधाओं और सेवाओं यथा संस्था में रह रहे बच्चों के लिए भोजन, कपड़ा, दवा, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा उनकी दरों का निरीक्षण करना,
- (iv) कोई अन्य विषय जो बच्चों के लिए लाभ, नीति निर्धारण योजना बनाने तथा योजना के कार्यान्वयन में यथावश्यक समझा जाए,
- (v) उच्चतम स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय।

(4) राज्य सरकार जिला सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) जिला पदाधिकारी	- अध्यक्ष
(ख) असैनिक शल्य चिकित्सक	- सदस्य
(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक	- सदस्य
(घ) जिला बाल संरक्षण इकाई का प्रधान	- संयोजक
(ङ.) गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि	- सदस्य

(5) सभी सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेंगे।

(6) इस अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के अनुसार गठित जिला या नगर स्तरीय सलाहकार बोर्ड इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन निरीक्षण समिति के रूप में भी कार्य करेगा।

(7) ये सलाहकार बोर्ड, अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत या गैर-संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) राज्य सरकार, इस नियमावली के नियम 99 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से राज्य, जिला और नगर स्तर पर सलाहकार बोर्डों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामों की सूची की अनुशंसा करेगी।

(9) सलाहकार बोर्ड में सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति उसी तरह से की जाएगी, जैसे कि सक्षम प्राधिकारी की दशा में की जाती है।

92. किशोर न्याय निधि।—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने वाले किशोरों या बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जिसे राज्य स्तर पर एक निधि का सृजन करेगी जिसे 'किशोर न्याय निधि' (इसमें इसके आगे निधि के रूप में निर्दिष्ट) के नाम से जाना जाएगा।

(2) धारा 61 की उप-धारा (2) के अधीन आने वाले संदानों, अंशदानों अथवा अभिदायों के अतिरिक्त, केन्द्रीय/राज्य सरकार भी इस निधि में अभिदाय कर सकेगी।

(3) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक स्वयंसेवी एवं अलाभकर निकाय होगा और निधि का प्रबंधन एवं प्रशासन, अधिनियम की धारा 62 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड के अधीन होगा।

(4) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा:—

- (क) किशोरों या बालकों के कल्याण, पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना;
- (ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देना;
- (ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के व्यय तथा इसके प्रयोजन की पूर्ति करना; और
- (घ) अन्य सभी कार्य करना, जो उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक और आवश्यक हों।

(5) इस निधि की परिसम्पत्तियों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक या गैर-सांविधिक निकायों से समस्त ऐसे अनुदानों या अंशदानों, आवर्ती या अनावर्ती और साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान सम्मिलित होंगे।

(6) निधि के सभी धन और सम्पत्तियों का सभी आय और व्यय का नियमित लेखा रखा जाएगा और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की अधिसूचित फर्म या किसी अन्य मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जायें, लेखा परीक्षा की जाएगी।

(7) सभी संविदाएँ और अन्य आश्वासन, प्रबंधन बोर्ड के नाम से किए जाएँगे तथा सचिव-सह-खजांची तथा इस प्रयोजनार्थ इसके द्वारा प्राधिकृत प्रबंधन बोर्ड के एक सदस्य द्वारा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएँगे।

(8) सभी राशियों का आहरण सचिव-सह-खजांची द्वारा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, चेक या मांग पर्चियों द्वारा किया जायेगा और दस हजार रुपये से अधिक की रकम की दशा में, वे सचिव-सह-खजांची तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबंध बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(9) बोर्ड प्रबंधन सम्पत्ति की बिक्री अथवा अन्य निपटारों से मिलने वाली आमदनी तथा कोष के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल अनापेक्षित सम्पत्ति या धन की जरूरत पड़ने पर न्यास धन के निवेशों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी एक अथवा एक से अधिक निवेशों के लिए, जैसा कि बोर्ड प्रबंधन उपयुक्त समझे, इस्तेमाल करेगा।

93. लम्बित मामले।—(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के लाभों से वर्चित नहीं रखा जाएगा।

(2) सभी लम्बित मामले, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अधीन निपटाए जाएंगे।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को, इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन फायदे दिए जाएंगे और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फायदे उन सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो किसी अपराध को करने के समय किशोर या बालक थे। ये फायदे उन्हें तब भी दिए जाएंगे जब वे किसी जाँच या विचारण के दौरान किशोर या बालक नहीं रह जाते हों।

(4) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक के निरोध या रहने या दण्ड की अवधि की संगणना करते समय, सभी ऐसी अवधि, जिसे कोई किशोर या बालक अभिरक्षा, निरोध, ठहरने या कारावास के दण्ड के रूप में पहले से ही बिता चुका है उसकी गणना न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में अंतर्विष्ट ठहरने या निरोध या कारावास दण्ड के अंश के रूप में की जाएगी।

94. खुलापन और पारदर्शिता।—(1) समस्त बाल गृह यथास्थिति, प्रभारी पदाधिकारी की अनुमति से आगन्तुकों के लिए खुला रहेगा और समिति या प्रभारी पदाधिकारी स्थानीय स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं,

अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, प्रख्यात व्यक्तियों, मीडिया के प्रतिनिधियों को तथा आगन्तुकों के रूप में किन्हीं ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्रभारी पदाधिकारी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समझे को अनुमति दे सकेंगे।

(2) यदि समुदाय के सदस्य संस्थाओं में सेवा करना चाहते हों या वे अपनी विशेषज्ञताओं के माध्यम से संस्था में योगदान देना चाहते हों, तो वृह के प्रभारी पदाधिकारी इन गृहों की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

(3) प्रभारी पदाधिकारी आगन्तुक पुस्तिका संधारित करेगा तथा इस पुस्तिका में आगन्तुकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षण प्राधिकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) किसी संस्था का दौरा करते समय, आगन्तुक न तो ऐसा कुछ कहेंगे या न ऐसा कुछ करेंगे, जो प्रभारी पदाधिकारी के प्राधिकार को नीचा दिखाता हो या जो अधिनियम या नियमों के उल्लंघन में हो या बालकों की गरिमा को ठेस पहुँचाता हो।

(5) उपर्युक्त उप-नियम में किसी बात के होते हुए भी प्रभारी पदाधिकारी द्वारा तब अनुमति अस्वीकार किया जाना विधिपूर्वक होगा जब वह समझता हो कि ऐसा दौरा अंतःवासियों के हित या गृहों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आगंतुकों को संप्रक्षण गृहों और विशेष गृहों में जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

95. अभिलेखों या दस्तावेजों का निपटान।—विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक से संबंधित अभिलेख या दस्तावेजों को सात वर्ष के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और उससे अधिक नहीं, और तत्पश्चात् यथास्थिति बोर्ड या समिति या बाल संरक्षण इकाई के परामर्श से नष्ट कर दिए जाएंगे।

96. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का निस्तारण।—(1) राज्य सरकार, या बोर्ड यथास्थिति, या तो स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजन के लिए किये गये आवेदन पर, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या व्यक्ति के मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा। अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और इस नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों में अन्तर्विष्ट शर्तों के अनुसार उसकी किशोरता विनिश्चित कर सकेगा और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की तुरन्त विमुक्ति के लिए, अधिनियम की धारा 64 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा जिसके निरोध या कारावास की अवधि उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपर्युक्त अधिकतम अवधि से अधिक हो गयी हो।

(2) उपरोक्त प्रयोजनार्थ एक समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जो, पुनर्विलोकन के पश्चात् अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी तथा राज्य सरकार समुचित आदेश पारित करेगी।

97. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण।—सौंपे गये कर्तव्यों के संपादन के दौरान अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी मामले के लिए किसी कार्यकारी, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

98. निरसन एवं व्यावृति।—(1) बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012 एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) इस नियमावली में अंतर्विष्ट कोई बात इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012 के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या जारी किए गए किसी आदेश को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० एम० राजू
सरकार के सचिव।

अनुसूची-1**कपड़े, विस्तर, प्रसाधन एवं अन्य सामग्री शियम 48 //**(1) किशोरों अथवा बालकों को निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदान की जाएँगी:-
विस्तर आदि

क्र० सं०	वस्तु	प्रति बालक आपूर्ति की मात्रा
1	2	3
1	तौलिया	4 प्रति वर्ष
2	सूती चादर	2 प्रति 2 वर्ष
3	तकिया (रुई भरा हुआ)	1 प्रति 2 वर्ष
4	तकिया के कवर	2 प्रति 2 वर्ष
5	उनी कम्बल	2 प्रति 2 वर्ष
6	सूती दरी	2 प्रति 2 वर्ष
7	रुई भरी रजाई	1 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
8	गद्दा	1 प्रति 2 वर्ष
9	मच्छरदानी	1 प्रति 2 वर्ष

लड़कियों के लिए कपड़े

1	स्कर्ट और ब्लाउज या सलवार कमीज या आधी साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट	आयु और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर 5 सैट प्रति वर्ष
2	बनियान (एक-एक मीटर)	छोटी लड़कियों के लिए 6 प्रति वर्ष
3	ब्रेजर	बड़ी लड़कियों के लिए 6 प्रति वर्ष
4	पेन्टीज (1 मीटर कपड़ा)	6 प्रति वर्ष
5	सैनिटरी टॉवल	बड़ी लड़कियों के लिए 12 पैकेट प्रति वर्ष
6	उनी स्वैटर	2 प्रति दो वर्ष (ठंडे इलाकों में)
7	उनी शॉल	1 प्रति दो वर्ष (ठंडे इलाकों में)

लड़कों के लिए कपड़े

1	कमीज	5 सैट प्रति वर्ष
2	निककर	छोटे बच्चों के लिए 5 सैट प्रति वर्ष
3	पैन्ट	बड़े बच्चों के लिए 5 सैट प्रति वर्ष
4	बनियान	4 सैट प्रति वर्ष
5	अण्डर वियर	4 सैट प्रति वर्ष
6	उनी जर्सी	2 प्रति 2 वर्ष ठंडे इलाकों में
7	स्कार्फ	2 प्रति 2 वर्ष ठंडे इलाकों में

विविध वस्तुएँ

1	चप्पल	1 जोड़ी प्रति वर्ष
2	जूते	1 जोड़ी प्रति वर्ष
3	स्कूल की वर्दी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 2 सैट प्रति वर्ष
4	स्कूल के जूते	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सैट प्रति वर्ष
5	स्कूल बैग और स्टेशनरी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सैट प्रति वर्ष
6	रुमाल	6 प्रति वर्ष

टिप्पणी:- उपर विनिर्दिष्ट पहनावे के अतिरिक्त, प्रत्येक बालक को समारोहों के अवसरों पर उपयोग के लिए, तीन वर्ष में एक बार, एक सूट दिया जाएगा, जिसमें एक सफेद कमीज, एक जोड़ी खाकी निकर या पैंट, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) शामिल होंगे। लड़कियों को आधी साड़ी (सफेद) या एक सलवार कमीज या एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) दिए जाएँगे।

(2) संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक अस्पताल में, जहाँ दाखिल मरीजों के लिए शय्याओं का प्रावधान है, निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाएँगे:-

रात के कपड़े एवं बिस्तर	आपूर्ति हेतु मापदण्ड
1 गददा	एक प्रति शय्या प्रति तीन वर्ष
2 सूती चादरें	चार प्रति शय्या प्रति वर्ष
3 तकिया	एक प्रति शय्या प्रति दो वर्ष
4 तकिया के कवर	चार प्रति शय्या प्रति वर्ष
5 उनी कम्बल	एक प्रति शय्या प्रति दो वर्ष
6 पायजामा एवं ढीली कमीज (लड़कों हेतु हॉस्पीटल टाइप)	तीन जोड़ी प्रति बालक प्रति वर्ष
7 लड़कियों हेतु स्कर्ट एवं ब्लाउज या सलवार कमीज	तीन जोड़ी प्रति बालक प्रति वर्ष
8 सूती दरी	एक प्रति शय्या प्रति तीन वर्ष

टिप्पणी:-

- (i) जब तक बालक संस्था के अस्पताल में दाखिल रोगी के रूप में भर्ती रहता है, तब तक संस्था का डॉक्टर दाखिल रोगी को अस्पताल के कपड़े देगा तथा उसके द्वारा पहने हुए कपड़े रख लिए जाएँगे। अस्पताल से बालक की छुट्टी के समय उन कपड़ों को धुलवाकर उन्हें बालक को वापस दे दिया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक बालक को सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार किट बॉक्स अथवा लॉकर दिया जाएगा।
- (iii) अधीक्षक सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार पारंपरिक चारपाइयों की जगह दो स्तरीय शय्याओं की व्यवस्था करेगा।

(3) प्रसाधन:- गृह के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री दी जाएगी:

बालों में लगाने के लिए तेल	100 मिंग्रा० प्रति मास
नहाने-धोने का साबुन अथवा कार्बोलिक साबुन	1 बड़ी टिकिया प्रति मास
टूथ पेस्ट एवं बुश	1 बुश प्रति 3 मास एवं 50 ग्राम पेस्ट प्रति मास
कघा	1 प्रति वर्ष

टिप्पणी:- (क) संस्था से बाहर विद्यालय जाने वाले बालकों को उनकी स्कूल यूनीफार्म धोने के लिए कपड़े धोने के साबुन की एक अतिरिक्त टिकिया (100 ग्राम) प्रति मास दी जाएगी।

(ख) कपड़े, तौलिए, चादरें आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगा:

1. कपड़े धोने का साबुन साबुन की 1 टिकिया (125 ग्राम) प्रति मास
2. सफेदी / विरंजक कर्मक सफेद कपड़े के लिए अपेक्षानुसार

तथापि, धुलाई के समय अन्य कपड़ों में अस्पताल के कपड़े शामिल नहीं किये जा सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो, अधीक्षक, अस्पताल के कपड़े धोने के लिए उपरोक्त मद्दें अलग से दे सकता है।

(4) गृहों को साफ-सथुरा रखने के लिए निम्नलिखित मद्दें उपलब्ध कराई जाएगी:-

क्र०	मद	आपूर्ति का मापदण्ड
1	झाड़ू	संस्था के क्षेत्र के आधार पर 25 से 40 नग प्रति मास
2	डी०डी०टी० का छिड़काव	संस्था के डॉक्टर की सलाह के अनुसार
3	खटमलों को मारने वाले कारगर कर्मक	आवश्यकतानुसार
4	फिनाईल एवं सफाई करने वाले एसिड (प्रति दिन)	साफ किए जाने वाले शौचालय क्षेत्र के आधार पर संस्था के डॉक्टर की सलाह के अनुसार

अनुसूची-2

पोषण एवं आहार मापदण्ड *भूलि e 51½*

क्रमांक	आहार की सामग्री का नाम	मपदण्ड प्रति व्यक्ति प्रति दिन
1	2	3
1	चावल / गेहूँ / रागी / ज्वार	600 ग्राम (700 ग्राम 16–18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए) जिसमें से कम से कम 100 ग्राम गेहूँ या रागी या ज्वार हो।
2	दाल / राजमा / चना	120 ग्राम
3	खाद्य तेल	25 ग्राम
4	प्याज	25 ग्राम
5	नमक	25 ग्राम
6	हल्दी	06 ग्राम
7	धनिया (पिसा हुआ)	05 ग्राम
8	अदरक	05 ग्राम
9	लहसुन	05 ग्राम
10	इमली / अमचूर	05 ग्राम
11	दूध (नाश्ते में)	150 मिली
12	मिर्च	05 ग्राम
13	सब्जी (पत्तेदार) (बिना पत्ते वाली)	100 ग्राम 130 ग्राम
14	दही या छाछ	100 ग्राम / मिली
15	मुर्गा सप्ताह में एक बार अथवा अण्डे सप्ताह में 4 दिन	115 ग्राम
16	गुड़ और मूँगफली (केवल 60–60 ग्राम) या पनीर (100 ग्राम) (शाकाहारी के लिए)	सप्ताह में एक बार
17	चीनी	40 ग्राम
50 बच्चों के लिए प्रतिदिन निम्नलिखित मद्दे		
18	काली मिर्च	25 ग्राम
19	जीरा	25 ग्राम
20	चना दाल	50 ग्राम
21	सरसों	50 ग्राम
22	अजवाईन	50 ग्राम
मुर्गा पकाने वाले दिन 10 किलोग्राम मुर्गा पकाने के लिए		
23	गरम मसाला	10 ग्राम
24	नारियल	150 ग्राम
25	खसखस	150 ग्राम
26	मूँगफली का तेल	500 ग्राम
रुग्ण बच्चों के लिए		
27	ब्रैड	500 ग्राम
28	दूध	500 मिली
अन्य मद्दे		
29	रसोई गैस	केवल खाना पकाने के लिए

अनुदेश:

2. आहार में विविधता

- (क) तीन प्रकार की दालें अर्थात् तूर (तुवारी), मूँग (हरा चना) तथा चना (बंगाली चना) बारी-बारी से वितरित की जाएँ।
- (ख) अधीक्षक स्व-विवेक से मुर्ग की जगह मछली की भी व्यवस्था कर सकता है, बशर्ते कि सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़े।
- (ग) मांसाहारी दिनों में, शाकाहारी बच्चों को लड्डू के रूप में प्रति बच्चा 60 ग्राम गुड़ एवं 60 ग्राम मूँगफली दाना अथवा अन्य कोई मिठाई अथवा 100 ग्राम पनीर वितरित किया जाए। सप्ताह में एक बार सब्जी की जगह आलू वितरित किए जाएं।
- (घ)

(ङ) सप्ताह में एक बार पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि मेथी, पालक, गोंगुरा थोटकुरा अथवा अन्य कोई साग भी वितरित की जाए। यदि कहीं किसी संस्था में किचन गाड़न हो तो वहाँ सहजन के पेड़, कड़ी पत्ता के पेड़, धनिया के अलावा पत्तेदार सब्जियाँ उगायी जानी चाहिए और अधीक्षक को अलग-अलग तरह की सब्जियाँ वितरित करनी चाहिए एवं ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रकार की सब्जी सप्ताह के भीतर पुनः वितरित न की जाए।

(च) अधीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अथवा संस्था के डॉक्टर की सलाह पर वह व्यक्ति विशेष मामलों में आहार के मापदण्ड में अस्थायी परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते की निर्धारित मापदण्ड से मात्रा अधिक न हो।

भोजन का समय एवं व्यंजन सूची

(क) पूर्वाहन 8:00 बजे के बाद नाश्ता

- (1) उपमा अथवा गेहूँ या रागी की रोटी अथवा अन्य कोई व्यंजन।
- (2) गोंगुरा अथवा ताजा कड़ी पत्ता अथवा ताजे धनिया अथवा नरियल की चटनी और पुल्ता दाल / सब्जी को एक व्यंजन के रूप में वितरित किया जाए।
- (3) दूध
- (4) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल

(ख) लंच दोपहर 1:00 बजे तथा रात्रि का भोजन अपराह्न 7:00 बजे के बाद

- (1) चावल / चपाती अथवा दोनों
- (2) पकी हुई सब्जी
- (3) सांभर अथवा दाल
- (4) दही अथवा छाछ

अन्य:-

(क) मौसम के अनुसार, अधीक्षक स्व-विवेक से भोजन वितरण के समय में परिवर्तन कर सकेगा।

(ख) संस्था के डॉक्टर की सलाह पर प्रत्येक बीमार बच्चे को, जिसे उसके अस्वस्थ होने के कारण नियमित भोजन करने से रोका गया है, आहार मापदण्डों में यथानिर्दिष्ट विकित्सीय आहार वितरित किया जाय।

(ग) वजन बढ़ाने के लिए अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों से संस्था के डॉक्टर की सलाह पर नियमित आहार के अलावा पोषण हेतु दूध, अण्डा, चीनी एवं फल जैसे अतिरिक्त आहार दिए जाने चाहिए और दैनिक राशन की गणना के प्रयोजनार्थ बीमार बच्चों को उस दिन बच्चों की संख्या में शामिल न किया जाए।

(घ) निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्वों एवं त्यौहारों के अवसर पर आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर गृह के सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाए:

1	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
2	अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल)
3	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
4	महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
5	बाल दिवस (14 नवम्बर)
6	बाल अधिकार दिवस (20 नवम्बर)
7	दशहरा (विजय दशमी)
8	दीपावली
9	रमजान (ईद-उल-फितर)
10	बकरीद (ईद-उल-जुहा)
11	क्रिसमस (25 दिसम्बर)

राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरिक्त त्यौहार विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

प्रपत्र-I***16/12/2015*****पर्यवेक्षण आदेश**

जब किशोर को उसके माता—पिता, संरक्षक या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखा जाए (दिनांक).....**20**..... की प्रोफाईल संख्या

चूंकि (किशोर का नाम) को आज की तारीख में अपराध करते पाया गया है और इसे (नाम) (पता) की देखरेख में उक्त द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रखा गया है और बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त किशोर/किशोरी को पर्यवेक्षण में रखकर उसके मामले का निपटान किया जाना समीचीन है।

एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उक्त किशोर को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की अवधि के लिए परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में रखा जाएः—

1. किशोर/किशोरी इस आदेश और उक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र की प्रतियों के साथ उसमें नामित परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. किशोर/किशोरी को उपर्युक्त परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में सौंपा जाएगा।
3. किशोर/किशोरी की अवधि तक पर/में रहेगा।
4. किशोर/किशोरी को परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता की अनुमति लिए बिना के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5. किशोर/किशोरी को दुष्वरित्र व्यक्तियों के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा।
6. किशोर/किशोरी ईमानदारी से और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा; तथा नियमित रूप से स्कूल जाएगा या ईमानदारी से जीविका कमाने का प्रयास करना।
7. किशोर/किशोरी नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित होगा।
8. जिस व्यक्ति की देखरेख में इस किशोर/किशोरी को रखा गया है, वह व्यक्ति इसकी देखरेख, शिक्षा, एवं कल्याण की समुचित व्यवस्था करेगा।
9. जिस व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा गया है, उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करने होंगे कि किशोर/किशोरी ऐसा कोई अपराध न करे, जो भारत में किसी विधि के अनुसार दंडनीय हो।
10. इस किशोर को स्वापक औषधियों अथवा मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।
11. परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता उपर उल्लिखित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए समय—समय पर जो निदेश देंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा।

(दिनांक).....(माह).....**20**.....।

(हस्ताक्षर)
प्रधान दंडाधिकारी
किशोर न्याय बोर्ड

अतिरिक्त शर्त/शर्त, यदि कोई हो, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्तः स्थापित की जा सकेंगी।

प्रपत्र II
#U/e 12 16/12/15

धारा.....की उपधारा.....,धारा.....की उपधाराऔर
 धाराकी उपधाराके
 अधीन निरोध के आदेश

प्रभारी अधिकारी

चूंकि(दिनांक).....माह 20.....(वर्ष) कोआयुमें
(किशोर/किशोरी का नाम), पुत्र/पुत्रीको प्रोफाईल संख्याप्रधान
 विधि/धाराका विरोधी आचरण करते पाया गया, इसलिए मैंप्रधान
 मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड उक्त किशोर/किशोरी को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा
 के अधीनअवधि तक पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह
में रखे जाने का आदेश देता हूँ।

इसके द्वारा आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त
 किशोर/किशोरी को अपनी देखरेख में लें और विधि के अनुसार उपर्युक्त आदेश का निष्पादन करने के
 लिए उसेअवधि तक पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह/
 में रखें।

मेरे हस्ताक्षर और किशोर न्याय बोर्ड की मुहर के अधीन(दिनांक)
(माह) 20.....(वर्ष) को दिया गया।

#U/e 12 16/15
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

संलग्नकः—

न्याय निर्णय, यदि कोई हो, या आदेशों की प्रति, गृह का विवरण, इतिवृत्त एवं व्यक्तिगत देखरेख
 योजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा:

जो अपेक्षित न हो, उसे काट दें।

प्रपत्र-III

नियम 12 ४/८ और 12 १६/८ ½
सामाजिक अन्वेषण / जॉच का आदेश

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति

चूंकि इस बोर्ड के समक्ष पेश किए गए(किशोर/किशोरी का नाम)
पुत्र/पुत्री श्री आयु लगभग निवासी
..... के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की
धारा के अधीन रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त हुई है।

आपको एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त किशोर के सामाजिक पूर्ववृत्त, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की परिस्थितियों की जॉच करके अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को/या इससे पहले अथवा इस बोर्ड द्वारा अनुज्ञात समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतद्वारा यह निदेश भी दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो आप बाल मनोविज्ञान, मनःचिकित्सा उपचार या परामर्श के किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर उनके विचार जाने तथा अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

.....(दिनांक).....(माह)20.....(वर्ष)

Lkky/
प्रधान मंजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र-IV

[नियम 13] $\frac{1}{2}rFkfu; e 80 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} v \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

क्र० संख्या

किशोर न्याय बोर्ड ----- Mr. / Ms. को प्रस्तुत

परिवीक्षा विभाग / राज्य सरकार का संबद्ध प्राधिकार / स्वैच्छिक संगठन
..... (हस्ताक्षर व मुहर)

प्रोफाइल संख्या:-

धारा:- के अधीन

प्रोफाईल का शीर्षक:

ଆଜାଃ

आरोपित अपराध का स्वरूप :

नाम	धर्म
पिता का नाम	जाति
स्थायी पता	जन्म का वर्ष
पकड़े जाने से पूर्व अंतिम पता	आयु

पूर्व का संस्थागत/केस इतिवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो,

परिवार

अन्य नजदीकी रिश्तेदार या इच्छुक एजेंसी

धर्म के प्रति दृष्टिकोण, गृह की सामान्य एवं आचार संहिता इत्यादि

समाजिक और आर्थिक स्थिति

परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकार्ड

वर्तमान जीवन दशा

माता-पिता / माता-पिता और बच्चों के बीच विशेषकर अन्वेषणाधीन किशोर/किशोरी के साथ संबंध

अन्य महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो,

किशोर का इतिवृत्त

मानसिक स्थिति

मौजूदा और विगत

शारीरिक स्थिति

मौजूद और विगत

आदतें, रुचि

नैतिक, आमोद-प्रमोदात्मक इत्यादि

उत्कृष्ट लाक्षणिक और व्यक्तित्व विषयक विशेषताएँ

साथी और उनका प्रभाव

बिना अनुमति गृह न्याग का ब्यौरा, यदि कोई हो

विद्यालय विद्यालय के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति किशोर/किशोरी का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण

कामकाज का रिकार्ड धारित कार्य, छोड़ देने के कारण, व्यावसायिक अभिरुचियाँ, कार्य या नियोक्ताओं के प्रति दृष्टिकोण

आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट घर में

घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया

अन्य कोई अभ्युक्ति

जाँच का परिणाम

भावनात्मक कारक

शारीरिक दशा

बौद्धिक क्षमता

सामाजिक व आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

समस्याओं के संबंध में जताए गए कारण

अपचारिता के कारणों सहित मामले का विश्लेषण

परामर्शित विशेषज्ञों की राय

उपचार एवं इसकी योजना के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिश

परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता

प्रपत्र V

५४; e 15 dk mi fu; e ५५ fu; e ९२ dk mi fu; e १२५

जिस माता—पिता/संरक्षक/नातेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा गया हो उसके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला वचनबंध/बंध पत्र
 चूंकि मैं माता—पिता, संरक्षक, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति होने के नाते, जिसकी देखरेख में (किशोर/किशोरी का नाम) को रखे जाने का आदेश किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिया गया है, उक्त बोर्ड द्वारा मुझे प्रतिभूति सहित
 रूपये (अंकों में)/ रूपये (शब्दों में) अथवा प्रतिभूति के बिना वचनपत्र/बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं अपनी देखरेख में रखे गए उक्त के संबंध में स्वयं को एतद् द्वारा आबद्ध करता हूँ। मैं उक्त की समुचित देखरेख की व्यवस्था करूँगा और मैं यह भी वचन देता हूँ कि यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि उक्त अच्छा व्यवहार करे और मैं दिनांक से वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करूँगा:—

1. मैं परिवीक्षा, अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूँगा;
2. मैं किशोर न्याय बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना किशोर/किशोरी को उक्त न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर नहीं ले जाऊँगा;
3. मैं उक्त किशोर/किशोरी को प्रतिदिन विद्यालय/उक्त बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित व्यवसाय के लिए भेजूँगा, वशर्त मेरे नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हो जाऊँ;
4. मैं उक्त किशोर/किशोरी को नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र पर भेजूँगा बशर्ते मेरे नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हो जाऊँ;
5. जब कभी बोर्ड द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाएगी मैं तुरन्त उसे रिपोर्ट करूँगा;
6. यदि मेरी देखरेख में रखे गए किशोर/किशोरी ने बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं किया या उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया तो मैं उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करूँगा;
7. मैं परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता को अपना पर्यवेक्षकीय दायित्व निभाने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करूँगा;
8. मैं वचन देता हूँ कि उपर्युक्त शर्तों के पालन में मुझसे कोई चूक हो जाने पर मैं, यथास्थिति, उपर्युक्त कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने या सरकार को रूपये (अंकों में) (..... रूपये) (शब्दों में) अदा करने के लिए आबद्ध करता हूँ।

दिनांक (माह) 20 (वर्ष)।

वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

मेरे समझ हस्ताक्षर किया गया

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

यदि किशोर न्याय बोर्ड कोई अतिरिक्त शर्त/शर्तें जोड़ना चाहे तो उसे/उन्हें समुचित संख्यांक देते हुए जोड़ा जा सकेगा।

(जहाँ प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित नहीं किया जाता हो, वहाँ निम्नलिखित जोड़े)

मैं/हम निवासी (निवासी)

स्थान का पूरा पता) इस वचनबंध/बंधपत्र की शर्तों के पालन हेतु उक्त
 (वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) के लिए स्वयं को एतद् द्वारा प्रतिभूति करता हूँ/करते हैं। यदि इन शर्तों के पालन में (वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) से कोई चूक होती है तो मैं/हम संयुक्त रूप से अथवा अलग—अलग सरकार को रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में) अदा करूँगा/करेंगे। की उपस्थिति में
 दिनांक (माह) 20 (वर्ष) को निष्पादित।

प्रतिमूल्यतिभूतानुसार हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षरकिया गया)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र-VI
‰u; e 15 ½r‰k fu; e 92 ½%
किशोर/बालक द्वारा मुचलका

उस किशोर/बालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला मुचलका जिसे अधिनियम की धारा
की उपधारा के खंड के अधीन आदेश दिया गया हो

चूँकि, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा
के अधीन किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समितिद्वारा मुझे
..... निवासी (पूरा ब्यौरा दें यथा मकान नं० संडक,
गाँव/शहर, तहसील, जिला, राज्य को अपने मूल निवास स्थान पर वापस भेज दिया गया है/प्रत्यावर्तित
कर दिया गया है और इस नियमावली के नियम उपनियम तथा
नियम के उपनियम के अधीन मुचलका भरने पर मुझे इसमें नीचे दी गई शर्तों का
पालन करना है। इसलिए, अब मैं सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि
अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा।

मैं एतद् द्वारा स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ:

1. अवधि के दौरान मैं सामान्यतः उस गाँव/शहर/जिला को छोड़कर कहीं नहीं
जाऊँगा, जहाँ मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड/समिति की पूर्वानुमति के बिना न तो
लौटूँगा और न ही उक्त जिला से बाहर कहीं जाऊँगा;
2. उक्त अवधि के दौरान उस गाँव/शहर में अथवा उक्त जिला में जहाँ मुझे भेजा जा रहा है,
स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लूँगा।
3. उक्त जिला में किसी अन्य स्थान पर स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लेने की स्थिति में, मैं
बोर्ड/समिति को अपने सामान्य निवास स्थान से अवगत रखूँगा।

मैं एतद् द्वारा यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मैं उपर्युक्त शर्तों, जो मुझे पढ़कर सुनाया/समझाया गया है,
से अवगत हूँ और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

‰d'‰j@clyd dk gLrk‰j@vaxB dk fu '‰u%

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्ते
(किशोर या किशोरी/बालक का नाम) को पढ़कर सुना या समझा दी गई है तथा उसने उन्हें ऐसी शर्तों के
रूप में स्वीकार किया है, जिन पर उसकी सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि रद्द की जा सकती है।

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त किशोर या किशोरी/बालक को
.....(दिनांक) को छोड़/रिहा कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी
अर्थात् संस्था के प्रमारी अधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र-VII
॥१॥ e 17 dk mi fu; e ९॥
उन्मोचन आदेश

मैं (उन्मोचन प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम
 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस आदेश के
 द्वारा पुत्र/पुत्री निवासी
 प्रोफाईल संख्या जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के
 अधीन (माह) 20 (वर्ष) को अवधि के लिए
 संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/उत्तर रक्षा गृह में निरुद्ध करने/रखने का आदेश दिया गया था और जिसे अब
 दिनांक को उक्त गृह से उन्मोचित किए जाने तथा उसके
 निवास की शेष अवधि के दौरान उसे के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रखे जाने
 की अनुमति देता हूँ।

यह आदेश आगे दर्शाई गई शर्तों के अध्यधीन दिया गया है और इनमें से किसी भी शर्त को भंग
 किए जाने की स्थिति में यह रद्द किये जाने योग्य होगा।

**उन्मोचन प्राधिकारी
 के हस्ताक्षर व पदनाम**

दिनांक:—

स्थान:—

शर्त

1. उन्मोचित व्यक्ति निरुद्ध किए जाने की अवधि के समाप्त होने तक, यदि यह माफी उससे
 पूर्व ही रद्द न की गई हो, में जाकर
 के पर्यवेक्षण एवं प्राधिकार में रहेगा/रहेगी।
2. वह की सहमति के बिना उस स्थान या उक्त
 द्वारा बताए गए किसी अन्य स्थान से कहीं नहीं
 जाएगा/जाएगी।
3. वह स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर या अन्यथा कहीं समयनिष्ठ और नियमित
 उपस्थिति के संबंध में उक्त के अनुदेशों का पालन
 करेगा/करेगी।
4. वह स्थित उपस्थिति केंद्र में नियमित रूप से उपस्थित
 होगा/होगी।
5. वह कोई भी अपराध करने से बचेगा/बचेगी और के लिए
 समाधान परक दंग से सीधा—सादा एवं परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा/करेगी।
6. उसके द्वारा किसी भी उपर्युक्त शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में एतद्द्वारा निरोध की
 अवधि की दी गई माफी रद्द किए जाने योग्य होगी और माफी रद्द किए जाने पर
 उसके साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 59
 की उप धारा (3) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

मैं एतद् द्वारा यह अभिस्वीकार करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त शर्तों से अवगत हूँ जो मुझे
 पढ़कर सुनाई/समझाई गई हैं और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

**उन्मोचित किशोर/किशोरी
 के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ॥**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्त
 (किशोर या किशोरी/बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई/समझाई गई है तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों
 के रूप में स्वीकार किया है जिनके आधार पर उसके निरोध की अवधि को रद्द किया जा सकेगा।

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त किशोर या किशोरी/बालक को
 को उन्मोचित किया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी
 अर्थात् संस्था के प्रभारी अधिकारी
 के हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र-VIII

[नियम 27 (18)]

पर्यवेक्षण आदेश

जब बच्चे को उसके माता—पिता, संरक्षक या किसी अन्य उपर्युक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए

20 _____ का मामला संख्या _____

चूँकि, आज के दिन यह पाया गया है कि _____ (बालक का नाम) को देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है तथा _____ (नाम), पता

तथा उक्त _____ (नाम) द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर उसकी देखरेख एवं पर्यवेक्षण में रखा गया और समिति का समाधान हो गया है कि उसे पर्यवेक्षण में रखने का आदेश पारित करने से उक्त बालक के साथ व्यवहार करना समीचीन है।

इसलिए, एतदद्वारा उक्त बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन _____ अवधि के लिए _____ (नाम) निवासी _____ (पता) के पर्यवेक्षण में रखा

जाएः

1. जब कभी बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाए, आदेश तथा _____ द्वारा निष्पादित बंधपत्र, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. बालक को उपर्युक्त माता—पिता/संरक्षक/उपर्युक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।
3. बालक _____ अवधि के लिए _____ पर निवास करेगा।
4. बालक को समिति की अनुमति के बिना _____ के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5. बालक नियमित रूप से विद्यालय जाएगा/ईमानदारी से आजीविका कमाने का प्रयास करेगा।
6. जिस व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखा जाएगा, वह उक्त बालक की समुचित देखरेख, शिक्षा व कल्याण की व्यवस्था करेगा।
7. बालक को अवांछनीय तत्वों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे कानून का उल्लंघन करने से रोका जाएगा।
8. बालक को नशीली औषधियों अथवा नशीले पदार्थ लेने या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।
9. उपर्युक्त शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाएगा।

दिनांक _____ (माह) 20 _____ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति।

अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों, बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेंगी।

प्रपत्र-IX

[नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2)]

माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो,

द्वारा वचनबंध

मैं _____ निवासी, मो नं० _____ गली _____ गाँव/शहर
 _____ जिला _____ राज्य _____ एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि
 मैं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति _____ के आदेशों के अनुसार _____
 (बालक का नाम) आयु _____ की देखरेख का दायित्व संभालने का इच्छुक हूँ :

- (i) यदि उसका आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं तत्काल समिति को सूचित करूँगा।
- (ii) जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूँगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूँगा।
- (iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी।
- (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक/बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।

_____ (दिनांक) _____ (माह) 20 _____ (वर्ष)

हस्ताक्षर

गवाह (गवाहों) के हस्ताक्षर और पता

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-X

[नियम 27 (19)]

जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेश

बालक का नाम	:
लिंग	:
आयु	:
पिता का नाम	:
माता का नाम	:
पता	:
संगठन/संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीख	:
प्रस्तुत करने वाला	:

इस आदेश द्वारा आपको यह प्राधिकार व निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (1) के अधीन आश्रय गृह/बाल गृह में रखें।

अगली तारीख :

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-XI

[नियम 27 का उप-नियम (20)]

किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेश

प्रभारी अधिकारी

चुंकि _____ (दिनांक) _____ (माह) 20 _____ (वर्ष) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (4) के अधीन देखरेख व संरक्षण में रह रहे _____ (बालक का नाम), पुत्र/पुत्री _____ आयु _____ निवासी _____ को _____ अवधि के लिए बाल गृह/आश्रय गृह _____ में रखे जाने का आदेश बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गया है।

एतदद्वारा आपको यह प्राधिकार दिया जाता है तथा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त आदेश के विधिवत् कार्यान्वयन हेतु उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे बाल गृह/आश्रय गृह में रखें।

मेरे हस्ताक्षर एवं बाल कल्याण समिति की मुहर से दिया गया।

_____ (दिनांक) _____ (माह) 20 _____ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक :

आदेशों की प्रतियां, गृह और पूर्व रिकॉर्ड की विशिष्टियां, मामले का इतिवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, जो भी लागू हो :

प्रपत्र-XII

[नियम 28 (1)]

जाँच आदेश

सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी/स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्ता/मामला

विशिष्ट कार्यकर्ता

चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _____ के अधीन इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए _____ (बालक का नाम), आयु (लगभग) _____ वर्ष, पुत्र/पुत्री _____, निवासी _____ के संबंध में _____ से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _____ के अधीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इसलिए आपको एतदद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि आप उक्त बालक की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि की जाँच करके अपनी जाँच रिपोर्ट _____ को या उससे पहले अथवा इस समिति द्वारा अनुज्ञेय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

आपको एतदद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि आप, यदि आवश्यक हो तो, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, उपचार या परामर्श के किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर उनकी राय जाने तथा अपनी जाँच रिपोर्ट के साथ ऐसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

आपको एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त किशोर के चरित्र एवं सामाजिक पूर्ववृत्त की जाँच करें और अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तारीख _____ को या उससे पहले अथवा बोर्ड/समिति द्वारा अनुज्ञेय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

_____ (दिनांक) _____ (माह) 20 _____ (वर्ष)

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य

बाल कल्याण समिति

मुहर :

प्रपत्र-XIII

[नियम 28 (3); 33 (3) (ज) (ii); और 33(4) (च); 80 (1) (क) और (2)]

जांच-रिपोर्ट का प्रपत्र

क्रम संख्या _____

बाल कल्याण समिति _____ (पता) के समक्ष प्रस्तुत।

मामला संख्या

संबद्ध सरकारी विभाग / स्वैच्छिक संगठन

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की कोटि :

नाम

धर्म :

पिता का नाम

जाति :

स्थायी पता

जन्म का वर्ष :

अंतिम निवास का पता :

आयु :

लिंग:

पिछली संस्थागत / मामले का इतिवृत्त और व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो

परिवार

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यवसाय	मासिक आय	विकलांगता	अन्य कोई व्यौरा यथा सामाजिक आदतें
पिता								
सौतेला पिता								
माता								
सौतेली माता								
सहोदर भाई—बहन								
अन्य कोई विधिक संरक्षक / नातेदार								

यदि विवाहित हो तो सुसंगत विशिष्टियां

अन्य इच्छुक

नजदीकी रिश्तेदार या एजेंसी

धर्म तथा

गृह की सामान्य एवं नैतिक संहिता इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण _____

सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति _____

परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकॉर्ड

मौजूदा जीवन दशा _____

माता—पिता / माता—पिता एवं बालकों, विशेषकर उक्त बालक के साथ संबंध _____

अन्य कोई महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो,

बच्चे का पूर्ववृत्त

मानसिक स्थिति

(मौजूदा एवं विगत) _____ शारीरिक

स्थिति

(मौजूदा एवं विगत) _____

आदतें एवं रुचियां

(नैतिक, मनोरंजनात्मक इत्यादि) _____

चरित्र एवं व्यक्तित्व की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं _____

साथी एवं उनके प्रभाव _____

बिना अनुमति के गृह से बाहर रहने का मामला, यदि कोई हो _____

विद्यालय (विद्यालय, अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति बालक का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण)

कामकाज का रिकॉर्ड (किए गए कार्य, छोड़ने के कारण, व्यवसाय संबंधी अभिरुचि, कार्य अथवा नियोक्ताओं के प्रति दृष्टिकोण)

पास-पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट _____

घर में अनुशासन बनाए रखने के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया

कोई अन्य अभ्युक्ति _____

जाँच के परिणाम

भावनात्मक कारक :

भौतिक परिस्थितियां :

बौद्धिक क्षमता :

सामाजिक एवं आर्थिक कारक :

धार्मिक कारक :

बालक के देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद होने के कारण :

परामर्शित विशेषज्ञों की राय :

बालक को प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के संबंध में बाल कल्याण अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना।

बाल कल्याण अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र-XIV

[नियम 33 (3) (घ)]

बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेश

1. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा _____ की उपधारा _____ तथा इस नियमावली के नियम _____ के उप-नियम _____ के अधीन गठित बाल कल्याण समिति _____ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति _____ के _____ (दिनांक) के आदेश _____ के द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी _____ (नाम व पता) की अभिरक्षा में रखे गए _____ (दिनांक) को जन्मे _____ अवयस्क को आगे दिए गए ब्यौरे के आधार पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से योग्य घोषित किया गया है:

- (क) बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता द्वारा की गई जाँच/पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन
- (ख) माता-पिता द्वारा निष्पादित अभ्यर्थण के दस्तावेज और इस नियमावली के नियम-21 के उपनियम-12 (ड.) और (ग) के अधीन समितियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित अभ्यर्थण विलेख
- (ग) इस नियमावली के नियम-21 के उपनियम-11 (छ) (iii) के अधीन विशेष दत्तक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा।

2. _____ (विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा तत्संबंधी नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करेगा और इस अवयस्क के संबंध में समिति एवं _____ राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा यथापेक्षित दत्तक ग्रहण डिक्री/संरक्षकता आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

दिनांक :

स्थान :

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा संपन्न किए जाने के लिए।

(i) मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अध्याय-III एवं IV तथा तदधीन नियमों को पढ़ एवं समझ लिया है और मैं उक्त अवयस्क का दत्तक ग्रहण कराते समय इन उपबंधों से आबद्ध होने/पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(ii) मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक _____ को प्रस्तुत घोषणा में उल्लिखित ब्यौरा सत्य एवं सही है। यदि वे असत्य अथवा गलत पाए जाते हैं तो समिति को यह अधिकार है कि वह _____ (अवयस्क का नाम) के रिहाई आदेश को निलंबित कर उक्त अवयस्क को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने को कहे।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता

दिनांक:

स्थान:

प्रपत्र-XV
[नियम 33 (4) (ग)]
अभ्यर्पण विलेख

मैं _____ पुत्र अथवा पुत्री _____ निवासी
_____ सामाजिक कारणों
से/एकल/बीमार/निःशक्त होने के कारण लगभग _____ वर्ष के अपने बालक (नाम, यदि
कोई हो) _____ की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे बाल
कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम) _____ तथा बाल कल्याण
समिति द्वारा मेरे बच्चे के अभ्यर्पण के परिणामों के बारे में बताया गया है। इन
सभी तथ्यों को पूरी तरह जानते हुए, मैं आज, दिनांक _____ को समिति के समक्ष अपने बच्चे
को अभ्यर्पित कर रहा/रही हूँ। उक्त तिथि से दो माह के भीतर यदि मैं अपने बच्चे को वापस लेने के अपने निर्णय का
पुनरीक्षण नहीं करता/करती हूँ तथा इसके लिए उक्त समिति से संपर्क नहीं करता/करती हूँ, तो समिति मेरे बच्चे को
दत्तक ग्रहण हेतु वैध होने की घोषणा करेगी तथा आगे मेरा अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।

माता—पिता/संरक्षक का हस्ताक्षर
दिनांक

मैंने _____ बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता ने
दिनांक _____ को संबंधित माता—पिता/संरक्षक को बच्चे के अभ्यर्पण की प्रक्रिया
तथा परिणामों से अवगत करा दिया है।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर
दिनांक

(मेरे समक्ष हस्ताक्षरित)
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र-XVI

[नियम 35 (3)]

(क) पालन—पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन

1. एजेंसी का ब्यौरा

एजेंसी का नाम

पता

टेलीफोन नं०

फैक्स

ई—मेल

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम

टेलीफोन नं०

तारीख _____ (प्रपत्र भरने की)

2. आवेदक का ब्यौरा

उपनाम

पूरा नाम

जन्म तिथि

धर्म

घर पर बोली जाने वाली भाषा/भाषाएँ

व्यवसाय

कार्य की प्रकृति

कार्य के घण्टे

पता

टेलीफोन नं०

3. पसन्द किए गए बालक का ब्यौरा

देखभालकर्ता किस प्रकार के बालक के पालन—पोषण पर विचार करेगा।

(देखभालकर्ता के साथ पूर्ण विचार—विमर्श के पश्चात् भरा जाए)

आयु वर्ग	2 वर्ष से कम आयु 3–6 वर्ष	7–12 वर्ष	13–15 वर्ष	16–18 वर्ष
कम से०	स्थापना का प्रकार			अवधि
(i)	दत्तक ग्रहण—पूर्व			
(ii)	आपातकालीन			
(iii)	अल्प—अवधि			
(iv)	मूल्यांकन			
(v)	दीर्घ—अवधि			

आवेदक किस बालक की देखभाल कर सकता है (कृपया चिन्हित करें)

वह बालक जो:

- (i) उपेक्षित है
- (ii) अनाथ है
- (iii) शारीरिक रूप से निःशक्त है
- (iv) मानसिक रूप से निःशक्त है
- (v) बधिर है
- (vi) मूक है
- (vii) विशेष शिक्षा का जरूरतमंद है
- (viii) सीखने में कठिनाई है
- (ix) शारीरिक रूप से उत्पीड़ित है
- (x) यौन उत्पीड़न का शिकार है
- (xi) जो आसानी से दूसरों से संबंध स्थापित नहीं करता
- (xii) जिसे नियंत्रण की जरूरत है/जो प्राधिकारी की अवज्ञा कर सकता है।

- (xiii) बलात्कार / कौटुंबिक व्याभिचार से उत्पन्न बालक
- (xiv) जिसके माता—पिता रोग से पीड़ित हैं
- (xv) जिसके माता—पिता एच०आई०वी० पॉजिटिव के शिकार हैं
- (xvi) जिसके माता—पिता एड्स रोग के रोगी हैं
- (xvii) जिसके माता—पिता शराबी हैं
- (xviii) नशीली दवाओं के आदी हैं
- (xix) कारागार में हैं
- (xx) त्यागे हुए बच्चे
- (xxi) दूसरी जाति के हैं
- (xxii) भिन्न धर्म के हैं

4. परिवार की संक्षिप्त रूपरेखा

नाम	लिंग	लगभग आयु	व्यवसाय	शिक्षा	आवेदक से संबंध

(व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, अनुभव आदि का व्यौरा दें। परिवार के ऐसे विशिष्ट गुणों को भी उजागर करें, जो बालक की आवश्यकताओं से मेल खाते हों। व्यौरे ऐसे होने चाहिए जिससे विनिर्दिष्ट बालक के साथ संभागित मिलान कर प्रारंभिक पहचान करने में सहूलियत हो)

आवास (घर)

प्रकार, आकार, अपना / किराए का स्थान, सुविधाओं आदि का व्यौरा
पास—पड़ोस

संरचना, सुख—सुविधाएँ, सार्वजनिक यातायात के साधन आदि का व्यौरा

5. आवेदक की पहचान का सत्यापन

निवास स्थान

निवास की अवधि

राष्ट्रीयता

वैवाहिक स्थिति

(विवाह की तारीख / विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं)

क्या आवेदक में से कोई पूर्व में विवाह किया है? व्यौरा दें

यदि पूर्व के विवाह से बच्चे हैं तो उनका व्यौरा;

देखे गए दस्तावेज तथा उन्हें देखने की तारीख विनिर्दिष्ट करें;

6. आजीविका का इतिवृत्त

शिक्षा, रोजगार, स्वैच्छिक कार्य, अंशकालीन कार्य, अवकाश क्रियाकलाप का व्यौरा

7. एजेंसी की जाँच :

चिकित्सा जाँच

पुलिस जाँच

नियोक्ता

8. व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से)

दो संदर्भ व्यक्तियों के साक्षात्कार के पश्चात् यह खण्ड भरा जाए और इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए :

- कितने समय से जानते हैं
- आवेदक से संबंध
- _____ में संलग्न कार्यों को निष्पादित करने की आवेदक की योग्यता का साक्ष्य दें
बालकों की देखरेख
- सुरक्षित एवं देखरेख वाला वातावरण प्रदान करना
- पड़ोसी के रूप में आवेदक
- अभिरुचि, प्रतिभा, व्यक्तित्व
- सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इन संदर्भों का मूल्यांकन

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट

उपर्युक्त प्रपत्र में एकत्रित सूचना के आधार पर विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पालन-पोषण देखरेखकर्ता(ओं) की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट में व्यापक रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

- सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि
- घर का विवरण
- जीवन स्तर, जैसा कि घर में हो
- घर के सदस्यों के बीच वर्तमान में संबंध
- पहले से घर में मौजूद बालकों के विकास की स्थिति
- रोजगार तथा आर्थिक स्थिति
- स्वास्थ्य का ब्यौरा
- आस-पड़ोस में उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सुविधाओं का ब्यौरा
- पालन-पोषण देखभाल हेतु किसी बालक को चाहने के कारण
- दादा-दादी तथा अन्य संबंधियों का दृष्टिकोण
- पोष्य बालक के लिए प्रत्याशित योजना
- पालन-पोषण देखरेखकर्ता(ओं) की विधिक स्थिति
- प्रशिक्षण लेने की रजामंदी

(ग) आवेदक (आवेदकों) का ब्यौरा

1. **पृष्ठीयमि |—माता-पिता तथा सहोदर भाई—बहनों के ब्यौरे के साथ पारिवारिक संरचना, परिवार के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण ब्यौरा, बचपन से संबंधित अनुभव आदि**

2. **संबंध |—यदि दम्पति है—तो वैवाहिक जीवन की अवधि, सहभागिता रखने में प्रत्येक आवेदक की क्या—क्या गुणवत्ताएँ हैं, कौन सी बात एक—दूसरे के लिए सकारात्मक संबंध बनाता है? संबंध बनाए रखने में आवेदक समस्याओं/तनाव/क्रोध का सामना किस प्रकार करता है? आवेदक किस तरह एक—दूसरे की सहायता करते हैं? पालन-पोषण के लिए दिए जाने पर उनका संबंध किस प्रकार प्रभावित होगा, इस बारे में प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन क्या है?**

3. **विनिश्चय करना |—इस संबंध में किस तरह से निर्णय लिया जाता है तथा हरेक आवेदक का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या दम्पति के निर्णय लने की प्रक्रिया में परिवार की व्यापक भागीदारी होती है? यदि हां, तो यह दिए जाने वाले बालक को किस तरह से प्रभावित करेगा?**

इस भागीदारी की मजबूती और कमजोरियाँ क्या हैं?

- बच्चे
- बच्चे और उनके माता-पिता के बीच संबंध
- किसी सहोदर भाई—बहन के पालन—पोषण स्थापन हेतु बच्चों के दृष्टिकोण एवं तत्परता, प्रत्येक बालक और उनके स्वभाव, किसी विशेष प्रतिभा एवं आवश्यकता का वर्णन करें, बालक इस तैयारी आदि में कैसे शामिल किए गए।

4. **आवेदकों की सहायता का नेटवर्क |—आवेदकों द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त समर्थन प्रणालियों का एक सामान्य ब्यौरा दें, जिसमें स्थल के ब्यौरे सहित परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, धार्मिक क्रियाकलापों, सामुदायिक समूहों आदि का विस्तृत ब्यौरा हो।**

5. **परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य |—घर में अथवा घर से बाहर रहने वाले हों। आवेदकों के साथ उनका संबंध, वे कितना समय घर में व्यतीत करते हैं, प्रस्तावित स्थापन के बारे में उनका दृष्टिकोण, स्थापन के लिए उनकी स्वीकारोक्ति आवेदक हेतु कितनी महत्वपूर्ण है?**

6. **परिवार की जीवन शैली का वर्णन |—परिवार किसे महत्वपूर्ण समझता है, उदाहरणार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार कितने महत्वपूर्ण हैं, रूपरेखा दें। परिवार में किस तरह की अनुरक्ति है? सदस्य कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? व्यक्तिगत स्थान के बारे में परिवार के सदस्यों की क्या अपेक्षाएँ हैं? शिक्षा/शैक्ष तथा अवकाश क्रियाकलाप पर पूरे परिवार की सहमति को कितना महत्व दिया जाता है?**

7. पालन–पोषण की क्षमताएँ ।—आवेदकों का बालकों की देखभाल एवं उनके साथ कार्य करने संबंधी अनुभव। माता–पिता के साथ उनके सामंजस्य का वर्णन करें। बच्चों का विकास कैसे होता है इस बारे में उनकी समझ क्या है?

बचपन के अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए वे पालन–पोषण का कौन सा पैटर्न दोहराएंगे तथा वे क्या परिवर्तन करेंगे? व्यक्ति विशेष बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खुद के पालन–पोषण शक्तियों/क्षमताओं के बारे में तथा पालन–पोषण की अपनी कुशलता के बारे में उनकी क्या समझ है। वे अपने बच्चों/दिए गए बच्चों के पालन पोषण में परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग की कितनी अपेक्षा करते हैं?

वे किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बालक उनके परिवार में तथा और अधिक व्यापक सहायता नेटवर्कों के भीतर शारीरिक यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहेगा?

8. अस्वीकार्य व्यवहार को संभालना ।—घर में क्या नियम हैं? आवेदक कैसे अनुमोदन/अननुमोदन दर्शाते हैं? वे कौन–कौन से अनुशासनात्मक उपाय करते हैं? दण्ड के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? उनके लिए, उनके बच्चों के लिए तथा उनके सहायता नेटवर्क के लिए कौन–कौन से मुद्रे और कठिनाईयों होंगी होंगी इसके संबंध में उनका अनुमान क्या है? वे बालकों के लिए भावी मुद्रों एवं कठिनाईयों का क्या पूर्वानुमान लगाते हैं? वे अपनी जीवन शैली में क्या–क्या परिवर्तन करने का पूर्वानुमान लगाते हैं?

9. समाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन ।—प्रपत्र के माध्यम से एकत्रित समस्त सूचना तथा पालन–पोषण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की क्षमता के बारे में इसकी महता का इसमें विश्लेषण होना चाहिए :

(बालकों से संबंधित तथा बालकों के साथ कार्य करने के संबंध में आवेदकों की कुशलता आवेदक एजेंसी तथा जन्म देने वाले माता–पिताओं के साथ कितनी अच्छी तरह से कार्य करेंगे? आवेदकों के सामर्थ्य तथा संसाधन क्या हैं तथा वो कौन सा क्षेत्र है जहां उन्हें कठिनाई महसूस हो सकती है? सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदकों के बीच असहमति का बिन्दु को भी यहां अभिलिखित किया जाना चाहिए)

10. बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिशें

(हस्ताक्षर)

प्रपत्र-XVII

[नियम 34 (1)]

*Ikkyu&ikkk I xalh nqkky LEKKu dk vlnsk**Jh _____ rEkk Jherh _____ vElok**I qJh _____ dk iq@iqh kule , oa irkk**ft l dh vk qyxHx _____ g\$ dksfdlh ifjolg
dh nqkyskrEkk I jikk dh t:jr g\$*

(पता) *I xBu ds cly dV;kk vf/kdjk@I lekt d dk ZdrkZ
I qJh@Jh ----- dh xg v';u fjiWZ ds vkkj ij Jh ----- vif
Jherh ----- ;k I qJh ----- fuokl h -----
yjkirk vif I EkdZI 0% dksikyu ikkk I xalh nqkky LEKKu dsfy, mi; qDr QfDr ?kkkr fd;k
tkrkg\$*

उपर्युक्त _____ (नाम तथा सम्पर्क सं0) बाल कल्याण

अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में _____ (दिनों / मासों) की अवधि के

लिए बालक (नाम) _____ का पालन-पोषण देखभाल गृह में स्थापन किया जाता है।

*v'; qk@InL;**cly dV;kk I sefr*

प्रपत्र—XVIII

[नियम 43 (5)]

IIk ht d dsLEMi u dk vknsh

श्री _____ तथा श्रीमती _____ अथवा सुश्री
 _____ का/की पुत्र अथवा पुत्री _____ किषोर/बालक (नाम एवं पता)
 जिसकी आयु लगभग _____ है, को राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तत्काल देखभाल और संरक्षण के
 जरूरतमंद जोखिम में रह रहे किषोर/बालक के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य/जिला बाल संरक्षण
 इकाई/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि
 उक्त किषोर/बालक को षिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों _____ (कृपया
 विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत है। उक्त किषोर/बालक को अवधि (दिवस/मासों) के लिए
 _____ रूपये प्रतिमाह और एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में तथा आवधक अनुवर्ती कार्रवाई
 के लिए _____ (रूपये) निर्मुक्त करने के लिए राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को
 एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को यह निदेश भी दिया जाता है कि प्रायोजक सहायता तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु
 निबंधन एवं शर्त स्पष्टतः विनिर्धारित करें।

मुख्य मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रति:

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्रपत्र-XIX

[नियम 44 (4)]

उत्तरक्षण स्थापन का आदेश

किशोर/बालक (नाम) _____ पुत्र अथवा पुत्री तारीख _____

_____ को 18 वर्ष की आयु का हो गया है/होने जा रहा है। उसे पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण के प्रयोजनार्थ अभी भी देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है। उसे पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए _____ (संगठन का नाम) में रखा जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि वह बालक को स्वीकार करे तथा उसे पुनर्वास और सही अर्थों में उसके पुनः एकीकरण के लिए सभी संभव अवसर प्रदान करे। इस व्यक्ति को अधिकतम 21 वर्ष की आयु होने तक ही अथवा समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने तक, जो भी पहले, हो, ये सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे। संगठन का प्रभारी, बाल कल्याण समिति को बालक/युवक की स्थिति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि _____ (दिन/मास) अवधि तक उक्त किशोर/बालक की पश्चातवर्ती देख-रेख की व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करें। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को यह भी निदेश दिया जाता है कि पश्चातवर्ती देख-रेख कार्यक्रम तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए निबंधनों और शर्तों का स्पष्टतः विनिर्धारण करें।

मुख्य मंजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रति: राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबद्ध विभाग

प्रपत्र-XX

[नियम 57 (8), 61 (1) (न)]

देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र

मामला/प्रोफाइल सं.

तारीख एवं समय

(क) व्यक्तिगत आंकड़े

1. नाम
2. पुरुष/महिला (उचित कोटि पर सही का निशान लगाएं)
3. (क) भर्ती के समय आयु
(ख) वर्तमान आयु
4. कोटि

- परिवार से अलग किया गया
- परित्यक्त/अभित्यक्त
- उत्पीड़न और हिंसा (ब्यौरा दें) का शिकार
- भागा हुआ
- कोई अन्य

5. धर्म हिन्दू (अन्य जाति/पिछड़ी जाति/अनु० जाति/अनु० जनजाति)
मुस्लिम/इसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निवास अवस्थिति शहरी/अर्द्धशहरी/ग्रामीण/मलिन बस्ती/
औद्योगिक क्षेत्र/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. मूल जिला और राज्य

8. आवास का विवरण:

- (i) पक्का भवन/खपरैल का मकान/झोपड़ी/गली में/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) तीन शयनकक्ष का/दो शयनकक्ष का/एक शयनकक्ष का/कोई पृथक शयन कक्ष नहीं
- (iii) अपना/किराए का

9. बाल कल्याण समिति के समक्ष किशोर किसके द्वारा लाया गया:

- (i) पुलिस—राजनीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/रेलवे पुलिस/महिला पुलिस
- (ii) परिवीक्षा अधिकारी
- (iii) समाज कल्याण संगठन
- (iv) सामाजिक कार्यकर्ता
- (v) माता—पिता/संरक्षक (संरक्षकों) (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट करें)
- (vi) बालक/बालिका स्वयं

10. परिवार छोड़ने के कारण:

- (i) माता—पिता / अभिभावक(कों) / सौतेले माता—पिता द्वारा दुर्व्यवहार
- (ii) रोजगार की खोज में
- (iii) मित्र मंडली का प्रभाव
- (iv) माता—पिता की असमर्थता
- (v) माता—पिता का आपराधिक व्यवहार
- (vi) माता—पिता का अलगाव
- (vii) माता—पिता का अलगाव
- (viii) गरीबी
- (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

11. बालक के प्रति किए गए दुरुपयोग के प्रकार:

- (i) मौखिक दुरुपयोग—माता—पिता / सहोदर भाई या बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) शारीरिक दुरुपयोग
- (iii) यौन दुराचार—माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iv) अन्य—माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

12. बालक के प्रति किए गए बुरा—बर्ताव के प्रकार:

- (i) भोजन न देना—माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) निर्दयतापूर्वक पीटा जाना— माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iii) चोट पहुंचाना—माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iv) अन्य— माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

13. बालक द्वारा झेला गया शोषण:

- (i) बिना वेतन दिए काम कराना
- (ii) अल्प (निम्न) मजदूरी देकर अधिक समय तक काम लेना
- (iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

14. प्रवेश होने से पूर्व बालक के स्वास्थ्य की स्थिति:

- (i) श्वसन संबंधी व्यतिक्रम— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (ii) बहरापन— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (iii) नेत्र रोग— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (iv) दन्त रोग— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (v) हृदय रोग— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (vi) चर्म रोग— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान
- (vii) यौन संक्रमित रोग— विद्यमान / अज्ञात / अविद्यमान

- (viii) तंत्रिका संबंधी रोग— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (ix) मानसिक विकलांगता— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (x) शारीरिक विकलांगता— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (xi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान

15. भर्ती होने से पूर्व बालक किसके साथ रहता था:

- (क) माता—पिता—माता/पिता/दोनों
- (ख) अभिभावक—नातेदार
- (ग) मित्र
- (घ) बेसहारा (गलियों में)
- (ङ) रात्रिकालीन आश्रय गृह
- (च) अनाथालय/होस्टल/इसी तरह के अन्य गृह
- (छ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

16. बालक से मिलने हेतु माता—पिता का आगमन:

- (क) संस्थागत किए जाने के पूर्व—
बार—बार/यदा—कदा/विरले/कभी नहीं
- (ख) संस्थागत किए जाने के बाद
बार—बार/यदा—कदा/विरले/कभी नहीं

17. बालक का अपने परिवार में जाना :

- (i) संस्थागत किए जाने के पूर्व—
बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
- (ii) संस्थागत किए जाने के बाद—
बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं

18. माता—पिता के साथ पत्र व्यवहार :

- (i) संस्थागत किए जाने के पूर्व—
बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
- (ii) संस्थागत किए जाने के बाद—
बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुटियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं

(ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक)

19. गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन :

- (क) पौष्टिक भोजन लिया गया
- (ख) सामान्य भोजन
- (ग) अपर्याप्त भोजन

20. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य :

- (क) मॉ संक्रामक रोग से संक्रमित हुई
- (ख) मां द्वारा गर्भ निरोधकों का सेवन/प्रयोग किया गया
- (ग) एंटीबायटिक (प्रतिजैविक) दवाओं का सेवन
- (घ) ऐसा कोई व्यौरा उपलब्ध नहीं

21. जन्म से संबंधित व्यौरा :

- (क) सामान्य प्रसव/दीर्घकालीन प्रसव/शल्य क्रिया द्वारा प्रसव
- (ख) कम वजन/सामान्य वजन/अधिक वजन

22. प्रतिरक्षण संबंधी व्यौरा :**23. निःशक्तता संबंधी व्यौरा :**

- (i) बहरापन – जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद
- (ii) गूंगापन – जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद
- (iii) शरीरिक निःशक्तता – जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद
- (iv) मानसिक निःशक्तता – जन्मजात/दुर्घटना/बीमारी के बाद
- (v) अन्य निःशक्तता (कृपया विवरित करें)

(ग) परिवार का व्यौरा :**24. घरेलू संरचना :**

क्र०सं०	नाम व संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय
1	2	3	4	5	6	7

स्वास्थ्य	मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत्त	निःशक्तता	आदत	समाजीकरण
8	9	10	11	12

25. परिवार का प्रकार:

एकल परिवार/संयुक्त परिवार/खंडित परिवार

26. परिवार के सदस्यों के बीच संबंध :

- (i) माता–पिता – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
- (ii) पिता–बालक – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
- (iii) माता–बालक – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
- (iv) पिता–सहोदर – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
- (v) माता–सहोदर – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात
- (vi) किशोर–सहोदर – सौहार्दपूर्ण/कटुतापूर्ण/अज्ञात

27. परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अपराध का पूर्ववृत्त :

क्र०सं०	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	गिरफ्तारी, यदि हुई हो	परिरोध की अवधि	दण्ड
1.	पिता				
2.	सौतेला पिता				
3.	माता				
4.	सौतेली माता				
5.	भाई (क) (ख) (ग) (घ)				
6	बहन (क) (ख) (ग) (घ)				
7.	बालक				
8.	अन्य (चाचा/दादा/दादी)				

परिवार

28. परिवार के नाम संपत्तियों का ब्यौरा :

- (i) भू—संपत्ति (कृपया क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) घरेलू सामग्री / संपत्ति (गायें / मवेशी / सांड)
- (iii) वाहन – दुपहिया / तिपहिया / चार पहिया (लॉरी / बस / कार / ट्रैक्टर / जीप)
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

29. परिवार के सदस्यों का वैवाहिक ब्यौरा :

- (i) माता—पिता – बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल—मिलाप
- (ii) भाई – बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल—मिलाप
- (iii) बहनें – बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल—मिलाप

30. परिवार के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियाँ :

- (i) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं
- (ii) सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं
- (iii) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते
- (iv) अज्ञात

31. भर्ती से पूर्व माता—पिता द्वारा किशोर की देखरेख :

- (i) अति संरक्षण
- (ii) स्नेहपूर्ण
- (iii) सतर्कतापूर्ण
- (iv) उपेक्षापूर्ण
- (v) सतर्कतारहित
- (vi) तिरस्कारपूर्वक

(घ) किशोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) :

32. (i) यौवनागम

- (ii) समय पूर्व
- (iii) मध्य आयु में
- (iv) विलम्ब से

33. अपचारी आचरण का व्यौरा, यदि कोई हो :

- (i) चोरी
- (ii) जेब कतरी करना
- (iii) ताड़ी बेचना
- (iv) नशीली दवाइयां बेचना
- (v) छोटे—छोटे अपराध
- (vi) हिंसक अपराध
- (vii) बलात्कार
- (viii) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

34. अपचारी आचरण के कारण :

- (i) माता—पिता द्वारा उपेक्षा
- (ii) माता—पिता द्वारा अति संरक्षण
- (iii) माता—पिता का आपराधिक व्यवहार

- (iv) माता—पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
- (v) संगी—साथियों का प्रभाव
- (vi) नशीली दवाइयां/शराब खरीदने के लिए
- (vii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

35. आदतें :

(क)	(ख)
(i) धूम्रपान	(i) टी०वी०/सिनेमा देखना
(ii) मद्यपान	(ii) इंडोर/आउटडोर खेल खेलना
(iii) नशीली दवाओं का सेवन करना (विनिर्दिष्ट करें)	(iii) पुस्तकें पढ़ना
(iv) जुआ खेलना	(iv) धार्मिक गतिविधियां
(v) शिक्षाटन करना	(v) आरेखन/रंगसाजी/अभिनय/गायन
(vi) कोई अन्य	(vi) कोई अन्य

(ड.) रोजगार का विवरण

गृह में आने से पूर्व किशोरों के रोजगार के ब्यौरे :

क्र.सं.	रोजगार के ब्यौरे	अवधि	कमाई गई मजदूरी
i.	कुली		
ii.	रद्दी (कबाड़) बीनना		
iii.	मैकेनिक		
iv.	होटल कार्य		
v.	चाय की दुकान में कार्य		
vi.	जूता पालिश		
vii.	घरेलू कार्य		
viii.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

36. आय की उपयोगिता के ब्यौरे :

- (i) परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु परिवार में भेजना
- (ii) कपड़े बनवाने के लिए
- (iii) जुआ खेलने के लिए
- (iv) वेश्यावृत्ति के लिए
- (v) शराब/नशे के लिए
- (vi) औषध के लिए
- (vii) धूम्रपान के लिए
- (viii) बचत के लिए

37. बचत के ब्यौरे:

- (i) नियोक्ता के पास
- (ii) मित्रों के पास
- (iii) बैंक / डाकघर में
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

38. कार्य करने की अवधि:

- (i) छ: घंटे से कम
- (ii) छ: से आठ घंटे के बीच
- (iii) आठ घंटे से अधिक

(च) शैक्षिक विवरण:**39. बाल गृह में भर्ती होने से पूर्व किशोर का शैक्षिक ब्यौरा:**

- (i) अशिक्षित
- (ii) पांचवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ
- (iii) पांचवीं कक्षा से अधिक परन्तु आठवीं से कम पढ़ा हुआ
- (iv) आठवीं कक्षा से अधिक परन्तु दसवीं से कम पढ़ा हुआ
- (v) दसवीं कक्षा से अधिक पढ़ा हुआ

40. विद्यालय छोड़ने का कारण:

- (i) अध्ययनरत अंतिम कक्षा में अनुतीर्ण होना
- (ii) विद्यालय के क्रियाकलाप में अभिरुचि की कमी
- (iii) शिक्षकों की उदासीन प्रवृत्ति
- (iv) संगी साथियों का प्रभाव
- (v) परिवार के लिए अर्जन करना तथा सहायता करना
- (vi) माता-पिता की अचानक मृत्यु
- (vii) विद्यालय का सख्त माहौल
- (viii) विद्यालय से अनुपस्थित रहना और फिर भाग जाना
- (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

41. उस विद्यालय का ब्यौरा जहाँ से अन्तिम अध्ययन किया:

- (i) निगम / नगर पालिका / पंचायत यूनियन
- (ii) सरकारी / अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय / पिछड़ी जाति कल्याण विद्यालय
- (iii) निजी प्रबंधन
- (iv) कान्वेंट

42. शिक्षा का माध्यम:

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड/तेलगू/अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

43. बाल गृह में प्रवेश के बाद आगमन की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षा:

वर्षों की संख्या	कक्षा, जिसमें अध्ययन किया	प्रोन्नत/रोक रखना
------------------	---------------------------	-------------------

44. बाल गृह में आगमन की तारीख से अब तक प्राप्त किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण:

वर्षों की संख्या	व्यावसायिक ट्रेड का नाम	प्राप्त प्रवीणता
------------------	-------------------------	------------------

45. बाल गृह में आगमन की तारीख से आज की तारीख तक विकसित पाठ्यक्रमेतर कार्यकलाप

- (i) स्काउट
- (ii) खेलकूद (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iii) व्यायाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iv) चित्रकला
- (v) पेटिंग
- (vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(छ) चिकित्सीय इतिवृत्तः**46. प्रवेश के समय लम्बाई और वजनः****47. शारीरिक स्थिति****48. बालक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)****49. माता-पिता/अभिभावक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)****50. बालक की वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति**

क्रमांक	वार्षिक प्रेक्षण	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
1	2	3	4	5	6
1	पुनर्विलोकन की तारीख				
2	लम्बाई				
3	वजन				
4	दिया गया पौष्टिक आहार				
5	तनावजनित बीमारी				
6	दंत रोग				
7	नाक, कान और गला-टांसिल				
8	बाह्य नेत्र समस्याएँ: बायीं ऑख्य दायीं ऑख्य				

51. लम्बाई और वजन का चार्ट:

तारीख, माह एवं वर्ष	लम्बाई	स्वीकार्य वजन	वास्तविक वजन

(ज) सामाजिक इतिवृत्तः

52. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व मित्रों का व्यौरा:

- (i) सहकर्मी
- (ii) विद्यालय के सहपाठी
- (iii) पड़ोसी
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

53. अधिकतर मित्रः

- (i) शिक्षित हैं
- (ii) अशिक्षित हैं
- (iii) हम उम्र हैं
- (iv) आयु में बड़े हैं
- (v) आयु में छोटे हैं
- (vi) उसी लिंग के हैं
- (vii) विपरित लिंग के हैं

54. समूह में सदस्यता का व्यौरा (कृपया सविस्तार विनिर्दिष्ट करें)

- (i) सिने प्रंशसक संगम से सहबद्ध हैं
- (ii) धार्मिक समूह से सहबद्ध हैं
- (iii) कला एवं खेलकूद कलब से सहबद्ध हैं
- (iv) गिरोहों से सहबद्ध हैं
- (v) रघुच्छक सामाजिक सेवा लीग से सहबद्ध हैं
- (vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

55. समूहों/लीग में बालक का स्थान

- (i) नेतृत्वकर्ता
- (ii) दोयम स्तरीय नेतृत्वकर्ता
- (iii) मध्यस्तरीय कार्यकर्ता
- (iv) सामान्य सदस्य

56. समूह की सदस्यता लेने का प्रयोजन:

- (i) सामाजिक सेवा कियाकलाप के लिए
- (ii) खाली समय व्यतीत करने के लिए
- (iii) सुखदायक कियाकलाप के लिए
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

57. समूह/लीग का दृष्टिकोण

- (i) सामाजिक मानदण्डों का सम्मान तथा नियमों का पालन करने वाला
- (ii) मानदण्डों के उल्लंघन करने में अभिरुचि
- (iii) नियमों के उल्लंघन करने में प्रेरक

58. समूहों की अवस्थिति/मिलने का स्थल

- (i) सामान्यतः नियत स्थान पर
- (ii) बार-बार स्थान परिवर्तित किए जाते हैं
- (iii) कोई विनिर्दिष्ट स्थान नहीं
- (iv) मिलने का स्थान सुविधानुसार नियत किया जाता है

59. बालक जब पहली बार परिवार से बाहर आया तब समाज की प्रतिक्रिया

- (i) समर्थनकारी
- (ii) तिरस्कार
- (iii) प्रताड़ना
- (iv) दुर्व्यवहारपूर्ण
- (v) शोषणपरक

60. बालकों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया

- (i) भावपूर्ण
- (ii) कूरतापूर्ण
- (iii) अपमानजनक
- (iv) शोषण का और
- (v) दुर्व्यवहारपूर्ण

61. बालक के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रिया**बालक का इतिवृत्त (संक्षेप में)**

- (i) शिक्षा
- (ii) स्वास्थ्य
- (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण
- (iv) पाठ्यक्रमेतर कार्यकलाप
- (v) अन्य

किशोर/बालक के अभिविन्यास के बाद तथा अभिविन्यास के प्रति बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का सुझाव प्रतिक्रिया।

बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई। प्रबंधन समिति द्वारा मामला विशिष्ट इतिवृत्त का तिमाही पुनर्विलोकन।

अधीक्षक/कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

(नियम 57(11)(क), 61(1)(ण), 80(1) (ट))

व्यक्तिगत देखरेख योजना

प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते समय देखरेख संबंधी विकल्पों को निम्नलिखित क्रम में प्राग्रता देने पर विचार किया जाएगा:

(i) जन्मदाता परिवार को बनाए रखना

(ii) बांधव्य देख-रेख

(iii) देशज दत्तक ग्रहण

(iv) पालन-पोषण देखरेख

(v) अन्तरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण

(vi) संस्थागत देखरेख

बोर्ड/समिति का वर्ष 20..... का मामला/प्रोफाइल सं0

प्रवेश संख्या

प्रवेश की तारीख

क. व्यक्तिगत ब्यौरे

1. बालक का नाम

2. आयु

3. लिंगः पुरुष/महिला

4. पिता/माता का नाम

5. राष्ट्रीयता

6. धर्म/जाति

7. शैक्षिक उपलब्धि

8. मामले के इतिवृत्त का सारांशः

- स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें
- भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी जरूरतें
- शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें
- अवकाश, रचनात्मकता तथा खेलकूद
- अनुरक्षित एवं नातेदारी
- धार्मिक विश्वास
- सभी प्रकार के उत्पीड़न, तिरस्कार एवं दुर्घटहार से संरक्षण
- समाज की मुख्य धारा में लाना
- बाल गृह से रिहा किए जाने/प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

भाग—1

1. परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर का नाम:
2. माह के
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या:
4. सक्षम प्राधिकारी:
5. प्रोफाईल संख्या:
6. बालक का नाम:
7. पर्यवेक्षण आदेश की तारीख:
8. बालक का पता:
9. पर्यवेक्षण की अवधि:

भाग—2

साक्षात्कार के स्थल

तारीख

.....
.....
.....

1. बालक कहाँ रह रहा है?
2. किसी शैक्षिक / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में की गई प्रगति
3. वह कौन सा काम कर रहा / रही है तथा यदि नियोजित हो तो उसका औसत मासिक आमदनी
4. डाकघर में रखी गई बचतें
5. उसके नाम से बचत बैंक खाता
6. उसके सामान्य आचरण एवं प्रगति पर टिप्पणी
7. क्या सम्पत्ति की देखभाल की गई है?

भाग—3

1. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही या:
 - (क) बंधपत्र की शर्तों में फेर-बदल
 - (ख) निवास स्थान में परिवर्तन
 - (ग) अन्य विषय
2. तारीख को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि
3. टिप्पणी यदि कोई हो, के साथ सहित पर्यवेक्षण का परिणाम
4. माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति का नाम एवं पता, जिसकी देख-रेख में किशोर को पर्यवेक्षण के बाद रहना है

रिपोर्ट की तारीख परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर के हस्ताक्षर

ग. निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट

जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ

अन्तिम निर्मुक्ति

--

स्थानान्तरण

--

1. स्थानान्तरण स्थान का व्यौरा तथा स्थानान्तरण/निर्मुक्ति के स्थान का उत्तरदायी सम्बद्ध प्राधिकारी
2. विभिन्न संस्थाओं में किशोर/बालक को भेजने संबंधी व्यौरे
3. लिया गया प्रशिक्षण एवं अर्जित कौशल
4. प्रभारी अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए)
5. निर्मुक्ति/स्थानान्तरण की तारीख
6. संप्रत्यावर्तन की तारीख
7. मार्गरक्षी की मांग, यदि अपेक्षित हो।
8. मार्गरक्षी की पहचान
9. संभावित स्थापन सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना
10. प्रायोजित किए जाने की अपेक्षा और रिपोर्ट, यदि लागू हो।
11. निर्मुक्ति के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन को चिन्हित करना
12. निर्मुक्ति के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित किए गए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन।
13. बालक की रिहाई के बाद उसको प्रायोजित करने वाली एजेंसी/व्यक्तिगत प्रायोजक, यदि कोई हो, को चिन्हित करना।
14. प्रायोजित करने वाली एजेंसी और व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन
15. बालक के बचत खाते का विस्तृत व्यौरा, यदि कोई हो
16. बालक की आमदनी तथा सामान, यदि कोई हो, का व्यौरा
17. बालक को मिले पुरस्कार का व्यौरा, यदि कोई हो
18. बालक की राय
19. कोई अन्य सूचना

टिप्पणी:- निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट किशोर/बालक की निर्मुक्ति/स्थानान्तरण की तारीख से 6 माह पूर्व तैयार की जाएगी तथा अंतिम पुनर्विलोकन रिपोर्ट की सिफारिशों और अन्य सभी सुसंगत जानकारी में उस पर ध्यान दिया जाएगा

घ. निर्मुक्ति पश्चात रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति: बन्द/अंतरित
2. बालक की आमदनी तथा सामान बालक को दिया गया या उसके माता-पिता/अभिभावकों को -हाँ/नहीं
3. निर्मुक्ति के बाद बालक के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित करने गए परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रथम विचार-विमर्श की रिपोर्ट
4. किशोर/बालक का स्थापन, यदि कोई हो
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार
6. बालक का सामाजिक वातावरण, खास तौर पर पड़ोसियों/समुदाय का दृष्टिकोण
7. बालक अर्जित कौशलों का किस प्रकार उपयोग कर रहा है ?
8. क्या बालक को किसी विद्यालय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया है? विद्यालय/संस्थान/किसी अन्य एजेंसी का नाम एवं भर्ती की तारीख दें।
9. दूसरी व तीसरी अनुवर्ती रिपोर्ट-क्रमशः दो माह और छः माह के बाद बालक से दूसरी एवं तीसरी अनुवर्ती बातचीत की रिपोर्ट।

प्रपत्र-XXII

(नियम 73(2))

मार्गरक्षण आदेश

मामला संख्या

बालक/बालिका के मामले में

उपर लगभग वर्ष को
 किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की
 धारा 33(3) के अधीन एकमात्र अभिरक्षा के लिए
 प्रभार में लिया गया/ली गई।

बालक/बालिका के माता-पिता के स्थान पर रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः समुचित पुलिस/गैर सरकारी संगठन मार्गरक्षण में अधीक्षण के अधीन बालक/बालिका को (स्थान) पर भेजा जाए। उपर्युक्त बालक/बालिका के माता-पिता या निकट नातेदारों का पता लगाने हेतु तथा बालक/बालिका को उन्हें सौंपने के लिए बालक/बालिका द्वारा दर्शाए गए उनके निवास स्थान के पते पर पुलिस की उचित निगरानी/गैर सरकारी संगठन के मार्गरक्षण में उन्हें भेज दिया जाए। यदि माता-पिता या नातेदार का पता नहीं चलता हो या पता चल जाता हो लेकिन वे बालक/बालिका का प्रभार लेने के लिए अनिच्छुक हो तो बालक/बालिका को बाल गृह के अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जाए और अगले आदेश के लिए उक्त बालक/बालिका को संबद्ध बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

आदेश

मार्गरक्षण की व्यवस्था होने तक उक्त बालक/बालिका बाल गृह में रहेगी, जो वर्तमान में पते पर रह रहे हैं। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस विभाग या गैर सरकारी संगठन/चाइल्ड लाईन तुरंत इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों की अन्यून अवधि के भीतर निश्चित रूप से व्यवस्था करेगा तथा उपर्युक्त बालक/बालिका को उपर्युक्त निवास स्थान पर भेज देगा।

तारीख मास वर्ष

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षक, बाल गृह
2. राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/गैर सरकारी संगठन/चाइल्ड लाईन को प्रेषित।

सन्दर्भ:- 1. अवयस्क जन्म तिथि
 प्रोफाईल का भर्ती आदेश

19 नवम्बर 2015

सं0 10/प्र0गु0स्था0-17/2003-2140 दिनांक 19.11.2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस0 एम0 राजू,
 सरकार के सचिव।

The 19th November 2015
Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2015

सं010/प्र0गु0स्था0-17/2003-2140—In exercise of the power conferred by Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, (No. 56 of 2000) (as amended from time to time) the State Government of Bihar makes the following Rules:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called “The Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2015”.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.— (1) *In these rules, unless the context otherwise requires-*

- (a) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) (as amended from time to time);
- (b) "Abandoned" means an unaccompanied and deserted child who is declared abandoned by the Committee after due inquiry;
- (c) "Best interest of the child" means a decision taken to ensure the physical, emotional, intellectual, social, cultural and moral development of juvenile or child;
- (d) "Child abuse" means maltreatment which includes any of the following:-
 - (i) Physical, mental, sexual or emotional maltreatment;
 - (ii) Any act by word or deed which degrades the dignity of the child;
 - (iii) Deprivation of his basic needs for survival;
- (e) "Child friendly" means any process, interpretation, attitude, environment and treatment that is humane, considerate and in the best interest of the child;
- (f) "Community service" implies service rendered to the society by juveniles in conflict with law in lieu of or in addition to other judicial remedies and penalties, which is not degrading and dehumanizing; Examples of this may include (only non hazardous part);
 - (i) Cleaning a park/setting up of a garden;
 - (ii) Serving the elderly in nursing homes or Old Age Homes;
 - (iii) Helping out at a local hospital or nursing home;
 - (iv) Serving children with disabilities;
 - (v) Community care of elderly person;
 - (vi) Group work;
 - (vii) Getting involved with Habitat for Humanity;
- (g) "Detention" in case of juveniles in conflict with law means "protective custody" in line with the principles of restorative justice;
- (h) "Form" means the form annexed to these rules;
- (i) "Foster care" means the care and protection of a child in need of care and protection for a stipulated period by a foster parent as ordered by the Child Welfare Committee;
- (j) "Group Counseling" means an order under Section 16 of the Act by the Juvenile Justice Board for the participation of a juvenile in any group counseling programme organized by the State Government or by any recognized voluntary organisation;
- (k) "Individual care plan" is a comprehensive development plan for a juvenile or child based on age specific and gender specific needs and the case history of the juvenile or child, prepared in consultation with the juvenile's or child's self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following needs of a juvenile or a child:
 - (i) Health needs;
 - (ii) Emotional and psychological needs;
 - (iii) Educational and training needs;

- (iv) Leisure, creativity and play;
- (v) Attachments and relationships;
- (vi) Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
- (vii) Social mainstreaming; and
- (viii) Follow-up, post release and restoration.

(l) "Institution" means an Observation Home , a Special Home, a Children's Home or a Shelter Home set up, certified or recognized and registered under Sections 8, 9, 34, sub-Section (3) of Section 34 and Section 37 of the Act respectively;

(m) "Superintendent" means a person appointed for the control and management of the institution;

(n) "Orphan" means a child who is without parents or without a willing and capable legal or natural guardian;

(o) "Place of safety" means any institution set up and recognized under sub-Section (3) of Section 12 and sub-Section (1) of Section 16 of the Act for juvenile in conflict with law or children;

(p) "Fit person", "Fit institution" means a person found fit by the competent authority or, an institution found fit by the State Government on the recommendation of the competent authority as per clauses (h) and (i) of Section (2) of the Act. This shall be done on a case to case basis for a temporary period of time for that specific child. These institutions may be registered under any Act;

(q) "Registered" means all institutions or agencies or voluntary organizations providing residential care or any other care to children in need of care and protection registered under sub-Section (3) of Section 34;

(r) "State Government" means the Government of Bihar;

(s) "Street and working children" means children without ostensible means of livelihood, care, protection and support in accordance with the provisions laid down under clause (d) (1) of Section 2 of the Act;

(t) "Surrendered child" means a child, who in the opinion of the Committee, is relinquished on account of physical, emotional and social factors beyond the control of the parent or guardian;

(2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF JUVENILE JUSTICE AND PROTECTION OF CHILDREN

3. Fundamental principles to be followed in administration of these rules.— (1) The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee or other competent authorities or agencies, as the case may be, while implementing the provisions of these rules shall abide and be guided by the principles, specified in sub-rule (2).

(2) The following principles shall, *inter alia*, be fundamental to the application, interpretation and implementation of the Act and the rules made hereunder:

I. Principle of presumption of innocence.—

- (a) A juvenile or child or juvenile in conflict with law is presumed to be innocent of any mala fide or criminal intent up to the age of eighteen years.
- (b) Right to presumption of innocence of the juvenile or juvenile in conflict with law or the child shall be respected throughout the process of justice and protection, from the initial contact to alternative care, including aftercare.
- (c) Any unlawful conduct of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law which is done for survival, or is due to environmental or situational factors or is done under control of adults, or peer groups, is ought to be covered by the principles of innocence.
- (d) The basic components of presumption of innocence are:
 - (i) **Age of innocence.**- Age of innocence is the age below which a juvenile or child or a juvenile in conflict with law cannot be subjected to the criminal

justice system. The Beijing Rule (1) clearly lays down that “the beginning of the age of criminal responsibility shall not be fixed at too low an age level bearing in mind the facts of mental and intellectual maturity”. In consonance with this principle, the mental and intellectual maturity of juvenile or child or a juvenile in conflict with law below eighteen years is considered insufficient throughout the world.

- (ii) ***Procedural protection of innocence.***- All procedural safeguards that are guaranteed by the Constitution and other statutes to the adults and that go in to strengthen the juvenile's or child's right to presumption of innocence shall be guaranteed to juveniles or the children or juveniles in conflict with law.
- (iii) ***Provisions of Legal aid and Guardian Ad Litem.***- Juveniles in conflict with law have a right to be informed about the accusations against them and a right to be legally represented. Provisions must be made for guardian *ad litem*, legal aid and other such assistance through legal services at State expense. This shall also include such juvenile's right to present his case before the competent authority on his own.

II Principle of dignity and worth.—

- (a) Treatment that is consistent with the child's sense of dignity and worth is a fundamental principle of juvenile justice. This principle reflects the fundamental human right enshrined in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Respect of dignity includes not being humiliated, personal identity, boundaries and space being respected, not being labeled and stigmatized, being offered information and choices and not being blamed for their acts.
- (b) The juvenile's or child's right to dignity and worth has to be respected and protected throughout the entire process of dealing with the child from the first contact with law enforcement agencies to the implementation of all measures for dealing with the child.

III. Principle of Right to be heard.— Every child's right to express his views freely in all matters affecting his interest shall be fully respected through every stage in the process of juvenile justice. Children's right to be heard shall include creation of developmentally appropriate tools and processes of interacting with the child, promoting children's active involvement in decisions regarding their own lives and providing opportunities for discussion and debate.

IV. Principle of Best Interest.—

- (a) In all decisions taken within the context of administration of juvenile justice, the principle of best interest of the juvenile or the juvenile in conflict with law or child shall be the primary consideration.
- (b) The principle of best interest of the juvenile or juvenile in conflict with law or child shall mean for instance that the traditional objectives of criminal justice, retribution and repression, must give way to rehabilitative and restorative objectives of juvenile justice.
- (c) This principle seeks to ensure physical, emotional, intellectual, social and moral development of a juvenile in conflict with law or child so as to ensure the safety, well being and permanence for each child and thus enable each child to survive and reach his or her full potential.

V. Principle of family responsibility.—

- (a) The primary responsibility of bringing up children, providing care, support and protection shall be with the biological parents. However, in exceptional situations, this responsibility may be bestowed on willing adoptive or foster parents.
- (b) All decision making for the child should involve the family of origin unless it is not in the best interest of the child to do so.
- (c) The family - biological, adoptive or foster (in that order), must be held responsible and provide necessary care, support and protection to the juvenile or child under

their care and custody under the Act, unless the best interest measures or mandates dictate otherwise.

VI. Principle of Safety (no harm, no abuse, no neglect, no exploitation and no maltreatment).—

- (a) At all stages, from the initial contact till such time he remains in contact with the care and protection system, and thereafter, the juvenile or child or juvenile in conflict with law shall not be subjected to any harm, abuse, neglect, maltreatment, corporal punishment or solitary or otherwise any confinement in jails and extreme care shall be taken to avoid any harm to the sensitivity of the juvenile or the child.
- (b) The state has a greater responsibility for ensuring safety of every child in its care and protection, without resorting to restrictive measures and processes in the name of care and protection.

VII. Positive measures.—

- (a) Provisions must be made to enable positive measures that involve the full mobilization of all possible resources, including the family, volunteers and other community groups, as well as schools and other mainstream community institutions or processes, for the purpose of promoting the well-being of the juvenile or child through individual care plans carefully worked out.
- (b) The positive measures shall aim at reducing vulnerabilities and reducing the need for intervention under the law, as well as effective, fair and humane dealing of the juvenile or child.
- (c) The positive measures shall include avenues for health, education, relationships, livelihoods, leisure, creativity and play.
- (d) Such positive measures must facilitate the development of identity for the child and provide them with an inclusive and enabling environment.

VIII. Principle of non-stigmatizing semantics, decisions and actions.— The non-stigmatizing semantics of the Act must be strictly adhered to, and the use of adversarial or accusatory words, such as, arrest, remand, accused, charge sheet, trial, prosecution, warrant, summons, conviction, inmate, delinquent, neglected, custody or jail is prohibited in the processes pertaining to the child or juvenile in conflict with law under the Act.

IX. Principle of non-waiver of rights.—

- (a) No waiver of rights of the child or juvenile in conflict with law, whether by himself or the competent authority or anyone acting or claiming to act on behalf of the juvenile or child, is either permissible or valid.
- (b) Non-exercise of a fundamental right does not amount to waiver.

X. Principle of equality and non-discrimination.-

- (a) There shall be no discrimination against a child or juvenile in conflict with law on the basis of age, sex, place of birth, disability, health, status, race, ethnicity, religion, caste, cultural practices, work, activity or behaviour of the juvenile or child or that of his parents or guardians, or the civil and political status of the juvenile or child.
- (b) Equality of access, equality of opportunity, equality in treatment under the Act shall be guaranteed to every child or juvenile in conflict with law.

XI. Principle of right to privacy and confidentiality.— The juvenile's or child's right to privacy and confidentiality shall be protected by all means and through all the stages of the proceedings and care and protection processes.

XII. Principle of last resort.— Institutionalization of a child or juvenile in conflict with law shall be a step of the last resort after reasonable inquiry and that too for the minimum possible duration.

XIII. Principle of repatriation and restoration.—

- (a) Every juvenile or child or juvenile in conflict with law has the right to be re-united with his family and restored back to the same socio-economic and cultural status that such juvenile or child enjoyed before coming within the purview of the Act or becoming vulnerable to any form of neglect, abuse or exploitation.

- (b) Any juvenile or child, who has lost contact with his family, shall be eligible for protection under the Act and shall be repatriated and restored, at the earliest, to his family, unless such repatriation and restoration is likely to be against the best interest of the juvenile or the child.

XIV. Principle of Fresh Start.—

- (a) The principle of fresh start promotes new beginning for the child or juvenile in conflict with law by ensuring erasure of his past records.
- (b) The State shall seek to promote measures for dealing with children alleged or recognized as having impinged the penal law, without resorting to judicial proceedings.

CHAPTER - III

JUVENILE IN CONFLICT WITH LAW

4. Juvenile Justice Boards.— There shall be one or more Juvenile Justice Boards in every district, which shall be constituted by the State Government as per Section 4 of the Act.

5. Composition of the Juvenile Justice Board.-

- (a) The Board shall consist of Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class, as Principal Magistrate and, two social workers from the district concerned as members of the Board of whom at least one shall be a woman, forming a Bench:
Provided that the Principal Magistrate of the Board shall assess the pendency of cases before the Board and take such steps, as may be necessary in the expeditious disposal of the cases.
- (b) Every such bench shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).
- (c) (i) A Magistrate with special knowledge or training in child psychology or child welfare shall be designated as the Principal Magistrate of the Board.
(ii) In case the Principal Magistrate with such special knowledge or training is not available, then, the State Government shall provide for such short-term training in child psychology or child welfare as it considers necessary.
- (d) The two social workers, of whom at least one shall be a woman, shall be appointed by the State Government from a panel of names on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 89 of these Rules;
- (e) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, national and international standards for juvenile justice to all members of the Board, as it considers necessary, in accordance with the schemes and programmes of the State Government/Central Government.

6. Tenure of the Board.—

- (1) The Board shall have a tenure of three years and the appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board.
- (2) A social worker being a member of the Board shall be eligible for appointment for a maximum of two consecutive terms.
- (3) Any re-appointment of the member of the Board shall be on the basis of his performance appraisal by the District Child Protection Unit or the State Government and on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 89 of these Rules and the performance assessment of members of the Board shall necessarily assess their participation in the proceedings of the Board and contribution in case disposal;
- (4) A Member may resign any time, by giving one month's advance notice in writing or may be removed from his office as provided in Sub-Section (5) of Section 4 of the Act.
- (5) Any vacancy in the Board may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and the person so appointed shall hold office for the remaining term of the Board.

7. Qualifications for Members of the Board.— (1) A social worker to be selected as a Member of the Board shall be a person not less than 30 years of age and not more than 65 years of age and have either of the following qualifications, in addition to a minimum of five years experience and engaged in planning, implementing or administering measures relating to health, education, child rights and other development activities related to children preferably:

- (i) A post-graduate degree in social work/health/education/psychology/child development or in any social science discipline.
- (ii) In case suitable candidates having minimum qualifications as per (i) are not available in the district, Selection Committee can recommend candidates having (a) graduate degree in subjects mentioned in sub para (i) and experience for at least five years;

(2) Under circumstances where two or more candidates are having similar qualification and experience, preference shall be given to members belonging to SC/ST communities.

Provided that, in case where eligibility of SC/ST members is the same the decision of State Level Selection Committee shall be final.

- (3) No person shall be considered for selection as a Member of the Board, if he, -

 - (i) has been convicted under any law;
 - (ii) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human rights violations or immoral act;
 - (iii) is holding such other full time or part time occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Board;
 - (iv) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and these rules and in such a case the Selection Committee shall, after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

- (4) No two members of the board shall be in consanguineous or conjugal relationship.

8. Sitting and conveyance allowances.— The Social Worker members of Board shall be paid such travel and sitting allowance as the state government may determine.

9. Sittings of the Board.—

- (a) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at any suitable premise, other than court premises.
- (b) The state government shall set up by notification in official gazette, Juvenile Justice Board under Section 4 of the Act in every district, with requisite infrastructure, human resources and finances for smooth functioning of the Board, as prescribed under the norms of existing scheme, if any, or as may be determined by the state government.
- (c) The premises where the Board holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a Court room in any manner whatsoever; for example, the Board shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform, and there shall be no witness boxes.
- (d) The proceedings of the Board shall be like a conference in which the Juvenile Justice Board members, the juvenile, the parents, the Probation Officer, the Police Officer, the legal representative etc., shall participate in the proceedings.
- (e) The Board shall meet on all working days of a week, but the sitting frequency can be extended by the Principal Magistrate. The State Government may also extend the number of sittings in a week by a general or special order.
- (f) A minimum of three-fourth attendance of the Principal Magistrate and members of the Board is necessary in a year.
- (g) Every member of the Board shall attend a minimum of five hours per sitting.

10. Functions of the Board.— (1) The Board shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-

- (a) Adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;
- (b) Take cognizance of crimes committed under Sections 23 to 28 of the Act;
- (c) Monitoring institutions for juvenile in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement based on suggestions of the Board;
- (d) Deal with non-compliance of any order passed by the Board on the part of concerned government functionaries or functionaries of voluntary organizations, as the case may be, in accordance with due process of law;
- (e) Pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the spirit of the Act;
- (f) Maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;
- (g) Liaison with Boards in other districts and other states or union territories to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law;
- (h) Take suitable action for dealing with unforeseen situations that may arise in the implementation of the Act and remove such difficulties in the best interest of the juvenile;
- (i) Send monthly and quarterly information about juveniles in conflict with law produced before them to the District Child Protection Unit, State Child Protection Society/Unit, the State Government and to the Chief Judicial Magistrate for review under Para (2) of Section 14 of the Act;
- (j) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law;
- (k) The Board shall initiate action against any media for publishing any matters relating to the children in conflict with law which would lead to the identification of the child;
- (l) The Board shall order to keep the child in an Observation Home or in a place of safety, as the case may, be if the child could not be released on bail to the care of parents/guardians;
- (m) The Board shall ensure that no girl child was taken charge by police between sunset and sunrise;

Provided if the circumstances warrants the police to take charge of a girl child during such time, the Board should ensure that the girl child was kept under the care of a female fit person or a relative of the girl child, who shall also be a female fit person or in a place of safety or in an Observation Home;

- (n) The Board shall, at any stage during the course of enquiry if satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, may dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of the child;
- (o) The Board can also direct the Probation Officer to conduct social enquiry and furnish the report to the Board and also direct him to cause the professional/expert opinion on cases pertaining to the psychological/psychiatric problems of the Child, provided the Board, can also direct the professionals to furnish a special report about the child in conflict with law;
- (p) The Department of Pediatric/Psychiatric medicines of the Medical colleges/hospitals shall be recognized as nodal agencies for giving professional opinion.

11. Pre and Post-Production action of Police and other Agencies.— (1) As soon as a juvenile alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the concerned police officer shall inform:

- (a) the designated Juvenile or the Child Welfare Officer in the nearest police station to take charge of the matter;
- (b) the parents or guardian of the juvenile alleged to be in conflict with law about the apprehension of the juvenile, about the address of the Board where the juvenile will

be produced and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board;

(c) the concerned probation officer, of such apprehension to enable him to obtain information regarding social background of the juvenile and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry.

(2) Soon after apprehension, the juvenile shall be placed under the charge of the Juvenile or Child Welfare Officer from the nearest police station, who shall produce the juvenile before the Board within twenty four hours as per sub-Section (1) of Section 10 of the Act and where such Juvenile or the Child Welfare Officer has not been designated as per provisions laid down under sub-Section (2) of Section 63 of the Act or is not available for some official reasons, the police officer who had apprehended the juvenile shall produce him before the Board.

(3) The police apprehending a juvenile in conflict with law shall in no case send the juvenile in lock-up or delay his charge being transferred to the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, if such an officer has been designated.

(4) A list of all designated Juvenile or the Child Welfare Officers in a district and members of Special Juvenile Police Unit with contact details shall be prominently displayed in every police station.

(5) For gathering the best available information it shall be incumbent upon the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, to contact the parents or guardians of the juvenile and also apprise them of the juvenile's law breaking behaviour.

(6) The police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall also record the social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed in the case diary of each juvenile, which shall be forwarded to the Board forthwith.

(7) The police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall exercise the power of apprehending the juvenile only in cases of his alleged involvement in serious offences (entailing a punishment of more than 7 years imprisonment for adults).

(8) In such cases where apprehension apparently seems to be in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall rather treat the juvenile as a child in need of care and protection and produce him before the Board, clearly explaining the juvenile's need for care and protection in its report and seek appropriate orders from the Board under rule 13 (1) (b) of these Rules.

(9) For all other cases involving offences of non-serious nature (entailing a punishment of less than 7 years imprisonment for adults) and cases where apprehension is not necessary in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall intimate the parents or guardian of the juvenile about forwarding the information regarding nature of offence alleged to be committed by their child or ward along with his socio-economic background to the Board, which shall have the power to call the juvenile for subsequent hearings.

(10) In case the Board is not sitting, the juvenile in conflict with law shall be produced before the single member of the Board as per the provisions laid down under the sub-Section (2) of Section 5 of the Act.

(11) In dealing with cases of juveniles in conflict with law the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall not be required to register an FIR or file a charge-sheet, except where the offence alleged to have been committed by the juvenile is of a serious nature such as rape, murder or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults; instead, in matters involving simple offences, the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station shall record information regarding the offence alleged to have been committed by the juvenile in the general daily diary followed by a report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence and forward it to the Board before the first hearing.

(12) The State Government shall recognize only such voluntary organizations that are in a position to provide the services of probation, counseling, case work, a safe place and also associate with the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit,

and have the capacity, facilities and expertise to do so as protection agencies that may assist the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the police at the time of apprehension, in preparation of the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence, in taking charge of the juvenile until production before the Board, and in actual production of the juvenile before the Board within twenty-four hours.

(13) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, or the recognized voluntary organization shall be responsible for the safety and provision of food and basic amenities to the juveniles apprehended or kept under their charge during the period such juveniles are with them.

(14) When a juvenile is produced before an individual member of the Board, and an order obtained, such order shall need ratification by the Board in its next meeting.

12. Procedure to be followed in determination of Age.— (1) Except in cases where a juvenile or child appears prima facie to be a juvenile or child, the court or the Board or the Committee, as the case may be, shall determine the age of such juvenile or child within a period of thirty days from the date of making of the application for that purpose.

(2) The Court or the Board or the Committee shall decide the juvenility or otherwise of the juvenile or the child in need of care and protection, prima facie on the basis of physical appearance or documents, if available, and send him to the observation home or children's home or in prison as the case may be.

(3) Save and except where a juvenile or a child, as the case may be, prima facie appears to be above 12 years of age, age determination shall be conducted by the court or the Board or the Committee, as the case may be, by seeking evidence, by obtaining--

- (a) (i) the matriculation and equivalent certificate along with copies of attendance record of class VIII attended by the juvenile or child; or,
- (ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof;
- (iii) the birth certificate given by the Municipal Corporation or a Municipal Authority or a Panchayat; and
- (b) only in the absence of either (i) and/or (ii) or (iii) of clause (a) above, or in case the Court or the Board or the Committee finds it necessary, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of the juvenile or child. In case exact assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons recorded by them, may, if to be considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of one year and, while passing orders in such case shall, after taking into consideration such evidence as may be available or the medical opinion as the case may be, record a finding in respect of his age and either of the evidence specified in any of the clauses (a) (i), (ii), (iii) or in the absence whereof, clause (b) shall be proof of the age as regards such child or the juvenile in conflict with law.

(4) The duly constituted Medical Board shall submit medical opinion to the competent authority within one week from the date of receipt of the order.

(5) If the age of a juvenile or child is found to be below 18 years on the date of offence, on the basis of any of the proof specified in sub-rule (3), the Court or the Board or, as the case may be, the Committee shall in writing pass an order stating the age and declaring the status of juvenility or otherwise, for the purpose of the Act and these Rules and a copy of the order shall be given to such juvenile or the parent/guardian/person concerned.

(6) The provisions contained in this rule shall also apply to those disposed of cases, where the status of juvenility has not been determined in accordance with the provisions contained in sub rule (3) and the Act, requiring dispensation of the sentence under the Act for passing appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law.

13. Post-production processes by the Board.— (1) On production of the juvenile before the Board, a report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed shall be provided by the concern juvenile/child welfare or

police officer, other officers, individuals, agencies producing the juvenile on the same day. Such report shall be reviewed by the Board, and the Board shall pass the following order in the first summary inquiry on the same day, namely:-

- (a) dispose of the case, if the evidence of his conflict with law appears to be unfounded or where the juvenile is involved in trivial law breaking;
- (b) transfer to the Committee, matters concerning juveniles clearly stated to be in need of care and protection in the police report submitted to the Board at the time of production of the juvenile;
- (c) release the juvenile in the supervision or custody of fit persons or fit institutions or probation officers as the case may be, through an order in **Form-I**, with a direction to appear or present a juvenile for an inquiry on a next date;
- (d) detain the juvenile in an Observation Home or fit institution pending inquiry, only in cases of juvenile's involvement in serious offences as per an order in **Form-II**;
- (e) in all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than 15 days of the first summary enquiry and also seek social investigation report from the concerned Probation Officer through an order in **Form-III**;

14. Enquiry.- (1) The Board shall take the following steps to ensure fair and speedy inquiry, namely:-

- (a) at the time of initiating the inquiry, the Board shall satisfy itself that the juvenile in conflict with law has not been subjected to any ill-treatment by the police or by any other person, including a lawyer or probation officer and take corrective steps in case of such ill-treatment;
- (b) in all cases under the Act the proceedings shall be conducted in as simple a manner as possible and care shall be taken to ensure that the juvenile, against whom the proceedings have been instituted, is given child-friendly atmosphere during the proceedings;
- (c) Every juvenile brought before the Board shall be given the opportunity to be heard and participate in his inquiry;
- (d) Cases of petty offences, if not disposed off by the Special Juvenile Police Unit or at the police station itself, may be disposed of by the Board through summary proceedings or inquiry within one month, while in cases of serious offences entailing punishment of 7 years or more, due process of inquiry in detail may follow;
- (e) Even in cases of inquiry pertaining to serious offences the Board shall follow the procedure of trial in summons cases.

(2) When witnesses are produced for examination in inquiry relating to a juvenile in conflict with law, the Board shall keep in mind that the inquiry is not to be conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by Section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to question the juvenile and proceed with the presumptions that favour the juvenile's right to be restored.

(3) While examining a juvenile in conflict with law and recording his statement, the Board shall address the juvenile in a child-friendly manner in order to put the juvenile at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence of which the juvenile is accused, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the juvenile might have been subjected.

(4) The record of the examination shall be in such form as the Board may consider suitable having regards to contents of the statement and circumstances in which it was made.

(5) The Board may take into account the report of the police containing circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed and the social investigation report in **Form IV** prepared by the Probation officer or the voluntary organization on the orders of the Board as per **Form III**, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion about the juvenile.

(6) Every inquiry by the Board shall be completed within a period of four months from the date of commencement of the case and only in exceptional cases involving trans-national criminality, large number of accused and inordinate delay in production of witnesses, the period of inquiry may be extended by two months on recording of reasons by the Board.

(7) In all other cases except where the nature of alleged offence is serious, delay beyond four to six months shall lead to the termination of the proceedings.

(8) Where the proceedings are delayed beyond six months on account of serious nature of the offence alleged to have been committed by the juvenile, the Board shall send a periodic report of the case to the District Judge stating the reason for delay as well as steps being taken to expedite the matter.

15. Legal Aid.- (1) The proceedings before the Board shall be conducted in non-adversarial environment, but with due regard to all the due process guarantees such as right to counsel and free legal aid.

(2) Bihar State Legal Services Authority shall nominate panel of lawyers as per the directions of National Legal Services Authority (NALSA) to facilitate the legal services to juvenile in conflict with law. Their services may also include to obtain relief in cases of abuse or exploitation of the child.

(3) The Board shall ensure that the Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall extend free legal services to all juvenile in conflict with law.

(4) The Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall be under an obligation to provide legal services sought by the Board.

(5) The Board may also deploy the services of the student, legal services volunteers and non-governmental organization volunteers in Para-legal tasks such as contacting the parents of juveniles in conflict with law and gathering relevant social and rehabilitative information about the juveniles.

16. Completion of Inquiry and Dispositional Alternatives.— (1) The Board shall complete every inquiry within the stipulated time of four months and on recording a finding about juvenile's involvement in the alleged offence, pass one of the seven dispositional orders enumerated in Section 15 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report prepared by the probation officer or by a recognized voluntary organization ordered to do so by the Board, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an individual care plan in **Form XXI** for the concerned juvenile in conflict with law, prepared by a probation officer on the basis of interaction with the juvenile and his family where possible.

(4) Where the Board decides to release the juvenile after advice and admonition or after participation in group counseling or orders him to perform community service, necessary direction may also be made by the Board to the District or State Child Protection Society/Unit or the State Government for arranging such individual counselling, group counselling and community service.

(5) Where the Board decides to release the juvenile in conflict with law on probation and place him under the care of the parent or guardian or fit person, the person in whose custody the juvenile is released may be required to submit a written undertaking in Form V for the good behaviour and well-being of the juvenile for a maximum period of three years.

(6) The Board may order release of a juvenile in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form VI**.

(7) In the event of placement of a juvenile in conflict with law in care of a fit institution or special home, the Board shall keep in mind that the fit institution or special home is located nearest to the place of residence of the juvenile's parent or guardian.

(8) The Board, where it releases a juvenile in conflict with law on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the juvenile is released on probation and places him under the care of fit institution, may order that the juvenile be placed under the supervision of a probation officer. The period of supervision shall be a maximum of three years.

(9) Where the Board decides that a juvenile in conflict with law ought to be treated as a child in need of care and protection, it shall make necessary orders for production of such juvenile before the nearest Committee for suitable care, protection and rehabilitation.

(10) Where it appears to the Board that the juvenile in conflict with law has not complied with probation conditions, it may order the juvenile to be sent for detention in a Special Home.

(11) Where a juvenile in conflict with law who has attained the age of sixteen years and the offence committed by him is of such a serious nature that in the satisfaction of the Board, it is neither in the interest of the juvenile himself nor in the interest of other juveniles of the special home, the Board may order the juvenile to be kept in a place of safety and in a manner considered most appropriate by it.

(12) The State Government shall make arrangement for complying with the detention of special category of juveniles in conflict with law in place of safety other than the special home.

(13) In no case, the period of detention shall exceed beyond the maximum period provided in clause (g) of sub-Section (1) of Section 15 of the Act.

17. Institutions for juveniles in conflict with law.— (1) The State Government, either by itself or under an agreement with the recognized voluntary organization, shall set up separate observation homes or place of safety and special homes for boys and girls in every district or in group of districts as per requirement.

(2) The observation homes and special homes shall set up separate residential facilities for boys and girls with a classification and segregation up to the age of 11 years, 12-15 years and 16 years and above.

(3) Every institution shall keep a copy of the Act, the rules made by the State, for use of staff, juveniles and children residing therein.

(4) The State Government shall develop an Operational Manual.

(5) All facilities and services for juveniles in conflict with law shall be made available and maintained as per the provisions of the Act and the State Rules.

18. Release.— (1) The Superintendent shall maintain a roster of the cases of juveniles in conflict with law to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board.

(2) Each case shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules by the concerned superintendent, probation officer, child welfare officer or case worker, for ensuring proper release and social mainstreaming of the juvenile post- release.

(3) The release shall be as per the pre-release and post release plan prepared under the individual care plan and reviewed from time to time by the management committee set up under Rule 62 of these rules and in all cases of release, necessary action and preparation shall be initiated well before the time of release and shall include preparation for post release follow up.

(4) Timely information of the release of a juvenile and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be invited to come to the institution to take charge of the juvenile on that date.

(5) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the juvenile on the appointed date, the juvenile shall be taken to his parent or guardian by the escort of the institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort, who shall hand over her custody to her parent/guardian.

(6) At the time of release or discharge, a juvenile shall be provided with a set of clothing and essential toiletries.

(7) If the juvenile has no parent or guardian, he may be sent to an Aftercare Home/Child Welfare committee for appropriate direction, or in the event of his employment, to the person who has undertaken to employ the juvenile.

(8) The Superintendent of a girl's institution may, subject to the consent of the girl and the approval of the Board, help the girl with her social re-integration by way of sending a girl above the age of eighteen years to an after care home or helping her with some vocation or gainful employment or, helping her settle into family life as per the procedure laid down by the state government from time to time.

(9) The Superintendent shall order the discharge in **Form VII** of any juvenile whose detention period has come to an end and inform the Board and Director of Social Welfare within

seven days of the action taken and if the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the juvenile may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge. The Superintendent shall be liable for disciplinary action including initiation of departmental proceeding, if he/she fails to release the juvenile on the date of such release or implement the order.

(10) The Superintendent shall in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway or road, or both, fares, as the case may be.

(11) In deserving cases, the Superintendent may provide the juvenile with such small tools, as may be necessary to start a work or business subject to such maximum cost as may be fixed by the institution which shall also form part of the post-release plan.

(12) Where a Juvenile in Conflict with law has no place to go after release or in order to complete the course and requests for stay in the institution after the period of his/her stay is over, the Superintendent may, subject to the approval of the competent authority, allow his/her to stay till the time some other suitable arrangements are made; or may be transferred to an After Care Home.

19. Procedure to be followed in respect of Sections 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of the Act.—

(1) In the event of violation of provisions laid down under Section 21 of the Act,-

- (a) The Board/Committee shall take cognizance of such violation by print or electronic media and shall initiate necessary inquiry and pass appropriate orders as per provisions contained in sub-Section (2) of Section 21 of the Act; and;
- (b) where the National or the State Commission for Protection of Child Rights takes *suo motu* cognizance of violation under Section 21 of the Act, it shall inform the District or the State Child Protection Unit of the concerned district and the State directing them to initiate necessary action through the Board.

(2) In the event of an escape of a juvenile in conflict with law or a child, the following action shall be taken within twenty-four hours,-

- (a) The Superintendent of the institution shall immediately send a report to the area Police Station or Special Juvenile Police Unit along with the details and description of the juvenile or child, with identification marks and a photograph, with a copy to the Board/Committee, District Child Protection Unit and other authorities concerned;
- (b) The Superintendent of institutions other than shelter homes or drop-in-centre shall send the guards or concerned staff in search of the juvenile, at places like railway stations, bus stands and other places where the juvenile is likely to go;
- (c) The parents or guardians, if any, shall be informed immediately about such escape; and
- (d) The Superintendent of the institution other than a shelter home or drop-in-centre shall hold an inquiry about such escape and send his report to the Board or Committee and the authorities concerned and the report shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules in the next meeting for review.

(3) The offences against a juvenile in conflict with law or a child specified in Sections 23, 24, 25 and 26 shall be either bailable or non-bailable besides being cognizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the procedures shall apply on the Police, the Board and the concerned authorities and functionaries accordingly

CHAPTER – IV

CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

20. Child Welfare Committee.—There shall be a Child Welfare Committee in every district, which shall be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette as per sub-Section (1) of Section 29 of the Act.

21. Composition of the Child Welfare Committee.— (1) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members, from the district concerned, of whom at least one shall be a woman and one from among the members belonging to SC/ST communities.

(2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee set up by the State Government, for the purpose under Rule 89.

(3) The Selection Committee, while selecting the Chairperson and Members of the Committee, shall ensure that none of them are from any voluntary organization running specialized adoption agency or child care institution or Childline.

(4) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, socialization and rehabilitation, national and international standards for child protection or juvenile justice and the relevant legal system to the Chairperson and all the members of the Committee as it considers necessary.

22. Tenure of the Committee.— (1) The Committee shall have a tenure of three years and the tenure of Chairperson and Members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.

(2) The Chairperson and a member of the Committee may be eligible for re-appointment for a maximum of two consecutive terms.

(3) Extension of the tenure of members of the Committee shall be on the basis of their performance appraisal by the District Child Protection Unit or the State Government and on the recommendation of the Selection Committee.

(4) With a view to ensuring continuity on completion of the tenure of a Committee, the State Government shall constitute a new Committee before the expiry of the term of the existing Committee; where after the existing Committee shall handover all records and information to the newly formed Committee.

(5) The Chairperson and Members may resign at any time by giving one month's notice in writing or may be removed from office as provided in sub-Section (4) of Section 29 of the Act.

(6) Any casual vacancy in the Committee may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and shall hold office for the remaining term of the Committee.

23. Qualifications for Chairperson and Members of the Committee.— (1) A person to be selected as a Chairperson or Member of the Committee shall be a person not less than 30 years of age and not more than 65 years of age and have either of the following qualifications, in addition to a minimum of five years experience and engaged in planning, implementing or administering measures relating to health, education, child rights and other development activities related to children preferably:-

- (i) A post-graduate degree in social work/psychology/child development/education/sociology/law/criminology or in any social science discipline.
- (ii) In case suitable candidates having minimum qualifications as per (i) are not available in the district, Selection Committee can recommend candidates having (a) graduate degree in subjects mentioned in sub para (1) and experience for at least five years;
- (iii) A teacher, doctor or retired government servant who has been involved in work related to children.

(2) Amongst shortlisted members, a person with higher educational qualification and experience will be selected as Chairperson of the Committee.

(3) No person shall be considered for Selection as a Chairperson or Member of the Committee, if he,

- (i) has a previous conviction record;

- (ii) has been involved in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;
- (iii) is holding such full-time occupation that may not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee as per the Act and these rules;
- (iv) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under, and in such a case the Selection Committee shall after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.

(4) No two members shall be in consanguineous or conjugal relationship.

24. Sitting and conveyance allowances.— The Chairperson and Members of the Committee shall be paid such travel and sitting allowance, as the State Government may determine.

25. Sitting of the Committee.—(1) The Committee shall hold its sittings in the premises of the Children's Home or, at a place in proximity to the Children's Home or, at a suitable premise in any institution running under the Act.

(2) On receiving information about child or children in need of care and protection, if circumstances are such that the child or children cannot be produced before the Committee, the Committee may move out to reach the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.

(3) The premises where the Committee holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Committee shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform and there shall be no witness boxes.

(4) The Committee shall meet at least a minimum of three days a week, which may be extended by the State Government depending on case and pendency of work.

(5) A minimum of three-fourth attendance of the Chairperson and Members of the Committee is necessary in a year.

(6) Every member of the Committee shall attend a minimum of five hours per sitting during the official working hours which may be extended by the state government depending on the pendency of the work.

26. Functions and Powers of the Committee.— *The Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-*

- (a) Take cognizance of and receive child produced before the Committee;
- (b) Decide on the matters brought before the Committee at the earliest ;
- (c) Reach out to such children in need of care and protection who are not in a position to be produced before the Committee, being in difficult circumstances, with support from the District Child Protection Unit or State Child Protection Society/Unit or the State Government;
- (d) Conduct necessary inquiry on all issues relating to and affecting the safety and well being of the child;
- (e) Direct the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations to conduct social inquiry and submit a report to the Committee;
- (f) Prepare individual care plan for the children;
- (g) Ensure necessary care and protection to the child, including immediate shelter;
- (h) Ensure appropriate rehabilitation and restoration, including passing necessary directions to parents or guardians or fit persons or fit institutions in this regard, in addition to follow-up and coordination with District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency and other agencies;
- (i) Direct the Superintendent of children's home/shelter homes/open shelters/drop-in-centres to receive children requiring shelter and care;
- (j) Document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee;
- (k) Ensure a child-friendly environment for children;
- (l) Recommend 'fit institutions' to the State Government for the care and protection of children;
- (m) Declare 'fit persons' for temporary period for specific cases;

- (n) Declare a child legally free for adoption;
- (o) Keep information about and take necessary follow-up action in respect of missing children in their jurisdiction;
- (p) Maintain liaison with the Board in respect of cases needing care and protection;
- (q) Visit each institution where children are kept and sent for care and protection and specialized adoption agency at least once in three months to review the condition of children in institutions, with support of the State Government and suggest necessary action;
- (r) Monitor associations and agencies within their jurisdiction that deal with children in order to check the exploitation and abuse of children;
- (s) Co-ordinate with the Education, Health, Police, Labour Department and other agencies involved in the care and protection of children with the support of District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or State Government;
- (t) Liaison and network with the corporate sector and non-governmental organisations for any of the above, including for social inquiry, restoration and rehabilitation, as and when required; and
- (u) Maintain a suggestion box to encourage inputs from children and adults alike and take necessary action.
- (v) The Committee may, with the help of District Child Protection Unit or any NGO, maintain a list of various governmental, non-governmental, corporate and community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of the child;
- (w) Liaison with Committees in other districts and other concerned bodies to facilitate speedy inquiry and restoration or rehabilitation of the child;
- (x) Prepare and send monthly report about child and any other related matter as and when required, to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Unit;
- (y) The CWC can issue order to the local authority to issue the birth certificate of the abandoned child after conducting necessary enquiries;
- (z) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with children in need to care and protection.

27. Procedure in relation to Committee.— (1) The quorum for the meeting shall be three members attending, which may include the Chairperson.

(2) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall require ratification by the Committee in its next sitting.

(3) The Committee shall send a copy of every order passed by it to the District Child Protection Unit for necessary compliance and follow-up.

(4) The Committee shall take into consideration the age, developmental stage, physical and mental health, opinion of the child and the recommendation of the child welfare officer or caseworker, prior to disposal of cases.

(5) For final disposal of a case, the order of the Committee shall be signed by at least two members, including the Chairperson.

28. Production of a Child before the Committee.— (1) A child in need of care and protection shall be produced before the Committee within twenty-four hours, excluding journey time, by one of the following persons—

- (a) any police officer or Special Juvenile Police Unit or a designated police officer;
- (b) any public servant;
- (c) Childline, a registered voluntary organization or by such other voluntary organization or an agency as may be recognized by the State Government;
- (d) social worker;
- (e) any public spirited citizen; or
- (f) by the child himself.

(2) Whenever the above mentioned person/s takes charge of child in need of care & protection, the information shall be given to the police station or Childline as soon as possible,

giving details of child, the situation from which rescued, the time at which the person took charge of the child including the place. The person taking charge of the child shall also give his details like name, address and organization for which he is working and other relevant details of members of rescue team.

(3) In case of a child under two years of age, who is medically unfit, the person or the organization shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

(4) The Committee can *suo motu* take cognizance of cases brought to its notice and reach out to a child in need of care and protection where necessary and the District or the State Child Protection Unit or the State Government shall provide necessary support and assistance to the Committee for carrying out such functions.

(5) In case the Committee is not sitting, the child may be produced before the single member of the Committee as per the provisions laid down under sub-Section (2) of Section 30 of the Act for being placed in safe custody of parent or guardian or fit person or fit institutions, as the case may be, till such time that the child can be produced before the Committee.

(6) In case the single member is also not accessible, or that the hours are odd, the child shall be taken by any non-governmental organisation or Childline or Police to an appropriate institution for children registered under the Act with all the necessary documents, and be placed in such institution till the time of production before the Committee.

(7) The concerned institution shall inform the Chairperson or a member of the Committee about such child and produce the child before the Committee within twenty four hours and in such cases, it may not be necessary for the person who brings a child in need of care and protection to an institution to be present at the time of production of the child before the Committee. If the institution is Government Children Home, the child may be produced during the next sitting of the committee.

(8) Whoever produces a child before the Committee may submit a report on the circumstances under which the child came to their notice and efforts made by them in informing the police and the missing persons squad and in cases where a recognized voluntary organization or any police personnel produce a child before the Committee, they shall also submit a report on the efforts made by them for tracing the family of the child.

(9) Any general medical or gynecological examination of child shall not be a pre-requisite for production of the child before the Committee or admission in an institution.

(10) The Committee shall facilitate the filing of a police complaint and First Information Report in cases of missing children as well as matters of violence, exploitation and abuse of children and arrange for required legal aid through the Legal Officer in the District Child Protection Unit or District or State Legal Aid Services Authority or voluntary organizations.

(11) Each Committee shall send monthly and quarterly information about children in need of care and protection received by them to the District and State Child Protection Society/Unit or State Government.

(12) Child shall be provided a child-friendly environment during the proceedings of the Committee.

(13) The Committee shall have an empanelled list of lawyers, social workers and mental health experts who may assist the Committee in dealing with cases of abused children and who may also interface with the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor to facilitate legal services to the abused children, when the cases relating to such children are taken up in regular criminal courts. As far as possible, the public prosecutor or Assistant public prosecutor may preferably be a female in case of girl child.

(14) Every possible effort shall be made to trace the family with support from the District Child Protection Unit, and assistance of recognized voluntary organizations, Child line or police may also be taken.

(15) The Committee shall send the child to the designated place of safety, with age and gender appropriate facilities, pending inquiry and in such eventuality, the State Government shall provide transport or make necessary budgetary allocations for such expenses based on the actual fare.

(16) The child may be escorted by the police officer in plain clothes or representative of the voluntary organization or by any other arrangement as considered appropriate by the Committee with support from the District Child Protection Unit and in case of a girl child, a female escort shall accompany the child.

(17) A list of all recognized child care institutions along with their capacity and appropriate facilities as prescribed under Section 34 of the Act, a list of all child related resource services and a list of contact details of all Child Welfare Committees across the country shall be provided to the Committee by State Government.

(18) The Committee may, while making an order in **Form VIII** placing a child under the care of a parent, guardian or fit person pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form IX**.

(19) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Superintendent of such institution a copy of the order of short term placement pending inquiry, in **Form X** with particulars of the home and parents or guardian and previous record.

(20) Whenever the Committee orders a child to be kept in a fit institution as part of restoration under clause (f) of sub-Section (3) of Section 39 of the Act, it shall forward a copy of its order of restoration in **Form XI** to the Superintendent of such institution.

- (21) (a) The Committee should also satisfy that, the child has not been subjected to any harassment either by the Police or by any other person, who takes charge of the child for the purpose of bringing before the Child Welfare Committee.
- (b) The Committee may release the child to the care of parents/guardian with without surety till such time the final disposition is made.
- (c) The Committee shall conduct the proceeding in an informal way to ensure that child's interest is of paramount importance.
- (d) The Committee shall initiate action against any media for publishing any matter relating to the children in need of care and protection, which would affect the interest of the child.
- (e) The Committee shall enquire the child in need of care and protection and shall record the statements in accordance with the procedure as laid down in the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (f) The Committee shall, if at any stage during the course of the enquiry is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of child.

(22) The child shall be placed in an institution closest to where his parents or guardians belong as far as possible, unless the child has been subjected to abuse or exploitation by parents or guardians.

29. Procedure for inquiry.- (1) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a social worker or probation officer or case worker or child welfare officer for conducting the inquiry through and order in **Form XII**.

(2) The Committee shall direct the concerned person or organization about the details or particulars to be enquired into for developing an individual care plan and suitable rehabilitation.

(3) All inquiries conducted by a probation officer or case worker or child welfare officer shall be as per **Form XIII** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

(4) The inquiry must be completed within four months or within such shorter period as may be fixed by the Committee. Provided that the Committee may, in the best interest of the child and for the reasons to be recorded in writing, extend the said period under special circumstances.

(5) After completion of the inquiry, if, the child is under orders to continue in the children's home, the Committee shall direct the Superintendent of the home to submit quarterly progress report of such child and produce the child before the Committee for an annual review of the progress.

30. Children's Home.- (1) The State Government itself or in association with voluntary organizations, shall set up separate homes for children in need of care and protection, in the manner specified below:

- (a) All children's homes shall be registered as child care institutions under sub Section (3) of Section 34 of the Act and rule 74 of these rules;
- (b) All Children's home shall be certified as per the procedure laid down in Rule 73;
- (c) All children's homes shall report to the concerned Committee about every child in need of care and protection received by them;
- (d) Separate children's homes shall be set up for boys and girls in the age group 06 to 18 years;
- (e) Every children's home shall include separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for the infants;
- (f) Children in the age group of 6 to 18 years shall be further segregated into three groups of 6 to 10 years, 11 to 15 years and 16 to 18 years.

(2) Each children's home shall be a comprehensive child care centre with the primary objective to promote an integrated approach to child care by involving the community and local Non-Governmental Organizations through the Management Committee set up under Rule 56 of these rules and the District Child Protection Unit or State Child Protection Society/Unit or the State Government shall make an annual performance review of functioning of the children's homes run by the state government or by any recognized voluntary organization, besides the regular reviews.

(3) The activities of such centre shall focus on:

- (a) preparing and following individual care plans for every child, with rights based approach, specifically addressing the child's physical and mental health, emotional needs, education, skill development, protection and special needs if any;
- (b) family based non-institutional services, such as, foster family care, adoption and sponsorship;
- (c) specialized services in situations of conflict or disaster and for juvenile or children affected by terminal or incurable disease to prevent neglect by providing family counselling, nutrition, health interventions, psycho-social interventions and sponsorship;
- (d) emergency outreach service through childline (toll free Help Line no. 1098);
- (e) linkages with Integrated Child Development Services to cater to the needs of children below six years;
- (f) linkages with organizations and individuals who can provide support services to children;
- (g) opportunities to volunteers willing to provide various services for children;
- (h) ensure that the child develop positive attitudes towards the family and creates a linkage with family; and arrange group counseling

31. Shelter Home.—(1) For children in urgent need of care and protection, such as street children and run-away children, the State Government shall support creation of requisite number of shelter homes or drop-in- centres (open shelters) through the voluntary organizations.

(2) Shelter homes shall include:

- a) short-stay homes for children needing temporary shelter, care and protection for a maximum period of one year,
- b) transitional facilities for providing immediate care and protection to a child for a maximum period of four months,
- c) 24 hour drop-in-centres running for children needing day care or night shelter facility.

(3) The shelter homes or drop-in-centres shall have the minimum facilities of boarding and lodging, besides the provision for fulfillment of basic needs in terms of clothing, food, health care and nutrition, safe drinking water and sanitation.

(4) There shall be separate shelter homes for girls and boys as per Rule 41(2)(d) of these rules.

(5) All shelter homes shall provide requisite facilities for education, vocational training, counseling and recreation or make arrangements for it in collaboration with voluntary organizations or corporate sector.

(6) The Committee, Special Juvenile Police Unit, public servants, Child Line, voluntary organizations, social workers and the children themselves may refer a child to such shelter homes.

(7) All shelter homes shall submit a report of children using the shelter home facility along with a photograph of the child to the Committee, the missing persons bureau or special juvenile police unit and the District Child Protection Unit or the State Child Protection Unit.

(8) The services of officer-in-charge, child welfare officer, social worker shall be provided for the proper care, protection, development, rehabilitation and reintegration needs of children in shelter homes.

(9) No child shall ordinarily stay in a shelter home for more than a year except in special circumstances with the approval of the Committee.

32. Guidelines for prevention of sexual abuse of children.— The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee, other competent authorities and agencies shall, in the best interest of children, ensure that every person, school or such other educational institutions abide by the guidelines issued from time to time by Central Government and state Government.

CHAPTER - V

REHABILITATION AND SOCIAL REINTEGRATION

33. Rehabilitation and Social Reintegration.— The primary aim of rehabilitation and social reintegration is to help children in restoring their dignity and self-worth and mainstream them through rehabilitation within the family where possible, or otherwise through alternate care programmes and long-term institutional care shall be of last resort.

34. Adoption.— (1) The primary aim of adoption is to provide a child who cannot be cared for by his biological parents with a permanent substitute family.

(2) For all matters relating to adoption, the guidelines issued by the Central Adoption Resource Authority and notified by the Central Government under sub-Section (3) of Section 41 of the Act, shall apply.

(3) In case of orphaned and abandoned children the following procedure shall apply, namely:-

- (a) Wherever a Specialized Adoption Agency receives an abandoned child, it shall, within twenty four hours inform the matter to the police station.
- (b) Specialized Adoption Agencies shall produce all orphaned and abandoned children who are to be declared legally free for adoption before the Committee within twenty-four hours of receiving such children, excluding the time taken for journey;
- (c) A child becomes eligible for adoption when the Committee has completed its inquiry and declares the child legally free for adoption;
- (d) Such declaration shall be made in **Form XIV**;
- (e) A child must be produced before the Committee at the time of declaring such child legally free for adoption;
- (f) Whenever intimation is received by the police about an abandoned infant, the police shall take charge of the infant and arrange to provide immediate medical assistance and care;
- (g) Subsequently, the child shall be placed in a specialized adoption agency or recognized and certified children's home or in a pediatric unit of a Government hospital followed by production of the child before the Committee within twenty-four hours;
- (h) Carry out procedure for declaring a child abandoned and certifying him legally free for adoption:
 - (i) in case of an abandoned child, the recognized agency shall within twenty four hours, report and produce the child before the Committee with the copy of the report filed with the police station in whose jurisdiction the child was found abandoned;

- (ii) the Committee will institute a process of inquiry, which shall include a thorough inquiry conducted by the Probation Officer or Child Welfare Officer, as the case may be and who shall give report in **Form XIII** to the Committee containing the findings within one month;
- (iii) there shall be a declaration by the specialized adoption agency, stating that there has been no claimant for the child even after making notification in at least one leading national newspaper and one regional language newspaper for children below two years of age and for children above two years, an additional television or any other prevalent mode or radio announcement and notification to the missing persons squad or bureau shall be made;
- (iv) the steps stated in (iii) shall be taken within a period of sixty days from the time when the child is found in case of a child below two years of age and in case of children above two years of age, this period shall be four months;
- (v) the period of notification shall run concurrently with the inquiry to be conducted and report submitted under clause (ii) of this sub-rule;
- (vi) The Committee shall declare the child legally free for adoption on completion of the process of inquiry, including declaration of the specialized adoption agency made under clauses (ii) and (iii) of this sub-rule;
- (vii) No child above seven years who can understand and express his opinion shall be declared free for adoption without his consent recorded before Child Welfare Committee.

(4) In case of surrendered child the following procedure shall apply, namely:-

- (a) A surrendered child is one who had been declared as such after due process of inquiry by the Committee and in order to be declared legally free for adoption, a 'surrendered' child shall be any of the following:
 - (i) born as a consequence of non-consensual relationship;
 - (ii) born of an unwed mother or out of wedlock;
 - (iii) a child in whose case one of the biological parents is dead and the living parent is incapacitated to take care;
 - (iv) a child where the parents or guardians are compelled to relinquish him due to physical, emotional and social factors beyond their control;
- (b) serious efforts shall be made by the Committee for counseling the parents, explaining the consequences of adoption and exploring the possibilities of parents retaining the child and if, the parents are unwilling to retain, then, such children shall be kept initially in foster care or arranged for their sponsorship;
- (c) if the surrender is inevitable, a deed of surrender in **Form XV** shall be executed on a non-judicial stamp paper in the presence of the Committee.
- (d) the adoption agencies shall wait for completion of two months reconsideration time given to the biological parent or parents after surrender;
- (e) in case of a child surrendered by his biological parent or parents, the document of surrender shall be executed by the parent or parents before the Committee;
- (f) after due inquiry, the Committee shall declare the surrendered child legally free for adoption in **Form XIV** as the case may be after a sixty days' reconsideration period as per Central Adoption Resource Agency guidelines.

(5) For the purposes of Section 41 of the Act, 'court' implies a civil court, which has jurisdiction in matters of adoption and guardianship and may include the court of the district judge, family courts and civil court.

35. Foster Care.- (1) For children who cannot be placed in adoption, order shall be issued by the competent authority in Form XVII for carrying out foster care, as given in sub-Section (2) of Section 42 of the Act under the supervision of a probation officer or case worker or social worker, as the case may be, and the period of foster care shall depend on the need of the child.

(2) State Government shall design its own foster care programme or adopt any guideline or programme or scheme as may be prescribed or notified by the central government so as to reduce institutionalization of children and enable a nurturing family environment for every child.

(3) The State Government shall consult the Boards or Committees, non-governmental organizations, academicians and organizations working on alternative care for children in developing the foster care programme.

(4) De-institutionalisation of children and placing them in foster care shall be made with the concurrence of the Child Welfare Committee.

36. Criteria for selection of families for foster care.— (1) In case of the children covered under Rule 35 of these rules, the following criteria shall apply for selection of families for foster care, namely:-

- (a) foster parents should have stable emotional adjustment within the family;
- (b) foster parents should have an income in which they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment;
- (c) the monthly family income shall be adequate to take care of foster children and approved by the Committee;
- (d) medical reports of all the members of the family residing in the premises should be obtained including checks on Human Immune Deficiency Virus (HIV) and Hepatitis B to determine that they are medically fit;
- (e) the foster parents should have experience in child caring and the capacity to provide good child care;
- (f) the foster parents should be physically, mentally and emotionally stable;
- (g) the home should have adequate space and basic facilities;
- (h) the foster care family should be willing to follow rules laid down including regular visits to pediatrician, maintenance of child health and their records;
- (i) the family should be willing to sign an agreement and to return the child to the specialized adoption agency whenever called to do so;
- (j) the foster parents should be willing to attend training or orientation programmes;
- (k) the foster parents should be willing to take the child for regular (at least once a month in the case of infants) checkups to a pediatrician approved by the agency; and

(l) Single parents cannot be given foster care of children of the opposite sex, having age difference less than 20 years.

(2) There shall be no discrimination in selection of foster-parents on the basis of caste, religion, ethnic status, disability, or health status and the best interest of the child shall be paramount in deciding foster care placement.

(3) The foster parents shall be declared ‘fit persons’ by the Committee before placing the child as per the provisions laid down in clause (i) of Section 2 of the Act after thorough assessment done by the Child Welfare Officer or Social Worker as per **Form XVI**.

37. Pre-adoption Foster Care.—In case of pre-adoption foster care, the provisions contained in sub-Section (1) of Section 42 and the corresponding guidelines notified under Subsection (3) of Section 41 of the Act, shall apply.

38. Sponsorship.—(1) The State Government shall prepare sponsorship programme in consultation with the Non Governmental Organizations, Child Welfare Committees, other relevant government agencies and the corporate sector.

(2) The State Government, with the help of District or State Child Protection Society/Unit shall identify families and children at risk and provide necessary support services in the form of sponsorship for child’s education, health, nutrition and other developmental needs.

(3) The children’s homes and special homes shall promote sponsorship programmes as laid down in Section 43 of the Act.

(4) The institutions receiving sponsorship, shall maintain proper and separate accounts of all the receipts and payments for the programme.

(5) The Board or the Committee shall make an order in **Form XVIII** for support to a juvenile or child through sponsorship and send a copy to the District or State Child Protection Unit or the State Government for appropriate action.

39. After Care Organisation.— (1) The state Government shall set up an after care programme for care of juveniles or children after they leave special homes and children's homes with the objective to facilitate their transition from an institution-based life to mainstream society for social re-integration.

(2) After care programmes shall be made available for persons up to age group of 18-21 years, who have no place to go to or are unable to support themselves, for the purpose of Section 44 of the Act and this rule.

(3) Once the Board or the Committee passes an order in **Form XIX** for placing a juvenile or a child completing 18 years of age under the after care programme, a copy of such order shall be sent to the District and the State Child Protection Unit and the Director of Social Welfare, who shall be responsible for arranging aftercare. A copy of information shall be made available to the superintendent of the concerned home.

(4) The Board of the Committee shall have jurisdiction over persons placed in after care programme.

(5) The objective of these organizations shall be to enable such children to adapt to society and during their stay in these transitional homes these children will be encouraged to move away from an institution based life to a normal one.

(6) All juveniles or children enrolled into an after care programme must be considered a beneficiary in all appropriate schemes and programmes run by the state government on priority basis.

(7) The key component of the programme shall include:-

- (a) community group housing on a temporary basis for groups of young persons aged 18-21 years;
- (b) imparting vocational training, job oriented training and encouragement to contribute towards the rent or other expenses of the accommodation and maintenance;
- (c) encouragement to gradually sustain themselves without state support and move out of the group home to stay in a place of their own after saving sufficient amount through their earnings;
- (d) provision for a peer counselor to stay in regular contact with these groups to discuss their rehabilitation plans and provide creative outlets for their energy and to tide over crisis periods in their life.

(8) Loans may be arranged for the youth in an after care programme aspiring to set up entrepreneurial activities on the basis of an application made by them and after due verification of the need for such a loan, and necessary professional advice and training shall be made available to the youth in the after care programme in this regard.

(9) The After Care Organization shall facilitate for the issuance of the documents such as Voter's ID Card, Aadhar card, Bank Savings Account, Residence Certificate, etc. in the name of the person enrolled into the after care programme.

40. Linkages and co-ordination.—(1) The State government shall establish effective linkages between various government, non government, corporate and other community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of juvenile or children through the Board or the Committee as the case may be.

(2) The Government shall identify the roles and responsibilities of each department at State or district levels for effective implementation of the Act and the rules and inform them through a notification.

(3) The State Government shall arrange for appropriate training and sensitization of functionaries of these departments from time to time in coordination with any appropriate agency.

(4) The State Government through State or District Child Protection Unit shall develop effective networking and linkages with local non-governmental organizations for specialized

services and technical assistance like vocational training, education, health care, nutrition, mental health intervention, drug de-addiction, legal aid services etc.

(5) Voluntary participation of organization of retired persons, social workers, health, personnel shall be encouraged, to organize workshops, cultural programme, sports, camps counseling and recreational services.

CHAPTER – VI

STANDARDS OF CARE AND INSTITUTIONS

41. Physical infrastructure.— (1) The homes for juveniles in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises.

(2) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(a) Observation Home or Place of Safety:

- (i) Separate observation homes for girls and boys;
- (ii) Classification and segregation of juveniles according to their age group preferably 7-11 years, 12-15 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(b) Special Home:

- (i) Separate special Home for girls above the age of 10 years and boys with further segregation in the age group of 11 to 15 and 16 to 18 years;
- (ii) Classification and segregation of juveniles on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.
- (iii) The State Government shall notify a ‘Place of Safety’ to accommodate juveniles who have been referred by the Board under Section 16 of the Act, in such manner as prescribed from time to time.

(c) Children’s Home:

- (i) Separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for infants.
- (ii) Separate children’s homes for boys and girls in the age group of 6 to 18 years with a further classification and segregation of girls and boys in the age group of 6 to 10 years, 11 to 15 years and 16 to 18 years;

(d) Shelter Home:

- (i) Separate shelter homes for girls and boys;
- (ii) Classification and segregation of girls and boys in the age group of 6 to 10 years, 11 to 15 and 16 to 18 years.

(3) The building or accommodation for an institution with 50 juveniles or children may include space for:-

- (i) 2 Dormitories or living room,
- (ii) 2 Classrooms,
- (iii) Sickroom/First aid room,
- (iv) Kitchen and Dining Hall, Store
- (v) Recreation room or hall, Library,
- (vi) Bathrooms, toilets/latrines,
- (vii) Counseling and guidance room
- (viii) Office rooms,
- (ix) Superintendent’s room,
- (x) Workshop,
- (xi) Residence for Superintendent,
- (xii) Rooms for Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee,
- (xiii) Play ground of sufficient area according to the total number of juveniles or children.

(4) The Superintendent shall stay within the institution and will be provided with quarters and in case he is not able to stay in the home for legitimate reasons (prior written permission of Director, Social Welfare shall be obtained) and in such case any other senior staff member of the

institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children or juvenile and, take decisions in the case of any crisis or emergency.

- (5) (i) the standards of accommodation as per the norms laid down in Rule 41(3) shall be observed to the extent possible and shall include a minimum of following facilities:
 - (a) Dormitory or living rooms: 40 Sq. ft. per juvenile or child.
 - (b) Toilet and bathrooms: at least one for every 8 children.
 - (c) Classroom: 300 Sq. ft for each classroom for 25 children.
 - (d) Sickroom/First aid room: 375 Sq. ft for each room.
 - (e) Workshop: 75 Sq. ft. per juvenile or child.
 - (f) Play ground: Sufficient play ground area shall be provided in every institution according to the total number of juveniles in institution
- (ii) there shall be proper and smooth flooring for preventing accidents;
- (iii) There shall be adequate lighting, ventilation, heating and cooling arrangements, safe drinking water and clean toilets, in terms of gender, age appropriateness and accessibility to persons with disability.
- (iv) All institutions under the Act shall make provision of first aid kit, fire extinguishers in kitchen, dormitories, store rooms, counseling room, periodic review of electrical installations, proper storage and inspection of articles of food stuffs, stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

(6) The Observation Homes and Special Homes shall be child-friendly and in no way shall they look like a jail or lock-up.

42. Clothing and Bedding.— The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each juvenile or child and the minimum standards for clothing and bedding are laid down in **Schedule-I** of these rules (The State Government may make changes in minimum standard as per the needs of a child or a juvenile).

43. Sanitation and Hygiene.— *Every institution shall have the following facilities, namely:-*

- (a) sufficient treated drinking water; water filters shall be installed;
- (b) sufficient water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;
- (c) proper drainage system;
- (d) arrangements for disposal of garbage;
- (e) protection from mosquitoes by providing mosquito nets;
- (f) annual pest control;
- (g) sufficient number of well lit and airy toilets and bathrooms in the proportion of at least one for 8 children;
- (h) sufficient space for washing;
- (i) clean and fly proof kitchen and separate area for washing utensils;
- (j) sunning of bedding and clothing;
- (k) maintenance of cleanliness in the sick room/ first aid room/Medical Centre.

44. Daily Routine.—(1) Every institution shall have a daily routine for the juveniles or children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(2) The daily routine shall provide, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organized recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.

45. Nutrition and Diet Scale.- The following nutrition and diet scale shall be followed by the institutions, namely:-

- (a) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;
- (b) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale set out in **Schedule II** of these rules;
- (c) every institution under this Act shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale specified in **Schedule II** (The State Government may make changes in minimum standard as per the needs of a child or a juvenile);
- (d) Juveniles or children may be provided special meals on holidays and festivals;
- (e) Infants and sick juveniles or children shall be provided special diet according to the advise of the doctor on their dietary requirement.

46. Medical Care.— Every institution shall-

- (a) maintain a medical record of each juvenile or child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;
- (b) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problem;
- (c) have arrangement for the medical facilities, including a doctor on call available on all working days for regular medical check-ups and treatment of juveniles or children;
- (d) have sufficient medical equipments to handle minor health problems including first aid kit with stock of emergency medicines and consumables;
- (e) train all staff in handling first aid;
- (f) tie-up with local Primary Health Centre, government hospital, medical colleges, other hospitals, clinical psychologists and psychiatrists and mental health institutes for regular visits by their doctors and interns and for holding periodic health camps within the institutions;
- (g) make necessary arrangements made for the immunization coverage and maintain proper records in respect thereof;
- (h) take preventive measures against out break of contagious or infectious diseases;
- (i) set up a system for referral of cases with deteriorating health or serious cases to the nearest civil hospital or recognized treatment centres;
- (j) keep sick children under constant medical supervision;
- (k) admit a juvenile or child without insisting on a medical certificate at the time of admission;
- (l) arrange for a medical examination of each juvenile or child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty four hours and in special cases or medical emergencies immediately;
- (m) arrange for a medical examination of the juvenile or child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;
- (n) not carry out any surgical treatment on any juvenile or child without the previous consent of his parent or guardian, unless either the parent or guardian cannot be found and the condition of the juvenile or child is such that any delay shall, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the juvenile or child, or otherwise without obtaining a written consent to this effect from the superintendent of the institution;
- (o) provide or arrange for regular counselling of every juvenile or child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution;
- (p) refer such children who require specialized drug abuse prevention and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified

personnel where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the concerned child.

47. Mental Health.— (1) A mental health record of every juvenile or child shall be maintained by the concerned institutions.

(2) Both milieu-based interventions that is creating an enabling environment for children and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, milieu based intervention is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take decisions regarding their life and thus, they develop and identify beyond their negative experiences and such intervention has a critical emotional impact on the child.

(3) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing juveniles or children to cope with their situation and regain confidence.

(4) All persons involved in taking care of the juveniles or children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists.

(5) Individual therapy is a specialized process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.

(6) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar government and non-governmental agencies, for specialized and regular individual therapy for every juvenile or child in the institution.

(7) A mental health care plan shall be developed for every juvenile or child by the child welfare officers in consultation with mental health experts associated with the institution and integrated into the individual care plan of the concerned juvenile or child.

(8) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file and integrated into the care plan for every child.

(9) All care plans shall be produced before the Management Committee set up under Rule 56 of these rules every month and before the Child Welfare Committee every quarter.

(10) No juvenile or child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by appropriately trained mental health professionals.

48. Education.—(1) Every institution shall provide formal, non-formal and life skill education to all juveniles or children according to the age and ability, both inside the institution or outside, as per the requirement.

(2) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, open schooling, non formal education and learning and input from special educators where needed.

(3) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centers.

49. Vocational Training.— (1) Every institution shall provide gainful and market oriented income generating vocational training to juveniles or children.

(2) The institutions shall develop networking with recognized Institute of Technical Instruction, Jan Shikshan Sansthan, Government and Private Organization or Enterprises, Agencies or nongovernmental organizations with expertise or placement agencies.

(3) Superintendent of the institution shall make reasonable efforts for placement of children of 16-18 years of age as an apprentice.

50. Recreation facilities.— (1) A provision of guided recreation shall be made available to all juveniles or children in the institutions.

(2) It shall include indoor and outdoor games, music, television, picnics and outings, cultural programmes and library.

(3) Every institution shall provide materials, toys, games in sufficient quantity to all children for recreational activities.

51. Institutional Management of juveniles or children.— (1) The following procedure shall be followed in respect of the newly admitted juvenile:

- (a) receiving and search. The girl juvenile or child shall be searched by a female member of the staff, and both the girl and boy shall be searched with due regard to decency and dignity;
- (b) disinfection and storing of juvenile's personal belongings and other valuables, entry of belongings in a separate register;
- (c) bath and haircut (unless prohibited by religion);
- (d) issue of toiletry items, new set of clothes, bedding and other outfit and equipment (as per scales);
- (e) medical examination and treatment where necessary and in case of every juvenile suspected to be suffering from contagious or infectious diseases, mental ailments or addiction;
- (f) segregation in specially earmarked dormitories or wards or hospitals in case of a child suffering from contagious disease requiring special care and caution;
- (g) attending to immediate and urgent needs of the juveniles like appearing in examinations, interview, letter to parents, personal problems and verification by the superintendent of age of juvenile as per order of the Board or the Committee.

(2) Every newly admitted juvenile or child shall be allotted a case worker from amongst the probation officers or child welfare officers or professionally trained social workers or counselors attached to the institution or professionally trained voluntary social workers or counselors.

(3) Every newly admitted juvenile shall be familiarized with the institution and its functioning and shall receive orientation in the following areas:

- (a) personal health, hygiene and sanitation;
- (b) institutional discipline and standards of behaviour, respect for elders and teachers;
- (c) daily routine, peer interaction, optimum use of developmental opportunities; and
- (d) rights, responsibilities and obligations within the institution.

(4) The designed officer shall enter the name of the juvenile or child in the Admission Register and allocate appropriate accommodation facility.

(5) The photograph shall also be taken immediately for records and the case worker or probation officer or welfare officer shall begin the investigation and correspondence with the person, the juvenile or child might have named.

(6) The Superintendent shall see that the personal belongings of the juvenile or child received by the institution is kept in safe custody and recorded in the Personal Belonging Register and the item must be returned to the juvenile or child when he leaves the institution.

(7) The educational level and vocational aptitude of the juvenile admitted, may be assessed on the basis of test and interview conducted by the teacher, the workshop supervisor and other technical staff and necessary linkages may also be established with outside specialists and community-based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and local doctors, open school or Jan Sikshan Sansthan.

(8) A case history of the juvenile or the child admitted to an institution shall be maintained as per **Form XX**, which shall contain information regarding his socio-cultural and economic background and this information may invariably be collected through all possible and available sources, including home, parents or guardians, employer, school, friends and community.

(9) A well conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from special homes shall be organized in all institutions in close collaboration with existing governmental and voluntary welfare organizations.

(10) In the event of a juvenile or child leaving the institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the Superintendent of the concerned institution to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the juvenile or child where the juvenile or child is missing, shall be sent to the Board or the Committee, as the case may be.

(11) An individual care plan for every juvenile or child in institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re-integrated based on their case

history, circumstances and individual needs and the individual care plan shall be based on following guidelines:

- (a) the Superintendent along with the child welfare officer or case worker, or social worker shall prepare an individual care plan for every child in an institution within one month of his admittance as per Form **XXI**;
- (b) all care plans shall include a plan for the juvenile's or child's restoration, rehabilitation, reintegration and follow-up;
- (c) the care plan shall be reviewed quarterly by the Management Committee set up under rule 62 of these rules for appropriate development and rehabilitation including options for release or restoration to family or sponsorship or foster care or adoption;
- (d) juveniles or children shall be consulted while determining their care plan;
- (e) continuity of care plan shall be ensured in cases of transfer or repatriation or restoration.

52. Prohibited Articles.—No person shall bring into the institution the following prohibited articles, namely:

- (a) fire-arms or other weapons, whether requiring license or not (like knife, blades, lathe, spears and swords);
- (b) alcohol and spirit of any description;
- (c) bhang, ganja, opium or other narcotics or psychotropic substances;
- (d) tobacco, cigarette, gutkha; or
- (e) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

53. Articles found on search and inspection.— (1) The Superintendent shall see that every juvenile received in the institution is searched, without adversely affecting the dignity of the juvenile, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the juvenile is kept in the safe custody of the Superintendent/officer-in-charge.

(2) The girls shall be searched by a female member of the staff and both the girls and boys shall be searched with due regard to decency and dignity.

(3) In every institution, a record of money, valuables and other articles and found with a juvenile shall be maintained in the "Personal Belongings Register".

(4) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each juvenile, shall be read over to juvenile in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Superintendent.

54. Disposal of articles.— The money or valuables belonging to a juvenile received or retained in an institution shall be disposed of in the following manner, namely:

- (a) on an order made by the competent authority in respect of any juvenile, directing the juvenile to be sent to an institution, the Superintendent shall deposit such juvenile's money together with the sale proceeds in the manner laid down from time to time in the name of the juvenile;
- (b) the juvenile's money shall be kept with the Superintendent and valuables, clothing, bedding and other articles, if any, shall be kept in safe custody;
- (c) when such juvenile is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be sent along with the juvenile to the Superintendent of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description and estimated value thereof;
- (d) at the time of release of such juvenile, the valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in name of the juvenile shall be handed over to the juvenile or the child himself or the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the Superintendent;
- (e) when a juvenile in an institution dies, the valuable and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the juvenile shall be handed over by the Superintendent to any person who establishes his claim thereto and executes an indemnity bond;

- (f) a receipt shall be obtained from such person for having received such valuables and other articles and the amount;
- (g) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of such juvenile, the valuables and other articles and amount shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee set up under Rule 56 of the rules. Any money shall be deposited in the Fund as described in Section 61 of the Act.

55. Maintenance of case file. — (1) The case file of each juvenile and child shall be maintained in the institution containing the following information;

- (a) report of the person or agency who produced the juvenile before the Board;
- (b) Superintendent's, probation officer's or child welfare officer's, counselor's and caseworker's reports;
- (c) information from previous institution, if any;
- (d) report of the initial interaction with the juvenile, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;
- (e) source of further information;
- (f) observation reports from staff members;
- (g) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, progress reports vis-à-vis psychological counselling or any other mental health intervention, where applicable;
- (h) Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, educational or vocational tests;
- (i) social history;
- (j) summary and analysis by case-worker and Superintendent;
- (k) instruction regarding training and treatment programme and about special precautions to be taken;
- (l) leave and other privileges granted;
- (m) special achievements and violation of rules, if any;
- (n) quarterly progress reports;
- (o) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed in **Form XXI**;
- (p) leave of absence or release under supervision;
- (q) final discharge;
- (r) follow-up reports;
- (s) annual photograph;
- (t) case history duly filled in prescribed **Form XX**;
- (u) follow-up report of post release cases as per direction of the competent authority if any; and;
- (v) remarks.

(2) All the case files maintained by the institutions and the Board or Committee shall, as far as possible, be computerized and networked so that the data is centrally available to the State and the District Child Protection Unit and the State Government.

56. Management Committee.— (1) Every institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every juvenile and child, constituted through an order of the concerned District Child Protection Unit.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, a juvenile or child shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay order.

(3) The Management Committee shall consist of the following persons:

- (i) District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)- Chairperson
- (ii) Superintendent- Member-Secretary
- (iii) Probation officer or child welfare officer or Case Worker- Member
- (iv) District Medical Officer-Member
- (v) Psychologist or counselor- Member
- (vi) Workshop supervisor or Instructor in Vocation-Member
- (vii) Teacher- Member

- (viii) Social Worker Member of Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee-Member
- (ix) A Juvenile or child representative from each of the Children's Committees (on a monthly rotation basis to ensure representation of juveniles of children from all age groups)-Member
- (x) A representative from senior citizen forum and/or Resident welfare Association-Member
- (xi) One Non-government organization Representative-Member
- (4) Where voluntary organization are involved in providing professional and technical services like education, vocational training, psychosocial care, mental health intervention and legal aid, the Management Committee may invite four representatives of such voluntary organization as a special invitee to the Management Committee meetings.
- (5) In the district where District Child Protection Unit is not constituted, the District Magistrate shall be the Chairperson of this committee.
- (6) (a) The Management Committee shall meet as frequently as possible but at least once in every three months to consider and review;
 - (i) custodial care or care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;
 - (ii) medical facilities and treatment;
 - (iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;
 - (iv) mental health interventions with the juveniles and children;
 - (v) individual problems of juveniles and children, provision of legal aid services and institutional adjustment, leading to the quarterly review of individual care plans;
 - (vi) vocational training and opportunities for employment;
 - (vii) education and life skills development programmes;
 - (viii) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counseling;
 - (ix) review of progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the juveniles and children;
 - (x) planning post-release or post-restoration rehabilitation programme and follow-up for a period of two years in collaboration with aftercare services;
 - (xi) pre-release or pre-restoration preparation;
 - (xii) release or restoration;
 - (xiii) post release or post-restoration follow-up;
 - (xiv) minimum standards of care, including infrastructure and services available;
 - (xv) daily routine;
 - (xvi) community participation and voluntarism in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;
 - (xvii) oversee that all registers as required under the Act and rules are maintained by the institution, check and verify these registers, duly stamped and signed in the monthly review meetings;
 - (xviii) matters concerning the Children's Committees;
 - (xix) any other matter which the Superintendent may like to bring up.
- (b) The Superintendent shall file a quarterly progress report of every juvenile or child in the case file and send a copy to the District Child Protection Unit and Board or Committee, as the case may be.
- (7) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible or rooms or dormitories of the children.
- (8)(a) The Children Suggestion Box, whose key shall remain in the custody of the Chairperson of the Management committee, shall be checked every week by the Chairperson of the Management committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

- (b) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.
- (c) The quorum for conducting the emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of Child Welfare Committee or the Board as the case may be and the Superintendent of the institution.
- (d) In the event of a serious allegation or complaint against the Superintendent of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.
- (e) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the quarterly meeting of the Management Committee.

(9) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after quarterly meeting of the Management Committee.

(10) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once in six months.

57. Children's Committees.—(1) Superintendent of every institution for juveniles or children shall facilitate the setting up of Children's Committee for three different age group of children, viz., 6-10 years, 11-15 years and 16-18 years and these Children's Committee shall be constituted solely by children. There may be cleaning and hygiene committee, education and vocational training committee, sports and cultural committee, recreational committee etc.

(2) Such Children's Committee shall be encouraged to participate in following activities:-

- (a) improvement of the condition of the institution;
- (b) reviewing the standards of care being followed;
- (c) preparing daily routine and diet scale;
- (d) developing educational, vocational and recreation plans;
- (e) supporting each other in managing crisis;
- (f) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;
- (g) creative expression of their views through wallpapers or newsletters or paintings or music or theater;
- (h) management of institution through the Management Committee.

(3) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees meet every month and maintain a register for recording its activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their quarterly meetings.

(4) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.

(5) The local voluntary organization or counselor may support the Children's Committees in the following:-

- (a) selecting their leaders;
- (b) conducting the monthly meetings;
- (c) developing rules for the functioning of Children's Committees and following it;
- (d) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents;
- (e) any other innovative activity.

(6) The Management Committee shall seek a report from the Superintendent on the setting up and functioning of the Children's Committees, review these reports in their quarterly meetings and take necessary action where required.

58.Rewards and Earnings. — The rewards to a juvenile or child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, shall be granted by the Superintendent as an encouragement to steady work and good behaviour and at the time of release, the reward shall

be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian who comes to take charge of the juvenile or child or juvenile or child himself.

59. Visits to and communication with juveniles or children.— (1) The parents and relatives of the juveniles or children shall be allowed to visit at least twice in a month or in special cases, more frequently at the discretion of the Superintendent as per the visiting hours laid down by him, except where parents or relatives or guardian have been found to be responsible for subjecting the juvenile or child to violence, abuse and exploitation.

(2) The receipt of letters by the juveniles or children of the institution shall not be restricted and they shall have freedom to write as many letters as they like at all reasonable times and the institution shall ensure that where parents, guardians or relatives are known, at least one letter is written by the juvenile or children every month for which the postage shall be provided by the institution.

(3) The Superintendent may peruse any letter written by or to the juvenile or children, and may for the reasons that he considers sufficient refuse to deliver or issue the letter and forward it to the Committee after recording his reasons in a book maintained for the purpose.

(4) The Superintendent shall, in special circumstances or as per orders of the Board or Committee, allow a juvenile or child to make telephonic communication with his parents or guardians or relatives.

60. Death of a juvenile or child.— On the occurrence of any case of death or suicide in an institution the procedure to be adopted shall be as under: -

(1) In the event of an unnatural death or suicide of a juvenile or child in an institution it is imperative for the institution to ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.

(2) In case of natural death or due to illness of a juvenile or child, the Superintendent shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the State Government, nearest Police Station, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other concerned authority and the parents or guardians or relatives of the juvenile or child.

(3) Whenever a sudden or violent death or death from suicide or accident takes place, immediate information shall be given by the case worker or probation officer or welfare officer to the Superintendent and the Medical Officer and the Superintendent shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and parents or guardians or relatives of the deceased juvenile or child.

(4) If a juvenile or child dies within twenty four hours of his admission to the institution, the Superintendent of the institution shall report the matter to the Officer in charge of the Police Station having jurisdiction and the District Medical Officer or the nearest Government Hospital and the parents or guardians or relatives of such juvenile or child without delay.

(5) The Superintendent shall also immediately give intimation to nearest Magistrate empowered to hold inquests and to the Board or as the case may be the Committee.

(6) The Superintendent and the Medical Officer at the institution shall record the circumstance of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the Officer in charge of the police station having jurisdiction, the Committee and the District Medical Officer or the nearest government hospital where the dead body of the juvenile or child is sent for examination, inspection and determination of the cause of death and the Superintendent and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of the death and submit it to the concerned Magistrate and the Officer in charge of the police station having jurisdiction.

(7) The Superintendent and the Medical Officer shall make themselves available for any inquiries initiated by the police or the Magistrate concerning the cause of death and other details regarding such juvenile or child.

As soon as the inquest is held, the body shall be handed over to the parents or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Superintendent in accordance with the known religion of the juvenile or child.

61. Abuse and exploitation of the juvenile or child.— (1) Every institution shall ensure the observance of the Protocol for prevention and protection of children from abuse, exploitation and neglect and maltreatment within the institutions, as prescribed by the State Government from time to time.

(2) Superintendent of the institution shall ensure that there is no abuse, neglect and maltreatment and this include the staff being aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment as well as early indicators of abuse, neglect and maltreatment and how to respond to these.

(3) The following action shall be taken in the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of juveniles and children in an institution by those responsible for care and protection:-

- (i) the incidence of abuse and exploitation or any crime must be reported by any staff member of the institution immediately to the Superintendent;
- (ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Superintendent, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn, shall order for special investigation.
- (iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance of such occurrences and conduct necessary investigations;
- (iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of all inquiry and provide protection, legal aid as well as counseling to the juvenile or child victim;
- (v) the Board or Committee shall transfer such a juvenile or child to another institution or place of safely or fit person;
- (vi) in the event of any other crime committed in respect of juveniles or children in institutions, the Board or committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police station or Special Juvenile Police Unit;
- (vii) the superintendent of the institution shall also inform the chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken before the Management Committee in its next meeting;
- (viii) the Board or Committee may consult Children's Committee set up in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from relevant voluntary organizations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of juveniles or children in an institution.

62. Mode of dealing with Child suffering from dangerous diseases or mental health problems.— (1) When a child kept in an institution under the provisions of the Act or under care of a fit person or a fit institution is found to be suffering from a disease or physical or mental health problems requiring prolonged medical treatment or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance, the child shall be transferred by an order of the competent authority to an approved place set up for the purpose for the remainder of the term for which he has to be kept in custody under the order of the competent authority or for such period as may be certified by medical officer to be necessary for the proper treatment of the child.

(2) Where it appears to the authority ordering the transfer of the child under sub rule (1) above that the child is cured of disease or physical or mental complaint the child is still liable to be kept in custody, order the person having charge to send to the institution or fit person from which or from whom he was transferred or if the child's is no longer required to be kept in home, order him to be discharged.

(3) Where action has been taken under sub-rule (1) in the case of a child suffering from an infectious or contagious disease, the authority empowered under the sub rule before restoring the said child to his parent or to the guardian, as the case may be, where it is satisfied that such action will be in the interest of the said child, call upon parents or the guardian, as the case may be, to satisfy it that such parents or guardian not re-infect the child.

(4) Where there is no organization either within the jurisdiction of the competent authority, or nearby District or State for care and protection of juveniles or children suffering from serious psychiatric or physical disorder and infection, as required under Section 58 of the Act, the child or the juvenile shall be referred to a suitable place or institution, as it may deem fit to cater to the special needs of such juveniles or children.

63. Leave of absence of a juvenile or child.—(1) A juvenile or child in an institution may be allowed to go on leave of absence or released under supervision for examination or admission, special occasions like marriage or emergencies like death or accident or serious illness in the family.

(2) While the leave of absence for short period generally not exceeding seven days excluding the journey time may be recommended by the Superintendent, but granting of such leave shall be by the Board or Committee.

(3) The parents or guardian of the juvenile or the Superintendent on behalf of the juvenile or child may submit an application to the Board or Committee requesting for relieving the juvenile or child on leave, stating clearly the purpose for the leave and the period of leave.

(4) While considering the application of leave of absence, the Board or Committee shall hear the juvenile or child or the parents or guardians of the juvenile or child and if the Board or Committee considers that granting of such leave is in the interest of the juvenile or child, appropriate order shall be made and the Board or Committee may call for a report from the probation officer or child welfare officer in case the preliminary information gathered from the juvenile or child or concerned parent or guardian is not sufficient for the purpose.

(5) While issuing orders sanctioning the leave of absence or relieving under supervision, as the case may be, the competent authority shall mention the period of leave and the conditions attached to the leave order, and if any of these conditions are not complied with during the leave period, the juvenile or child may be called back to the institution.

(6) The parent or guardian shall arrange to escort the juvenile or child from and to the institution and where this is not possible, the Superintendent may arrange to escort the juvenile or child to the place of the family and back. In case the parents or guardian is willing to arrange escort but does not have requisite financial means, the Superintendent shall arrange for the traveling expenses as admissible under the rules.

(7) If the juvenile or child runs away from the family during the leave period, the parent or guardian is required to inform the Superintendent of the institution immediately, and try to trace the juvenile or child and if found, the juvenile or child shall be brought back to the institution immediately.

(8) If the juvenile or child is not found within twenty four hours, the Superintendent shall report the matter to the nearest police station and missing person's bureau, but no adverse disciplinary action shall be taken against the juvenile or child and procedure laid down under the Act shall be followed.

(9) If the parent or guardian does not take proper care of the juvenile or child during the leave period or does not bring the juvenile or child back to the institution within the stipulated period, such leave may be refused on later occasions.

(10) If the juvenile or child does not return to the institution on expiry of the sanctioned leave, the Board or Committee shall refer the case to police for taking charge of the juvenile and bring him back to the institution.

(11) The period of such leave shall be counted as a part of the period of stay in the institution and the time which elapses after the failure of a juvenile to return to the institution within the stipulated period, shall be excluded while computing the period of his stay in the institution.

64. Inspection. — (1)The State Government shall constitute State, District or City level inspection committee on the recommendation of Selection Committee, constituted under Rule 89 of these rules, for a period of 3 years.

(2) The inspection committee shall visit and oversee the conditions in the institutions and appropriateness of the processes for safety, well being and permanence, review the standards of care and protection being followed by the institutions, look out for any incidence of violation of child rights, look into the functioning of the Management Committee and Children's Committees set up under Rules 56 and 57 of these rules and give appropriate directions.

(3) The team shall also make suggestions for improvement and development of the institution.

(4) The team shall consist of seven members with representation from the Judiciary/State Government, local authority, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights or the State Human Rights Commission, medical and other experts, voluntary organizations and reputed social workers.

(5) The inspection shall be carried out at least once in every three months.

(6) The inspection visit shall be carried out by not less than three members.

(7) The team shall visit the institutions either by prior intimation or make a surprise visit.

(8) The team shall interact with the children during the visits to the institution, to determine their well being and uninhibited feedback.

(9) The follow up action on the findings and suggestion of the children shall be taken by all concerned authorities.

(10) The action taken report, finding and suggestions from the Inspection Committee shall be sent to the District Child Protection Unit and the State Government.

65. Social Audit.—(1)The State Government shall monitor and evaluate the implementation of the Act annually by reviewing matters concerning establishment of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit where required, functioning of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit, functioning of institutions and staff, functioning of adoption agencies, child friendly administration of juvenile justice and any other matter concerning effective implementation of the Act in the State.

(2) The Social audit shall be carried out with support and involvement of organizations working in the field of mental health, child care and protection and public accountability.

66. Restoration and Follow-up.— (1) The order for restoration of the juvenile or child shall be made by the Board or Committee on the basis of a fair hearing of the juvenile or child and his parents or guardian, as well as on the reports of the Probation Officers or Child Welfare Officers or non-governmental organizations directed by the Board or Committee to conduct the home study and any other relevant document or report brought before the Board or Committee for deciding the matter.

(2) The Board or Committee shall send a copy of the restoration order along with a copy of the order for escort as per **Form XXII** to the District Child Protection Unit or State Government who shall provide funds for restoration of the juvenile or child.

(3) Every restoration shall be planned for as part of the individual care plans prepared by the case-workers or counselors or child welfare officers or probation officer, as the case may be, and shall be based on the review and recommendations of the Management Committee set up under Rule 56 of these rules.

(4) Besides police, the Board or Committee may seek collaboration with non-governmental organizations to accompany juveniles or children back to their family for restoration.

(5) In case of girls, the juvenile or child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(6) The expenses incurred on restoration of a juvenile or child, including travel and other incidental expenses, shall be borne by the District Child Protection Unit or State Government, if directed by the competent authority.

(7) When a juvenile or child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or Committee shall make a note of it in its records in writing and such juvenile or child shall not be coerced or persuaded to go back to the family, particularly if the social investigation report of the child welfare officer or probation officer establishes that restoration to family may not be in the best interest of the juvenile or child or, if the parents or guardians refuse to accept the juvenile or child back.

(8) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations assigned by the Board or Committee to assist in restoration of the child.

(9) A quarterly follow up report shall be submitted to the Board or Committee by the concerned Child Welfare Officer or Probation Officer or non-governmental organization for a period

of two years with a copy to the superintendent of the institution from where the juvenile or child is restored.

(10) The follow up report shall clearly state situation of the juvenile or child post restoration and the juvenile's or child's needs to be met by State Government in order to reduce further vulnerability of the juvenile or child.

(11) The Superintendent shall file the follow up report in the case-file of the juvenile or child and place the report before the Management Committee set up under Rule 56 of these rules in its next meeting.

(12) The Superintendent shall also send a copy of the follow up reports to the District Child Protection Unit.

(13) Where a follow up is not possible due to unavailability of government functionaries or non-governmental organizations, the concerned District Child Protection Unit shall provide necessary assistance and support to the concerned Board or Committee.

67. Visitor's Book.— (1) A Visitor's Book shall be maintained, in every institution, in which the person visiting the home shall record the date of his visit with remarks or suggestions, which he may think proper.

(2) The Superintendent shall forward a copy of every such entry to the District Child Protection Unit or Director of Social Welfare, with such remarks as he may desire to offer in explanation or otherwise; and thereon, the designated authority shall issue such orders as he may consider necessary.

68. Maintenance of Registers.— The Superintendent shall maintain in his office, registers and forms, as required by the Act and as specified by these rules made thereunder and the list of registers or files or books to be maintained shall minimally comprise of,-

- (a) Admission and discharge register;
- (b) Supervision register;
- (c) Medical file or medical report;
- (d) Nutrition diet file;
- (e) Stock register;
- (f) Log book;
- (g) Order book;
- (h) Meeting book;
- (i) Cash book;
- (j) Budget statement file;
- (k) Inquiry report file;
- (l) Individual case file with individual care plan;
- (m) Children's suggestion book;
- (n) Visitor's book;
- (o) Staff movement register;
- (p) Personal belongings register;
- (q) Minutes register of Management Committee;
- (r) Minutes register of Children's Committees;
- (s) Attendance register for staff and juveniles or children;
- (t) complaint & action taken report register; and
- (u) rewards & punishment register of inmates.

69. Personnel or Staff of a Home. — (1) The personnel strength of a home and the number of posts in each category shall be determined by the State Government.

(2) The institutional organizational set up shall be fixed in accordance with the size of the home, the capacity, workload, distribution of functions and requirements of programmes.

(3) The whole-time staff in a home may consist of Superintendent, Probation Officer (in case of Observation home or Special home), Case Workers (in case of Children's home or shelter home or after care organization), Counselor, Educator, Vocational Training Instructor, Medical Staff, Administrative staff, Care Takers, volunteers, store keeper, cook, helper, washerman, safai karamchari, gardener as required.

(4) The part-time staff, shall include Psychiatrist, Psychologist, Occupational therapist, and other professionals as may be required from time to time.

(5) The staff of the home shall be subject to control and overall supervision of the Superintendent who by order, shall determine their specific responsibilities and shall keep the concerned authority informed of such orders made by him from time to time.

(6) The duties and responsibilities of the staff under the Superintendent shall be fixed in keeping with the statutory requirements of the Act.

(7) The staff shall be appointed in accordance with the rules prescribed by the State Government.

(8) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 50 juveniles or children could be as mentioned below:-

Sl.	Staff/Personnel	No. of Posts
1	Officer-in-Charge (Superintendent)	1
2	Counsellor	1
3	Probation Officer or Case Worker	1
4	House Mother or House Father (one for every 25 children)	2
5	Educator (voluntary or part time)	1
6	PT Instructor cum Yoga Trainer (voluntary or part time)	1
7	Doctor (voluntary or part time)	1
8	Art and Craft-cum- Music Teacher (voluntary or part time)	1
9	Paramedical staff	1
10	Store-keeper cum Accountant	1
11	Cook	1
12	Helper	1
13	Housekeeping staff	2
14	Security Guards	3
Total		18

(9) In case of institutions housing infants or children up to 12 years of age or physically or mentally challenged ones provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per the need.

70. Duties and responsibilities of Superintendent of an institution.—(1)The Superintendent shall have the primary responsibility of maintaining the institution and shall stay within the institutional premises to be readily available as and when required by the juvenile or children and the staff and in case where an accommodation is not available within the institutional premises, the Superintendent shall stay at a place in close proximity to the institution till such time that such an accommodation is made available within the institution.

(2) The general duties and functions of the Superintendent shall include:

- (a) compliance with provisions of the Act and the rules and orders made there under;
- (b) compliance with the orders of the Board or Committee;
- (c) providing homely atmosphere of love, affection, care, development and welfare for juveniles or children;
- (d) maintaining minimum standards of care in the institution.
- (e) proper maintenance of buildings and premises;
- (f) security measures and periodical inspection, including daily inspection and rounds of the institution, proper storage and inspection of food stuffs as well as food being served;
- (g) supervision and monitoring of juvenile's or children's discipline and well being;

- (h) planning, implementation and coordination of all institutional activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;
- (i) prompt action to meet emergencies including regular fire drills and evacuation plan;
- (j) ensuring accident and fire preventive measures within the institutional premises;
- (k) stand by arrangements for water storage, power plant, emergency lighting;
- (l) careful handling of plants and equipments;
- (m) segregation of a juvenile or child suffering from contagious or infectious diseases;
- (n) observance and follow up of daily routine;
- (o) filling of monthly report of juvenile or child in the case file;
- (p) organize local and national festivals in the institution;
- (q) organize recreational activities including trips or excursions or picnics for juveniles or children;
- (r) preparation of budget and control over financial matters;
- (s) allocation of duties to personnel;
- (t) supervision over office administration, including attending to personnel welfare and staff discipline;
- (u) prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;
- (v) organize the meetings of the Management Committee and provide necessary support;
- (w) maintenance of all documents and registers required under the Act and the rules;
- (x) liaison, coordination and cooperation with the District Child Protection Unit or State Government as and when required; and
- (y) coordination with the legal officer in the District Child Protection Unit to ensure that every juvenile is legally represented and provided free legal aid and other necessary support or, where the District Child Protection Unit has not been set up, services of the District or State Services Authority shall be made available.
- (z) organize children committee meetings and provide necessary support.

(3) The Superintendent also have the other duties **like:-**

- (i) to ensure the Rights of child in all possible manner within the frame of these rules and regulations;
- (ii) he shall exercise control over the staff and shall issue instructions for the smooth and effective functioning of the institutions;
- (iii) the Superintendent shall ensure that all the staff are discharging their duties in accordance with the rules and regulations and the children are provided with quality and quantity of food, educational and vocational training in accordance with the aptitude and need base of the children, control over budget and accounts, financial management of the institution, propose plan and non-plan schemes for the further development of the institution;
- (iv) the Superintendent of the institution shall be the custodian of important confidential documents, deeds, agreements, personal files of staff, valuable articles of children etc;
- (v) the Superintendent shall be responsible for safe drinking water, proper sanitary and hygienic conditions in the institution, proper health care of children/juveniles etc;
- (vi) the Superintendent shall pay surprise visits at least once in fortnight during night and ensure that the institutional management is in control and vigil during night;
- (vii) the Superintendent shall nurture a congenial relationship among inmates and convene the meetings of various committees and conduct the proceedings and supervise that the decisions of the Committees are implemented effectively;he
- (viii) shall be responsible for evolving a rehabilitation plan for every child.

71. Duties of Deputy Superintendent.— The duties and responsibilities of Deputy Superintendent will be as follows:-

- (a) Custodian of placement orders.
- (b) Supervision of food preparation, food distribution and maintenance of related records etc.
- (c) To conduct open house meeting with children and staff to encourage children's participation in the activities.
- (d) To conduct interviews with parents of children and regulation of communication of children with outsiders.
- (e) To facilitate the children to participate in seminars, cultural programmes, meetings etc.
- (f) Monitor the application of positive reinforcement/cognitive restructuring, prepare a status report in consultation with the house parents or wardens.
- (g) To monitor the supply of external eatables if any supplied to children by parents.
- (h) Custodian of clothing and bedding being supplied to Children's Home.
- (i) Organization of camps, picnics, cultural programmes, extra-curricular activities like Scouts, Red Cross work etc
- (j) To see that the protective and developmental rights of children are ensured.
- (k) Ensuring that the children's need of food and cloth are met as per standard..
- (l) Ensuring the cleanliness of the premises and maintenance of physical infrastructure including provisions of water and electricity etc.
- (m) Any other duties and responsibilities assigned by the Superintendent. In the absence of the post of Deputy Superintendent the work shall be performed by the Superintendent.

CHAPTER – VII MISCELLANEOUS

72. Recognition of fit persons or fit institution.— (1) Any individual who is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care, protection or treatment for a period as may be necessary, may be recognized by the competent authority as a fit person after due verification of their credentials and reputation.

(2) Any suitable place or institution, the manager of which is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care and protection for a period as may be necessary, may be recognized by the State Government as a fit institution on the recommendation of the competent authority.

(3) An institution recognized as a fit institutions shall,—

- (a) meet the standards of care laid down in the Act and the rules made thereunder;
- (b) have the capacity and willingness to meet the standards of care laid down in the Act and the rules;
- (c) receive and provide basic services for care and protection of the juveniles and children;
- (d) prevent subjection of juvenile or child to any form of cruelty or exploitation or neglect; and
- (e) abide by the orders of the competent authority.

(4) A list of fit institutions approved by the State Government shall be kept in the office of the Board and the Committee.

(5) A fit institution with collateral branches may send the juvenile or child placed therein by an order of the competent authority to any of its branches after seeking permission from the competent authority.

(6) Before declaring any person as a fit person or recommending an institution as a fit institution, the competent authority shall hold due enquiry and only on being satisfied, recognition shall be given.

73. Certification or recognition and transfer of Management of Institutions and After Care Organizations.— (1) Any organization requiring certification under the Act shall make an application together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past record of specialized child care services provided by the organization, to the State Government, along with a copy to competent authority. The state government shall after getting verified the provisions made by the organization for the boarding and lodging, general health, educational facilities, vocational training and treatment services may grant certification or recognition for a maximum period of 3 years at a time, under Sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act, as the case may be, on the condition that the organization shall comply with the standards or services as laid down under the Act and the rules framed there under, from time to time and to ensure an all round growth and development of juvenile or child placed under its charge.

(2) Any organization desiring recognition under the Act shall make an application to the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government from time to time. The competent authority, within a month of receipt of the application, shall after due inquiry, recommend or advise the state government for such recognition.

(3) The State Government may, transfer the management of any State run institution under the Act to a voluntary organization, who has the capacity to run such an institution; and certify or recognize the said voluntary organization as a fit institution to own the requisite responsibilities under a Memorandum of Understanding for a specified period of time.

(4) The State Government may, if dissatisfied with the conditions, rules, management of the organization certified or recognized under the Act, at any time, by notice served on the manager of the organization, declare that the certificate or recognition of the organization, as the case may be, shall stand withdrawn as from a date specified in the notice and from the said date, the organization shall cease to be an organization certified or recognized under Sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act, as the case may be:

Provided that the concerned organization shall be given an opportunity of making a representation in writing, within a period of thirty days, against the grounds of withdrawal of certificate or recognition of that organization.

(5) The decision to withdraw or to restore the certificate or recognition of the organization may be taken, on the basis of a thorough investigation by the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government.

(6) On the report of the District Child Protection Unit or such other authority, the Officer-in-charge of the institution shall be asked to show cause so as to give an explanation within thirty days.

(7) When an organization ceases to be an organization, certified or recognized under Sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act, the juvenile or the child kept therein shall, be transferred to some other institution of like nature, certified or recognized under Sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act or discharged, in accordance with the provisions of the Act and the rules relating to their discharge and transfer by giving intimation of such discharge or transfer to the Board or the Committee, as the case may be.

74. Registration under the Act.— (1) All institutional care services for children in need of care and protection, whether run by Government or voluntary organization, shall get themselves registered under sub-Section (3) of Section 34 of the Act.

(2) All such institutions shall make an application together with a copy each of rules, byelaws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, balance sheet of past three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organization to the State Government, who shall after verifying that provisions made in the institution or organization for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, if any, vocational facilities and scope of rehabilitation, may issue a registration certificate to such organization under sub-Section (3) of Section 34 of the Act and as per this rule.

75. Grant in aid to certified or recognized organization.— (1) An organization certified or recognized or registered under Sections 8, 9, 34, 37, 41 or 44 of the Act may during the period of certification or recognition in force, may apply for grants in aid to the State Government for

maintenance of children received by them under the provision of Act and for expenses incurred on their education, treatment, vocational development and rehabilitation; and the government may sanction the amount as per availability of funds.

(2) The grants-in-aid shall not be admissible if the organization is receiving grant in aid under Orphanage Control Board or from foreign sources.

(3) In case of transfer of management of government run homes under Sections 8, 9, 34, 37, 44, sub Section (3) of Section 34, sub Section (4) of Section 44 of the Act to a voluntary organization, the same budget which the Government was spending on that home, shall be given to the voluntary organization as grant-in-aid under the Memorandum of Understanding signed between both the parties describing their role and obligations.

76. Admission of outsiders.—(1) No stranger shall be admitted to the premises of the institution, except with the permission of the Superintendent or on an order from the Board or Committee.

(2) In special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another state or district, the Superintendent shall allow parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children, provided they possess proper identification and are not reported to have subjected the juvenile or child to abuse and exploitation.

77. Identity Photos.— (1) On admission to a home established under the Act, every juvenile or child shall be photographed.

(2) One photograph shall be kept in the case file of the juvenile or the child, one shall be fixed with the index card, a copy shall be kept in an album serially numbered with the negative in another album, and a copy of the photograph shall be sent to the Board or Committee as the case may be, as well as to the District or State Child Protection Unit.

(3) In case of a child missing from an institution or in case of lost children received by an institution, a photograph of the child with relevant details shall be sent to the missing person's bureau and the local police station.

78. Police Officers to be in plain clothes.— While dealing with a juvenile or a child under the provisions of the Act and the rules made there under, except at the time of arrest, the Police Officer shall wear plain clothes and not the police uniform to maintain friendly atmosphere.

79. Prohibition on the use of handcuffs and fetters.— No child or the juvenile in conflict with law dealt with under the provisions of the Act and the rules made there under shall be handcuffed or fettered.

80. Procedure to be followed by a Magistrate not empowered under the Act.— (1) When any juvenile or child is produced before a Magistrate other than Board or Committee, and the Magistrate is of the opinion that such person is a juvenile or child, he shall record his reasons and send the juvenile or child to the appropriate competent authority.

(2) In case of a juvenile produced before a Magistrate not empowered under this Act, such Magistrate shall direct the case to be transferred to the Board for inquiry and disposal.

(3) In case of a child in need of care and protection produced as a victim of a crime before a Magistrate not empowered under the Act, such Magistrate shall transfer the matter concerning care and protection, rehabilitation and restoration of the child to the appropriate Committee.

81. Transfer.— (1) During the inquiry, if it is found that the juvenile or child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or Committee, the Board or Committee shall order the transfer of the juvenile or child and send a copy of the order to the State Government or State or District Child Protection Unit, provided that:

- (i) such transfer is in the best interest of the juvenile or child;
- (ii) no child shall be transferred or proposed to be transferred only on the ground that the child has created problems or, has become difficult to be managed in the existing institution or, is suffering from a chronic or terminal illness or, on account of disability;
- (iii) Such transfer shall only take place after the completion of evidence and cross examination that may be required in a legal proceeding involving a juvenile or child and the reasons for and circumstances of such transfer are recorded in writing.

(2) The State Government or State or District Child Protection Unit shall accordingly:

- (i) send the information of transfer to the appropriate competent authority having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and
- (ii) send a copy of the information to the Superintendent of the institution where the child is placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) On receipt of copy of the information from the State Government or State or District Child Protection Unit, the Superintendent shall arrange to escort the child at government expenses to the place or person as specified in the order.

(4) On such transfer, case file and records of the juvenile or child shall be sent along with the juvenile or child.

82. Procedure for sending a juvenile or child outside the jurisdiction of the competent authority.— (1) In the case of a juvenile or a child whose ordinary place of residence lies outside the jurisdiction of the competent authority, and if the competent authority considers it necessary to take action under Section 50 of the Act, it shall direct a probation officer or case worker or child welfare officer, as the case may be, to make enquiries as to the fitness and willingness of the relative or other person to receive the juvenile or the child at the ordinary place of residence, and whether such relative or other fit person can exercise proper care and control over the juvenile or the child.

(2) Where a juvenile or child is ordered to be sent to the ordinary place of residence or to a relative or fit person, execution of a bond by the juvenile or child without any surety, in **Form VI**, is necessary along with an undertaking by the said relative or fit person in **Form V** or **Form IX** as the case may be.

(3) Any breach of a bond or undertaking or of both given under sub rule (2) of this rule, shall render the juvenile liable to be brought before the competent authority, who may make an order directing the juvenile to be sent to an institutional home.

(4) Any juvenile or a child, who is a foreign national and who has lost contact with his family shall also be entitled for protection.

(5) The Juvenile or the child, who is a foreign national, shall be repatriated, at the earliest, to the country of his origin in coordination with the respective Embassy or High Commission.

(6) The Board or Committee shall keep the Ministry of External Affairs informed about repatriation of every juvenile or child of foreign nationality carried out on the orders of the Board or Committee.

(7) A copy of the order passed by the competent authority under Section 50 of the Act shall be sent to-

- (a) The probation officer or child welfare officer who was directed to submit a report under sub-rule (1) of this rule;
- (b) The Probation Officer or child welfare officer, if any, having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;
- (c) The competent authority having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;
- (d) The relative or the person who is to receive the juvenile or the child; and
- (e) The approved escort by fax or any other instantaneous mode of communication.

(8) During the pendency of the order under sub-rule (6) of this rule, the juvenile or the child shall be sent by the competent authority to an observation home or children's home as the case may be.

(9) Where the competent authority considers it expedient to send the juvenile or the child back to his ordinary place of residence under Section 50, the competent authority shall inform the relative or the fit person, who is to receive the juvenile or the child accordingly and shall invite the said relative or fit person to come to the home, to take charge of the juvenile or the child on such date, as may be specified by the competent authority.

(10) The competent authority inviting the said relative or fit person under sub rule (8) of this rule may also direct, if necessary, the payment to be made by the Superintendent of the home, of the actual expenses of the relative or fit person's journey both ways, by the appropriate class and the

juvenile's or child's journey from the home to his ordinary place of residence, at the time of sending the juvenile or the child.

(11) If the relative or the fit person fails to come to take charge of the juvenile or the child on the specified date, the juvenile or the child shall be taken to his ordinary place of residence by the escort as decided by the competent authority and in the case of a girl, at least one escort shall be a female.

83. State Child Protection Unit.— (1) The state government shall set up an office of a State Child Protection Unit with such officials and employees as it considers necessary.

(2) Functions of the State Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions setup under the Act, the Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions:

- (a) set up, support and monitor the District Child Protection Units;
- (b) represent as a member in the Selection Committee for appointment of members of Boards or Committees;
- (c) prepare annual budget and facilitate for necessary and timely allocation of funds to the Child Welfare Committee, Juvenile Justice Boards, District Child Protection Units, Juvenile homes, or any other institutions or agencies to ensure their effective functioning.
- (d) documentation of all data related to children and units established under the Act, publishing such reports as required from time to time, development of IEC (Information, Education, Communication) materials or other such materials for awareness and sensitization, including documentary, materials on website, posters, brochures etc;
- (e) network and coordinate with all government departments (state and central) to build inter-sectoral linkages on child protection issues, including departments dealing with health, education, social welfare, welfare child labour, child marriage, trafficking, abuse, child rights, police, judiciary, HIV/AIDS etc. The Unit shall coordinate with any other state units in the State so created for the welfare and protection of children, including State level Adoption Coordinating Agency, State Adoption Resource Agency, Child Line, etc;
- (f) network and coordinate with NGOs and civil society organizations working on the issues related to children, including the processing of the NGO's and civil society organisation's application for recognition, certification, registration or grant-in-aid;
- (g) training and capacity building of all personnel (Government and Non Government) working under the Act and development of training manuals and curriculum, development of a list of resource persons and publication of such materials and manuals for distribution among the stakeholders;
- (h) establish minimum standards of Care and ensure its implementation in all institutions set up under the Act;
- (i) review of the functioning of Committees;
- (j) formulation and implementation of such schemes and programmes necessary for implementation of the provisions of the Act and any scheme of the Central Government, as the case may be, including non-institutional services such as adoption, foster care, after care programme, sponsorship etc;
- (k) to accomplish capacity building, awareness, documentation, survey, studies or impact assessment and such other programmes in association with research and training institutes;
- (l) to provide necessary inputs to the Department of Social Welfare or the concerned Department responsible for the implementation of the Act by any other name, as and when required for effective policy planning, formulation and implementation.

84. District Child Protection Unit.— (1) The State Government shall constitute a District Child Protection Unit in every district with such officials and employees as it considers necessary.

(2) Functions of the District Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions set up

under the Act, the District Child Protection Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions,-

- (i) work under the overall guidance from the State Child Protection Unit and implement the directions issued from the State Government from time to time;
- (ii) support to district level units such as Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, District Advisory Board, Special Juvenile Police Unit, children's institutions, juvenile homes, etc. and facilitate to set up their offices with adequate infrastructure, funding and staff;
- (iii) performance appraisal of the Board members and the Committee and send the report to the State Government;
- (iv) The screening of the applications and verifications of the credentials of the applicants for the selection of social members of the Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, District Advisory Board and Inspection Committee as per the criteria laid down in the Act and these rules by a three-member Screening Committee comprising of District Magistrate, an senior officer representing Education or Health Department and Assistant Director Child Protection of the District Child Protection Unit. The member Secretary of the Screening Committee will be Assistant Director Child Protection of the District Child Protection Unit of the concerned district. The District Child Protection Unit will send all such applications with the remarks of the Screening Committee.
- (v) Committee members, Advisory Board/Inspection Team members and process all such applications as directed by the State Child Protection Unit or the State Government from time to time.
- (vi) identify and maintain data base of such children in need of care and protection through survey, campaigns or such other methods as may be necessary and like them to agencies for protection, emergency services, care, restoration or rehabilitation;
- (vii) network and coordinate with all government departments to build inter-sectoral linkages on child rights issues, including Departments of Health, Education, Social Welfare, Welfare, Urban Development, Backward classes & Minorities, Youth Sports and Culture, Police, Judiciary, Labour, State AIDS Control Society, among others through monthly meetings;
- (viii) network and coordinate with civil society organizations working under the Act;
- (ix) implement family based non-institutional services including sponsorship, foster care, adoption and after care;
- (x) identify families at risk and children in need of care and protection;
- (xi) assess the number of children in difficult circumstances and creating district specific database to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;
- (xii) periodic and regular mapping of all child related services in the district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;
- (xiii) ensure setting up of District, Block and Village level Child Protection Committees for effective implementation of programmes as well as discharge of its functions;
- (xiv) facilitate transfer of children at all levels for either their restoration to their families or placing the child in long or short-term rehabilitation through institutionalization, adoption, foster care and sponsorship;
- (xv) supporting State Adoption Resource Agency in implementation of family based non institutional services at district level;
- (xvi) develop parameters and tools for effective monitoring and supervision of agencies and institution in the district in consultation with experts in child welfare;

- (xvii) supervise and monitor all institutions or agencies providing residential facilities to children in district;
- (xviii) train and build capacity of all personnel (Government and Non government) implementing the Act to provide effective services to children;
- (xix) organize quarterly meeting with all stakeholders at district level including CHILDLINE, Specialized Adoption Agencies, Superintendent of homes, non-government organizations and members of public to review the progress and implementation of the Act; and
- (xx) liaison with the state Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency at State level and District Child Protection Unit of other districts.

85. Special Juvenile Police Unit.—(1) The State Government shall constitute special Juvenile Police Unit at the district level to handle cases related to juvenile in conflict with law and the children in need of care and protection.

(2) The Special Juvenile Police Unit shall also coordinate with all the police stations in the District, Special Juvenile Police Units established in other districts and the District Child Protection Unit.

(3) The Special Juvenile Police Unit at the district level shall consist of Special Juvenile Police Officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) along with two paid social worker (one woman) and all the Juvenile-cum-Child Welfare Officers of the district.

(4) A police officer shall be designated as Child Welfare Officer in all the police stations of the district, who shall sensitively handle the cases of children and report the matter to Special Juvenile Police Unit in the District.

(5) The Special Juvenile Police Unit may associate recognized voluntary organizations, Gram Sabha, Panchayat or Child Line to assist the Unit under the guidance of the Special Juvenile Police Officer in a manner which may help him/her in the care and protection of children, including social investigation, counseling, care, restoration and rehabilitation.

(6) The District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other designated training institute shall provide regular training and such orientation as may be necessary, to the Special Juvenile Police Officers and other persons associated with the handling of child related matters. It shall be mandatory for the Special Juvenile Police Officers and Child Welfare Officer to undertake the trainings.

(7) In case there is any contradiction between the provisions of the juvenile Justice (Care and Protection of children) Act, 2000 (as amended in 2006) and the Rule framed there under on the one hand and other provisions of the Bihar Police Act, 2007 or any other Rules made there under or any Manual or Official Directions, it shall be decided in the best interest of the child.

(8) The Special Juvenile Police Units shall particularly seek assistance from Gram Sabha, Panchayat, voluntary organizations recognised as protection agencies by the State Government for the purpose of assisting Special juvenile Police Units and local Police Stations at the time of apprehension, in preparation of necessary reports, for taking charge of juveniles until production and at the time of production before the Board as per rule 11(12) of these rules.

(9) The Superintendent of Police in a district shall head the Special Juvenile Police Unit and oversee its functioning from time to time.

(10) A Nodal Officer from Police not less than the rank of Inspector General of Police shall be designated in each State to coordinate and upgrade role of police on all issues pertaining to care and protection of children or juveniles under Act.

(11) Any police officer found guilty, after due inquiry, of torturing a child, mentally or physically, shall be liable to be removed from service, besides being prosecuted for the offence.

86. Honorary or Voluntary Welfare Officers and Probation Officers.—To augment the existing probation service, honorary or voluntary welfare officers and probation officers may be appointed from the voluntary organization and social workers found fit for the purpose by the competent authority and their services may also be co-opted into the implementation machinery by the orders of the competent authority.

87. Disqualification for officer-in-charge, probation officer or case worker and other care givers and staff.—(1) The Superintendent, Probation officer or case worker and other care givers and staff shall not employ a juvenile or child under their supervision or care and protection for their own purpose or take any private service from them.

(2) Any report of physical, sexual or emotional abuse of a juvenile or a child in an institution or outside, by a caregiver, shall hold them liable for disqualification after due inquiry.

88. Training of Personnel.— (1) The State Government with the help of the State Child Protection Unit, shall organize regular training and capacity building of personnel involved in the implementation of the Act and the rules made thereunder, in keeping with their statutory responsibilities and specific jobs requirements, either itself or in collaboration with training and research institutes.

(2) The training programme shall include—

- (a) orientation and training or the newly-recruited officials, staff, care givers, officials, members, Police etc;
- (b) refresher training courses and skill enhancement programmes for all care givers once a year;
- (c) staff conferences, seminars, workshops.

89. Selection Committee and its composition.— (1) The State Government shall constitute a Selection Committee by notification in the official gazette, for a period of three years, consisting of the following seven members, namely:

- (a) a retired Judge of a high court or a retired district Judge or a person who has served as Secretary to the Government of Bihar and has retired from active service to be nominated as the Chairperson.
- (b) one representative from the department concerned not below the rank of Director as the Member-Secretary.
- (c) one representative from a reputed non-governmental organization, working on the child rights issues but not running any child care institution;
- (d) two representatives from the Academic bodies concerned with social work, psychology, sociology, child development, gender/women studies, education, law, criminology and with experience or working on children's issues;
- (e) a representative of the State Commission for Protection of Child Rights or the State Human Rights Commission;
- (f) one Government official from SC/ST communities, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government.

(2) The selection committee shall hold its sittings as per requirement and the member secretary shall be responsible for organizing such a sitting.

(3) Any member of the selection committee may resign any time giving in writing to the state government. Any vacancy so arising from resignation shall be immediately filled preferably within 4 weeks as per the composition of the selection committee and tenure of such a member shall be co-terminus with the remaining period of the selection committee.

90. Functions of the Selection Committee.— (1) The Selection Committee shall select and recommend a panel of names to the State Child Protection Unit or State Government for appointment as members of the Juvenile Justice Board, the Chairperson and Members of the Child Welfare Committee, the non official members of the State Advisory Board or District or City Level Inspection Committee/Advisory Board.

(2) The Selection Committee shall take into consideration the panel of names recommended by the District Child Protection Unit. For any State level Committee or Board, the State Child Protection Unit shall recommend the names to the Selection Committee. The Selection Committee may prescribe the manner for processing application for selection including a personal interview with the short-listed applications.

(3) The panel of names so recommended by the Selection Committee shall be considered by the State Government to fill in any vacancies, which may arise during the tenure of the Board, Committee or the Unit.

(4) Applications of appointment in the Board or committee shall be invited through public advertisement in the prescribed format.

(5) In making appointment of members of the Board or Committee, the Selection Committee shall take into consideration the applications received in this regard in response to a public advertisement to this effect by the District or State Child Protection Unit or the State Government.

(6) In the event of any complaint against a member of the Board or Committee, the Selection Committee shall hold necessary inquiry and recommend termination of appointment of such member to the State Child Protection Unit or State Government, if required.

(7) The Selection Committee, at the time of recommending names for appointment as member of Board or Committee shall also prepare a panel of names for each Board or Committee to fill in vacancies, which may arise during the tenure of the Board or Committee.

(8) In the event of a vacancy in the Board or Committee, the District Child Protection Unit shall inform the State Child Protection Unit or State Government for filling up such vacancy.

(9) The State Child Protection Unit or State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee.

91. Advisory Boards.- (1) The State Government shall constitute Advisory Board at State, District and City levels for a period of 3 years.

(2) The State Government shall constitute the State Advisory Board consisting of:-

- (a) The Chief Secretary-Chairperson;
- (b) Principal Secretary, Department of Social Welfare-Convenor
- (c) Secretary or its representative from the departments of Health, Education, Police, Law, Labour, and Building Construction Department;
- (d) Chairperson of the Selection Committee
- (e) Two representatives from NGOs working in the field of child welfare;
- (f) Representatives from Legal Services Authority.

(3) The functions of the State Advisory Board shall be;

- (i) to advise the government on matters relating to the establishment and maintenance of the homes,
- (ii) to advise on creation and management of the Fund as prescribed under Section 61 of the Act,
- (iii) to inspect various provisions, facilities and services such as food, clothes, medicine, education, vocational training, economic and social rehabilitation for the children in institution and their rates.
- (iv) Any other matter considered necessary for policy, planning and implementation of any scheme for the benefit of the children
- (v) Inter-departmental coordination at the apex level.

(4) The State Government shall constitute District Advisory Board consisting of;

- (a) The District Magistrate-Chairperson,
- (b) Civil Surgeon- Member,
- (c) District Superintendent of Education- Member,
- (d) Head of the District Child Protection Unit-Convener
- (e) Two representatives from NGOs.

(5) All the Advisory Boards shall hold at least two meetings in a year.

(6) The District or City level Advisory Board constituted in terms of sub-Section (3) of Section 62 of the Act shall also function as the inspection committee under Section 35 of the Act.

(7) The Advisory Boards shall inspect the various institutional or non-institutional services in their respective jurisdictions; and the recommendations made by them, shall be considered by the State Government.

(8) The State Government, through the Selection Committee constituted under Rule 99 of these rules, shall recommend a panel of names for the non-official members of the State, District and City level Advisory Boards.

(9) The termination, resignation, or other vacancy with regard to the non-official members, caused in an advisory board and appointment of new members therein shall be done in the same manner as is done in case of the competent authority.

92. Juvenile Justice Fund.— (1) The State Government shall create a Fund at the State level under Section 61 of the Act to be called the ‘Juvenile Justice Fund’ (herein under referred to as the Fund) for the welfare and rehabilitation of the juvenile or the child dealt with under the provisions of the Act.

(2) In addition to donations, contributions or subscriptions coming under Sub-Section (2) of Section 61, the Central Government/ State Government shall also make contribution to the Fund

(3) There shall be an autonomous and non-profit body registered under the Societies Registration Act, 1860 and the management and administration of the Fund shall be under the State Advisory Board, constituted under Section 62.

(4) The Fund shall be applied, -

- (a) To formulate and implement programmes and schemes necessary for the welfare, rehabilitation and restoration of juveniles or children;
- (b) To pay grant-in-aid to non-governmental organizations;
- (c) To meet the expenses of State Advisory Board and its purpose;
- (d) To do all other things that are incidental and necessary for the above purpose.

(5) The assets of the Fund shall include all such grants and contributions, recurring or non-recurring, from the Central Government and State Government or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations from any individual or organization.

(6) The regular accounts shall be kept of all money and properties, and all incomes and expenditure of the Fund and shall be audited by a registered firm of Chartered Accountants, or any other recognized authorities as may be appointed by the Board.

(7) All contracts and other assurances shall be in the name of the board of management and signed on their behalf by the secretary-cum-treasurer and one member of the board of the management authorized by it for the purpose.

(8) All withdrawals shall be made by cheques or requisitions, as the case may be, signed by the secretary-cum-treasurer and in the case of amount exceeding rupees ten thousand, they shall be signed duly by the secretary-cum-treasurer and a member of the board of management to be nominated by the State Advisory Board.

(9) The board of management shall invest for the time being the proceeds of sale or other disposal of property, as well as any money or property not immediately required to be used to serve the objective of the Fund, in any one or more of the modes of investment authorized by law for the investment of trust moneys as the board of management may think proper.

93. Pending Cases.— (1) No Juvenile in conflict with law or a child shall be denied the benefits of the Act and the rules made there under.

(2) All pending cases which have not received finality shall be dealt with and disposed of in terms of the provisions of the Act and the rules made there under.

(3) Any juvenile in conflict with law, or a child shall be given the benefits under sub rule (1) of this rule, and it is hereby clarified that such benefits shall be made available to all those accused who were juvenile or a child at the time of commission of an offence, even if they cease to be a juvenile or a child during the pendency of any inquiry or trial.

(4) While computing the period of detention or stay or sentence of a juvenile in conflict with law or of a child, all such period which the juvenile or the child has already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

94. Openness & Transparency.— (1) All Children's homes shall be open to visitors with the permission of the Officer-in-charge and the Committee or Officer-in-charge as the case may be, may consider appropriate to allow representatives of local self-government, voluntary organizations, social workers, researchers, medicos, academicians, prominent personalities, media and any other persons as visitors, as the Officer-in-charge considers appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.

(2) The Officer-in-charge of the home shall encourage active involvement of local community in improving the conditions in the homes, if, the members of the community want to serve the institution or want to contribute through their expertise.

(3) The officer-in-charge shall maintain a visitors book and the remarks of the visitors given therein shall be considered by the advisory inspecting authority.

(4) While visiting an institution, the visitors will not say or do anything that undermines the authority of the Officer-in-charge or is in contravention of the Act or rules or impinges on the dignity of the children.

(5) Notwithstanding anything contained in the above sub-rules it shall be lawful for the officer in charge to refuse permission when he thinks that such visit will be prejudicial to the interest of the inmates or the running of homes.

(6) The visitors may be allowed to visit observation homes and special homes with the permission of the competent authority.

95. Disposal of records or documents.— The records or documents in respect of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law shall be kept in a safe place for a period of seven years and no longer, and thereafter be destroyed in consultation with the Board or the Committee, or the Child Protection Unit, as the case may be.

96. Disposed of cases of juveniles in conflict with law.— (1) The State Government or as the case may be the Board may, either suo motu or on an application made for the purpose, review the case of a person or a juvenile in conflict with law, determine his juvenility in terms of the provisions contained in the Act and rule 12 of these rules and pass an appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law under Section 64 of the Act, for the immediate release of the juvenile in conflict with law whose period of detention or imprisonment has exceeded the maximum period provided in Section 15 of the said Act.

(2) For the purpose aforementioned a Review Committee will be constituted by the State Government which will submit its recommendation after reviewing the matter.

97. Protection of action taken in good faith.— No suit or legal proceedings shall lie against any functionary under the Act including the members of the voluntary organization and social worker, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the Act during the performance of the duties assigned to them.

98. Repeal and Saving.— (1) The Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012 in hereby repealed.

(2) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect any act done or order issued in pursuance of the Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012 before these rules come into force.

By order of the Governor of Bihar,
S.M. RAJU,
Secretary to Government.

SCHEDULE-1**Clothing, bedding, toiletries and other articles (rule 48)****(1) Juvenile or children shall be provided with the following articles:**

Bedding		
Sl No.	Article	Quantity to be provided per child
1	Towels	4 per year
2	Cotton Bed Sheets	2 per 2 year
3	Pillow (Cotton Stuffed)	1 per 2 year
4	Pillow Covers	2 per 2 year
5	Woolen blankets	2 per 2 years
6	Cotton Durry	2 per 2 years
7	Cotton filled quilt	1 per 2 year (in cold regions)
8	Mattress	1 per 2 years
9	Mosquito Net	1 per 2 years

Clothing for girls		
1	Skirts & Blouse or Salwar Kameez or Half sari with blouses and petticoats	5 sets per year for girls depending on age and regional preferences
2	Banyans (1 Metre each)	6 per year for younger girls
3	Brassieres	6 per year for older girls
4	Panties (1 Metre Cloth each)	6 per year
5	Sanitary Towels	12 packs per year for older girls
6	Woolen Sweaters	2 in 2 years (in cold regions)
7	Woolen Shawls	1 in 2 years (in cold regions)

Clothing for boys		
1	Shirts	5 sets per year
2	Shorts	5 sets per year for younger boys
3	Pants	5 sets per year of older boys
4	Vest	4 set per year
5	Underwear	4 set per year
6	Woolen Jerseys	2 in 2 years (for cold regions)
7	Scarfs	2 in 2 years (for cold regions)

Miscellaneous Articles		
1	Slipers	1 pair per year
2	Shoes	1 pair per year
3	School Uniform	2 sets per year for children attending outside schools
4	School shoes	1 pair per year for children attending outside schools
5	School Bag and Stationery	1 set per year for children attending outside schools
6	Handkerchiefs	6 per year

Note:-In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of khaki shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer (for cold regions) for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white blouse, a pair of white canvas shoes and a blazer (for cold regions).

(2) In every hospital attached to the institution where there is provision for in patient cots the following scale has to be followed:

Sl	Night clothing & bedding	Scale for supply
1	Mattress	One per bed per 3 years
2	Cotton Bed Sheets	Four per bed per year
3	Pillows	One per bed per two year
4	Pillows Covers	Four per bed per year
5	Woollen blankets	One per bed per 2 year
6	Pyjamas and loose shirts (Hospital type for boys)	3 Pairs per child per year
7	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 Pairs per child per year
8	Cotton durry	One per bed per three years

Note:

- (i) When a child is admitted as an in patient in the institution Hospital, the Institution Doctor shall issue the in patient with the hospital clothing, the clothes on body being preserved duly washed and handed back at the time of the child's discharge from the hospital.
- (ii) Each child shall be provided with kit Box or a Locker as per convenience and necessity.
- (iii) The Superintendent shall make arrangement for two-tier bed system in place or conventional cots, as per convenience and necessity.

(3) Toiletry: Every resident to the Home shall be issued with oil, soap and other material for in accordance with the following scales:

Hair oil for grooming the hair	100 mgs per month
Toilet soap or carbolic soap	1 large bar per month
Tooth Paste and brush	1 Brush per 3 months 50 gms paste per month
Comb	1 Per Year

Note:-(a) For washing of cloth and towels, bed-sheet etc, the following scale may be followed:

(i) Washing Soap 1 Soap for one month (125gms)
(ii) Whitening/bleaching agent to the extent required only for white clothing

Provided, however, the hospital clothing is not mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing.

(b) The children attending school outside the institution may be issued with one additional bar of washing soap (100 gms) per head per month for washing their school uniform.

(4) The following items shall be provided for maintaining the Homes in a healthy and sanitary condition:

Sl No.	Item	Scale of supply
1	Broom Stick	25 to 40 Nos per month depending on the area of the institution
2	DDT spray	As per the institution Doctor's advice
3	Effective bugs killing agent	As required
4	Phenyl and cleaning acid (daily)	Depending on the area of lavatories to be cleaned as per institution Doctor's advice

SCHEDULE II
Nutrition and Diet Scale (rule 44)

Sl	Name of the articles of diet	Scale per head per day
1	Rice/Wheat/Ragi/Jowar	600 Gms (700 Gms for 16-18 yrs age) of which atleast 100 gms to be either wheat or ragi or jower
2	Dal/Rajma/Chana	120 Gms
3	Edible Oil	25 Gms
4	Onion	25 Gms
5	Salt	25 Gms
6	Turmeric	05 Gms
7	Coriander Seed Powder	05 Gms
8	Ginger	05 Gms
9	Garlic	05 Gms
10	Tamarind/Mango Powder	05 Gms
11	Milk (at breakfast)	150 ml
12	Dry Chillies	05 Gms
13	Vegetables Leafy	100 Gms
14	Vegetables Non Leafy	130 Gms
15	Curd or Butter Milk	100 Gms/MI
16	Jaggery & Ground Nut Seeds or Paneer (vegetarian only)	60 Gms each (100 Gms for paneer) Once in a week
17	Sugar	40 Gms
Following items for 50 Children per day		
18	Pepper	25 Gms
19	Jeera Seeds	25 Gms
20	Black Gramdall	50 Gms
21	Mustard Seeds	50 Gms
22	Ajwain Seeds	50 Gms
On Chicken Day for 10 kg. of Chicken		
23	Garam Masala	10 Gms
24	Kopra	150 Gms
25	Khas Khas	150 Gms
26	Groundnut Oil	500 Gms
For Sick Children		
27	Bread	500 Gms
28	Milk	500 MI
Other Items		
29	LP Gas for Cooking only	

Instructions:**(2) Variation in Diet**

- (a) Three varieties of dal i.e., Toor (Tuvari), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be issued alternatively.
- (b) The Superintendent may also arrange to substitute chicken with fish at his discretion, provided that there is no extra expenditure to Government.
- (c) On non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 Gms of Jaggery and 60 Gms of Groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer.
- (d) Potatoes shall be issued in lieu of vegetables once in a week.
- (e) Leafy vegetables such as Fenugreek(Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) Gongura Thotkaura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen graden is attached to any institution leafy vegetables, in addition

to drumstick trees, curry leaves trees and coriander leaves, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week.

- (f) The Superintendent may make temporary alternations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the institution Doctor's advice subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(3) Meal Timing and Menu:-

- (a) Breakfast after 8:00 am
 - (i) Upma or chapattis made of Wheat or Ragi or any other dish.
 - (ii) Chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and putnadal etc., dal/vegetable may be issued as a dish.
 - (iii) Milk
 - (iv) Any seasonal fruit in sufficient quantity

(b) Lunch at 1:00 P.M. and Dinner After 7:00 P.M.

- (i) Rich/Chapattis or combination of both
- (ii) Vegetable Curry
- (iii) Sambar or Dal
- (iv) Butter Milk or curd

(4) Others:-

- (a) Depending on the season, the Superintendent shall have the discretion to alter the time for distribution of food.
- (b) On the advise of the Institution Doctor, every sick who is prevented from taking regular food, on account of his ill, health, may be issued with medical diet, as indicated in diet scale.
- (c) Extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution Doctor in addition to the regular diet, to pick up weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength.
- (d) On the following national and festival occasions, sweet dishes may be distributed to all the children at the Home at the rate fixed by the Commissioner from time to time.
 - 1. Republic Day (26th January)
 - 2. Ambedkar's Birthday (14th April)
 - 3. Independence Day (15th August)
 - 4. Mahatma Gandhi's Birth Day (2nd October)
 - 5. Children's Day (14th November)
 - 6. Child Rights Day (20th November)
 - 7. Dussehra (Vijayadasami)
 - 8. Deepavali
 - 9. Ramzan (Id-Ul-Fitr)
 - 10. Bakrid (Id-Ul-Zuha)
 - 11. Christmas (25th December)

The States may specify additional festivals depending upon local preferences.

Form-I**[Rule 12(6)(c)]****SUPERVISION ORDER**

When the juvenile is placed under the care of a parent, guardian or other fit person/fit institution Profile No.of20

Whereas (name of the juvenile) has this day found to have committed an offence and has been placed under the care of (name) (address) on executing a bond by the said and the Board is satisfied that it is expedient to deal with the said juvenile by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said juvenile be placed under the supervision of probation officer/case worker, for a period of subject to the following conditions:-

1. that the juvenile along with the copies of the order and the bond executed by the said shall be produced before the probation officer/caseworker named therein
2. That the juvenile shall be submitted to the supervision of the aforesaid probation officer/case worker.
3. That the juvenile shall reside at for a period of
4. That the juvenile shall not be allowed to quit the district jurisdiction of without the permission of the probation officer/case worker.
5. That the juvenile shall not be allowed to associate with bad characters.
6. That the juvenile shall live honestly and peacefully; and will go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.
7. That the juvenile shall attend the attendance centre regularly.
8. That the person under whose care the juvenile is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the juvenile.
9. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the juvenile is placed to see that the juvenile does not commit any offence punishable by any law in India.
10. That the juvenile shall be prevented from taking narcotic durgs or psychotropic substances or any other intoxicants.
11. That the directions given by the probation officer/case worker from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated thisday of20

(signature)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Additional, conditions, of any may be inserted by the Juvenile Justice Board

FORM-II
[Rule 12(6)(d)]

Order of detention under Sub-Section.....of Section....., Sub-Section, of Sectionand Sub-Sectionof Section.....

To

The Officer in charge

.....
.....

Whereas on the day of 20(name of the juvenile), son/daughter of aged, residing at being found in Profile No. to be juvenile in conflict with law/section is order by me Principal Magistrate, Juvenile Justice Board under section of Juvenile Justice Act, 2000 to be kept in the Observation Home/Special Home/..... for a period of

This is to authorize and require you to receive the said juvenile; into your charge, and to keep him/her in the Observation Home/ Special Home/..... for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board

Thisday of 20.....

(signature)
Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Encl:

Copy of the judgment, if any, or orders, particulars of home and case history and individual care plan, if any:

Strike which is not required.

FORM-III
ORDER OF SOCIAL INVESTIGATION/INQUIRY
[Rule 12(1) and 12(6) (e)]

To

Probation Officer/Case Worker/Person-in-charge of Voluntary Organization/Case Worker

Whereas a report/complaint under section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 has been received from in respect of (name of the juvenile), son/daughter of approximate age residing at , who has been produced before the Board.

You are hereby directed to enquire into the social antecedents family background and circumstances of the alleged offence by the said juvenile and submit your social investigation report on or before or within such time allowed to you by the Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report.

Dated this day of 20.....

(signature)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM IV
[Rules 13(5) and 80(1)(a) and (2)]
SOCIAL INVESTIGATION REPORT

Sl. No.....

Submitted to the Juvenile Justice Board (address)

Probation Department/Concerned State Government Authority/Voluntary Organisation
..... (Signature and Stamp)

Profile No.

Under section:

Title of Profile:

Police Station:

Nature of offence charge:

Name	Religion
Father's Name	Caste
Permanent Address	Year of birth
Last address before apprehension	Age
	Sex

.....
Previous institutional/case history and individual care plan, if any

FAMILY

Members of family	Name	Age	Health	Education	Occupation	Monthly earnings	Disabilities	Any other e.g. Social habits
Father								
Step-Father								
Mother								
Step-mother								
Siblings								
Any other legal guardian/relative								

If married, relevant particulars

.....
Other near relatives or agencies

Interested

Attitude towards religion normal

And ethical code of the home etc.

Social and economic status

Delinquency record of members
of family
Present living conditions
Relationship between parents/
Parents and children especially
With the juvenile under investigation
Other factors of importance if any

JUVENILES HISTORY

Mental condition
(Present and past)
Physical condition
(Present and past)
Habits, interests
(moral,recreational etc.).....
Outstanding characteristics and
Personality traits
Companions and their influence
Truancy from home, if any
.....
School (attitude towards school,
Teachers, class mates and vice-versa)
.....
Work record (jobs held, reasons for leaving,
Vocational interests, attitude towards job or employers)
Neighbourhood and neighbours report
Parent's attitude towards discipline
In the home and child's reaction
Any other remarks
.....

RESULT OF INQUIRY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Suggested causes of the problems

Analysis of the case including reasons for delinquency

Opinion of experts consulted

Recommendation regarding treatment and its Plan by Probation Officer

Signature of the Probation Officer/Case Worker

FORM V

[Rules 15(5) and 92 (2)]

UNDERTAKING/BOND TO BE EXECUTED A PARENT/GUARDIAN/ RELATIVE/FIT PERSON WHOSE CARE A JUVENILE IS PLACED

Whereas I being the parent, guardian, relative or fit person under whose care (name of the juvenile) has been ordered to be placed by the Juvenile Justice Board have been directed by the said Board to execute an undertaking/bond with surety in the sum of Rs./- (Rupees) or without surety. I hereby bind myself on the said or being placed under my care. I shall have the said properly taken care of and I do further bind myself to be responsible for the good behavior of the said and to observe the following conditions for a period of years w.e.f.....

1. that I shall not charge my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer/Case Worker;
2. that I shall not remove the said juvenile from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board;
3. that I shall send the said juvenile daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond my control;
4. that I shall send the said juvenile to an Attendance Centre regularly unless prevented from doing so by circumstances beyond my control;
5. that I shall report immediately to the Board whenever so required by it;
6. that I shall produce the said juvenile in my care before the Board, if he/she does not follow the orders of Board or his/her behaviour is beyond control;
7. that I shall render all necessary assistance to the probation Officer/Case Worker to enable him to carry out the duties of supervision;
8. in the event of my making default herein, I undertake to produce myself before the Board for appropriate action or bind myself, as the case may be, to forfeit to Government the sum of Rs (Rupess).

Dated this day of 20.

Signature of person executing the Undertaking/Bond.

(Signed before me)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly;

(Where a bond with sureties is to be executed add)

I/We.....of
 (Place of residence with full particulars) hereby declare myself/ourselves as surety/sureties for the aforesaid(name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of(name of the person executing the bond) making fault therein, I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to government the sum of Rs./- (Rupees) dated this the day of 20 in the presence of

Signature of Surety(ties)

(Signed before me)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM VI
 [Rules 15(6) and 92 (2)]
PERSONAL BOND BY JUVENILE/CHILD

Personal Bond to be singed by juvenile/child who has been ordered under Clause of Sub-Section..... of Sectionof the Act.

Whereas, I inhabitant of (give full particulars such as house number, road, village/town, tehsil, district, state) have been ordered to be sent back/restored to my native place by the Juvenile..... Justice Board/ Child Welfare Committee under Section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 on my entering into a personal bond under sub rule of Rule and sub rule of Rule of these Rules to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I do solemnly promise to abide by these conditions during the period

I hereby bind myself as follows:

1. That during the period I shall not ordinarily leave the village/ town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board/Committee;
2. That during the said period I shall attend school/vocational training in the village/town or in the said district to which I am sent;
3. That in case of my attending school/vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board/Committee informed of my ordinary place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb impression of the juvenile/child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of Juvenile/Child)..... and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her period of detention/placement in safe custody may be revoked.

Certified accordingly that the said juvenile/child has been released/relieved on the

**Signature and Designation of the certifying authority
i.e. Officer-in-charge of the institution**

FORM VII
[Rule 17(9)]
DISCHARGE ORDER

Iname and designation of the discharging authority
..... State Government/Union Territory
Administration, do by this order permit
son/daughter of residence
Profile Number Who was ordered to be detained/placed in a
observation home/special home/after care home by the Juvenile Justice Board
under section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, for a term of
..... on the day of20..... and who is now in the
home, at to be discharged from the said home and
supervision and the authority of during the remaining period of
stay.

This order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any of which it shall be liable to be revoked.

Dated _____ Signature and Designation of Releasing Authority.
Place:

Conditions:

1. The discharged person shall proceed to and live under the supervision and authority of until the expiry of the period of his/her detention unless the remission is sooner cancelled.
2. He/She shall not, without the consent of the remove himself/herself from that place or any other place, which may be named by the said
3. He/She shall obey such instruction as he/she may receive from the said with regard to punctual and regular attendance at school/vocation or otherwise.
4. He/She shall attend the Attendance Centre located at regularly.
5. He/She shall abstain from committing any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of
6. In the even of his/her committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of detention hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with under sub section (3) of section 59 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or mark of the released juvenile)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of Juvenile/child)..... and that he/she has accepted them as the conditions upon which his/her period of detention may be revoked.

Certified accordingly that the said juvenile/child has been discharged on the

**Signature and Designation of the certifying authority
i.e. Officer-in-charge of the institution**

FORM VIII
[Rule 27(18)]
SUPERVISION ORDER

When the Child is placed under the case of a parent/guardian or other fit person
Case No.of20....

Whereas (name of the child) has this day been found to be in need of care and protection, and has been placed under the care and supervision of (name) (address) on executing a bond by the said and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name)(address) for a period of subject to the following conditions that:

1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the said shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond.
2. the child shall be placed under the supervision of the aforesaid parent/guardian/fit person
3. the child shall reside at for a period of
4. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction ofwithin the permission of the Committee.
5. the child shall go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.
6. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care education and welfare of the child.
7. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be prevented from coming in conflict with law.
8. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.
9. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated thisday of20.....

(Signature)

Chairperson, Child Welfare Committee

- Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee

FORM IX**[Rules 27(18) and 92(2)]****UNDERTAKING BY THE PARENT OR 'FIT PERSON' TO WHOM CHILD IS RESTORED**

I resident of House no.

Street Village/Town District State

..... Do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child)

..... Aged under the orders of the Child Welfare

Committee subject to the following terms and conditions:

- (i) If his/her conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.
- (ii) I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he/she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.
- (iii) In the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital.
- (iv) I undertake to produce him/her before the competent authority as and when required.

Date this day of

Signature**Signature and address of witness (es)****(Signed before me)****Chairperson, Child Welfare Committee**

FORM X
[Rule 27 (19)]
ORDER OF SHORT TERM PLACEMENT PENDING INQUIRY

Name of the child : _____

Sex : _____

Father's Name : _____

Mother's Name : _____

Address : _____

Date of receiving by Organization/Institution : _____

Produced by:

This is to authorize and direct you to receive the said child in your charge, and keep her/him in the Shelter Home/Children's home for care and protection under section 33 (1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

Next Date:

(Signature)
**Chairperson/Member
Child Welfare Committee**

FORM XI

[Rule 27(20)]

ORDER OF RESTORATION OF A CHILD TO AN INSTITUTION

To

The Officer-in-Charge

Whereas on the Day of 20 (name of the child) , son/daughter of aged residing at being in care and protection under section 33 (4) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is ordered by the Child Welfare Committee , to be kept in the children's Home/Shelter Home for a period of

This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to keep him/her in the Children's Home/Shelter Home for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee.

This day of 20.

(Signature)
Chairperson/Member
Child Welfare Committee

Encl:

Copy of the orders, particulars of home and previous record, case-history and individual care plan, whichever is applicable:

FORM XII**[Rule 28 (1)]****ORDER FOR ENQUIRY**

To

Child Welfare Officer/Person in charge of Voluntary Organization/Social Worker/Case Worker

Whereas a report under section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 has been received from in respect of (name of the child) aged (approximate),, son/daughter of residing at....., who has been produced before the Committee under section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

You are hereby directed to enquire into the social and family background of the said child and submit your inquiry report on or before or within such time allowed to you by the Committee.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Inquiry Report.

You are hereby directed to enquire into the character and social antecedents of the said juvenile and submit your social investigation report on or before or within such time allowed to you by the Board/Committee.

Dated this day of 20.....

(Signature)

**Chairperson/Member
Child Welfare Committee**

SEAL

FORM XIII

[Rules 28(3); 33(3) (h)(ii); and 33(4)(f); 80(1)(a) and (2)]

FORMAT FOR INQUIRY REPORT

Sl. No.....

Produced before the Child Welfare Committee.....(address)

Case No.

Concerned Government Department/Voluntary Organisation

Category of child in need of care and protection:

Name	Religion
Father's Name	Caste
Permanent Address	Year of birth
Address of last residence	Age
	Sex

Previous institutional/case history and individual care plan, if any

FAMILY

Members of family	Name	Age	Health	Education	Occupation	Monthly earnings	Disabilities	Any other eg. Social habits
Father								
Step-Father								
Mother								
Step-mother								
Siblings								
Any other legal guardian/relative								

If married, relevant particulars

Other near relatives or agencies

interested_____

Attitude towards religion, normal and ethical code of the home etc._____

Social and economic status

Delinquency record of members of family_____

Present living conditions _____

Relationship between parents/
parents and children especially
with the said child _____

Other factors of importance if any _____

CHILD'S HISTORY

Mental condition
(Present and past) _____

Physical condition
(Present and past) _____

Habits, interests
(moral, recreational etc) _____

Outstanding characteristics and Personality traits _____

Companions and their influence _____

Truancy from home, if any _____

School (attitude towards school, teachers, class mates and vice-versa)

Work record (jobs held, reasons for leaving Vocational interests, attitude towards job or employers) _____

Neighbourhood and neighbour's report _____

Parent's attitude towards discipline In the home land child's reaction _____

Any other remarks _____

RESULT OF INQUIRY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Reasons for child's need for care and protection

Opinion of experts consulted

Recommendation of Child Welfare Officer/Case-Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan

Signature of the Child Welfare Officer/Case Worker/Social Worker

FORM XIV

[Rule 33 (3) (d)]

ORDER FOR DECLARING CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee _____ constituted under sub-section _____ of section _____ of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and sub-rule _____ of rule _____ of these rules, minor _____ born on (date) _____ placed in custody of Specialised Adoption Agency (name & address) _____, vide order _____ dated _____ of the Chairperson, Child Welfare Committee _____, has been declared legally free for adoption on the basis of details furnished through:

- Inquiry/home study conducted by Child Welfare Officer/Social Worker/Case- Worker
- Document of surrender executed by the parents(s) and surrender deed signed in the presence of the Committees under sub-rules _____ of rule _____ of these rules.
- Declaration submitted by the specialised Adoption agency under sub-rules _____ of rule _____ of these rules.

2. _____ (name of the Specialised Adoption Agency) shall fulfill all conditions specified in Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the rules relating thereto and furnish a copy of adoption decree/guardianship order in respect of the minor as may be required by Committee and the concerned Department of the State Government of _____.

Date:

Place:

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

For completion by the Specialised Adoption Agency.

- I have read and understood Chapters III and IV of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the rules thereunder and agree to abide/be bound by the same while placing said minor in adoption.
- I further declare that the particulars stated in the declaration submitted by me on _____ are true and correct. In case they are found to be false or incorrect, the Committee has right to suspend this Release Order for (name of the minor)_____ and ask for production of said minor before the Committee.

Date:

Place:

Child Welfare Officer/Social Worker

FORM XV

[Rule 33 (4) (c)]

DEED OF SURRENDER

I _____ d/o or s/o _____ residing at _____ am not in a position due to social reasons/due to being single/ill/disabled to take care of my child (name, if any) _____ approximate age _____ years. I am explained the consequences of surrendering my child by the Child Welfare Officer/Social Worker (name) _____ and the Child Welfare Committee _____. In full knowledge of all these facts, I am surrendering my child before the Committee today, dated _____. Within two months from this stated date if I do not revise my decision to take back my child and do not approach the said Committee for the same, the Committee shall declare my child legally free for adoption and I shall have no further claim on my child.

Signature of parent/guardian**Date**

That I _____ Child Welfare Officer/Social Worker have explained the procedure and the consequences of surrendering the child to the concerned parent/guardian on (date) _____.

Signature of Child Welfare Officer/Social worker**Date**

(Signed before me)

**Chairperson/Member
Child Welfare Committee**

FORM XVI

[Rule 35 (3)]

A. FOSTER CARER'S ASSESSMENT**1. Agency Details**

Name of the Agency

Address

Telephone

Fax

E-mail

Name of the Social Worker

Tel

Date _____ (Form Completed)

2. Details of the Applicant

Surname

Full Name

Date of Birth

Religion

Language (s) spoken at home

Occupation

(a) Nature of Work

(b) Hours of Work

Address

Telephone

3. Description of a preferred child

The type of child, the foster-carer would consider

(To be filled after a full discussion with the Foster-carer)

Age Range	Under 2 years	3-6 years	7-12 years
-----------	---------------	-----------	------------

16-18 years

Sl. No.	Type of placement	Duration
(i)	Pre adoption	
(ii)	Emergency	
(iii)	Short term	
(iv)	Assessment	
(v)	Long term	

The Child an applicant can care for (please Tick)**A child who is:**

- i. Neglected
- ii. Orphaned
- iii. With Physical impairment
- iv. Mental impairment
- v. Hearing impairment
- vi. Speech impairment
- vii. Special Education needs
- viii. Learning difficulties
- ix. Physical abuse
- x. Sexual abuse
- xi. Who does not relate easily
- xii. Who needs control/may defy authority
- xiii. Born of rape/incest
- xiv. Whose parent (s) is suffering from disease
- xv. Whose parent (s) is HIV positive

- xvi. Whose parent (s) are AIDS patient
- xvii. Whose parent (s) is alcoholic
- xviii. Drug addicts
- xix. Are in jail
- xx. Relinquished
- xxi. Belong to another caste
- xxii. Are of different religion

4. Profile of the family

Brief Family Profile					
Name	Gender	Approx. Age	Occupation	Education	Relationship with the applicant

(Give details of personalities, family life, experiences etc. Also highlight specific qualities of the family that can match with a child's needs. The details should facilitate initial identification of a potential match with a specific child.)

Accommodation (House)

(Details of type, size, own/ rented space, amenities etc.)

Neighbourhood

(Details of composition, amenities and facilities, public transport etc.)

5. Verification of applicant's identity

Place of residence

Period of stay

Nationality

Marital status (date/ length of marriage)

Has either of the applicant had a previous marriage? Details

If children from previous marriage? Details

Specify documents seen with date

6. Career History

(Details of education, employment, voluntary work, part-time work, leisure activities)

7. Agency Inquiries:

Medical check

Police check

Employer

8. Personal references (from 2 persons)

This section to be completed after interviews with two references; information gathered through these interviews should include:

- Length of time known
- Relationship to the applicant
- Provide evidence on the applicant's ability to perform the tasks involved in_____
 - Caring for children
 - Providing a safe and caring environment
 - Applicant as a neighbor
 - Interests, talents, personality

Assessment of the social worker for these references

B. HOME STUDY REPORT

A Home Study Report of the foster carer(s) being a crucial document being prepared by the social worker of the Specialised Adoption Agency based on the information collected by the format given above should broadly include the following information:

- Social Status and family background
- Description of the home
- Standard of living as it appears in the home
- Current relations amongst the members in the home
- Status of development of the children already in the home
- Employment and economic status
- Health details
- Details of facilities of education, medical, vocational trainings available in the neighborhood
- Reasons for wanting a child in foster care
- Attitudes of the grandparents and other relatives
- Anticipated plans for the foster child
- Legal status of the foster carer(s)
- Willingness to undergo training

C. DETAILS OF APPLICANT(S)

1. Background.—Family structure with details of parents and siblings, significant details of other family members, childhood experiences, etc.

2. Relationship.—If couple- Length of married life, what qualities does each applicant bring to the partnership, what makes the relationship positive for each other? Within the relationship how do applicants cope with problems/stress/anger? How do applicants support each other? What is each applicant's assessment of how the Foster placement will affect his or her relationship?

3. Decision making.—How is decision-making exercised in this relationship and how does each of the applicants view this? Is there wider extended family involvement in the couple's decision-making process? If so, how will this affect the child to be placed?

What are the strengths and vulnerabilities of this partnership?

- Children
- Children and their parents' relationships
- Children's attitude and readiness for a foster placement sibling. Describe each child and their temperament, any special talent and need, how children have been involved in preparation etc.

4. Applicants support networks.—Give a general picture of support systems currently used by the applicants including expended family, friends, neighbours, religious activities, community groups etc. including details of the location etc.

5. Other significant members of the family.—Living in the house or not. Their relationship to the applicants, how much time they spent within the home, their attitude to the proposed placement. How important is their acceptance of placement to the applicants.

6. Description of the family life style—Outline what family considers important e.g. how important are religious and cultural practices. How is affection show in the family? How do the members spend their time? What expectations family members have with regard to personal space? What value is placed on education/hobbies and leisure activities that the whole family undertakes?

7. Parenting capacities.—Experience of the applicants of caring and working with children. Describe their adjustment to parenthood. What is their understanding of how children develop?

Using their own childhood experiences what patterns of parenting would they repeat and what would they change? What is their understanding of their own parenting strengths/potentials and about their parenting skills to meet the needs of individual child? To what extent they would expect other family members to be involved in parenting of their children/placed children.

How will they ensure that a child will be safe from physical sexual abuse in their family and within wider support networks?

8. Managing Unacceptable Behavior—What are the rules in the household? How do the applicants show approval/disapproval? What are the discipline measures that they use? Their attitude towards punishment?

What do they anticipate would be the issues and difficulties for themselves and for their own children and for their support network? What do they anticipate would be the issues and difficulties for the child? Which changes do they anticipate would be needed in their lifestyle?

Social Workers assessment.—It should provide an analysis of all the information collected through the format and its significance with regard to the capacity of the applicant to carryout fostering task:

(What skills do the applicants have in relating to and working with children? How well will the applicant work with the agency, with biological parents? What are the strengths and resources of the applicants and which are the areas where they may experience difficulty? Also the point of disagreement between the social worker and the applicants should be recorded here.)

Recommendations of the Child Welfare Officer/Social Worker

(Signature)

FORM XVII
[Rule 34 (1)]
ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT

The child (name and address) _____

approximate age _____ d/o or s/o Mr. _____

and Mrs. _____ or Ms. _____

is in need of care and protection of a family. Mr. _____

and Mrs. _____ or Ms. _____

resident of (complete address and contact numbers) _____

_____ is/are declared fit person/persons for foster-care placement of the child based on the home study report of the Child Welfare Officer/Social Worker Ms./Mr. _____ of the organization (address) _____.

The child (name) _____ is placed in foster care for a period of _____ (days/months), under the supervision of the aforesaid Child Welfarer Officer/Social Worker (name and contact) _____.

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

FORM XVIII

[Rule 43 (5)]

ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT

The juvenile/child (name and address) _____
 approximate age _____ d/o or s/o Mr. _____ and
 Mrs. _____ or Ms. _____

has been identified by the State/District Child Protection Unit as a juvenile/child at risk needing urgent care and protection. On the basis of the Inquiry Report submitted by the State/District Child Protection Unit/Child Welfare Officer/Social Worker it is established that the said juvenile/child needs sponsorship support for education/health/nutrition/other developmental needs _____ (please specify). The State/District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs. _____ per month/Rs. _____ as one time sponsorship support to the said juvenile/child for a period of _____ (days/month) and carryout necessary follow up.

State/District Child Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and conditions for sponsorship support and follow up.

Pricipal Magistrate, Juvenile Justice Board/

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government

FORM XIX

[Rule 44(4)]

ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT

The juvenile/child (name) _____ d/o _____ or s/o _____ has /will be completing 18 years of age on (date)_____. She/he is still in need of care and protection for the purpose of rehabilitation and reintegration. She/he is placed in (name of organization) _____ for providing aftercare. The in-charge of the organization is directed to admit the child and providing all possible opportunities for her/his rehabilitation and reintegration in its truest sense. The person shall be provided all these opportunities maximum till the age of 21 years only or till reintegration in the society, whichever is earlier. The in-charge will send halfyearly report on the status of the child/youth to the Child Welfare Committee.

The State/District Child Protection Unit is hereby directed to arrange for aftercare for the said juvenile/child for a period of _____ (days/month) and carryout necessary follow up. The State/District Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and conditions for aftercare programme and carryout necessary follow up.

**Pricipal Magistrate, Juvenile Justice Board/
Chairperson/Member, Child Welfare Committee**

Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government

FORM XX

[Rule 57(8) and 61(1) (t)]

CASE HISTORY FORM FOR CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION

Case/Profile No. _____

Date & Time _____

A. PERSONAL DATA

1. Name
2. Male/Female (tick the appropriate category)
3. a.) age at the time of admission
b.) present age:
4. Category:
 - Separated from family
 - Abandoned/deserted
 - Victim of exploitation and violence (give detail)
 - Run-away
 - Any other
5. Religion Hindu(OC/BC/SC/ST)
Muslim/Christian/Other(pl. specify)
6. Location of Residence Urban/Sub-urban/Rural/Slum/Industrial/Other (pl. specify)
7. Native District & State:
8. Description of the Housing:
 - i) Concrete building Tiled house/Hut/On the street/Others (please specify)
 - ii) Three bed room/two-bed room/one-bed room/no separate bed room
 - iii) Owned/rental
9. By whom the juvenile was brought before the Child Welfare Committee:
 - i) Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/Railway Police/Women Police
 - ii) Probation Officers
 - iii) Social Welfare Organization
 - iv) Social Worker
 - v) Parent (s)/Guardian (s) (please specify the relationship)
 - vi) Child himself/herself
10. Reasons for leaving the family
 - i) Abuse by parent(s) guardian(s) /step parents(s)
 - ii) In search of employment
 - iii) Peer group influence
 - iv) Incapacitation of parents
 - v) Criminal behaviour of parents
 - vi) Separation of parents
 - vii) Demise of parents
 - viii) Poverty
 - ix) Others (please specify)
11. Types of abuse met by the child
 - i) Verbal abuse – Parents/siblings/employers/others (pl. specify)
 - ii) Physical abuse
 - iii) Sexual abuse-Parents/siblings/employers/others (pl. specify)
 - iv) Others – Parents/siblings/Employers/others (pl. specify)
12. Types of ill-treatment met by the child.
 - i) Denial of food - parents/siblings/employers/other(pl. specify)
 - ii) Beaten mercilessly– parents/siblings/employers/other (pl. specify)

iii) Causing injury – parents/siblings/employers/other (pl. specify)
 iv) Other (pl. specify) – parents/siblings/employers/other (pl. specify)

13. Exploitation faced by the child

- i) Extracted work without payment
- ii) Little (low) wages with longer duration of work
- iii) Other (pl. specify)

14. Health status of the child before admission.

i) Respiratory disorders	- present/not known/absent
ii) Hearing impairment	- present/not known/absent
iii) Eye diseases	- present/not known/absent
iv) Dental disease	- present/not known/absent
v) Cardiac diseases	- present/not known/absent
vi) Skin disease	- present/not known/absent
vii) Sexually transmitted diseases	- present/not known/absent
viii) Neurological disorders	- present/not known/absent
ix) Mental handicap	- present/not known/absent
x) physical handicap	- present/not known/absent
xi) Other (pl. specify)	- present/not known/absent

15. With whom the child was staying prior to admission

- a. Parent(s) – Mother/Father/Both
- b. Guardian(s) – Relationship
- c. Friends
- d. On the street
- e. Night shelter
- f. Orphanages/Hostels/Similar Homes
- g. Other (pl. specify)

16. Visit of the parents to meet the child

- a. Prior to institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/Never
- b. After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/Never

17. Visit of the child to his family

- a. Prior to institutionalization– Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never
- b. After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

18. Correspondence with parents –

- i) Prior to institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never
- ii) After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

B. CHILDHOOD HISTORY (up to the age of 12 years)

19. Diet of Mother during pregnancy

- a. Taken nutritious diet
- b. Ordinary diet
- c. Inadequate food intake

20. Health during pregnancy

- a. Mother infected with contagious diseases
- b. Mother consumed/used contraceptives
- c. Intake of antibiotics
- d. No such details available
- e.

21. Birth details

- a. Normal delivery/prolonged delivery/caesarian
- b. Under weight/normal weight/over weight

22. Details of immunization provided**23. Details of handicap/disability**

- i) Hearing impairment By birth /After accident/diseases
- ii) Speech impairment By birth /After accident/diseases
- iii) Physical handicap/disability By birth /After accident/diseases
- iv) Mental handicap/disability By birth /After accident/diseases
- v) Other (please specify)

C. FAMILY DETAILS:**24. Household Composition:**

S. No.	Name & Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income
1	2	3	4	5	6	7

Health	History of Mental illness	Handicap/Disability	Habit	Socialization
8	9	20	11	12

25. Type of family.—Nuclear family / Joint family/ Broken family

26. Relationship among the family members:

- i) Father & mother Cordial/ Non cordial/ Not known
- ii) Father & child Cordial/ Non cordial/ Not known
- iii) Mother & child Cordial/ Non cordial/ Not known
- iv) Father & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known
- v) Mother & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known
- vi) Juvenile & siblings Cordial/ Non cordial/ Not known

27. History of crime committed by family members:

Sl. No.	Relationship	Nature of crime	Arrest if any made	Period of confinement	Punishment awarded
1.	Father				
2.	Step-father				
3.	Mother				
4.	Step-mother				
5.	Brother (a) (b) (c) (d)				
6.	Sister (a) (b) (c) (d)				
7.	Child				
8.	Others (uncle/aunty/ grandparents)				

28. Properties owned by the family:

- i) Landed properties (pl. specify the area)
- ii) Household articles-Crows/cattle/Bull
- iii) Vehicles-two wheeler/three wheeler/four wheeler (lorry/bus/car/tractor/jeep)
- iv) Others (please specify)

29. Marriage details of family members:

- i) Parents Arranged/Special Marriage/Local Union
- ii) Brothers Arranged/Special Marriage/Local Union
- iii) Sisters Arranged/Special Marriage/Local Union

30. Social activities of family members:

- i) Participate in social and religious functions
- ii) Participate in cultural activities
- iii) Does not participate in social and religious function
- iv) Not known

31. Parental care towards juvenile before admission:

- i) Over protection
- ii) Affectionate
- iii) Attentive
- iv) Not affectionate
- v) Not attentive
- vi) Rejection

D. ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 years)**32. puberty**

- Early
- Middle age
- Late

33. Details of delinquent behaviour if any

- i) Stealing
- ii) Pick pocketing
- iii) Arrack selling
- iv) Drug pedaling
- v) Petty offences
- vi) Violent crime
- vii) Rape
- viii) None of the above
- ix) Others (Please specify)

34. Reason for delinquent behaviour

- i) Parental neglect
- ii) Parental overprotection
- iii) Parents criminal behaviour
- iv) Parents influence (negative)
- v) Peer group influence
- vi) To buy drugs/ alcohol
- vii) Others (pl. specify)

35. Habits

A	B
i) Smoking	i) Watching TV/movies
ii) Alcohol consumption	ii) Playing indoor/outdoor games
iii) Drug use (specify)	iii) Reading books
iv) Gambling	iv) Religious activities
v) Begging	v) Drawing/painting/acting/singing
vi) Any other	vi) Any other

E. EMPLOYMENT DETAILS**Employment details of the juveniles prior to entry into the Home:**

S. No.	Details of employment	Duration	Wages earned
i	Cooly		
ii	Rag picking		
iii	Mechanic		
iv	Hotel work		

S. No.	Details of employment	Duration	Wages earned
v	Tea shop work		
vi	Shoe Polish		
vii	Household works		
viii	Others (Pl specify)		

36. Details of income utilization:

- (i) Sent to family to meet family need
- (ii) For dress materials
- (iii) For gambling
- (iv) For prostitution
- (v) For alcohol
- (vi) For drug
- (vii) For smoking
- (viii) Savings

37. Details of savings

- i) With employers
- ii) With friends
- iii) Bank/post Office
- iv) Others (pls specify)

38. Duration of working hours

- i) Less than six hours
- ii) Between six and eight hours
- iii) More than eight hours

F. EDUCATIONAL DETAILS**39. The details of education of the juvenile prior to the admission to Children's Home**

- (i) Illiterate
- (ii) Studied up to V Standard
- (iii) Studied above V Std but below VIII Standard
- (iv) Studied above VIII Std but below X Standard
- (v) Studied above X Standard

40. The reason for leaving the school

- (i) Failure in the class last studied
- (ii) Lack of interest in the school activities
- (iii) Indifferent attitude of the teachers
- (iv) Peer group influence
- (v) To earn and support the family
- (vi) Sudden demise of parents
- (vii) Rigid school atmosphere
- (viii) Absenteeism followed by running away from school
- (ix) Other (pls specify)

41. The details of the school in which studied last:

- (i) Corporation/Municipal/Panchayat Union
- (ii) Government/SC welfare School/BC Welfare School
- (iii) Private management
- (iv) Convents

42. Medium of instruction:

Hindi/English/Urdu/Tamil/Malayalam/Kannada/ Telugu Other language (please specify)

43. After admission to Children's Home, the educationl attainment from the date of admission till date:

No. of years	Class studied	Promoted/ detained
--------------	---------------	--------------------

44. Vocational training undergone from the date of admission into Children's Home till date.

No. of years	Name of Vocational Trade	Proficiency Attained
--------------	--------------------------	----------------------

45. Extra curricular activities developed form the date of admission into the Children's Home till date.

- i.) Scout
- ii.) Sports (please specify)
- iii.) Athletics (please specify)
- iv.) Drawing
- v.) Painting
- vi.) Others (pl. specify)

G. MEDICAL HISTORY

46. Height and weight at the time of admission:-

47. Physical condition:

48. Medical History of child (gist):

49. Medical History of parent/guardian (gist):

50. Present Health Status of the Child:

Sl. No.	Annual Observation	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
1.	Date of review				
2.	Height				
3.	Weight				
4.	Nutritious diet given				
5.	Stress disease				
6.	Dental				
7.	ENT-Tonsils				
8.	External eye problem: vision				
	Left				
	Right				

51. Height and Weight Charr:

H. SOCIAL HISTORY

52. Details of friendship prior to admission into Children' s Home:

- i. Co-workers
- ii. School/Classmate
- iii. Neighbours
- iv. Others (pl. specify)

53. Majority of the friends are

- i. Educated
- ii. Illiterate
- iii. The same age group
- iv. Older in age
- v. Younger in age
- vi. Same sex
- vii. Opposite sex

54. Details of membership in group (please specify details)

- i. Associated with cine fans association
- ii. Associated with religious group
- iii. Associated with arts and sports club
- iv. Associated with gangs
- v. Associated with voluntary social service league
- vi. Others (please specify)

55. The position of the child in the groups/league

- i. Leader
- ii. Second level leader
- iii. Middle level functionary
- iv. Ordinary member

56. Purpose of taking membership in the group:

- i. For social service activities
- ii. For leisure time spending
- iii. For pleasure seeking activities
- iv. For deviant activities
- v. Others (please specify)

57. Attitude of the group/league

- i. Respect the social norms and follow the rules
- ii. Interested in violating the norms
- iii. Impulsive in violating the rules

58. The location/meeting point of the groups

- i. Usually at fixed place
- ii. Places are changed frequently
- iii. No specific places
- iv. Meeting point is fixed conveniently

59. The reaction of the society when the child first came out of the family

- i. Supportive
- ii. Rejection
- iii. Abuse
- iv. Ill-treatment
- v. Exploitation

60. The reaction of the police towards children

- i. Passionate
- ii. Cruel
- iii. Abuse
- iv. Exploitation
- v. Ill-treatment

61. The response of the general public towards the child**HISTORY OF THE CHILD(GIST)**

- i. Education
- ii. Health
- iii. Vocational training
- iv. Extra curricular activities
- v. Others

Suggestion of Child Welfare Officer/Probation Officer after orientation to juvenile/child and the response towards orientation.

Follow up by Child Welfare Officer/Probation Officer/Case-Worker/Social Worker
Quarterly Review of Case History by Management Committee

**SUPERINTENDENT/
WELFARE OFFICER/PROBATION OFFICER**

FORM XXI**[Rules 57(11)(a), 61(1)(o) and 80(1)(k)]****INDIVIDUAL CARE PLAN**

Individual care plan for each child shall be prepared following the principle of the best interest of the child. In preparing individual care plan the care options in the following order of preferences shall be considered:-

- (i) Preserving the biological family
- (ii) Kinship Care
- (iii) In-country adoption
- (iv) Foster Care
- (v) Inter-country Adoption
- (vi) Institutional Care

Case/profile No.....of 20 -----(year) of the Board/Committee

Admission No.

Date of Admission:

A. PERSONAL DETAILS

- 1. Name of the Child:**
- 2. Age:**
- 3. Sex: Male/Female**
- 4. Father's/Mother's name:**
- 5. Nationality:**
- 6. Religion/Caste:**
- 7. Educational attainment:**
- 8. Summary of Case History:**
 - Health needs
 - Emotional and psychological support needed
 - Educational and Training needs
 - Leisure, creativity and play
 - Attachments and Relationships
 - Religious beliefs
 - Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment
 - Social mainstreaming
 - Follow-up post release/restoration

B. FORTNIGHTLY PROGRESS REPORT OF PROBATIONER**Part One**

1. Name of the Probation Officer/Case-Worker
2. For the month of
3. Registration No.
4. Competent Authority
5. Profile No.
6. Name of the Child
7. Date of Supervision Order
8. Address of the Child
9. Period of Supervision

Part Two**Places of interview**

.....
.....
.....

Date

.....
.....
.....

1. Where the child is residing?
2. Progress made in any educational/training course.
3. What work he/she is doing and his/her monthly average earning, if employed.
4. Savings kept in the Post Office.
5. Savings Bank Account in his/her name.
6. Remarks on his/her general conduct and progress
7. Whether property cared for?

Part Three

- 1. Any proceedings before the competent authority or**
 - a) Variation of conditions of bond
 - b) Change of residence
 - c) Other matters
2. Period of supervision completed on
3. Result of supervision with remarks (if any)
4. Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the juvenile is to live after the supervision is over.

Date of report _____ Signature of the Probation Officer/Case Worker_____

C. PRE-RELEASE REPORT

Tick whichever is applicable.

Final Release

Transfer

1. Details of place of transfer and concerned authority responsible in the place of transfer/release
2. Details of placement of the juvenile/child in different institutions
3. Training undergone and skills acquired
4. Final progress report of the officer-in-charge/probation officer/ child welfare officer/ case worker/ social worker (to be attached)
5. Date of release/transfer
6. Date of repatriation
7. Requisition for escort if required
8. Identification of escort
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements
10. Sponsorship requirement and report, if applicable
11. Identification of Probation Officer/ Case-worker/ social worker/non-governmental organization for post-release follow-up
12. Memorandum of Understanding with non-governmental organization identified for post-release follow-up
13. Identification of sponsorship agency/individual sponsor for the child post-release, if any
14. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor
15. Details of Savings Account of the child, if any
16. Details of child's earnings and belongings if any
17. Details of awards/rewards due to the child if any
18. Opinion of the child
19. Any other information

Note:— Pre-release reports shall be prepared 6 months prior to the date of release/transfer of juvenile/ child and shall take into account the recommendations of the last review report and all other relevant information.

D. POST-RELEASE REPORT

1. Status of Bank Account: Closed/ Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his/her parents/guardians-Yes/ No
3. First interaction report of the probation officer/child welfare officer/ case worker/social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release
4. Placement of the juvenile/child if any
5. Family's behaviour towards the child
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/ community
7. How is the child using the skills acquired?
8. Whether the child has been admitted to a chool or vocation? Give date and name of the school/ institute/ any other agency
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively

FORM XXII
[Rule 73 (2)]
ESCORT ORDER

Case No.....

In the matter of Boy/Girl Child

.....

Aged about year taken
Charged for sole custody under
Section 33(3) of the Juvenile
Justice Act 2000

The Parents of the boy/girl child are reported to be residing at:

He/She therefore be sent under supervision of a proper police/non-governmental organization escort to the

For tracing and for handing over to the parents or close relatives of the said Boy Child/Girl Child residing at the aforesaid address or at other place which may be shown by the Child, if no such parents or relative are traced or if traced but they are unwilling to take charge of the boy/girl be kept in the custody of the Superintendent Children's Home and the said Boy/Girl child be produced before the concerned Child Welfare Committee for further orders.

Orders

Pending Escort, the said Boy/Girl Child shall remain in Children's Home, residing at present at The State/District Child Protection Unit, or Police Department or non-governmental organization/Childline shall positively make immediate arrangement not less than 15 days from the date of receipt of this order by him and send the said Boy Child/Girl Child at his/her aforesaid place of residence.

Dated this day of 20.....

Chairperson/Member
Child Welfare Committee

CC to:

1. The Superintendent, Children's Home.,
- 2.The State/District Child Protection Unit or non governmental organization or Childline.

Ref.: 1. Order of admission of minorborn onProfile No.....

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1283-571+2000-३०८०८०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>